RNI NO. DELHIN/2012/48369
वर्ष 8 अंक 12
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, 14 नवंबर, 2019
पृष्ठ 16 मूल्य ₹ 3
नगर संस्करण

नई दिल्ली, लखनऊ, रायपुर और फरीदाबाद से प्रकाशित

पायनियर

'पवन पूजा' को लेकर उत्साहित हैं एंजेला
विविध-16

www.dailypioneer.com

प्रदूषण से फिर इमरजेंसी जैसे हालात

स्कूल 15 तक बंद, ऑड ईवन को आगे बढ़ा सकती है सरकार

● प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर रोक भी बढ़ाई गई

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

नई दिल्ली वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर के बीच मास्क लगाए साइकिल से जातीं लड़कियां

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार को वायु प्रदूषण फिर बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच गया और इमरजेंसी जैसे हालात बन गए। सरकारी एजेंसी सफर के अनुसार बुधवार रात नौ बजे राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 472 तक पहुंच गया। दिन में तीन बजे यह 464 था। लगातार बिगड़ते हालात के चलते दिल्ली-एनसीआर के सरकारी और निजी स्कूल 15 नवंबर तक बंद कर दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑड ईवन को भी आगे बढ़ाने के संकेत दिए हैं। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने आप सरकार से ऑड ईवन के प्रभाव का आकलन करने के लिए अक्टूबर से 14 नवंबर तक के आंकड़े उपलब्ध कराने को कहा है।

राजधानी में पिछले 15 दिन में दूसरी बार प्रदूषण का स्तर आपात स्थिति में पहुंचा है। पिछले दो दिन से इसमें बढ़ोतरी हो रही है। बुधवार को सुबह साढ़े 11 बजे एक्यूआई 454 रहा। इसके बाद लगातार बढ़ता गया। रात को यह 472 अंक पर पहुंच गया जो बेहद गंभीर स्थिति के करीब है।

जहांगीरपुरी और रोहिणी सबसे अधिक प्रदूषित इलाके रहे, जहां एक्यूआई 483 रहा। मुंडका और बवाना में एक्यूआई 479, नोएडा में 470, गाजियाबाद में 467, ग्रेटर नोएडा में 462, ग्रुग्राम में 447 और फरीदाबाद में 446 के अंक को छू गया। एक्यूआई 500 अंक पार करते ही यह अति गंभीर श्रेणी में आ जाता है और आपात स्थिति घोषित कर दी जाती है। जिसमें स्कूल बंद करने, निर्माण कार्य रोकने, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग बंद करने, खुले में कूड़ा-कचरा जलाने से रोकने और उपायों के तहत पानी का छिड़काव करने के आदेश दिए जाते हैं। पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण (ईपीसीए) ने दिल्ली-एनसीआर में स्कूल बंद करने के साथ-साथ हॉट-मिक्स प्लांट्स और स्टोन-क्रशर पर लगे प्रतिबंध को भी 15 नवंबर तक बढ़ा दिया है।

हरियाणा और पंजाब में पराली जलने में वृद्धि के कारण उत्तर-पश्चिमी हवाएं दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में अधिक धुआं ला रही है। हालांकि सरकार की वायु गुणवत्ता निगरानी सेवा सफर के अनुसार अफगानिस्तान और पड़ोसी इलाकों के ऊपर चक्रवाती तूफान के कारण नए सिरे से पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है। अगले दो दिन में इसका असर देश के उत्तर पश्चिमी इलाकों पर पड़ेगा और इससे शुक्रवार (शेष पेज 10)

सुप्रीम कोर्ट ने मांगे प्रदूषण के आंकड़े

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जहरीली होती हवा का प्रभाव कम करने के लिए लागू ऑड ईवन योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को नोटिस जारी कर दिल्ली सरकार से अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच प्रदूषण के आंकड़े पेश करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने इसके साथ ही यह भी कहा कि पिछले साल एक अक्टूबर से 31 दिसंबर, 2018 की अवधि के भी प्रदूषण संबंधी आंकड़े उसके समक्ष रखे जाएं। न्यायालय ने नोएडा निवासी एक अधिवक्ता की याचिका पर यह आदेश दिया।

इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वायु प्रदूषण की समस्या के स्थाई समाधान के लिए हाइड्रोजन आधारित जापानी प्रौद्योगिकी अपनाने पर विचार-विमर्श किया जाए। शीर्ष अदालत ने सरकार से आगामी तीन दिसंबर को अपने नतीजों से अवगत कराने का निर्देश दिया है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एसए बोबडे ने कहा कि चूंकि सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने स्वयं ही जापानी प्रौद्योगिकी की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है, इसलिए केंद्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उत्तर भारत के दूसरे राज्यों में इस प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की व्यवहार्यता की संभावना तलाशे।

कर्नाटक के 17 बागी विधायकों को राहत

अयोग्यता सही लेकिन लड़ सकते हैं चुनाव: सुप्रीम कोर्ट

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली/बेंगलुरू

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कर्नाटक में कांग्रेस-जद (एस) के 17 विधायकों की अयोग्यता को सही ठहराया लेकिन उन्हें थोड़ी राहत देते हुए 15 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव लड़ने की अनुमति दे दी। इन विधायकों की बगावत के कारण कुमारस्वामी की सरकार गिर गई थी और भाजपा ने सत्ता में वापसी की थी।

न्यायमूर्ति एनवी रमण, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष केआर रमेश कुमार के आदेश का वह हिस्सा निरस्त कर दिया जिसमें इन विधायकों को 15वीं विधानसभा के कार्यकाल के अंत तक के लिए अयोग्य घोषित किया गया था। विधान सभा कार्यकाल 2023 तक है।

पीठ ने अपने फैसले में कहा कि संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत अध्यक्ष को प्रदत्त अधिकारों में उन्हें न तो अयोग्य घोषित व्यक्ति की अयोग्यता की अवधि निर्धारित करने और न ही किसी को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने का अधिकार प्राप्त है। पीठ ने अपने 109 पेज के फैसले में कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा खरीद फरोख्त और भ्रष्ट आचरण में संलिप्त होने के अलावा अध्यक्षों में भी तटस्थ रहने के संवैधानिक कर्तव्य के खिलाफ काम करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है और इस वजह से नागरिकों को स्थाई सरकार नहीं मिल पा रही है।

पीठ ने कहा कि अध्यक्ष के एक तटस्थ व्यक्ति होने की वजह से अपेक्षा की जाती है कि सदन की कार्यवाही के संचालन या याचिकाओं पर निर्णय लेते समय वह स्वतंत्र तरीके से काम करेंगे।

न्यायालय ने कहा कि अध्यक्ष को सौंपी गई संवैधानिक जिम्मेदारी का ईमानदारी से पालन करना होगा और न्याय करते समय उसकी राजनीतिक संबद्धता आड़े नहीं (शेष पेज 10)

भाजपा में आज शामिल होंगे बागी एमएलए

बेंगलुरु। उच्चतम न्यायालय में कांग्रेस और जद एस के 17 अयोग्य विधायकों के लिए पांच दिसंबर को होने वाले उपचुनाव लड़ने का मार्ग प्रशस्त किए जाने के कुछ ही घंटे बाद उप मुख्यमंत्री अश्वत्थनारायण सीएन ने दावा किया कि विपक्षी दलों के ये नेता 14 नवंबर को भाजपा में शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा, उनलोगों (अयोग्य विधायकों) ने भाजपा में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है और हमारे वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है। पार्टी में शमिल होने के लिए उनका स्वागत है। दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि कल सुबह साढे दस बजे बेंगलुरू में वह मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार कतील की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अश्वत्थनारायण के साथ कुछ अयोग्य विधायकों ने फैसले के बाद भाजपा के संगठन महासचिव बीएल संतोष से (शेष पेज 10)

विपक्ष के पास सरकार बनाने के लिए अब पूरा मौका: शाह

● महाराष्ट्र के सियासी संकट पर तोड़ी चुप्पी, कहा-शिवसेना की शर्तें हमें मंजूर नहीं

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने बुधवार को महाराष्ट्र के सियासी हालात पर पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि अब वहां सभी विपक्षी दलों के पास सरकार बनाने का मौका है। उन्होंने कहा कि कई बार मैं और पीएम नरेंद्र मोदी सार्वजनिक तौर पर कह चुके थे कि अगर हमारा गठबंधन चुनाव जीतेगा तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे।

उन्होंने कहा कि उस समय किसी ने इसका विरोध नहीं किया था। शिवसेना अब नई मांग के साथ सामने आई है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन लगाए जाने पर उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उचित कदम उठाया है और अब सबके पास सरकार बनाने के लिए 6 महीने का वक्त है। राज्यपाल के कदम का बचाव करते हुए कहा कि इससे पहले सरकार गठन के लिए इतना वक्त किसी राज्य में नहीं दिया गया था। 18 दिन का समय दिया गया। राज्यपाल में सभी पार्टियों को तभी बुलाया जब विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया। शिवेसना, कांग्रेस, एनसीपी और न हमने सरकार बनाने का दावा किया। अगर आज भी किसी दल के पास नंबर है तो वो (शेष पेज 10)

सीएमपी पर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का मंथन जारी

पायनियर समाचार सेवा। मुंबई

महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के एक दिन बाद बुधवार को शिवसेना, कांग्रेस और राकांपा नेताओं ने सरकार गठन के लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम (सीएमपी) तैयार करने के लिए गहन चर्चा की। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने सुबह करीब एक घंटे तक महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि सरकार गठन के लिए बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख बालासाहेब थोराट ने ठाकरे के साथ बैठक को शिष्टाचार भेंट बताया और कहा कि वे मिल रहे हैं, यह अपने (शेष पेज 10)

प्रधान न्यायाधीश का कार्यालय भी आरटीआई के दायरे में

● उच्चतम न्यायालय की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने दिया अहम फैसला

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि प्रधान न्यायाधीश का कार्यालय सार्वजनिक प्राधिकरण है और वह सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आता है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्ईय संविधान पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 2010 के निर्णय को सही ठहराते हुए इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय के सेक्रेटरी जनरल और शीर्ष अदालत के केन्द्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी की अपील खारिज कर दी।

यह व्यवस्था देते हुए संविधान पीठ ने आगाह किया कि सूचना के अधिकार कानून का इस्तेमाल निगरानी रखने के हथियार के रूप में नहीं किया जा सकता है और पारदर्शिता के मुद्दे पर विचार करते समय न्यायपालिका की स्वतंत्रता को ध्यान में रखना चाहिए। यह निर्णय सुनाने वाली संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति एनवी रमण, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना शामिल थे। संविधान पीठ ने कहा कि कॉलेजियम द्वारा न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के लिए की गई सिफारिश में सिर्फ न्यायाधीशों के नामों की जानकारी दी जा सकती है लेकिन इसके कारणों की नहीं। प्रधान न्यायाधीश, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने एक फैसला लिखा जबकि न्यायमूर्ति एनवी रमण और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ ने अलग निर्णय (शेष पेज 10)

राफेल मामले पर आज निर्णय करेगा कोर्ट

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय राफेल सौदे पर सरकार को क्लीन चिट देने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार की मांग कर रही याचिकाओं पर गुरुवार को फैसला सुनाएगा। शीर्ष अदालत राफेल मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री - यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी तथा कार्यकर्ता-वकील प्रशांत भूषण समेत कुछ अन्य की याचिकाओं पर फैसला सुनाएगी जिनमें पिछले साल के 14 दिसंबर के उस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई है जिसमें फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट से 36 लड़ाकू विमान खरीदने (शेष पेज 10)

सबरीमाला मामले में भी पुनर्विचार याचिकाओं आज आएगा फैसला

नई दिल्ली। केरल में स्थित सबरीमला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने के उच्चतम न्यायालय के फैसले पर पुनर्विचार के लिए दायर याचिकाओं पर सर्वोच्च अदालत बृहस्पतिवार को फैसला सुनाएगी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्ईय संविधान पीठ 28 सितंबर, 2018 के फैसले के पश्चात हुए हिंसक विरोध के बाद 56 पुनर्विचार याचिकाओं सहित कुल 65 याचिकाओं पर फैसला सुनाएगी। संविधान पीठ ने इन याचिकाओं पर इस साल छह फरवरी को सुनवाई पूरी की थी और कहा था कि इन पर फैसला बाद में सुनाया जाएगा। इन याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली संविधान पीठ के सदस्यों में न्यायमूर्ति आर एफ नरिमन, न्यायमूर्ति ए एम (शेष पेज 10)

राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना मामले में भी आज ही होगा निर्णय

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय राफेल मामले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बारे में चौकीदार चोर है टिप्पणी के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ लंबित अवमानना मामले में बृहस्पतिवार को फैसला सुनाएगा। राफेल मामले में न्यायालय के 14 दिसंबर, 2018 के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका के समर्थन में चुनिन्दा दस्तावेज की स्वीकार्यता पर केन्द्र की प्रारंभिक आपत्तियां अस्वीकार करने के शीर्ष अदालत के फैसले के बाद दस अप्रैल को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ये टिप्पणी की थी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही के लिए लंबित इस मामले पर 10 मई को सुनवाई पूरी की थी। पीठ ने कहा (शेष पेज 10)

मौसम

अधिकतम	28.3°C (0)
न्यूनतम	13.4°C (0)

बाजार

सेंसेक्स	40,116	↓ 229	
निफ्टी	11,840	↓ 73	
सोना	38,715	↑ 225	/10g
चांदी	45,480	↑ 440	/kg

क्विक न्यूज

कोर्ट ने न्यायाधिकरणों पर तय नियमों को निरस्त किया

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सरकार को झटका देते हुए बुधवार को विभिन्न न्यायाधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति और सेवा शर्तों के संबंध में केंद्र द्वारा बनाए गए नियमों को खारिज कर दिया। न्यायालय ने धन विधेयक के रूप में वित्त अधिनियम 2017 को पारित कराने की वैधता की जांच के लिए इसे बड़ी पीठ के पास भेज दिया। विपक्षी दलों ने संसद में इस विधेयक का जोरदार विरोध किया था। उच्चतम न्यायालय ने संशोधित वित्त अधिनियम 2017 में वर्णित नियमों को रद्द कर दिया।

अयोध्या की सूरत बदलने की तैयारी, तिरुपति जैसा होगा शहर

बनेगा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, सरयू नदी में चलेगा क्रूज

● मंदिर के पास 77 एकड़ परिसर में बनाए जाएंगे कई धार्मिक संस्थान

● रामनगरी में तैयार किए जाएंगे 10 श्रीराम द्वार

● दिसंबर से पांच सितारा होटल का काम हो जाएगा आरंभ

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/अयोध्या

फाइल फोटो

मंदिर निर्माण के लिए अभी तक 65 प्रतिशत पत्थर तराशे जा चुके हैं और अगर 2000 कारीगर एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं तो ढाई वर्ष में मंदिर बन कर तैयार हो जाएगा : अयोध्या मंडल के सूचना उप निदेशक मुरलीधर सिंह

अयोध्या प्रकरण पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अब अयोध्या के विकास की कार्ययोजना बनाई जा रही है जिसमें सरयू नदी पर क्रूज (पानी का छोटा जहाज) चलाना भी शामिल है। अयोध्या मंडल के सूचना उप निदेशक मुरलीधर सिंह ने विकास योजनाओं के बारे में बताया, सबसे पहले अयोध्या तीर्थ विकास परिषद का गठन किया जाएगा। सरयू नदी पर एक क्रूज चलाए जाने की योजना है। अयोध्या को तिरुपति जैसा शहर बनाने में कम से कम चार साल का समय लगेगा। सिंह ने बताया कि अयोध्या में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की दिशा में कार्य होगा। अप्रैल 2020 में राम नवमी पर पहली उड़ान भरी जा सकेगी। अयोध्या में रेलवे स्टेशन का विस्तार किया जाएगा जिसमें 100 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। उन्होंने बताया कि अयोध्या से फैजाबाद के (शेष पेज 10)

विहिप का सुझाव : मंदिर के प्रस्तावित ट्रस्ट में शाह, योगी को किया जाए शामिल

अयोध्या। अयोध्या में रामजन्मभूमि स्थल पर मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट का गठन करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश के पालन की दिशा में केंद्र सरकार ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसी बीच विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस ट्रस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। विहिप के प्रवक्ता शरद शर्मा ने बुधवार को यहां एक बार फिर उम्मीद जताई कि ट्रस्ट राम मंदिर का निर्माण रामजन्मभूमि न्यास द्वारा तैयार डिजाइन के अनुरूप ही करेगा। न्यास अयोध्या के कारसेवकपुरम में वर्ष 1990 से कलाकारों और शिल्पकारों के लिए कार्यशाला चला रहा है। इसमें कलाकारों ने कई पत्थरों और खंभों पर कलाकृतियां उकेरी हैं, इस उम्मीद के साथ, कि जब भी राम लला का मंदिर बनेगा तो इन्हें उसमें लगाया जाएगा। कार्यशाला के प्रभारी 79 वर्षीय अन्नू भाई सोमपुरा ने बताया कि रामजन्मभूमि न्यास की योजना (शेष पेज 10)

जेएनयू ने की फीस में आंशिक कमी, छात्रों ने बताया छलावा

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

● हॉस्टल किराया 300 से 100 और 600 से 200 किया गया

● मेंटीनेंस शुल्क 17,00 रुपये में नहीं की गई कोई कमी

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने छात्रों के उग्र विरोध के बाद हॉस्टल व अन्य मदों में फीस बढ़ाने का प्रस्ताव वापस ले लिया है। यह फैसला बुधवार को विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद की बैठक में लिया गया। नए प्रस्ताव के अनुसार दो सीट वाले हॉस्टल कमरे का किराया अब 100 और एक सीट वाले का 200 रुपये होगा। पहले इसे क्रमश: 10 रुपये से बढ़ाकर 300 और 20 रुपये से 600 किया गया था। कार्यकारिणी ने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की मदद योजना का ऐलान भी किया है।

छात्रों के आंदोलन के मद्देनजर आखिरी क्षणों में इसके आयोजन स्थल में बदलाव किया गया और इसे परिसर के बाहर आयोजित किया गया। इससे लेकर भी छात्रों और शिक्षकों ने विरोध दर्ज कराया है और कहा कि फीस वापसी सिर्फ दिखावा है। छात्रों ने कहा कि जेएनयू कार्यकारिणी परिषद ने साफ-सफाई, रखरखाव, कुक, मेस आदि में तय किया गया 17,00 रुपये शुल्क कम नहीं किया है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव आर सुब्रमण्यम ने ट्वीट कर ऐलान किया कि जेएनयू कार्यकारिणी परिषद (शेष पेज 10)

होमगार्ड ड्यूटी घोटाले में दर्ज हुआ मुकदमा

मंत्री ने डीजी को तलब कर मांगा स्पष्टीकरण-पूछा क्यों हुई देरी

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

जनपद गौतमबुद्धनगर में होमगार्डों की कथित तौर पर फर्जी हाजिरी लगाकर सरकार को करोड़ों रुपए की चपत लगाने के मामले में बुधवार को एक मुकदमा दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के होमगार्ड मंत्री चेतन चौहान ने होमगार्ड महानिदेशक को तलब कर पूरे प्रकरण की जानकारी मांगी और जानना चाहा कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कराने में देर क्यों हुई।

शासन स्तर की एक समिति होमगार्ड घोटाला मामले की जांच कर रही है। मामले में जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अपनी खुद की जांच के बाद होमगार्ड विभाग के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा लिखने की संस्तुति की थी। शासन ने अपने स्तर से भी जांच कराने का निर्णय लिया। अब इस मामले की जांच चार सदस्यीय टीम कर रही है।

एसएसपी वैभव कृष्ण ने सोमवार को बताया था कि उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ होमगार्ड ड्यूटी पर नहीं आते, लेकिन विभाग के अधिकारी थानों में उनकी उपस्थिति दिखाकर उनका वेतन निकाल लेते हैं। विभाग के ही एक संगठित गिरोह के माध्यम से यह हुआ। पुलिस अधिकारी के अनुसार, फर्जी उपस्थिति के आधार पर होमगार्ड जवानों के खाते में पैसा चला जाता था। घोटाले में शामिल लोग बाद में जवानों से अपना हिस्सा ले लेते थे।

इस मामले में प्रदेश के होमगार्ड मंत्री चेतन चौहान ने डीजी, होमगार्ड को तलब कर पूरा ब्यौरा मांगा। उन्होंने डीजी से यह स्पष्टीकरण भी मांगा कि मुकदमा दर्ज कराने में देर क्यों हुई? बहरहाल, बुधवार को जनपद गौतम बुद्ध नगर में इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है।

एसएसपी वैभव कृष्ण ने बताया करीब 5 थानों के सैंपल लिए गए थे, इसमें 2 महीने में करीब साढ़े सात लाख का घोटाला सामने आया है। अगर वहीं पूरे प्रदेश स्तर में इस तरह की गड़बड़ी की जा रही है तो करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आएगा, जिसमें जांच के बाद ही कई बड़े चेहरे भी बेनकाब हो सकते हैं।

एसएसपी ने बताया कि इस मामले में उन्होंने शासन को पत्र लिखा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की, उनके द्वारा सरकार को पत्र लिखे जाने के बाद होमगार्ड महानिदेशक ने इस मामले की जांच के लिए एक समिति बनाई। समिति में एसएसओ लखनऊ मुख्यालय सुनील कुमार, मिर्जापुर के जिला कमांडेंट शैलेंद्र प्रताप सिंह, बागपत की मंडल कमांडेंट नीता भारती और मेरठ के मंडल कमांडेंट डीडी मौर्या शामिल हैं। एसएसपी ने बताया कि जांच टीम के सदस्यों ने जिले के एक-एक थाने में जाकर 12 से 13 घंटे तक पत्रावालियों की जांच की जिसमें होमगार्ड की सबसे ज्यादा फर्जी उपस्थिति नॉलेज पार्क थानांतर्गत पाई गई हैं।

सोशल साइट पर अमर्यादित पोस्ट करने की शिकायत

नोएडा। सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी की पत्नी ने कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर उनकी बेटी तथा नातिन के खिलाफ कथित अमर्यादित पोस्ट करने की शिकायत की है।

थाना सेक्टर 49 के थानाध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा ने बुधवार को बताया कि बरौला गांव में रहने वाली, एक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी की पत्नी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनके परिवार के खिलाफ सोशल मीडिया पर अमर्यादित टिप्पणियां की गई हैं। शर्मा ने शिकायत के हवाले से बताया कि महिला को उनके एक परिचित जितेंद्र ने इस बारे में सूचित किया है। महिला के अनुसार, उनकी विवाहित बेटी तथा उनके दामाद के विरुद्ध अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है।

थानाध्यक्ष के अनुसार, महिला ने अपनी नातिन के खिलाफ भी सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक शब्द लिखे जाने का दावा किया। महिला का कहना है कि उनके दामाद भारतीय सेना में एक बड़े अधिकारी हैं। थानाध्यक्ष ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

50 करोड़ के टैक्स घोटाले में नगर आयुक्त ने बैठाई जांच

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

नगर निगम के टैक्स विभाग में 50 करोड़ के घोटाले में नगर आयुक्त दिनेश चंद्र ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। इस सिलसिले में एक जांच कमेटी गठित की गई है जो अपर नगर आयुक्त आरएन पांडेय की देखरेख में काम करेगी। मेयर आशा शर्मा ने देर रात एक बयान जारी कर टैक्स घोटाले से संबंधित कुछ साक्ष्य जारी किए थे। सुबूत जारी करते ही नगर निगम में हड़कंप मच गया।

पिछले काफी समय से मेयर आशा शर्मा व नगर आयुक्त दिनेश चंद्र के बीच खींचतानी चल रही है। भाजपा के ही दो वरिष्ठ पार्षदों राजेंद्र त्यागी व हिमांशु मित्तल ने मंगलवार शाम को मेयर को चुनौती दी थी वह हवा में बयानबाजी करने के बजाय टैक्स चोरी के सुबूत दें। दोनों पार्षदों की चुनौती के बाद मंगलवार को देर रात मेयर ने करोड़ों रुपयों की कर चोरी के सुबूत सार्वजनिक कर दिए।

इस संबंध में बुधवार सुबह कार्यालय पहुंचते ही नगर आयुक्त ने मेयर के पत्र का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश जारी कर दिए। नगर आयुक्त ने बताया कि मामले की जांच के बाद जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में मेयर ने बताया कि करोड़ों के टैक्स चोरी व हेराफेरी का मामला उनके संज्ञान में जून माह में ही आ गया था और इस पूरे प्रकरण की जानकारी लिखित रूप में नगर निगम प्रशासन को भेजी थी। लेकिन, आज तक इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी, इसलिए उन्हें यह मामला सार्वजनिक करना पड़ा। उन्होंने कहा कि मैं भ्रष्टाचार के मामले उठाती रहूंगी चाहे अंजाम कुछ भी हो।

उधर भाजपा पार्षद दल के नेता राजेंद्र त्यागी का कहना है कि मेयर ने जो सुबूत दिए हैं वह काफी पुराना मामला है।

गाजियाबाद रीजन को जल्द मिलेंगी 100 बसें

गाजियाबाद। प्रदूषण कम करने के लिए यूपी रोडवेज मुस्तैद नजर आ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग गाजियाबाद रीजन के बेड़े में बीएस-6 श्रेणी की 100 बसें शामिल करने जा रहा है। इसके साथ ही 50 सीएनजी बसों का संचालन भी जिले में किया जाएगा। इन बसों के जनवरी या फरवरी में यहां पहुंचने की संभावना है।

रोडवेज के आरएम एके सिंह ने बताया कि हाल ही में ईपीसीए के अध्यक्ष भूरे लाल की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। इस दौरान कमिटी ने रोडवेज से कहा था कि वह दिल्ली-एनसीआर में डीजल बसों का संचालन कम करें। इसके बाद ही यूपी रोडवेज ने गाजियाबाद रीजन को और सीएनजी 50 व 100 बीएस-6 श्रेणी की बसें आवंटित करने का फैसला लिया है। यहां से दिल्ली और यूपी के अन्य जिलों के लिए बसें संचालित होती हैं। इन बसों के मिलने से यूपी के अन्य हिस्से में भी प्रदूषण कम होगा।

गाजियाबाद में एक्यूआई लेवल पहुंचा 472

गाजियाबाद। एनसीआर में इस वक्त सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद बन चुका है। गाजियाबाद में प्रदूषण का स्तर डार्क रेड जोन में पहुंच गया है। प्रदूषण बढ़ने से बच्चों और बुजुर्गों को स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

दिल्ली-एनसीआर समेत गाजियाबाद में लगातार बढ़ते प्रदूषण से आम आदमी को जल्द राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। बीते दो दिनों से गाजियाबाद का प्रदूषण स्तर डार्क रेड जोन में चल रहा है। मंगलवार के मुकाबले बुधवार को गाजियाबाद के प्रदूषण में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। बुधवार को गाजियाबाद का प्रदूषण स्तर 472 एक्यूआई दर्ज किया गया।

सुनार से आभूषण लेकर फरार हो गया युवक

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

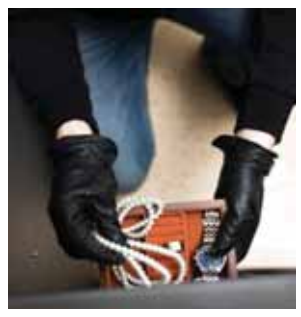

गाजियाबाद निवासी एक युवक सुनार को बहन की शादी का झांसा देकर 15 लाख रुपये के आभूषण लेकर भाग गया। पुलिस मामले की जांच करते हुए आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है। वहीं दोनों पक्षों में समझौते के प्रयास की बात भी कही जा रही है।

मिली जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल निवासी युवक ने ग्रेटर नोएडा के जगत फार्म में दो माह पूर्व किराये पर दुकान लेकर सुनार का काम शुरू किया था। एक फर्नीचर विक्रेता ने सुनार से एक युवक की जान पहचान कराई थी। युवक उसकी दुकान से एक दो बार आभूषण लेकर भी गया था। कुछ दिन पूर्व आरोपी सुनार के पास पहुंचा और कहा कि उसकी बहन की शादी है। वह कुछ आभूषण खरीदने से पहले अपने पिता को दिखाना चाहता है।

सुनार आरोपी के झांसे में आ गया और उसने करीब 15 लाख के आभूषण युवक को दे दिए। इसके बाद आरोपी वापस नहीं लौटा और अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लिया। पीड़ित सुनार, फर्नीचर विक्रेता के पास पहुंचा तो उसकी दुकान भी बंद थी। इसके बाद सुनार ने पुलिस से शिकायत की। मंगलवार को पुलिस ने गाजियाबाद में आरोपी के घर दबिश दी और उसके परिवार के एक सदस्य को थाने ले आई।

इस दौरान गाजियाबाद में आरोपी के परिजनों ने हंगामा भी किया। बाद में आरोपी के परिजन थाने पहुंचे और पीड़ित को सभी आभूषण वापस करने का भरोसा देने लगे। पुलिस का कहना है कि पीड़ित पक्ष अपने आभूषण वापस चाहता है, कार्रवाई नहीं चाहता। उसके आभूषण वापस दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रदूषण के चलते बंद कराए उद्योगों को चालू करने की मांग को लेकर डीआईसी के उपायुक्त बीरेंद्र कुमार से मिलते गाजियाबाद के उद्यमी।

प्रदूषण के चलते 19 दिन से बंद कारखानों को खोलने की मांग

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

● डीआईसी अधिकारी से मिले शहर के उद्यमी

शहर में प्रदूषण के लगातार बढ़ते स्तर के चलते विगत 19 दिनों से बन्द चल रहे उद्योगों से आहत इण्डस्ट्रीयल एरिया मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि मण्डल एवं अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल, जिलाधिकारी अजय शंकर पाण्डेय एवं उपायुक्त, डीईसी बीरेन्द्र कुमार से भेंट की।

इस दौरान संस्था द्वारा प्रदूषण के आंकड़े जारी करते हुए उनके सामने साफ किया कि प्रदूषण उद्योगों के कारण नहीं अन्य कारणों से बढ़ रहा है। जिसे अधिकारियों ने भी स्वीकार किया और जल्द उद्योगों को खुलवाने के आश्वासन दिया।

बैठक में महासचिव राजीव अरोड़ा ने कहा कि उद्योग पहले ही मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, अब बढ़ते प्रदूषण के लिए उद्योगों को कारण मानते हुए उनको बन्द करने के आदेश के चलते कोयला आधारित इंडस्ट्रीज़ बंदी के कगार पर आ गईं है। निर्यातक इकाइयां अपना आर्डर पूरा नहीं कर पा रही हैं।

संक्षिप्त समाचार

पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी से मिलकर उन्हें धन्यवाद अर्पित करते पार्षद हिमांशु लव, राकेश स्वामी व अन्य।

आडवाणी से भेंटकर धन्यवाद दिया

गाजियाबाद। राम मंदिर बनवाने के अभियान में मुख्य भागीदारी निभाने वाले पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के निवास पर पार्षद हिमांशु लव, रमते राम रोड व्यापार मंडल के अध्यक्ष राकेश स्वामी, चेयरमैन राजेश बंसल ने बुके देकर धन्यवाद किया। राकेश स्वामी ने कहा कि 25 सितंबर 1990 को लालकृष्ण आडवाणी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि - बाबरी मस्जिद विवादित स्थल पर राममंदिर निर्माण के लिए समर्थन जुटाने की खातिर गुजरात के सोमनाथ से रथयात्रा शुरू की थी। उनका इरादा राज्य-दर-राज्य होते हुए 30 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के अयोध्या पहुंचने का था, जहां वह मंदिर निर्माण शुरू करने के लिए होने वाली 'कारसेवा' में शामिल होने वाले थे। 23 अक्टूबर को उन्हें बिहार के समस्तीपुर में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के आदेश पर गिरफ्तार कर लिया गया था। हिमांशु लव ने बताया ऐसी शख्सियत का आशीर्वाद मिलना परम् सौभाग्य की बात है।

दिव्यांग छात्र-छात्राओं को बांटे उपकरण

हापुड़। शिक्षा विभाग की तरफ से दर्जनों दिव्यांगजन छात्र व छात्राओं को सहायक उपकरण वितरित किये गए जिन्हे पाकर दिव्यांग बच्चों और उनके परिजनों को काफी प्रसन्नता हुई। बेसिक शिक्षा विभाग समग्र शिक्षा अभियान के तत्वाधान में दिव्यांगजन छात्रों के सहायतार्थ कार्य करने वाली प्रमुख एजेंसी भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर एवं सर्व शिक्षा अभियान हापुड़ के संयुक्त प्रयास सक बुधवार को एक शिविर लगाकर दिव्यांगजन छात्रों को 7 ट्राई साईकिल, 5 व्हील चेयर, 2 वैशाखी, 11 केलिपर्स, 8 रॉकेटर, 6 ब्रेल किट, 4 श्रवण यंत्र, 2 सीपी चेयर, 7 एम्पायर कीट बांटे। जिला बेशिक अधिकारी देवेंद्र गुप्ता ने बताया की दिव्यांग बच्चों के लिए वितरण कैंप आज आयोजित किया गया है। इसका एक माह पूर्व मापन शिविर लगाया गया था। उन्होंने बताया कि सरकारी विद्यालयों में जो दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं उनकी आवश्यकतानुसा उनका मापन करके कानपुर की टीम ले गई थी। आज उन्हीं बच्चों को उपकरण बांटे गए।

योजनाओं एवं कार्यकारिणी की घोषणा

गाजियाबाद। अखिल भारतीय खत्री युवा महासभा ने बुधवार को अपनी योजनाओं एवं कार्यकारिणी की घोषणा की। खत्री सभा के संरक्षक महेश आहूजा और संचालक रत्न महेश कुमार सेठ ने संयुक्त रूप से बताया कि खत्री समाज कुरीतियों को दूर करने के लिए हमेशा काम करता रहा है। महिला सुरक्षा, कन्या सुरक्षा, महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण करना समाज की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि जिला अध्यक्ष के माध्यम से समाज मां-बेटा योजना चलाएगा। इसमें खत्री समाज की महिलाओं के खाते में प्रतिमाह दो हजार रुपये जमा कराने की योजना है। साथ ही रोजगार के क्षेत्र में भी खत्री समाज बेरोजगार लोगों को काम देने का काम करेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद अरोड़ा ने प्रेसवार्ता में अपनी टीम की भी घोषणा की। कार्यकारिणी में विरेन्द्र खन्ना को राष्ट्रीय महामंत्री, नीरज खत्री को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, प्रभुजीत सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आशीष कपूर को राष्ट्रीय सचिव, नितिन मल्होत्रा को कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त किया गया है।

शहर के रेलवे स्टेशन पर लगेगी बड़ी टीवी स्क्रीन, भेजा प्रस्ताव

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

जल्द ही गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों को दिल्ली और लखनऊ की तरह ट्रेनों की जानकारी देने के लिए बड़ी स्क्रीन लगेगी। इसके लिए मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा गया है। इससे स्टेशन पर यात्रियों को ट्रेन की जानकारी के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी।

बता दें कि लखनऊ स्टेशन पर टिकट विंडों के पास एक बड़ी एलईडी स्क्रीन लगी है। स्क्रीन पर एक घंटे के दौरान स्टेशन पर आने और जाने वाली ट्रेनों के अलावा प्रमुख ट्रेनों की जानकारी दी जाती है। इसमें ट्रेन के आने-जाने का समय, प्लैटफॉर्म और ट्रेन के लेट होने की भी जानकारी दी जाती है। ऐसी ही स्क्रीन दिल्ली स्टेशन पर लगी हैं।

स्टेशन अधीक्षक कुलदीप त्यागी ने बताया कि गाजियाबाद स्टेशन के बाहर 20 फुट लंबी और चौड़ी स्क्रीन लगाने का प्रस्ताव एक निजी कंपनी की ओर से आया है, जिसे मुख्यालय भेजा गया है।

स्क्रीन के 70 प्रतिशत हिस्से पर गाजियाबाद स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों की जानकारी होगी और 30 प्रतिशत हिस्से पर विज्ञापन होंगे।

निगम ने मुक्त कराई करोड़ों की जमीन

गाजियाबाद। शहर के गांव बोझा इलाके में नगर निगम ने बुधवार को भूमाफियाओं के कब्जे से करीब 26 हजार वर्ग मीटर जमीन कब्जामुक्त कराई। भूमि का बाजार मूल्य 200 करोड़ से रुपए से अधिक है। अब इस भूमि पर इलेक्ट्रिक बस चार्ज स्टेशन व शेड बनाया जायेगा। यह जानकारी बुधवार की शाम को नगर आयुक्त दिनेश चंद्र ने दी।

उन्होंने बताया कि इस भूमि पर काफी समय से देवेंद्र त्यागी नाम के व्यक्ति का अवैध कब्जा था। जिसका खसरा नंबर 2 व 16 है। यह सभी जमीन नगर निगम के स्वामित्व की थी। उन्होंने बताया कि इस भूमि पर इलेक्ट्रिक बसों के लिए शेड व चार्ज स्टेशन बनाया जायगा।

दादी का इलाज कराने आई महिला से दुष्कर्म

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

● शिकायत के बाद पुरुष नर्स को पुलिस ने हिरासत में लिया

शहर के एक निजी अस्पताल में कार्यरत एक पुरुष नर्स ने अपनी दादी का उपचार कराने आई एक महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है।

थाना सेक्टर 20 के प्रभारी निरीक्षक राजवीर सिंह चौहान ने बुधवार को बताया कि मामले में दर्ज शिकायत के अनुसार, अलीगढ़ निवासी युवती की शादी फरीदाबाद में हुई है। उन्होंने बताया कि युवती जून में अपनी दादी को उपचार के लिए नोएडा के सेक्टर 27 स्थित विनायक अस्पताल आई। उन्होंने बताया कि इलाज के दौरान, अस्पताल के एक पुरुष नर्स रजत मलिक ने दादी को नींद की गोली दी तथा शीतल पेय में मिलाकर नशीली दवा युवती को पिला दी।

शिकायत के हवाले से चौहान ने बताया कि आरोपी ने महिला से अस्पताल के एक कमरे बलात्कार किया। उन्होंने बताया कि सुबह जब महिला को अपने साथ हुई घटना का एहसास हुआ तो उसने रजत से शिकायत की। रजत ने उसे धमकी दी कि उसने घटना का वीडियो बनाया है और पीड़िता के मुंह खोलने पर वह वीडियो को सार्वजनिक कर देगा।

थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़िता अश्लील वीडियो की बात सुन कर डर गई और ससुराल चली गई। उन्होंने बताया कि चार नवंबर को पीड़िता ने पति को आपबीती बताई और फिर उन दोनों ने फरीदाबाद के महिला थाने में शिकायत की। चौहान ने बताया कि फरीदाबाद पुलिस ने मामले को जांच के लिए थाना सेक्टर 20 भेजा। उन्होंने बताया कि बीती रात को थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बुधवार सुबह आरोपी को हिरासत में ले लिया। उससे पूछताछ की जा रही है।

बाबा रामदेव के बयान पर उबाल, वाद दायर

गाजियाबाद। अनुसूचित जाति जनजाति, आदिवासी व मुस्लिम समुदाय के लोगों व बहुजन समाज के महापुरुषों पर बाबा रामदेव द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में गाजियाबाद के वकील ने न्यायालय में वाद दायर किया है।

साथ ही एक ज्ञापन बहुजन समाज के लोगों ने राष्ट्रपति को संबोधित जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा है। ज्ञापन में बहुजन समाज के लोगों ने बाबा रामदेव के बयान को शर्मनाक बताते हुए उनके खिलाफ कार्यवाही की मांग की है।

ट्रायल के बाद गौड़ सिटी मॉल के सामने कट बंद

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

ग्रेनो वेस्ट में गौड़ सिटी मॉल के सामने 130 मीटर एक्सप्रेसवे पर सर्विस लेन के कट को बंद कर दिया गया। कई दिनों से इसे बंद करने का ट्रायल किया जा रहा था।

इस कट से होकर वाहन मुख्य सड़क पर आते थे, जिससे जाम लगता था। अब सर्विस लेन से जाने वाले वाहनों को मुख्य सड़क पर आने के लिए इटैड़ा गोल चक्कर के पास पहुंचना होगा। गौड़ सिटी गोल चक्कर किसान चौक की तरफ से आने वाले लोगों को अगर मॉल जाना है तो उन्हें इटैड़ा गोल चक्कर से लेफ्ट यू-टर्न लेना होगा।

गाजियाबाद की तरफ से आने वाले वाहन जाम से बचने के लिए गौड़ सिटी गोल चक्कर जाने के बजाय इसकी सर्विस लेन पर चले जाते थे। गौड़ सिटी मॉल के पास सर्विस लेन पर मुख्य सड़क पर जाने के लिए कट था। सर्विस लेन से मुख्य सड़क पर आने के लिए वाहनों के मुड़ने के दौरान इस जगह पर काफी जाम लगता रहा है। साथ ही सर्विस लेन पर सामने से आने वाले वाहनों के कारण और भी बुरी स्थिति हो जाती थी।

पीक आवर में जाम के हालात ज्यादा खराब हो जाते थे। इससे बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने इस कट को सोमवार से अस्थायी रूप से बंद कर दिया। नोएडा की तरफ से आने वाले वाहनों को अगर गौड़ सिटी मॉल जाना है तो उन्हें इटैड़ा गोल चक्कर से लेफ्ट में दूसरी सर्विस लेन पर यू.टर्न लेना होगा। मॉल से नोएडा या बिसरख रोड की ओर जाने वालों को इटैड़ा गोल चक्कर से राइट में यू.टर्न लेना होगा।

साहिबाबाद स्थित सब्जी मंडी का निरीक्षण करते नगर मजिस्ट्रेट।

डीएमई में लगेगा मीडिया पेशवरों और छात्रों का जमावड़ा

दो दिवसीय वार्षिक मीडिया उत्सव 'वृतिका' का आयोजन आज से

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन (डीएमई) मीडिया स्कूल अपने कैंपस में 14 और 15 नवंबर को एक इंटर कॉलेज फेस्ट 'वृतिका 2019' आयोजित कर रहा है। यह वार्षिक मीडिया उत्सव, पत्रकारिता एवं मीडिया में रुचि रखने वाले छात्र-छात्रों के लिए रोमांचक प्रतियोगिताओं में भाग लेने का एक बेहतरीन अवसर है। इसके अतिरिक्त यह छात्रों को विभिन्न कॉलेजों से आये छात्र-छात्राओं और मीडिया क्षेत्र के पेशेवरों के साथ मिलने जुलने और संवाद करने का सुनहरा अवसर भी प्रदान कर रहा है।

इस दो दिवसीय मीडिया उत्सव में दिल्ली-एनसीआर के 43 अलग-अलग विश्वविद्यालयों और संस्थानों के लगभग 500 युवा मीडिया छात्र और पेशेवर शामिल होने जा रहे हैं। इस दौरान रेडियो जिंगल, डिजिटल पोस्टर मेकिंग, फोटोग्राफी, टैलेंट हंट, एड-मैड, एंकर हंट जैसे 15 विभिन्न प्रतियोगिताओं में भी बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं के भाग लेने की उम्मीद है।

14 नवंबर को उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर जाने माने लेखक, नाटककार, थिएटर निर्देशक और पूर्व आईएएस अधिकारी डीपी सिन्हा, समारोह में शिरकत करेंगे।

इसके अतिरिक्त प्रख्यात पत्रकार डॉ. संजियो सिंह, न्यूज़ एडिटर-इन-चार्ज मार्केट मंत्रा, न्यूज सर्विसेज डिवीजन, ऑल इंडिया रेडियो की उपस्थिति में समापन समारोह संपन्न किया जाएगा। कार्यक्रम में वरिष्ठ एंकर / संपादक, न्यूज़ नेशन पीनाज त्यागी, वरिष्ठ प्रसारण पत्रकार और एंकर दीप्ति सचदेवा, पायनियर हिंदी अखबार के वरिष्ठ संपादक प्रदीप तिवारी भी इस दो दिवसीय उत्सव में शामिल होने जा रहे हैं। तिवारी को धार्मिक सद्भाव बरकरार रखने के लिए और सामाजिक कार्यों में उनके अथक परिश्रम और योगदान के लिए उन्हें 'मूल्य-आधारित पत्रकारिता के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार' से सम्मानित किया जाएगा।

महोत्सव निदेशक, डॉ सुस्मिता बाला, प्रमुख डीएमई मीडिया स्कूल ने कहा कि 'वृतिका का आयोजन छात्रों और मीडिया पेशेवरों की प्रतिभा को एक साथ लाने और इसे आगे बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए किया गया है।'

डीन डीएमई मीडिया स्कूल, प्रोफेसर (डॉ) अंबरीश सक्सेना ने इस अवसर पर कहा, 'यह आयोजन पहले से कहीं अधिक बड़ा है। यह मीडिया के छात्रों और विस्तृत तौर पर जनता के लिए एक अच्छा अवसर है।'

दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन (डीएमई) एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है, जो गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से संबद्ध है और जिसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदित किया गया है।

मंडी में गंदगी और अतिक्रमण देख भड़के नगर मजिस्ट्रेट

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

● व्यवस्था में तत्काल सुधार लाने को कहा

साहिबाबाद क्षेत्र स्थित सब्जी मंडी का नगर मजिस्ट्रेट शिव प्रताप शुक्ल ने बुधवार को औचक निरीक्षण किया जिसमें मंडी परिसर में व्याप्त गंदगी, अतिक्रमण व अन्य समस्याओं को देखकर नगर मजिस्ट्रेट भड़क उठे और उन्होंने मंडी समिति के सचिव को निर्देश दिए कि 15 दिन के अंदर सभी समस्याओं का निराकरण कराएं और मंडी परिसर स्थित दुकानदारों से उनकी तमाम समस्याओं को लेकर बैठक करें और उनका निराकरण कराएं।

इसके अलावा कुछ दुकानें अभी भी वहां खाली पड़ी हुई हैं। नगर मजिस्ट्रेट ने मंडी समिति के सचिव को आदेश दिया कि वह जल्द से जल्द इन दुकानों की नीलामी कराएं। शुक्ल बुधवार को दल बल के साथ दोपहर साहिबाबाद सब्जी मंडी पहुंचे और औचक निरीक्षण किया।

इस दौरान मंडी का सबमरसेबल पंप खराब पाया गया। इतना ही नहीं जगह-जगह गंदगी के ढ़ेर और अतिक्रमण को देख उन्होंने मंडी समिति के सचिव विश्वेंद्र को तत्काल व्यवस्थाओं में सुधार लाने को कहा । निरीक्षण के दौरान उनके साथ सहायक अभियंता अवनीश जैन प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

सीएमवाईके प्रिंटेक लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक चन्दन मित्रा द्वारा नं. 6, गुलाब भवन के पीछे, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002, दूरभाष: 011-40110455 से प्रकाशित तथा बीएफएल इन्फोटेक लिमिटेड सी-9 सेक्टर-3, नोएडा-201301 (उ.प्र.) से मुद्रित। सम्पादक: चन्दन मित्रा, स्थानीय सम्पादक: उषा श्रीवास्तव। पाठकों को सुझाव दिया जाता है कि इस अखबार के किसी भी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया करने से पहले पूरी तरह उसके बारे में दिए गए दावों, शर्तों और तथ्यों की जांच कर लें। पायनियर ग्रुप के मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक या उसका कोई भी कर्मचारी विज्ञापनदाता द्वारा उनके किसी उत्पाद तथा सेवा हेतु किए गए किसी दावे की सच्चाई का आश्वासन या उत्तरदायित्व नहीं लेता है। ऐसे विज्ञापनों के बाद किसी आर्थिक क्षति के लिए वे जिम्मेदार भी नहीं हैं। पत्रवार्ता ऑफिस- एफ-31, सेक्टर 6, नोएडा, गौतमबुद्धनगर-201301, उत्तर प्रदेश, दूरभाष- 120-4879800-4879900।

अमीरों को भी भाने लगा है मोहल्ला क्लीनिक : सीएम

क्लीनिक की सुविधाएं और सेवाएं बनीं देश के लिए मिसाल, निरीक्षण करने ग्रेटर कैलाश पहुंचे

● सुविधाओं के बारे में लोगों से ली जानकारी

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पहले लोगों का मानना था कि सरकारी अस्पतालों में बेहतर चिकित्सा सुविधा नहीं मिलेगी।

लेकिन अब सभी मोहल्ला क्लीनिक बहुत अच्छी स्थिति में हैं। जो लोग महंगे निजी अस्पतालों का खर्च उठा सकते हैं। उन्होंने भी सरकारी चिकित्सा सुविधाओं का इस्तेमाल करने लगे हैं। यह गुणवत्ता का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है।

केजारीवाल बुधवार को ग्रेटर कैलाश में खोले गए पहले मोहल्ला क्लीनिक का निरीक्षण के दौरान यह बात कही। उन्होंने अपने निरीक्षण के दौरान कई रोगियों और क्लिनिक के कर्मचारियों के साथ मुलाकात की और मोहल्ला क्लिनिक में दी जा रही सुविधाओं के बारे में लोगों से जानकारी ली। अरविंद केजरीवाल ग्रेटर कैलाश के हेमकुंट कॉलोनी में स्थित मोहल्ला क्लिनिक के निरीक्षण के दौरान कई मरीजों से मुलाकात की और उनसे पूछा कि क्या वे क्लिनिक में सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता से संतुष्ट हैं।

फोटो : रंजन डिमरी
ग्रेटर कैलाश स्थित मोहल्ला क्लीनिक में अपनी जांच करते मुख्यमंत्री।

जवाब में उनकी प्रतिक्रिया सकारात्मक थी। सीएम ने कहा कि उन्हें खुशी है कि सभी को सरकारी अस्पतालों पर भरोसा है। खून जांच कराने आई बत्रा ने बताया कि वह यह देखकर खुश है कि यह सुविधा इतनी अच्छी और साफ है। सीएम ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से क्लीनिकों को बेहतर बनाए हुए है और वे व्यक्तिगत रूप से रखरखाव और संचालन की निगरानी कर रहे हैं। केजरीवाल ने डॉक्टर और फार्मासिस्ट से मुलाकात की और उनके अनुभवों के बारे में जानकारी ली।

डॉ रेजिना ने सीएम केजरीवाल के रक्तचाप को चेक किया और बताया कि वह पूरी तरह से ठीक है। उन्होंने डॉक्टर को धन्यवाद दिया और समाज के प्रति उनकी सेवा के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने बाद में ट्वीट कर कहा कि जो लोग महंगे निजी अस्पतालों का खर्च उठा सकते हैं वे सरकारी चिकित्सा सेवाओं को इस्तेमाल करने लगे हैं। यह गुणवत्ता का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है। पॉश जीके कॉलोनी में उन्हें एक मोहल्ला क्लिनिक में संपन्न व मध्यम वर्ग के लोग मिले। वे मोहल्ला क्लीनिक में मिलने वाली सुविधाओं से खुश है। बड़े अस्पताल में जाने वाले अब मोहल्ला क्लीनिक में आ रहे हैं। जब उच्च मध्य वर्ग मोहल्ला क्लीनिक में आकर इलाज करा रहे हैं तो इससे बड़ा लोगों का सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर कभी भरोसा नहीं रहा है। जिस तरह लोग कहते हैं उन्होंने स्कूलों का कायापलट कर दिए हैं। सरकारी स्कूल निजी स्कूल की तरह हो गए। इसी तरह सरकारी अस्पताल भी निजी अस्पताल की तरह हो गए है। मोहल्ला क्लीनिक में आई एक महिला ने सीएम को बताया कि उसकी बहन को डायलिसिस की जरूरत होती है। वह मोहल्ला क्लीनिक गई। वह काफी स्वस्थ भी है। केजरीवाल ने क्लीनिक के लिए बहुत कुछ किया है। गरीब महिलाएं पहले पैसे की कमी की वजह से बीमारी छुपा लेती थीं।

प्राइवेट डॉक्टर ने जुड़ने की जताई इच्छा

ग्रेटर कैलाश में निजी डेंटर क्लीनिक चलाने वाले डॉ. मल्होत्रा ने भी दौरे के वक्त मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। उन्होंने जन सेवा के लिए क्लीनिक से जोड़कर इलाज करने की इच्छा जताई। मोहल्ला क्लीनिक दिल्ली वालों के लिए सस्ती और अच्छी स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करती हैं। दिल्ली सरकार ने एक हजार आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक खोलने का लक्ष्य रखा था। वर्तमान में 302 चालू हैं। यहां लगभग 109 आवश्यक दवाओं और 212 नि:शुल्क जांच मुहैया कराई जा रही है।

इस साल प्रदूषण में पराली का रहा बड़ा योगदान : सीपीसीबी

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

प्रदूषण से निपटने के लिए राजनीतिक दल और सरकारें लुभावनी घोषणाओं से आगे नहीं बढ़ती दिख रहीं। हर वर्ष पराली निपटान के लिए बेहतर उपाय करने की बात होती है लेकिन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्पष्ट कहा है कि राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए इस साल पराली का बड़ा योगदान रहा है।

बोर्ड ने इस प्रकार सरकारी दावों की पोल खोल दी है। क्योंकि केंद्र और हरियाणा-पंजाब की सरकारें दावा करती रहती हैं कि पराली के निपटान के बेहतर उपाय किए जा रहे हैं और अब पराली नहीं, स्थानीय कारणों से हवा जहरीली हो रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के सदस्य सचिव प्रशांत गर्गवा ने कहा कि इस साल दिल्ली की जहरीली हवा में पराली की बड़ी भूमिका रही। सफर के मुताबिक पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के कारण उठने वाले धुएं का योगदान इस साल एक नवंबर को दिल्ली में सर्वोच्च 44 प्रतिशत रहा।

'केंद्र जापानी तकनीक अपनाने पर करे विचार'

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि वायु प्रदूषण की समस्या के स्थाई समाधान के लिए हाइड्रोजन आधारित जापानी प्रौद्योगिकी अपनाने की व्यावहार्यता तलाशी जाए। शीर्ष अदालत ने केंद्र को इस विषय पर विचार-विमर्श तेज करने और न्यायालय को तीन दिसंबर को अपने नतीजों से अवगत कराने का निर्देश दिया। पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं और प्रतिकूल मौसम की वजह से दिल्ली में वायु गुणवत्ता की स्थिति फिर आपात अवस्था में पहुंचने के परिप्रेक्ष्य में यह मुद्दा प्रमुखता से उठा। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एसए बोबडे ने कहा कि चूंकि सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने स्वयं ही इस प्रौद्योगिकी की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है, केन्द्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उत्तर भारत के दूसरे राज्यों में इस प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की व्यवहार्यता की संभावना तलाशे। प्रौद्योगिकी जापान में एक विश्वविद्यालय के अनुसंधान का नतीजा है। पीठ ने कहा कि वायु प्रदूषण का स्थाई समाधान खोजना जरूरी है।

सार्वजनिक परिवहन में निवेश की जरूरत

गर्गवा ने बताया कि पराली जलाने से हुए प्रदूषण का भी बहुत योगदान रहा। दिल्ली में धुंध गहराने में इस साल इसका योगदान 44-45 प्रतिशत रहा। हवा भी धीमी है, कुछ भी बाहर नहीं जा रहा। उन्होंने हर साल अक्टूबर के पहले निर्माण अवशेष और मलबा हटाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि मलबा गिराने और जलाए जाने से बहुत समस्या होती है। हमें साथ मिलकर काम करना होगा और मलबा हटाना होगा ताकि यह समस्या ना बने। शहर में जमा निर्माण अपशिष्ट और मलबा हटाने के लिए जुलाई, अगस्त या सितंबर में विशेष सफाई अभियान चलाना होगा। सचिव ने वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को घटाने के लिए सार्वजनिक परिवहन में जल्द और भारी निवेश की जरूरत पर भी जोर दिया।

गुरुद्वारा बंगला साहिब पहुंचे प्रिंस चार्ल्स, लंगर के लिए सेंकी रोटियां

प्रिंस को सम्मानित करते गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारी।

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली।

इंग्लैंड के शहजादे प्रिंस ऑफ वेल्स प्रिंस चार्ल्स गुरुद्वारा बंगला साहिब में नतमस्तक हुए और उन्होंने लंगर हॉल में जाकर लंगर की सेवा भी की और इस दौरान लंगर के लिए रोटियां भी सेंकी। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा, महासचिव हरमीत सिंह कालका, कुलवंत सिंह बाठ, परमजीत सिंह चंडोक व अन्यों ने प्रिंस चार्ल्स को सिरोपा दे कर सम्मानित किया और श्री साहिब (किरपान) भेंट की।

इस बारे में जानकारी देते हुए सिरसा ने बताया कि प्रिंस चार्ल्स प्रिंस आफ वेल्स गुरु नानक देव जी के 550 वें प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारा बंगला साहिब में नतमस्तक हुए। उनके साथ महिंद्र सिंह व अन्य शख्सियतें भी थीं। उन्होंने बताया कि प्रिंस ने गुरु हरिकृष्ण साहिब के इस स्थान के बारे मे जानकारी हासिल करने में बहुत दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने भारी गिनती में संगत की मौजूदगी और उनके लिए लंगर तैयार करने व बांटने की प्रक्रिया जानने की इच्छा प्रकट की।

उन्होंने लंगर हॉल में जा कर स्वयं प्रसाद बनाने की सेवा भी की। इस मौके पर प्रिंस चालर्स ने बताया कि गुरु नानक देव का फलसफा सारी दुनिया में फैल रहा है और एक बहादुर कौम के रूप् में जाने जाते सिख जिस भी मुल्क में जाते हैं वहां की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करते हैं। इन्होंने इंगलैंड, कैनेडा व जिस भी मुल्क में जा कर बसे वहां की तकदीर बदलने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रिंस ने आशा प्रकट की कि इंगलैंड में भी यह साहिब इसी सिद्धांत की पहरेदारी करेगी। सिरसा ने इस मौके पर इंगलैंड की संगत को बधाई दी।

'जेएनयू का रुका पैसा आवंटित करेगी यूजीसी'

● एबीवीपी का प्रतिनिधि मंडल यूजीसी सचिव से मिला, ज्ञापन सौंपा

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के लिए 6.7 करोड़ रुपये का रूका बजट देने का भरोसा दिया है।

यूजीसी ने कहा कि जेएनयू प्रशासन से जरूरी प्रक्रिया पूरी कर यह बजट रिलीज किया जाएगा। साथ ही जेएनयू प्रशासन ने गरीब छात्रों की मदद के लिए जिस अतिरिक्त बजट की मांग की थी। उसको जरूरी कार्यवाही के लिए मंत्रालय भेज दिया गया है। एबीवीपी का एक प्रतिनिधि मंडल फीस में हुई बढ़ोतरी को वापस लेने, गरीब छात्रों को अतिरिक्त रियायतें देने के लिए यूजीसी के सचिव से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा और सभी मांगों पर कार्रवाई की मांग की।

संगठन के प्रदेश मंत्री सिद्धार्थ यादव के अनुसार वह लगातार सरकार के समक्ष शिक्षा बजट में बढ़ोतरी की मांग को रखते आए हैं। उनका स्पष्ट मत है कि ऐसा कोई भी निर्णय न लिया जाए जो एक भी छात्र के हित में नहीं हो।

एबीवीपी जेएनयू इकाई के अध्यक्ष दुर्गेश कुमार के मुताबिक जेएनयू की समावेशी और सस्ती पढ़ाई के स्वरूप को बचाए रखने और उसको और अधिक पोषित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

दक्षिण दिल्ली निगम ने काटे 119 चालान

नई दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के चारों जोनों में कुल 119 चालान हुए और छह लाख नब्बे हजार का जुर्माना लगाया। निगम ने वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति और राजाधानी में बढ़ते हुए प्रदूषण के खिलाफ चारों जोनों में सख्त कार्रवाई की। इस दौरान एनजीटी एक्ट और डीएमसी एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों में संबधित अधिकारियों ने चालान जारी किए। चारों जोन में कुल 119 चालान किए गए और जुर्माने के रूप में 6,90,000 रुपए प्राप्त किए। इसके अलावा 1183 साइटों का भी निरीक्षण किया गया। सभी चारों जोनों में चिन्हित हॉटस्पॉट पर अतिरिक्त कार्रवाई करते हुए नाइट पैट्रोलिंग टीमों को तैनात किया।

कॉलोनियों को नियमित करने का भाजपा का वादा कोरा झूठ: आप

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

वरिष्ठ आप नेता और पार्टी विधायक अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के भाजपा के कथित झूठे वादे के खिलाफ शनिवार को धोखा दिवस मनाएंगे। अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की भाजपा की घोषणा को चुनावी तिकड़म करार देते हुए वरिष्ठ आप नेता गोपाल राय ने कहा कि उनके इरादे सच्चे नहीं हैं।

उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि लोगों को यह बताने के लिए कि उन्हें भाजपा कैसे धोखा दे रही है, हम शनिवार को धोखा दिवस मनाएंगे।

हमारे वरिष्ठ नेता और पार्टी विधायक इसमें शामिल होकर अनधिकृत कॉलोनियों के लोगों को बताएंगे कि कैसे भाजपा उन्हें धोखा दे रही है तथा अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करना बस एक झूठा वादा है। अक्टूबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रह रहे लोगों को जमीन का मालिकाना हक देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी।

भाजपा ने चलाया जनसंपर्क और हस्ताक्षर अभियान

नई दिल्ली। भाजपा, अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों को साधने में जुट गई। पार्टी के सांसद, विधायक व नेता पीएम उदय योजना के तहत उनके घर का मालिकाना हक दिये जाने की जानकारी जनसम्पर्क एवं हस्ताक्षर अभियान के माध्यम दे रहे हैं।

जनसभा को सम्बोधित करते हुये भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू ने कहा कि अनधिकृत कॉलोनी में रह रहे 40 लाख से अधिक लोगों को सम्माननीय जीवन देने के लिए पीएम मोदी ने वह काम किया जिस पर अन्य दलों ने राजनीति के अलावा कुछ और नहीं किया।

अज्ञात वाहन की टक्कर से मासूम की मौत

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

● सीसीटीवी की मदद से चालक की पुलिस कर रही है तलाश

पूर्वी दिल्ली के प्रीति विहार में अज्ञात वाहन की टक्कर से दो साल के मासूम की मौत हो गई। मरने वाले बच्चे की पहचान प्रियांश के रूप में हुई है। बच्चे पिता के बयान पर पुलिस ने लापरवाही से गाड़ी चलाने से हुई मौत का मामला दर्ज कर चालक का पता लगाने की कोशिश कर रही है। देर रात तक मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी।

पुलिस उपायुक्त जसमीत सिंह के अनुसार मंलवार रात साढ़े नौ बजे मैक्स अस्पताल से जानकारी मिली थी कि सड़क दुर्घटना में घायल दो साल के बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

जांच में पता चला कि बच्चा मंगलवार की रात खेलते खेलते घर से बाहर चला गया था। तभी किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। घटना के समय बच्चे के परिजन घर के अंदर थे। कुछ देर बार उसके पिता मोहन कुमार घर से बाहर निकले तो उन्होंने प्रियांश को बेहोशी की हालत में सड़क पर पड़ा हुआ पाया। वह अपने मालिक के साथ बच्चे को अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

पिता के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। वाहन आरोपी को पकड़ने के लिए इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर आरोपी की पहचान की कोशिश की जा रही है कुमार प्रीत विहार सी-ब्लॉक में एक घरेलू सहायक के तौर पर काम करते हैं।

आंदोलन को धार देने की तैयारी में जुटे वकील

हड़ताल जारी, आज पटियाला हाउस से इंडिया गेट तक निकाल सकते हैं मार्च

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

वकीलों पर दो नवंबर को हुई झड़प के दौरान कथित तौर पर गोली चलाने वाले पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे दिल्ली की जिला अदालतों के वकीलों ने बुधवार को भी कामकाज का बहिष्कार जारी रखा। अब वे अपने आंदोलन को धार देने की तैयारी में जुटे हैं।

ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन की समन्वय समिति के महासचिव धीर सिंह कसाना ने बताया कि सभी जिला अदालतों के वकील बुधवार को पटियाला हाउस से इंडिया गेट तक मार्च कर सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि वकील संसद का घेराव भी कर सकते हैं। कसाना ने कहा कि वकीलों पर गोली चलाने वाले पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। इसलिए दिल्ली की सभी जिला अदालतों में पूरी तरह कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। वकीलों पर गोली चलाने वाले पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस अधिकारियों ने इसका विरोध किया, इसलिए हम काम का बहिष्कार कर रहे हैं। कसाना के अनुसार ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एसोसिएशन के सदस्यों, दिल्ली पुलिस के प्रतिनिधियों और उपराज्यपाल के बीच बैठक में कोई समाधान नहीं निकल सका, जिसके चलते यह हड़ताल जारी रही।

वकीलों पर कार्रवाई की मांग को लेकर याचिका

दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है जिसमें वकीलों और पुलिस के बीच हुई झड़प के बाद जिला अदालतों में हड़ताल के दौरान वादियों, पुलिसकर्मियों और आम लोगों को कथित तौर पर पीटने वाले वकीलों के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। दाखिल जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि वकीलों ने वादियों को अपने मामलों की सुनवाई में शामिल होने के लिए अदालत परिसरों में प्रवेश करने से रोका।

शरद पवार को 2011 में थप्पड़ मारने वाला व्यक्ति गिरफ्तार

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार पर हमला करने वाले हरविंदर सिंह को बुधवार को नई दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया।

हरविंदर सिंह

हरविंदर सिंह ने साल 2011 में शरद पवार को नडीएमसी कन्वेंशन हॉल में थप्पड़ जड़ दिया था। उसे 25 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस को अनुसार, हरविंदर सिंह को पहली बार वर्ष 2011 में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन वह सुनवाई के दौरान गायब हो गया था और 29 मार्च 2014 को पटियाला हाउस अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के स्वरूप नगर के निवासी सिंह को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस की टीम कई बार सिंह के पैतृक गांव भी गई लेकिन वह कहीं अज्ञात स्थान पर रहने लगा था। उसके बारे में जानकारी मिलने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस उपायुक्त ईश सिंघल ने कहा कि शरद पवार के साथ मारपीट करने को लेकर सिंह के खिलाफ कनॉट प्लेस थाने में मामला दर्ज किया गया था।

निगम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं : गंभीर

पूर्वी दिल्ली नगर निगम के स्मार्ट स्कूल का किया उद्घाटन

मयूर विहार स्थित निगम के स्कूल का उद्घाटन करते गंभीर व शामिल लोग

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने मयूर विहार फेस-1, पॉकेट-4 में नगर निगम के प्रतिभा विद्यालय (स्मार्ट स्कूल) का उद्घाटन किया। इस अवसर पर, महापौर अंजु कमलकांत, स्थायी समिति अध्यक्ष, संदीप कपूर, नेता सदन, निर्मल जैन, शिक्षा समिति के अध्यक्ष राज कुमार बल्लन, स्थानीय पार्षद व पूर्व महापौर बिपिन बिहारी और निगम के वरिष्ठ अधिकारी व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

स्मार्ट क्लास

इस अवसर पर निगम स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि समाज का भविष्य बच्चों के वर्तमान से तय होता है इसलिए हमें बच्चों के विकास के लिए अधिकतम प्रयास करने चाहिए ताकि हम बेहतर राष्ट्र व समाज का निर्माण कर सकें।

वहीं पूर्वी दिल्ली नगर निगम की सराहना करते हुए सांसद ने कहा कि उन्हें बेहद खुशी है कि निगम, बच्चों की शिक्षा को लेकर बेहद गंभीर है। गंभीर ने कहा कि निगम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे प्रतिभा में किसी से कम नहीं है, हमें उन्हें सर्वांगीण विकास के अवसर उपलब्ध कराने होंगे। महापौर, सुश्री अंजु कमलकांत ने कहा कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम, बच्चों के लिए शैक्षणिक व मानसिक विकास के प्रति पूर्णतया: प्रतिबद्ध है।

उन्होंने यह भी कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद पूर्वी दिल्ली नगर निगम छात्रों को अधिकतम सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

महापौर ने कहा कि हमारा नवनिर्मित स्मार्ट विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं जिसमें छात्रों के लिए स्मार्ट बोर्ड व कम्प्यूटर रूम जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं।

रेस्टोरेंट में परिवार संग गए व्यक्ति पर हमला

शराब के नशे में युवकों ने सिर पर फोड़ी बीयर की बोतल

सारी घटना रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी में कैद एफआईआर दर्ज

पायनियर समाचार सेवा, गुरुग्राम।

दिल्ली से सटे मिलेनियम सिटी में लोगों को शायद पुलिस का डर नहीं रह गया है। यहां सेक्टर-47 स्थित एक रेस्टोरेंट में शराब के नशे में कुछ युवकों ने अपने परिवार के साथ खाना खाने गए एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर दिया। यही नहीं नशे में धुत युवकों ने व्यक्ति के सिर पर बीयर की बोतल भी फोड़ दी, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोटें आईं। घायलावस्था में व्यक्ति का भाई उसे लेकर पास के अस्पताल पहुंचा। वहीं सारी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है।

पुलिस के अनुसार, पीड़ित ने अपनी शिकायत में युवकों के कार का नंबर दिया है, जिसके आधार पर उनकी पहचान की जा रही है। वहीं मारपीट का ये वीडियो काफी वायरल भी हो रहा है। हालांकि ये घटना कुछ दिन पहले की है, लेकिन वीडियो अब सामने आया है। पुलिस को दी गई शिकायत में सेक्टर-49 स्थित साउथ सिटी-2 निवासी राजेश जैन ने बताया है कि वह अपने परिवार के साथ स्पेशल चैंबर में खाना खाने गए थे। उनके साथ बच्चे और उनका भाई था। अपनी शिकायत में पीड़ित ने बताया है कि वह जहां खाना खा रहे थे, वहां 3-4 लड़के जो साथ की टेबल पर बैठे थे, उन्होंने अभद्रता शुरू कर दी। पीड़ित ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो शराब के नशे में धुत युवकों ने उन पर हमला बोल दिया। यही नहीं एक युवक ने पीड़ित के सिर पर बीयर की बोतल फोड़ दी। इस घटना में पीड़ित बुरी तरह घायल हो गया। वहीं शराब के नशे में धुत युवक वहां से उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। बाद में पीड़ित का भाई उसे लेकर पास के अस्पताल पहुंचा।

चार दिवसीय दिव्य गीता सत्संग का आयोजन आज से

गुरुग्राम। धार्मिक संस्था श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति द्वारा आज से चार दिवसीय दिव्य गीता सत्संग कार्यक्रम का आयोजन न्यू कॉलोनी स्थित दशहरा ग्राउंड परिसर में किया जा रहा है।

संस्था के प्रधान गोविंद लाल आहूजा ने बताया कि कार्यक्रम में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज श्रीमदभागवत गीता के प्रसंगों पर प्रवचन करेंगे। जहां योग एवं ध्यान साधना का कार्यक्रम भी होगा, वहीं स्वास्थ्य जांच व रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में पटौदी हरि मंदिर आश्रम के अधिष्ठाता स्वामी धर्मदेव महाराज, स्वामी विवेकानंद महाराज, देवता महाराज, पूनम माता महाराज भी शामिल होंगी। मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सुधीर सिंगला, मेयर मधु आजाद, सोहना विधायक संजय सिंह, पूर्व मंत्री धर्मवीर गाबा आदि शामिल होंगे। आयोजन को सफल बनाने के लिए बलेदव राज खुराना, सुभाष गाबा, ठाकुरदास कुमार, ओपी नरुला, धर्मवीर चौहान, एलएस यादव, जयदयाल कुमार आदि जुटे हुए हैं।

नेशनल मिन्स कम मैरिट स्कॉलरशिप परीक्षा एक को, मिलेंगे 48 हजार

कक्षा 8वीं उत्तीर्ण कर चुके 2712 विद्यार्थी लेंगे भाग

गुरुग्राम। नेशनल मिन्स कम मैरिट स्कॉलरशिप के लिए जिला के राजकीय विद्यालयों में परीक्षा एक दिसंबर को होगी। इस परीक्षा में जिला के कक्षा 8वीं उत्तीर्ण कर चुके 2712 विद्यार्थी भाग लेंगे। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा विभाग द्वारा 48 हजार रुपये की स्कॉलरशिप दी जाती है।

इस बारे में जानकारी देते हुए उपायुक्त अमित खत्री ने बताया कि इस योजना के तहत केवल वही विद्यार्थी भाग ले सकते हैं, जिनकी सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय डेढ़ लाख रुपये है। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे गरीब परिवारों के बच्चों के भविष्य को सशक्त व उज्ज्वल बनाना है, ताकि वे पढ़-लिखकर अपने परिवार के लिए आय के साधन जुटा सकें। योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए श्री खत्री ने बताया कि इस परीक्षा में आठवीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके परीक्षार्थी भाग ले सकते हैं। इस परीक्षा की तैयारी के लिए जिला शिक्षा विभाग के पास बुकलेट भी पहुंच चुकी है, जिसे राजकीय विद्यालयों में वितरित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा में आठवीं कक्षा तक का सिलेबस आता है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी को कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक किश्तों में यह स्कॉलरशिप दी जाती है।

जिला शिक्षा अधिकारी इंदु बोकन ने बताया कि इस परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को प्रत्येक माह एक हजार रुपये की राशि दी जाती है। इस स्कॉलरशिप योजना का लाभ लेने के लिए सामान्य वर्ग से संबंधित विद्यार्थी का कक्षा आठवीं व 9वीं में 55 प्रतिशत अंक तथा कक्षा 10वीं व 12वीं में 60 प्रतिशत तक अंक होने अनिवार्य है। इसी प्रकार, अनुसूचित व पिछड़ा जाति से संबंध रखने वाले विद्यार्थी के आठवीं व नौंवी कक्षा में 50 प्रतिशत अंक तथा 10वीं व 12वीं कक्षा में 55 प्रतिशत तक अंक होने अनिवार्य है।

संक्षिप्त समाचार

बाइक लुटेरे को दो भाइयों ने दबोचा

सोहना। बाइक लुटेरे को दो सगे भाइयों ने दबोचकर पुलिस को सौंप दिया। लुटेरे ने पहले लिफ्ट मांगी फिर हथियार दिखाकर बाइक लूटने लगा। पुलिस ने बाइक मालिक की शिकायत पर लुटेरे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सोहना के वार्ड-10 जखोपुर की परमार कॉलोनी में रहने वाले संजीव पुत्र राजेन्द्र ने बताया कि रविवार की रात साढ़े नौ बजे वह अपने मनीष को शहर की फ्रैंड्स कॉलोनी में लेने के लिए बाइक लेकर गया था। बीच रास्ते में उसे एक युवक ने रुकने का इशारा किया और उससे लिफ्ट मांगी। उसने उसे बैठा लिया। जब वह फ्रैंड्स कॉलोनी में पहुंचा तो पीछे बैठे युवक ने नुकीला हथियार दिखाया और बाइक देने को कहने लगा। उस समय उसका भाई मनीष उसे अपनी तरफ आता दिखाई दिया। दोनों भाइयों ने लुटेरे को काबू कर लिया। उसने अपना नाम इकबाल निवासी गांव सुनारी थाना तावडू बताया। जिसे सोहना सिटी थाना में ले जाकर पुलिस के हवाले कर दिया।

जिला जेल में बंदी से मोबाइल बरामद

सोहना। भोंडसी जिला जेल में बंदी के पास से मोबाइल फोन मिला है। पुलिस ने जेल अधिकारी की मिली शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। भोंडसी जिला जेल के उपाधीक्षक साजिद खान ने बंदी सरफुद्दीन के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। जेल अधिकारी ने पुलिस को बताया कि बंदी सरफुद्दीन बैरिक नंबर 4/ए में रह रहा है। जिसके पास मोबाइल फोन होने का शक हुआ। जेल वार्डन की मदद से बंदी सरफुद्दीन की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान सरफुद्दीन के पास से मोबाइल फोन मिला। भोंडसी थाना पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है।

विशाल स्वास्थ्य जांच व रक्तदान शिविर का आयोजन

गुरुग्राम। बसई रोड स्थित अल्फा अस्पताल प्रबंधन द्वारा क्षेत्र के दादा भईया मंदिर में विशाल स्वास्थ्य जांच व रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 220 लोगों ने जहां अपने स्वास्थ्य की जांच कराई, वहीं 35 लोगों ने स्वैच्छा से रक्तदान किया। अस्पताल के प्रवक्ता ने बताया कि स्वास्थ्य जांच शिविर में आए लोगों की जहां स्वास्थ्य जांच कर उन्हें निशुल्क दवाइयां वितरित कीं, वहीं उन्हें मौसमी बीमारियों के बारे में जानकारी देते हुए बीमारियों से बचाव के उपाय भी बताए गए। उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया गया। प्रवक्ता ने बताया कि रक्तदाताओं से भी आग्रह किया गया कि वे समय-समय पर रक्तदान अवश्य करें। रक्त की कुछ बूंदें मरणासन्न व्यक्ति को जीवनदान दे सकती हैं।

विधायक के पिता के सम्मान समारोह में उठा भ्रष्टाचार का मुद्दा

गुरुग्राम। फर्रुखनगर नगरपालिका में भ्रष्टाचार किस कदर हावी है, इस बात का खुलासा बादशाहपुर विधानसभा के विधायक राकेश दौलताबाद के नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में उसकी गैर मौजूदगी में उनके पिता जिले सिंह के समक्ष हुआ।

नपा पार्षद मुकेश सैनी ने आरोप लगाए कि नपा कार्यालय में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सड़क, गली, नाले, अस्पताल निर्माण पर धांधले बाजी जमकर की जा रही है। इतना ही नहीं अवैध कॉलोनियों में बिना नक्शे बनाए जा रहे अवैध रूप से बनाए जा रहे मकानों के मालिकों से अवैध रूप से की जा रही वसूली के आरोप भी लगाए। इतना ही नहीं पार्षद ने यहां तक कह दिया कि अगर भ्रष्टाचार नहीं रुका तो वह खुलेआम आंदोलन करेंगे। जनता के बीच मंच से भ्रष्टाचार की बात सुन कर विधायक के पिता जलसिंह ने लोगों को आश्वासन दिया कि बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचार का मूल नाश विधायक राकेश द्वारा किया जाएगा। भ्रष्टाचार की जांच कराई जाएगी। राकेश विधायक बाद में पहले क्षेत्र की जनता का बेटा व भाई है। क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इसके लिए विधायक राकेश दिन रात एक कर देगें। फर्रुखनगर क्षेत्र के लोगों ने विधायक पिता का फूलमालाओं व पगड़ी बांध कर स्वागत किया।

निर्माण करने पर 50 हजार का जुर्माना

पायनियर समाचार सेवा, गुरुग्राम।

प्रतिबंध के बावजूद भवन निर्माण करने वाले दो उल्लंघनकर्ताओं पर नगर निगम गुरुग्राम द्वारा 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। ये दोनों निर्माण डीएलएफ फेज-2 क्षेत्र में किए जा रहे थे।

नगर निगम को सूचना मिली कि डीएलएफ फेज-2 क्षेत्र में प्लॉट नंबर-एम 15/13 तथा जे-4/9 में भवन निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जबकि पर्यावरणीय प्रदूषण (नियंत्रण एवं रोकथाम) प्राधिकरण द्वारा 14 नवंबर तक गुरुग्राम सहित पूरे एनसीआर क्षेत्र में भवन निर्माण गतिविधियों पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया हुआ है। सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर जूनियर इंजीनियर हरीकिशन मौके पर पहुंचे तथा उन्होंने प्लॉट नंबर-एम 15/13 पर 20 हजार रुपये तथा प्लॉट नंबर-जे 4/9 पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

नगर निगम आयुक्त अमित खत्री ने बताया कि ईपीसीए द्वारा जारी हिदायतों अनुसार नगर निगम द्वारा ग्रेडिड रैस्पांस एक्शन प्लान की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। नगर निगम की टीमें क्षेत्र में रात-दिन निगरानी कर रही हैं तथा ग्रैप का उल्लंघन करने वालों के चालान किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 10 उल्लंघनकर्ताओं पर 42 हजार रुपये का जुर्माना टीमों द्वारा किया गया है। उन्होंने बताया कि धूल को उड़ने से रोकने के लिए सड़कों और पेड़ों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इस कार्य के लिए चार दमकल गाड़ियां तथा 16 वाटर टैंकर तैनात किए गए हैं। छिड़काव के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का शोधित पानी इस्तेमाल किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा मुख्य सड़कों की सफाई रात्रि के समय 4 स्वीपिंग मशीनों से की जा रही है।

पुलिस के चंगुल से कार चोर फरार

सोहना। कार चोरी के दौरान पकड़ा बदमाश पुलिस के हाथों से छूटकर भाग गया। फरार बदमाश के साथी ने चोरी के दौरान युवक पर फायरिंग करके जान लेवा हमला किया था।

गांव धुनेला के मूल निवासी ललित पुत्र हरीचंद ने पुलिस को बताया कि उसका हाल निवास वार्ड-3 की सुशील कॉलोनी है। वह दौला जाने वाले मार्ग पर गैस गोदाम के पास अपने ऑफिस जिम क्लब पर शनिवार की रात अपनी कार खड़ी करके सो गया था। रविवार की सुबह करीब तीन बजे उसकी आंखें खुलीं तो उठकर जिम के गेट से बाहर आया तो देखा तो कोई कार की खिड़की के लॉक को तोड़ रहा था। तीन लड़के पास में खड़ी स्कॉर्पियो में बैठे हुए थे। जैसे ही वह कार के नजदीक गया, एक बदमाश ने लोहे की सरिया से उसके ऊपर हमला कर दिया।

बाइक चोरों ने पुलिस पर की फायरिंग

पायनियर समाचार सेवा, गुरुग्राम।

मिलेनियम सिटी में बाइक चोरी कर भाग रहे बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। हालांकि इसमें कोई पुलिसकर्मी हताहत नहीं हुआ। वहीं बिलासपुर क्राइम यूनिट एक एनकाउंटर के बाद दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाश शातिर वाहन चोर बताए जाते हैं और उन्होंने वाहन चोरी की कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। दरअसल क्राइम ब्रांच को कंट्रोल रूम से मंगलवार रात सूचना मिली थी कि सेक्टर-10 इलाके से तीन युवक एक बाइक को चोरी कर फरार हुए हैं, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने तमाम नाकों पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करने के साथ ही शहर से बाहर जा रहे पुलिस नाकों को अलर्ट कर दिया।

सहायक पुलिस आयुक्त अपराध ने बताया कि इस दौरान खेड़कीदौला थाना क्षेत्र के बार गुर्जर इलाके में पुलिस नाका के पास जब तैनात पुलिस टीम ने बाइक से भाग रहे संदिध युवकों को रोकने की कोशिश की, तब इनमें से एक ने पुलिस पर पिस्टल से फायर कर दिया। एसीपी ने बताया कि पुलिस टीम पर हत्या की नीयत से फायरिंग की गई थी। इस बीच पुलिस ने भी अपना बचाव करते हुए जवाबी कार्रवाई की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बाइक सवार दो युवक पकड़े गए, जबकि उनका एक साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। पकड़े गए लोगों की पहचान नूंह के पुन्हाना निवासी जुनेद खान और मोसिन खान के रूप में की गई है। पुलिस के अनुसार जुनेद खान ने ही पुलिस टीम पर पिस्टल से फायरिंग की थी। इनके पास से पुलिस ने एक पिस्टल, आधा दर्जन जिंदा कारतूस, चोरी की बाइक, मास्टर चाबी बरामद की है। बदमाशों को पकड़ने में हेड कांस्टेबल रजत की काफी भूमिका रही। सहायक पुलिस आयुक्त ने बताया कि दोनों को कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा।

धर्म पालन से ही संभव हो सकता है जीवन का संपूर्ण विकास

गुरुग्राम। परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है और पर-पीड़ा के समान कोई पाप कर्म नहीं है। जीवन का संपूर्ण विकास धर्म पालन से ही संभव हो सकता है। मानव जीवन दुर्लभ माना गया है। इसलिए जीवन को सुख-शांति व सौहार्द्रपूर्ण बनाने के लिए परोपकार के महत्व को समझें। उक्त उद्गार पटौदी हरि मंदिर आश्रम के अधिष्ठाता महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव महाराज ने न्यू कॉलोनी स्थित गीता भवन परिसर में धार्मिक संस्था केंद्रीय श्रीसनातन धर्मसभा द्वारा आयोजित छह दिवसीय नेत्र ऑपरेशन एवं स्वास्थ्य शिविर में श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए व्यक्त किए।

उन्होंने कहा कि मनुष्य प्रत्येक स्थिति में अपना या किसी जरूरतमद का भला कर सकता है। मनुष्य होने के नाते यह नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि हम सब मनुष्यता का परिचय दें।

अस्पताल निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप

फर्रुखनगर। सीएचसी फर्रुखनगर प्रांगण में मुख्यमंत्री की घोषणा अंतर्गत करीब 11 करोड़ 65 लाख रुपये की लागत से तैयार किए जा रहे निर्माणाधीन 50 बैड के अस्पताल की इमारत में प्रयोग की जा रही घटिया सामग्री की शिकायत के बाद बुधवार को सायं के समय एडीएम पटौदी राजेश प्रजापति ने मौके का निरीक्षण कर घटिया सामग्री के सैंपल भरे और जांच के लिए लैब में भेजने के आदेश दिए।

एसडीएम राजेश प्रजापति ने बताया कि अस्पताल के निर्माणाधीन भवन जो लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है, भवन निर्माण में अनियमितता का खेल खेला जा रहा है। इसकी कई शिकायतें मिल चुकी हैं। शिकायतों के आधार पर उन्होंने मौके का निरीक्षण किया और निर्माण में बरती जा रही सामग्री जैसे ईंट, करेसर, सीमेंट, मसाला आदि के नमूने भर कर उन्हें जांच के लिए भेज दिया है। मौके पर ठेकेदार नहीं मिला है। लोक निर्माण विभाग के एसडीओ को जांच के लिए कहा गया है। एसडीएम ने माना कि अस्पताल के भवन निर्माण में पीली ईंट, पुरानी ईंटों तथा लगाया जा रहा मशाला भी सही गुणवत्ता वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि नपा क्षेत्र ही नहीं पूरे पटौदी उप मंडल में कहीं भी भ्रष्टाचार को पनपने नहीं दिया जाएगा। वहीं चले रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता जांच के लिए अलग से एक टीम का गठन करके जांच कराई जाएगी। जांच में दोषी पाए जाने वाले ठेकेदारों, कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि पिछले कुछ माह से फर्रुखनगर में डिलिवरी नहीं हो रही है तथा स्टाफ की शिकायत है। इस बारे में एसएमओ से जवाब तलब के लिए उन्हें गुरुवार को पटौदी एसडीएम कार्यालय में आने के लिए बोला है।

PUBLIC NOTICE

To be known to all that My client Sh. Lukman Ahemad S/o Sh.Yaseen Khan R/o C-5/10,Gali No.4, C-Block, CHauhan Bangar, Garhi Medoo, East Delhi-110053. Owner of Shop No. 75, New Subji Mandi, Okhla New Delhi-110020, has applied for convertion his said shop into Free hold in DDA. The original Demand Letter/Allotment letter, Possession Letter, Site Possession letter, N.O.C. and receipts of payment made to DDA have been lost in the last month October 2019. In this regard any person(s) claiming any right, interest having any objection or found in possession of original documents may write/contact to above said owner or can personally contact to Dy. Dir.,(Commercial Estate) DDA, A-Block, 2nd Floor, Vikas Sadan, INA, New Delh.

Sd/-
Sumit Kumar, Advocate
Delhi Highcourt
E-No.-D/3178/11

ADITYA BIRLA CAPITAL
PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING
Aditya Birla Finance Limited
पंजीकृत कार्यालयः इंडियन रेयन कम्पाउण्ड, वेरावाल, गुजरात – 362 266
सीआईएनः U65990GJ1991PLC064603

परिशिष्ट – IV
[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 का नियम 8 (1) देखें]
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि,
अधोहस्ताक्षरी ने आदित्य बिड़ला फाइनैंस लिमिटेड, द्वितीय तल, यूको बैंक बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना दिनांकित 07–09–2019 जारी की थी, जिसमें कर्जदार/कर्जदारों मैस डैंगस आरएम इंडिया कम्पनी, श्री संजय सिंह, अर्चना सिंह से सूचना में वर्णित बकाया राशि रू. 1,41,01,652.72 (रूपए एक करोड़ इकतालीस लाख एक हजार छह सौ बावन तथा पैसे बहत्तर मात्र) का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।
कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा 08 नवम्बर, वर्ष दो हजार उन्नीस को प्राप्त कर लिया है।
कर्जदार/सह–कर्जदार को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार आदित्य बिड़ला फाइनैंस लिमिटेड, द्वितीय तल, यूको बैंक बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 की बकाया राशि रू. 1,41,01,652.72 (रूपए एक करोड़ इकतालीस लाख एक हजार छह सौ बावन तथा पैसे बहत्तर मात्र) तथा उस पर ब्याज का भुगतान करने के बाद ही किया जा सकता है।
कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का वर्णनः–
सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : श्री संजय सिंह तथा श्रीमती अर्चना सिंह द्वारा स्वाधिकृत मकान नंबर एच–16, एसएफ, परिमाप क्षेत्रफल 1720 वर्ग फीट, जो मेफील्ड गार्डन्स, सेक्टर–57, गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है।

आदित्य बिड़ला फाइनैंस लिमिटेड
स्थान : नई दिल्ली
हस्ता./–
तिथि : 14–11–2019
प्राधिकृत अधिकारी

सांकेतिक कब्जे की सूचना

ICICI Bank
शाखा कार्यालयः आईसीआईसीआई बैंक द्वितीय तल, वीडियोकॉन टॉवर, झंडेवालान एक्स., नई दिल्ली– 110055

जबकि
अधोहस्ताक्षरी ने वित्तिय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतरर्गत आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रुप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित कर्जदारों को मांग सूचनाएं निर्गमित की थी जिसमें उक्त सूचना के प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर सूचना में वर्णित राशि को प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।
कर्जदार/सह–कर्जदार/जमानतदार राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल रहे है अतएव एतद् द्वारा कर्जदार तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षर दाता द्वारा सांकेतिक अधिग्रहण किया गया है जो कि उक्त अधिनियम धारा 13(4) के तहत नियम 8 में दर्शाया गया है। संपत्ति तथा अधिग्रहण की तिथि नीचे दर्शाई गई है एतद् द्वारा विशेष रुप से कर्जदार एवं जनसाधारण को सम्पत्ति के संव्यवहार नहीं करने के लिए सचेत किया जाता है तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी संव्यवहार इसमें वर्णित राशि तथा उस पर आगे ब्याज हेतु आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

क्र.	कर्जदार/ सह–कर्जदार का नाम/ खाता क्र.	सम्पति का विवरण/ सांकेतिक कब्जे की तिथि	डिमांड नोटिस की तिथि/ डिमांड नोटिस में राशि (रु.)	शाखा का नाम
1.	शुभम पेपर्स/ उषा अग्रवाल/ शलभ अग्रवाल/ राहुल अग्रवाल/113205500212	प्लॉट नंबर –785, पॉकेट– सी आईएफसी गाजीपुर, दिल्ली / 08 नवंबर, 2019	अगस्त 21, 2019 ₹. 1,00,30,639/-	दिल्ली

उपरोक्त दर्शाये गये कर्जदार/सह–कर्जदार एवं जमानतदारों को सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन से 30 दिनों के अंदर राशि का भुगतान करें अन्यथा 30 दिनों की समाप्ति के पश्चात अधिग्रहित संपत्ति की नीलामी कर दी जायेगी जो पूर्णतः नियम 8 और 9 सुरक्षित ब्याज 2002 के अंतर्गत है।

दिनांकः नवम्बर 14, 2019
स्थानः दिल्ली
हस्ते/
प्राधिकृत अधिकारी
आईसीआईसीआई बैंक लि.

रोटोग्राफिक्स (इंडिया) लिमिटेड
सीआईएन : एल74899डीएल1976पीएलसी008036
पंजी. कार्यालय : यूनिट नंबर 8, भू तल, पाकेट एम, सरिता विहार, दिल्ली–110076
फोन : 011–42334176, ई–मेल : info@rotoindia.co.in वेबसाइट : www.rotoindia.co.in
30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही और अर्द्ध वर्ष हेतु अ–लेखापरीक्षित पृथक्कृत वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण
(रू. लाख में)

विवरण	तिमाही समाप्त 30–09–2019 अ–लेखापरीक्षित	अर्द्ध समाप्त 30–09–2019 अ–लेखापरीक्षित	तिमाही समाप्त 30–09–2018 अ–लेखापरीक्षित
परिचालन से कुल आय (शुद्ध)	2.87	2.87	5.50
अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदो से पहले)	(0.65)	(2.93)	2.26
अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) कर से पहले (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदो के बाद)	(0.65)	(2.93)	2.26
अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) कर पश्चात (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदो के बाद)	(0.65)	(2.93)	2.26
अवधि हेतु कुल समावेशी आय खजिसमें अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) सम्मिलित है,	(0.65)	(2.93)	2.26
इक्विटी शेयर पूंजी	360.13	360.13	360.13
प्रति शेयर अर्जन (रू. 10/– प्रत्येक का) मूल एवं तनुकृत (वार्षिककृत नहीं)	(0.02)	(0.08)	(0.06)

नोट :
1. उपरोक्त विवरण सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेन्जेज में प्रस्तुत किए गए तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का संक्षिप्त विवरण है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजेज की वेबसाइट www.bseindia.com और कम्पनी की वेबसाइट www.rotoindia.co.in पर उपलब्ध है।
2. वित्तीय परिणाम कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015, कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) (संशोधन) नियमावली, 2016 द्वारा संशोधित के अधीन अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (आईएनडी एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं।
3. उपरोक्त अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामो की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा तथा अनुमोदन निदेशक मंडल द्वारा 13–11–2019 को सम्पन्न उनकी बैठक में किया गया है।

वास्ते रोटोग्राफिक्स (इंडिया) लिमिटेड
स्थान : नई दिल्ली
नरेश कुमार बंसल
तिथि : 13–11–2019
निदेशक

TECHNO ELECTRIC & ENGINEERING COMPANY LTD.
(Formerly Simran Wind Project Limited)
CIN No :L40108UP2005PLC094368
Corporate Office : " Park Plaza " 71, Park Street, Kolkata - 700 016
Email : desk.investors@techno.co.in : Website: www.techno.co.in

Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter and half year ended September 30, 2019 (₹ in Lakhs)

PARTICULARS	Quarter ended		Half Year Ended			Year ended 31st March 2019
	30th September 2019	30th June 2019	30th September 2018	30th September 2019	30th September 2018	
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Total income from operations (net)	26,375.84	23,748.77	22,934.72	50,124.61	53,160.95	98,864.36
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	9,850.67	7,074.94	7,741.13	16,925.61	17,236.49	26,533.25
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	9,850.67	7,074.94	7,741.13	16,925.61	17,236.49	26,533.25
Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and /or Extraordinary items)	9,104.96	5,197.56	6,261.55	14,302.52	12,912.09	19,101.05
Total Comprehensive Income for the period	9,217.07	5,321.80	6,349.94	14,538.87	13,077.76	19,316.50
Equity Share Capital	2,200.00	2,200.00	2,253.65	2,200.00	2,253.65	2,253.65
Other Equity (excluding Revaluation Reserves)						1,40,369.26
Earnings Per Share (After tax and before Exceptional items) (of ₹2/- each)						
Basic :	8.37	4.82	5.64	13.19	11.62	17.16
Diluted:	8.37	4.82	5.64	13.19	11.62	17.16

Key numbers of Standalone Financial Results:

PARTICULARS	Quarter ended		Half Year Ended			Year ended 31st March 2019
	30th September 2019	30th June 2019	30th September 2018	30th September 2019	30th September 2018	
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Total income from operations (net)	26,375.84	23,748.77	22,934.72	50,124.61	53,160.95	98,864.36
Profit before Tax	9,735.78	6,972.89	6,646.19	16,708.67	16,141.61	25,427.93
Net Profit after Tax	9,022.93	5,125.19	5,359.06	14,148.12	12,009.66	18,159.32

Note : The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the Quarter and Half Year eneded September 30,2019 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the Stock Exchange websites, www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website www.techno.co.in.

For and on behalf of the Board of Directors
(P. P. Gupta)
Managing Director
Dated : The 13th day of November 2019

हरी झंडी के लिए विपुल ने दिखाई हरी झंडी!

राकेश चौरासिया। फरीदाबाद

हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बाद पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल बुधवार को पहली बार अपने रंग में दिखे। हालिया चुनाव में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने खटका बदलकर गोयल की गाड़ी लूप लाइन में डाल दी थी और गोयल अब तक इस लाइन पर ही विश्राम मुद्रा में थे। गुर्जर ने जब नरेंद्र गुप्ता नाम की नई एक्सप्रेस ट्रेन लांच की, तो सबको शिद्दत से इसका इंतजार था कि विपुल गोयल अब क्या करेंगे। बुधवार को विपुल गोयल हरी झंडी लेकर 'हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में' वाले अंदाज में अपने सागर सिनेमा वाले दफ्तर के सामने खड़े हो गए। यानि वे फिर मैदान में आ डटे हैं।

नेता की हालत टिकट कटने के बाद विधवा जैसी हो जाती है, लेकिन इससे परे विपुल गोयल अपने दोस्त नरेंद्र गोयल को ट्विटर पर कई बार बधाईयां देते दिखे। इस बीच राजनीति के चतुरसुजान यह चर्चा करते रहे कि क्या विपुल गोयल का बारूद इतनी जल्दी खत्म हो गया है। फुलझड़ी भी बुझने से पहले एक-दो बार झटके मारती है। इसलिए लोगों को इस बात का बेसब्री से इंतजार था कि गोयल का अगला कदम अब क्या होगा। अपने मुलाकातियों और कार्यकर्ताओं तक सीमित रहने के बाद वे पहली बार अपने पुराने सेवा-प्रकल्प के माध्यम से नमूदार हुए। चुनाव बाद पब्लिक डोमेन में उनके इस अवतार को लेकर यह कयास लगाए जा रहे हैं कि लो, अब डट गया हूं मैदान में।

राजनीतिक क्षेत्रों में विपुल का टिकट कटना उतना ही हैरतअंगेज था, जितना सीमा त्रिखा और नगेंद्र भड़ाना को टिकट मिलना। किंतु गुर्जर ने अपने धोबीपाट से इसे असंभव को भी संभव कर दिखाया। अमित शाह से ऑक्सीजन पाने वाले शोमैन ऑफ फरीदाबाद विपुल गोयल की बॉडी लेंग्वेज हाथों में झंडी लिए यही कह रही है कि याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन-जय या मरण होगा।

यात्राएं जारी रहेंगी : विपुल गोयल

विपुल गोयल ने सेक्टर 16 के सागर सिनेमा स्थित अपने कार्यालय से श्रद्धालुओं की बस को शिरडी साईं धाम के लिए रवाना किया और तीर्थ यात्रियों को मंगलमय यात्रा के लिए शुभकामनाएं दीं। विपुल गोयल जब कार्यालय पर पहुंचे, तो उनके सभी कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से जोरदार नारे लगाते हुए अपने नेता का स्वागत किया और चुनाव न लड़ने पर भी यात्राओं के दौर को जारी रखने पर प्रशंसा करते नजर आए। इस पर विपुल गोयल ने कहा कि इस तरह की तीर्थ यात्राएं वो हर महीने भेजते हैं और पिछले पांच सालों से हजारों लोगों को शिर्डी साईं के अलावा हरिद्वार, वैष्णों देवी माता के आशीर्वाद ओर दर्शन हेतु भेजते आये हैं। इसके साथ साथ मुस्लिम भाइयों को हज और उमरा भेजने कार्य भी करते रहे हैं। इसी तरह चाहे अपने सिख भाईयों के साथ पोंटा साहिब के दर्शन करना हो। ऐसा करने के पीछे उनकी सोच है कि जो लोग किसी भी अभाव में अपने जीवनकाल में कोई तीर्थयात्रा नहीं कर पाते हैं, उन्हें एक बार अवश्य किसी न किसी तीर्थ को अवश्य करना चाहिए। इससे उन्हें आत्म शान्ति तो मिलती ही है। साथ ही जो लोग दर्शन करने जा रहे है, उन्हें भी खुशी प्राप्त होती है। वो हर श्रद्धालु से फरीदाबाद और हरियाणा में तरक्की और अमन के लिए प्रार्थना करने की अपील करते हैं। गोयल का कहना है की वो इन यात्राओं का दौर इस बार चुनाव न लड़ने पर भी बंद नहीं करेंगे, अपितु ये सब यात्राएं पहले की तरह जारी रहेंगी। इस कार्यक्रम में मुकेश शास्त्री, प्रवीण चौधरी, विजय शर्मा, नरेश नंबरदार, बलवान शर्मा, पं. सुरेंदर बबली, मनीष राघव, रंजीत भाटी, सुरजीत अधाना, बालकिशन चौहान, जगबीर पहलवान, कपिल पाराशर, राकेश गर्ग, विनोद प्रधान, डॉ. कुलदीप जयसिंह, संजय, हरीश सैनी, योगेश गर्ग, बशीर अहमद व अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे।

डॉक्टर परिवार के चार लोगों का हत्यारोपी शिरडी से गिरफ्तार

पायनियर समाचार। फरीदाबाद

आरोपी जिम ट्रेनर मुकेश।

सेक्टर सात निवासी डॉ. प्रवीन मेहंदीरत्ता, उनकी पत्नी, बेटी व दामाद की तेज धारदार हथियार से बेरहमी के साथ हत्या करने वाले आरोपी जिम ट्रेनर मुकेश को अपराध शाखा सेक्टर 48 की टीम ने महाराष्ट्र के शिरडी से बुधवार सुबह गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस हवाई जहाज से आरोपी को फरीदाबाद ला रही है। फरीदाबाद आने पर आरोपी को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। तब इस सामूहिक हत्याकांड की परते खुल पाएंगी। पुलिस की चूक से आरोपी एक बार बच निकलने में कामयाब हो गया था।

क्या है मामला : गत नौ नवंबर की दोपहर को सेक्टर सात के डॉ. प्रवीन मेहंदीरत्ता के पड़ोसियों ने पुलिस को एक सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर देखा, तो बेसमेंट में डॉ. प्रवीन मेहंदीरत्ता, ग्राउंड फ्लोर के एक कमरे में उनकी पत्नी भारती, दूसरे कमरे में बेटी प्रियंका और दामाद सौरभ कटारिया मृत हालत में पड़े थे। किसी ने तेज धारदार हथियार से चारों की हत्या की थी। डॉ. मेहंदीरत्ता का बेटा दर्पण गुड़गांव काम पर गया हुआ था। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटैज खंगाली, तो पता चला कि एक स्कूटी सवार डॉ. मेहंदीरत्ता के घर आया था। करीब 25 मिनट में वारदात के बाद वह अपनी स्कूटी पर फरार हो गया।

शिरडी से गिरफ्तार : घटना के बाद से अपराध शाखा की टीमें मुकेश की सरगर्मी के साथ तलाश कर रही थी। गतदिवस अपराध शाखा सेक्टर 48 को मुकेश के शिरडी में मौजूद होने की सूचना मिली। अपराध शाखा टीम तुरंत शिरडी के लिए रवाना हो गई। जहां बुधवार सुबह टीम ने मुकेश को दबोच लिया। पुलिस प्रवक्त सूबेसिंह ने बताया कि आरोपी को फरीदाबाद लाया जा रहा है। यहां आने पर आरोपी से पूछताछ की जाएगी।

पुलिस की चूक

सूत्रों के मुताबिक मृतक के बेटे दर्पण से पूछताछ और जांच-पड़ताल के दौरान पुलिस को चार लोगों पर हत्या करने का शक हुआ था। इनमें से एक युवक दर्पण का दोस्त डबुआ कॉलोनी निवासी मुकेश है और वह सामने स्थित जिम में ट्रेनर की नौकरी करता है। पुलिस जिम पहुंची, तो वहां मुकेश मौजूद था। मुकेश के हाथ पर चोट भी लगी हुई थी। पुलिस के पूछने पर उसने दुर्घटना की कहानी बता कर टाल दिया। पुलिस ने लापरवाही बरतते हुए उसे सुबह अपराध शाखा के कार्यालय पहुंचने के लिए कह दिया। रात को घर लौटने के बाद मुकेश ने हत्या की बात स्वीकार करते हुए एक पत्र लिखकर घर में छोड़ दिया और फरार हो गया। अगले दिन मुकेश के न आने पर पुलिस उसके घर पहुंची और स्कूटी, पत्र और अन्य चीजें बरामद कीं।

जश्न-ए-फरीदाबाद : दो दिन के मेले में जुटेंगे साहित्य के पुरोधा

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

फरीदाबाद लिटरेरी एंड कल्चरल सेंटर (एफएलसीसी) शहर में साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जश्न-ए-फरीदाबाद के नाम से दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजित करेगा। 16 व 17 नवंबर को होने वाले इस कार्यक्रम में पुस्तक मेला, मुशायरा, एक शाम गालिब के नाम, ओ जमिया नईं-जिन लाहौर नईं वेख्या नामक नाटक और जीवा स्कूल की चित्रकला प्रतियोगिता सहित कई प्रस्तुतियां शामिल की हैं।

संस्था के अध्यक्ष विनोद मलिक ने बुधवार को यहां एक पत्रकार सम्मेलन में बताया कि वाईएमसीए यानि जेसी बोस विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम के लिए प्रवेश निशुल्क है। मलिक ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी मोबाइल फोन तथा कंप्यूटर में खोती जा रही है। इसलिए शहर में साहित्यिक व सांस्कृतिक आयोजन भी लगभग समाप्त से हो गए हैं। उनकी संस्था ने शहर की नयी पीढ़ी को सामाजिक, सांस्कृतिक व साहित्यिक आयोजनों से जोड़ने का बीड़ा उठाया है।

फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष बीआर भाटिया ने एफएलसीसी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि साहित्य मनुष्य को संवदेनशील बनाता है और वह सामाजिक उत्तदायित्वों के लिए प्रवृत्त होता है। इसलिए इस शहर में साहित्यिक गतिविधियों का होना जरूरी है। इंटरनेट के कारण आज के युवाओं के व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जरूरी है कि उन्हें साहित्य से जोड़ा जाए। इस अवसर पर वीके अग्रवाल, जगत मदान, मनोहरलाल नंदवानी, जगदीप मैनी, हरीश अरोड़ा, अश्वनी सेठी, शुभ तनेजा तथा वासु मित्र सत्यार्थी मौजूद थे।

फरीदाबाद की पहचान 'सस्ती दारू की दुकान'

विनोद मलिक ने विनोदी लहजे में कहा कि पहले फरीदाबाद की पहचान उद्योगों से थी। फिर उसकी पहचान बड़खल झील से हुई। अब झील सूखने के बाद दिल्ली में फरीदाबाद की पहचान 'सस्ती दारू वाली जगह' की बन गई है। इस पहचान को बदलना है और युवाओं को साहित्य से जोड़ना है।

बदमाशों ने युवक से एटीएम कार्ड छीनकर 24 हजार रुपये उड़ाए

बल्लभगढ़। यहां की अनाजमंडी के पास स्थित एक एटीएम से रुपये निकालने के लिए गए एक युवक से दो अज्ञात बदमाशों ने मारपीट कर एटीएम कार्ड छीन लिया। बाद में आरोपियों ने कार्ड की मदद से उसके खाते से 24 हजार रुपये निकाल लिए।

थाना आदर्श नगर में दर्ज मामले के मुताबिक पलवल निवासी अशोक कुमार ने अपनी शिकायत में कहा है कि मंगलवार को वह पैसे निकालने के लिए अनाज मंडी स्थित एटीएम बूथ पर चला गया। वहां पर उसने कार्ड डाल कर पैसे निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी, लेकिन रकम नहीं निकली। इस पर वह वहां से चल दिया। आरोप है कि तभी उसके पास आए दो युवकों ने मारपीट शुरू करते हुए उससे एटीएम कार्ड छीन लिया। कार्ड छीनने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। आरोप है कि थोड़ी ही देर बाद उसके मोबाइल पर 24 हजार रुपये निकाले जाने का संदेश आ गया।

जीवा के सभी क्लीनिकों में नि:शुल्क परामर्श

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

प्रमुख आयुर्वेद उपचार कंपनी जीवा आयुर्वेद राष्ट्र भर में अपने सभी क्लीनिकों में महीने भर के लिए निशुल्क परामर्श शिविर का आयोजन कर रही है। इस मेगा इवेंट के दौरान, पिछले 25 वर्षों में 15 लाख रोगियों के इलाज के अनुभव से 40 हजार से अधिक रोगियों को लाभ होने की उम्मीद है। जीवा चिकित्सक से रोगी अपने व्यक्तिगत उपचार के लिए किसी भी जीवा क्लिनिक में आ सकते हैं।

'भारत को 'डायबिटीज कैपिटल' के रूप में जाना जाता है, जो वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि यह आयुर्वेद की भूमि है, जो मधुमेह जैसी अन्य कई जीवनशैली सम्बंधित समस्याओं के इलाज और रोकथाम में प्रभावी है। जीवा आयुर्वेद के निदेशक डॉ. प्रताप चौहान ने कहा कि उन्हें यकीन है कि हर कोई इस अवसर का लाभ उठाएगा और अपने स्वास्थ्य समस्याओं और निरोग रहने के लिए हमारे डॉक्टर से परामर्श करेगा।'

उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के अनुसार 7.20 करोड़ भारतीयों को डायबिटीज है, और 2045 तक यह संख्या बढ़कर 15.10 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। डायबिटीज मुख्य रूप से गलत जीवनशैली और आहार के कारण होता है, जो आयुर्वेदिक उपचार का मुख्य क्षेत्र है। जीवा आयुर्वेद ने पिछले 25 वर्षों में डायबिटीज के 15 लाख रोगियों का सफलतापूर्वक परामर्श कर सम्पूर्ण उपचार प्रदान किया है, जिसमें व्यक्तिगत, विशेष दवाइयां, आहार और जीवनशैली संबंधी सुझाव सम्मिलित हैं।

संक्षिप्त समाचार

जिला स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता आयोजित

फरीदाबाद। सेक्टर 55 स्थित राजकीय आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कक्षा छह से आठ तक प्रतिभा खोज कला एवं संस्कृति और कक्षा नौ से 12 के लिए कला उत्सव का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला परियोजना अधिकारी अनीता शर्मा ने किया व अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य सतेन्द्र सौरोत ने की। प्रतिभा खोज में चार विधाओं की प्रतियोगिताओं में से 3 प्रतियोगिताओं में नृत्य, नाट्य कला व दृश्य कला का आयोजन किया, जिसमें जिले के विभिन्न स्कूलों की टीमों ने बेहतर प्रदर्शन किया। जिला परियोजना अधिकारी अनीता शर्मा ने सभी छात्र-छात्राओं को प्रतियोगिता में भाग लेने व विजयी होने की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने से हम सबके व्यक्तित्व में निखार आता है। प्रधानाचार्य व हरियाणा विद्यालय शिक्षा अधिकारी संगठन के जिलाध्यक्ष सतेन्द्र सौरोत, प्रधानाचार्य हेमलता, सहायक परियोजना समन्वयक अंजू चौधरी, जय सिंह शेखावत, प्राध्यापक संदीप सिंह, वीरेश कुमार, देशराज गोला, पंकज गुप्ता, मनीष कुमार, बृजेश कुमार, वसीम खान, सुमित कुमार, रचना शर्मा, सोनिका सरोहा, मधु लता, सुषमा यादव व सीमा भाटिया आदि ने विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं संभालीं और उपस्थित लोगों को संबोधित किया।

ट्रेन में झपटमारी करने वाले को पांच साल की कैद

फरीदाबाद। लोकल ट्रेन में महिला का पर्स झपट कर भागने वाले आरोपी को जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विरेंद्र मलिक की अदालत ने पांच साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला करीब दस महीने से अदालत में विचाराधीन था। अदालत में पेश मामले के मुताबिक ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर स्थित आरपीएफ थाने में तैनात एएसआई कृपाल सिंह ने यह मामला 31 जनवरी 2019 को आरपीएफ में दर्ज करवाया था। उसने अपनी शिकायत में कहा है कि वह अपने साथी पुलिस कर्मचारियों के साथ घटना वाले दिन रेलवे स्टेशन के प्लेट फार्म नंबर दो पर जांच-पड़ताल कर रहा था। उसी दौरान पलवल से दिल्ली की ओर जाने वाली एक ईएमयू ट्रेन प्लेटफार्म पर आकर रुकी। तभी यात्रियों द्वारा चोर-चोर की आवाज लगाई जाने लगी। उन्होंने देखा कि एक युवक ट्रेन से उतर कर तेजी के साथ भाग रहा था। युवक के हाथ में एक महिला का पर्स था। उन्होंने घेराबंदी कर तुरंत आरोपी को दबोच कर पर्स कब्जे में ले लिया। पकड़े गए आरोपी की पहचान ददसिया गांव निवासी नौशाद के रूप में हुई थी। उस समय आरपीएफ ने मामला दर्ज कर आरोपी को अदालत में पेश कर दिया था। जहां यह मामला तभी से विचाराधीन था। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है।

आरोपी डॉक्टर के खिलाफ निकाला कैंडल मार्च

फरीदाबाद। श्याम नगर कॉलोनी निवासी भगवत दयाल की गलत इलाज से मौत के बाद परिवार के लोगों ने ऑपरेशन करने वाले एक निजी अस्पताल के चिकित्सक और प्रबंधन पर हत्या का आरोप लगाते हुए पलवल शहर में कैंडल मार्च निकाला। मार्च में शहर के हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। परिजनों ने मांग की कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए भगवत दयाल को न्याय दिलाया जाए। मृतक के भाई भरतलाल ने बताया कि उनके भाई का पथरी के ओप्रशन के लिए सेक्टर 16 के एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया था। जहां डॉक्टरो ने कई सर्जरी कर दी। बाद में उसे वेंटिलेटर पर बिना कारण बताए शिफ्ट कर दिया। बार-बार पूछने पर भी डॉक्टर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। पांच नवंबर शाम को डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की वजह से उनके भाई की जान गई है। वह पुलिस प्रशासन व सरकार से मांग करते हैं कि दोषी डॉक्टरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए।

शादी से लौट रहे चार दोस्तों पर रॉड से हमला

फरीदाबाद। सेक्टर दो में आयोजित शादी समारोह से लौट रहे चार दोस्तों पर कार सवार युवकों ने रॉड व डंडों से हमला कर दिया। हमला करने के बाद आरोपित धमकी देते हुए फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने आरोपित युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सिटी थाने में दर्ज मामले के अनुसार तिरखा कॉलोनी निवासी हरिमोहन ने दी शिकायत में बताया कि सात नवंबर को उसके परिचित का सेक्टर-दो स्थित कम्युनिटी सेंटर में लग्न सगाई समारोह आयोजित था, जिसमें हरिमोहन अपने दोस्त शिवम कुमार, चंकित कुमार व भोली के साथ शामिल होने गया था। समारोह में हरिमोहन की पवन भाटी नामक युवक से कहासुनी हो गई। कहासुनी होने पर हरिमोहन अपने दोस्तों के साथ वहां से वापिस आ गया और सेक्टर दो स्थित एक ढाबे में खाना खाने लगे। खाना खाकर जब वह बाहर आए, तो वहां पर 4-5 लड़के ईको गाड़ी में आए और उन पर डंडे व रॉड से हमला कर दिया। इन युवकों में तरखा कॉलोनी निवासी पवन भाटी भी शामिल था।

हथौड़े से पत्नी की हत्या करने वाले को उम्रकैद

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

फरीदाबाद। हथौड़े से वार कर पत्नी की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी को जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कुमुद गुगनानी की अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत में पेश मामले के मुताबिक बिहार के बक्सर जिले के उमाशंकर ओझा ने यह मामला 28 नवंबर, 2017 को थाना सराय ख्वाजा में दर्ज करवाया था कि उसने अपनी बेटी पम्मी का विवाह यहां के सूर्या विहार भाग तीन के विरेंद्र पांडे से किया था। पम्मी ने तीन बेटियों को जन्म दिया। फिर भी विरेंद्र पांडे ने कामधंधा शुरू नहीं किया। इसलिए पम्मी और विरेंद्र के बीच आए दिन झगड़े होते थे। 26 नवंबर की शाम को भी कामधंधे को लेकर विरेंद्र व पम्मी के बीच झगड़ा हुआ, तो विरेंद्र ने हथौड़े से ताबड़तोड़ वार कर पम्मी को मौत के घाट उतार दिया।

उमाशंकर का कहना है कि पुलिस की सूचना पर वह अगले दिन वह वहां पहुंच गया। पम्मी की छह साल की बेटी से पूछताछ करने पर उसने पूरी घटना के बारे में बता दिया। उस समय पुलिस ने आरोपी विरेंद्र के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया था। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर दिया था। जहां यह मामला तभी से विचाराधीन था। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी को यह सजा सुनाई है।

टॉवर की नौवीं मंजिल से युवक कूदा, मौत

फरीदाबाद। सूरजकुंड इलाके में स्थित एक टॉवर की नौवीं मंजिल पर एक युवक जा पहुंचा। जहां उसने संदिग्ध परिस्थितियों में छलांग लगा दी। जमीन पर गिरते ही युवक की मौके पर ही युवक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए बीके अस्पताल भेज दिया है।

थाना सूरजकुंड पुलिस के मुताबिक सूरजकुंड पर्यटन स्थल के नजदीक पिनाकल टॉवर स्थित है। इस टॉवर में रिहायशी फ्लैट बने हुए हैं। बताया गया है कि बुधवार की दोपहर को इस टावर की नौवीं मंजिल से एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में छलांग लगा दी। सीधे जमीन पर गिरते ही युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान बल्लभगढ़ की भाटिया कॉलोनी में रहने वाले 30 वर्षीय सौरभ के रूप में हुई है। पुलिस ने शव फिलहाल मोरचरी में रखवा दिया है। घटना की सूचना परिजनों को दे दी गई। बृहस्पतिवार को शव का पोस्टमॉर्टम करवाया जाएगा

तनाव से मुक्ति के लिए डॉक्टरों ने लिया गीता का ज्ञान

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

भागदौड़ भरी जीवनशैली में जिस प्रकार आम लोग तनावग्रस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार डॉक्टर भी आए दिन बढ़ते मरीजों की संख्या के कारण तनावपूर्ण जीवन जी रहे हैं। डॉक्टरों को तनावरहित करने के उद्देश्य से आईएमए और ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सहयोग से श्रीमद्भगवत गीता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में मुख्यातिथि के रूप में मंडलायुक्त जी. अनुपमा, गरिमा भगत और जिला सिविल सर्जन डॉ. गुलशन राय अरोड़ा मुख्यातिथि रहे। आईएमए की अध्यक्ष डॉ. पुनीता हसीजा ने बताया कि बदलते समय के कारण मरीजों की संख्या बढ़ गई है, जिससे डॉक्टरों पर मरीजों को दबाव अधिक रहता है। इस कारण वे तनाव में रहते हैं। खासकर सरकारी अस्पतालों में एक डॉक्टर रोजाना 150 से 200 मरीजों की जांच करता है, वह तनावपूर्ण जीवन जीता है। जबकि डॉक्टरों का मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। इसे देखते हुए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने डॉक्टरों ने गीता में श्री कृष्ण द्वारा दिए उपदेश का वर्णन किया। प्रत्येक उपदेश का मनुष्य जीना में महत्व बताया। इस दौरान सभी डॉक्टरों को भगवत गीता भेंट की गई। उन्हें नियमित रूप गीता पढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. असीम दास ने कार्यक्रम की प्रशंसा की। इस अवसर पर डॉ. मार्कान डे आहुजा, डॉ. श्रीधन द्ववेदी, डॉ. एएसएन राव, कॉलेज रजिस्ट्रार डॉ. अनिल पांडे, फिजीशियन डॉ. प्रवीन मलिक सहित अनेक डॉक्टर मौजूद रहे।

डायबिटिक राजधानी के खिलाफ लड़ाई में जुटे कई योद्धा

डायबिटिज दिवस

कविता। फरीदाबाद

विशेषज्ञों ने 2035 तक भारत को डायबिटिक राजधानी के तौर पर पहचाने जाने की घोषणा की है, लेकिन विश्व डायबिटिज दिवस पर सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में में डायबिटीज क्लीनिक खोल कर इस बीमारी पर रोक लगाने का प्रयास किया है। जिले में डायबिटीज के लिए बने एनसीडी क्लीनिक में रोजाना 150 मरीज पहुंच रहे हैं। मरीजों के साथ उनके परिजनों को भी डायबिटीज के प्रति जागरूक किया जा रहा है। ताकि आगामी वर्ष 2025 तक प्रदेश को डायबिटीज मुक्त किया जा सके। यह कहना है बीके सिविल अस्पताल की पीएमओं डॉ. सविता यादव का।

डॉ. सविता यादव ने बताया कि आजकल खान-पान में आए बदलाव से शहर में डायबिटीज के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। बीके अस्पताल में एनसीडी क्लीनिक कमरा नंबर 21 में चलाया जा रहा है, जिसमें डायबिटीज और बीपी की जांच की जा रही है। इस सेंटर के इंचार्ज डॉ. विकास शर्मा ने बताया कि यहां जिले के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों से मधुमेह के रोगियों को भेजा जा रहा है और मरीजों की जांच करने के पश्चात ही उनका इलाज शुरू किया जाएगा।

स्वास्थ्य चर्चा का आयोजन : सर्वोदय हॉस्पिटल में 'जन्मजात टाइप-1 डायबिटीज के साथ बेहतर जीवन' विषय पर एक स्वास्थ्य चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों और उनके माता-पिता के मध्य डायबिटीज के प्रति जागरूकता विकसित करने के उद्देश्य से टाइप-1 डायबिटीज से जुड़ी सावधानियां और इलाज के आधुनिक विकल्प सांझा किए गए। बच्चों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता के साथ-साथ अन्य मनोरंजक कार्यक्रम रखे गए। सर्वोदय हॉस्पिटल के चेयरमैन और वरिष्ठ डायबिटोलॉजिस्ट डॉ. राकेश गुप्ता ने बताया कि 'मधुमेह एक ऐसा जानलेवा रोग है, जिससे हमारे देश में लाखों लोग पीड़ित है और दुर्भाग्य वश इस बिमारी का कोई अंत नहीं है। ज्यादातर लोग इसकी जटिलताओं को नहीं समझते और यही वजह है कि अपनी सेहत को नजरअंदाज करते हैं। टाइप-2 डायबिटीज के प्रति अज्ञानता भी इसके इतनी तेज गति से बढ़ने के लिए जिम्मेदार है।'

जानकारी का अभाव

डॉ. सविता यादव ने कहा कि आधे से ज्यादा लोगों को यह जानकारी नहीं होती, कि वे मधुमेह रोग से ग्रस्त हैं। इस बार की थीम परिवार और मधुमेह है, जिसका उद्देश्य है कि मधुमेह के प्रति सभी जागरूक हो। उन्होंने कहा कि अगर डायबिटीज का समय पर इलाज न किया जाए, तो किडनी रोग, हृदय रोग, अंधापन आना, लकवा होना, पांव के इंफेक्शन, अल्सर गैंग्रीन का खतरा बढ़ जाता है। केवल 40 प्रतिशत लोग ही अपनी डायबिटीज पर नियंत्रण कर पाते हैं।

डायबिटीज है दीमक

क्यूआरजी हेल्थ सिटी हॉस्पिटल के सीनियर मेडिसिन कंसल्टेंट डॉ. सुंदरी श्रीकांत ने बताया कि डायबिटीज की बीमारी एक दीमक की तरह है, जो बाहर से नही दिखाई देती है, लेकिन अंदर ही अंदर सारे शरीर को खत्म कर देती है। इस बीमारी के प्रति लोग ज्यादा गंभीर नहीं दिखाई देते हैं और दवाईयां भी कुछ समय बाद अपनी मर्जी से बंद कर देते हैं। डायबिटीज एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जो अन्य खतरनाक बीमारियों को न्यौता देती है। इसका सबसे ज्यादा असर किडनी पर पड़ता है।

किसान ने दी आत्महत्या की चेतावनी

फरीदाबाद। थाना छांयसा क्षेत्र के मोहना गांव निवासी एक किसान ने पुलिस की प्रताड़ना से दुखी होकर गुरुवार दोपहर बाद किसी भी समय आत्महत्या करने का फैसला लिया है। पीड़ित ने इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर सीएम व पीएम तक को अलटीमेटम पत्र भेजन का दावा किया है। मोहना गांव निवासी किसान के बेटे ने मीडिया को जारी पत्र में कहा कि उसके पिता को थाना छांयसा पुलिस बेवजह प्रताड़ित कर रही है। उसके पिता के खिलाफ पुलिस दबंग लोगों के दबाव में आकर उलटे-सीधे मामले दर्ज कर रही है। युवक का यह भी आरोप है कि दबंगों ने उसकी पत्नी के साथ भी छेड़खानी की थी, जिसकी शिकायत महिला थाना पुलिस को दी गई। मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

कांग्रेस के साथ हिंदुत्व का एजेंडा कैसे फिट होगा

● भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना पर किया तंज

एजेंसी। मुंबई

भाजपा ने बुधवार को सहयोगी से राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी बन चुकी शिवसेना पर हिंदुत्व को लेकर तंज कसा जो विपरीत विचारधारा वाले दलों कांग्रेस और राकांपा के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाने की संभावनाएं तलाश रही है।

महाराष्ट्र में मंगलवार से राष्ट्रपति शासन लग चुका है। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे ने कहा, ये शिवसेना पर है कि वह कांग्रेस के साथ न्यूनतम साझा कार्यक्रम (सीएमपी) में अपने हिंदुत्व के एजेंडे को कैसे फिट करती है। उन्होंने समाचार चैनलों से कहा, कांग्रेस, जो 150 साल पुरानी पार्टी है, जाहिर तौर पर (सरकार में) वह अपने एजेंडा को आगे बढ़ाएगी।

शिवसेना अक्सर खुद को हिंदुत्ववादी दल के रूप में पेश करती है, और यही वह वैचारिक धरातल है जो उद्धव ठाकरे की पार्टी तथा भाजपा को आपस में जोड़ता है। ठाकरे ने मंगलवार रात को कहा कि अगर सरकार बनती है तो कांग्रेस और राकांपा की तरह शिवसेना को भी न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर स्पष्टता चाहिए। दानवे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का बचाव करते हुए कहा, राज्यपाल के खिलाफ आपत्ति करना सही नहीं है। उन्होंने केवल संवैधानिक अधिकारों का उपयोग किया। उन्होंने कहा कि चूंकि अब

राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है, इसलिए अब शिवसेना के पास बहुमत साबित करने के लिए पर्याप्त समय है। उन्होंने कहा, अगर शिवसेना के पास आंकड़े हैं तो वह कभी भी दावा कर सकते हैं।

अपनी पार्टी की रणनीति के बारे में उन्होंने कहा कि जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो भाजपा विपक्ष में बैठेगी। गौरतलब है कि हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 288 सदस्ईय विधानसभा में भाजपा 105 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी लेकिन 145 के बहुमत के आंकड़े से 40 सीट दूर रह गई। भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली शिवसेना को 56 सीटें मिलीं। वहीं राकांपा ने 54 और कांग्रेस ने 44 सीटों पर जीत दर्ज की।

फडणवीस ने ट्विटर पर अपना परिचय बदलकर महाराष्ट्र का सेवक किया

मुंबई। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को ट्विटर पर अपना परिचय बदलकर उसे महाराष्ट्र का सेवक कर दिया। मुख्यमंत्री के रूप में फडणवीस ट्विटर पर काफी सक्रिय रहते थे। भाजपा और शिवसेना के बीच सत्ता की साझेदारी को लेकर सहमति नहीं बन पाने के चलते उन्होंने आठ नवंबर को पद से इस्तीफा दे दिया था। फडणवीस (49) कांग्रेस के नेता वसंतराव नाइक के बाद महाराष्ट्र के दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। भाजपा द्वारा सरकार बनाने का दावा नहीं करने के बाद भाजपा नेता ने पिछले सप्ताह ट्विटर पर अपना परिचय महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री से बदलकर कार्यवाहक मुख्यमंत्री कर दिया था। राज्य में मंगलवार को राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया।

संजय राउत को अस्पताल से छुट्टी, कहा- शिवसेना से होगा अगला मुख्यमंत्री

बुधवार को मुंबई के लीलावती अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अपने सर्मथकों के साथ शिवसेना नेता संजय राउत

एजेंसी। मुंबई

शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत को बुधवार की दोपहर मुंबई के लीलावती अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। दो दिन पहले वह अस्पताल में भर्ती हुए थे। हृदय की वाहिकाओं में आए दो ब्लॉकेज को हटाने के लिए राउत (57) की सोमवार की शाम अस्पताल में एंजियोप्लास्टी हुई थी।

अस्पताल से दोपहर एक बजे के आसपास रवाना होते समय राउत ने कहा, महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री शिवसेना से ही होगा। राउत के परिवार के एक सदस्य ने बताया कि डॉक्टरों ने उन्हें कुछ समय के लिए आराम करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा, एंजियोप्लास्टी प्रक्रिया की प्रगति के आकलन के लिए कुछ दिन बाद उनकी एक और जांच होगी।

सीने में दर्द के बाद राउत सोमवार की शाम लीलावती अस्पताल पहुंचे थे। डॉ. जलील पारकर ने उनका उपचार किया। शिवसेना के मुखपत्र सामना के कार्यकारी संपादक राउत पिछले कुछ समय से लगातार अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए मीडिया से बात कर रहे थे। राज्य में 24 अक्टूबर को चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद से वह भाजपा-शिवसेना में हुए सत्ता के बंटवारे के कथित समझौते का हवाला देते हुए ढाई-ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री पद के संबंध में मांग दोहरा रहे थे।

अयोग्य ठहराए गए विधायकों पर न्यायालय के फैसले का कोई मतलब नहीं: कुमारस्वामी

एजेंसी। बेंगलुरु

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एवं जदएस नेता एच डी कुमारस्वामी ने बुधवार को दावा किया कि अयोग्य ठहराए गए विधायकों को लेकर उच्चतम न्यायालय के फैसले का कोई मतलब नहीं है।

कुमारस्वामी ने संवाददाताओं से कहा, एक ओर उन्हें अयोग्य ठहराए जाने को बरकरार रखा गया और दूसरी ओर उन्हें चुनाव लड़ने की इजाजत दी। उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के 17 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को सही ठहराया

लेकिन राज्य में 15 सीटों पर पांच दिसंबर को होने वाले उपचुनाव में हिस्सा लेने का उनका मार्ग प्रशस्त कर दिया। अदालत ने तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार के आदेश का वह हिस्सा निरस्त कर दिया जिसमें इन विधायकों को 15वीं विधानसभा के कार्यकाल के अंत तक के लिए अयोग्य घोषित किया गया था।

कुमारस्वामी ने कहा, दलबदल विरोधी कानून को शक्ति दिए बिना हमने यह कहते हुए अपनी पीठ थपथपाई कि हम कानून लाए हैं। दलबदल निरोधी कानून में क्या है? उन्हें (जनप्रतिनिधियों को) जब वे चाहें इस्तीफा देने के मनमाने कृत्यों से रोकना। कुमारस्वामी ने कहा, जिस तरह से आप बढ़ावा दे रहे हैं, आपके निर्णय का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा, यदि देश के लोकतंत्र को बचाए रखना है, कुछ सीमा तक अनुशासन प्रदर्शित किया जाना चाहिए। यदि दलबदल विरोधी कानून का सम्मान न हो तो, कोई मतलब नहीं है।

यह पूछे जाने पर कि क्या भाजपा के साथ सुलह की कोई संभावना है, कुमारस्वामी ने कहा कि उन्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर जदएस के बारे में ऐसी धारणा बनाए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, जब 2018 विधानसभा चुनाव हुए थे, उन्होंने, राहुल गांधी से जदएस को भाजपा की बी-टीम घोषित करने के लिए कहा था। वह फिर से वही चाल चलना चाहते हैं। इस बार यह नहीं चलेगा।

सीबीआई अदालत ने एसएमएच मिर्जा की जमानत याचिका खारिज की

कोलकाता। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने नारद टेप मामले के सिलसिले में भ्रष्टाचार को लेकर गिरफ्तार निलंबित आईपीएस अधिकारी एचएमएच मिर्जा की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी। साथ ही, उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि 26 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी। मिर्जा के वकील ने कोलकाता स्थित अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल इस कांड से किसी तरह से जुड़े हुए नहीं है लेकिन वह 49 दिनों से हिरासत में है। उन्होंने अदालत से मिर्जा को जमानत देने का अनुरोध किया क्योंकि उनकी गिरफ्तारी के बाद से मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है। वहीं, सीबीआई के वकीलों ने दलील दी कि मिर्जा की अपील खारिज की जाए क्योंकि पूछताछ के लिए उन्हें और अधिक समय तक हिरासत में रखे जाने की जरूरत है।

मिजोरम के राज्यपाल पी श्रीधरन पिल्लई ने बुधवार को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की

क्विक न्यूज

कश्मीर में आतंकवादियों ने दुकानदार को गोली मारी

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले मे बुधवार को आतंकवादियो ने एक दुकानदार की हत्या कर दी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियो ने मेहराजउद्दीन को दक्षिण कश्मीर के त्राल इलाके मे उनकी दुकान मे गोली मार दी। मेहराजउद्दीन त्राल के निवासी थे। अधिकारी ने बताया कि मौके पर ही दुकानदार की मौत हो गई।

भाजपा ने किश्तवाड़ में आतंकवाद के सिर उठाने की जांच कराने की मांग की

जम्मू। भाजपा ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील किश्तवाड़ जिले मे आतंकवाद के बढ़ते मामलो की पूरी जांच कराने का आह्वान किया। इस जिले को एक दशक पहले आतंकवाद मुक्त घोषित किया गया था। पिछले एक साल मे जिले मे भाजपा के एक वरिष्ठ नेता और आरएसएस के पदाधिकारी सहित चार लोगो की हत्याएं हुई और हथियार छीनने की दो घटनाएं सामने आई। जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रवक्ता ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने यहां संवाददाताओ से कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने करीब एक दशक पहले आतंकवाद मुक्त घोषित इस इलाके (किश्तवाड़) मे आतंकवाद के फिर से सिर उठाने की साजिश की पूरी जांच की मांग की है। जिले मे आतंकवाद संबंधी मामलो की छानबीन का जिम्मा गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौपे जाने के फैसले की सराहना करते हुए ब्रिगेडियर गुप्ता ने कहा कि नेटवर्क का भंडाफोड़ करने और कुछ संदिग्ध लोगो की गिरफ्तारी किया जाना प्रशंसनीय है। भाजपा ने कहा कि साजिश की जड़े बहुत गहरी है और इसका नापाक इरादा अल्पसंख्यको के बीच खौफ पैदा कर उन्हे फिर से पलायन के लिए मजबूर करना है।

महिला कॉन्स्टेबल का पीछा करने के मामले में आईबी अधिकारी गिरफ्तार

मुम्बई। एक महिला कॉन्स्टेबल का कथित तौर पर पीछा करने के मामले मे पूर्वी उपनगर के घाटकोपर मे खुफिया ब्यूरो (आईबी) के एक अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। पंत नगर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि स्पेश कुमार अनिल कुमार को उसके एंटॉप हिल स्थित घर से रविवार को गिरफ्तार किया गया। 34 वर्षीय एक महिला कॉन्स्टेबल ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। अधिकारी ने बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तैनाती के दौरान स्पेश और पीड़िता की जान पहचान हुई थी। उन्होने बताया कि महिला का बाद मे मुम्बई पुलिस की सोशल ब्रांच द्वितीय मे तबादला हो गया और उसने आईबी अधिकारी से बात करनी बंद कर दी। अधिकारी ने बताया कि पीड़िता के उससे बात ना करने पर आरोपी ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया।

अयोध्या फैसले को लेकर भड़काऊ फेसबुक पोस्ट पर 35 वर्षीय व्यक्ति गिरफ्तार

एजेंसी। इंदौर (मध्यप्रदेश)

अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले को लेकर फेसबुक पर लगातार आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने के आरोप में पुलिस ने यहां 35 वर्षीय व्यक्ति को बुधवार को गिरफ्तार किया।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) शैलेन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि कनाड़िया पुलिस थाने में हुई शिकायत पर जांच के बाद पकड़े गए आरोपी की पहचान जितेन्द्र चौहान (35) के रूप में हुई है। वह नजदीक के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में एक टायर कम्पनी के संयंत्र में मशीन ऑपरेटर के रूप में काम करता है। एएसपी ने बताया कि चौहान पर अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के नौ नवंबर के फैसले के बाद से फेसबुक पर लगातार भड़काऊ सन्देश पोस्ट करने का आरोप है। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 295-ए (किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जान-बूझकर किए गए विद्वेषपूर्ण कार्य) और अन्य संबद्ध कानूनी प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। एएसपी के मुताबिक आरोपी अलग-अलग सियासी पार्टियों के लिए काम कर चुका है। वह पहले भी एक साइबर अपराध में गिरफ्तार हो चुका है। मामले में विस्तृत जांच जारी है।

उत्तराखंड में आपदा संवेदनशील भवनों के सर्वेक्षण के लिए बजट आवंटन

देहरादून में अपने मंत्रिमंडल के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत

एजेंसी। देहरादून

उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को आपदा नियंत्रण हेतु संवेदनशील भवनों के सर्वेक्षण के लिए 3.73 करोड़ रुपए के बजट आवंटन को मंजूरी देने तथा उत्तराखण्ड जैविक कृषि विधेयक के मसौदे को स्वीकृति देने जैसे कई फैसलों पर अपनी मुहर लगा दी।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तथा राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने संवाददाताओं को बताया कि उच्च भूकंप न्यूनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत एकीकृत सुरक्षा कार्यक्रम बनाए जाने को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा, सुरक्षित भवन तकनीक से निर्माण के लिए राज मिस्त्री का मानदेय 350 रु से बढाकर 500 रुपए किया गया है। उन्होंने बताया कि एक अन्य फैसले में सामुदायिक रेडियो स्टेशन की अनुदान राशि पांच लाख से बढ़ाकर 10 लाख रु करने को भी सवीकृति दे दी गई।

सबरीमाला फैसला: केरल में संगठनों और श्रद्धालुओं की धड़कने बढ़ीं

तिरुवनंतपुरम। उच्चतम न्यायालय द्वारा सबरीमाला मंदिर में सभी आयुवर्ग की महिलाओं के प्रवेश की इजाजत के अपने फैसले की समीक्षा के मामले में गुरुवार को फैसला सुनाए जाने से पूर्व केरल में राजनीतिक दलों, दक्षिणपंथी संगठनों और श्रद्धालुओं की धड़कनें तेज हो गई हैं। केरल में पिछले साल शीर्ष अदालत के आदेश को लागू करने के माकपा नीत वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार के फैसले को लेकर श्रद्धालुओं और दक्षिणपंथी संगठनों के विरोध प्रदर्शन से माहौल गर्मा गया था। उच्चतम न्यायालय का फैसला मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अगुवाई वाली एलडीएफ सरकार के लिए भी अहम है क्योंकि बस तीन दिन बाद सबरीमला में वार्षिक तीर्थयात्रा शुरू होने जा रही है। केरल में पथनमथिट्टा जिले के पश्चिमी घाटी पर संरक्षित वनक्षेत्र में स्थित इस पहाड़ी धार्मिक स्थल के द्वार 16 नवंबर की शाम को दो महीने तक चलने वाले मंडलम मकराविलाक्कू के लिए खोले जाएंगे।

कश्मीर में 101वें दिन भी इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहीं

एजेंसी। श्रीनगर

केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 के कई प्रावधानों को रद्द करने के बाद से कश्मीर में निलंबित इंटरनेट सेवाएं बुधवार को 101वें दिन भी पूरी तरह बंद रहीं। इसके चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित रहा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

इंटरनेट सेवाएं बहाल करने की बढ़ती मांग के बावजूद अधिकारियों ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है। खासतौर से पत्रकारों द्वारा इंटरनेट सेवाओं की मांग की जा रही है। मीडियाकर्मियों ने इंटरनेट सेवाओं को तत्काल बहाल करने की मांग को लेकर मंगलवार को एक विरोध मार्च भी निकाला। जम्मू-कश्मीर को दिया गया विशेष दर्जा केंद्र सरकार द्वारा पांच अगस्त रद्द करने और राज्य को दो हिस्सों में बांटने की घोषणा के बाद राज्य में सभी संचार साधनों- लैंडलाइन फोन, मोबाइल फोन सेवाएं और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थीं।

कश्मीर घाटी में हालांकि लैंडलाइन और पोस्टपेड मोबाइल फोन सेवाएं बहाल कर दी गई हैं, लेकिन प्रीपेड मोबाइल फोन और इंटरनेट सेवाएं अभी भी रद्द हैं। अधिकारियों ने बताया कि ऐसी आशंका है कि निहित स्वार्थ के चलते कुछ तत्व घाटी में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने के लिए इंटरनेट सेवाओं का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इन सुविधाओं के बहाल करने के बारे में उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा। केंद्र द्वारा पांच अगस्त को लिए गए निर्णय के बाद से ही कश्मीर घाटी में अघोषित बंदी है, जिससे घाटी में सामान्य जनजीवन काफी हद तक प्रभावित हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि घाटी में बाजार अब नए ढंग से खुल रहे हैं। दुकानें सुबह जल्दी खुलती हैं और दोपहर तक बंद हो जाती हैं। इस तरह दुकानदार अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बुधवार को भी ऐसा ही देखने को मिला। उन्होंने कहा कि उपद्रवियों और आतंकवादियों ने व्यापारियों को धमकी देकर दुकानें बंद करा रखी हैं।

अधिकारियों ने बताया कि शहर के व्यस्त गोनी खान बाजार और काका सराय इलाकों में हाल में दो ग्रेनेड हमले करके आतंकवादियों ने दुकानदारों को भयभीत किया है। उनके मुताबिक शहर में सार्वजनिक परिवहन अब धीमे-धीमे सामान्य होने लगा है क्योंकि अब मिनी-बस सड़कों पर चलने लगी हैं। जिले के बीच चलने वाली कैब और आटो-रिक्शा भी चल रहे हैं। कश्मीर में सभी प्रमुख अलगाववादी नेताओं को ऐतिहातन हिरासत में लिया गया है। जबकि दो पूर्व मुख्यमंत्रियों उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत मुख्यधारा के नेताओं को नजरबंद किया गया है।

आरटीआई के तहत प्रधान न्यायाधीश का कार्यालय आने से जुड़े मामले में घटनाक्रम

एजेंसी। नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के 2010 के उस फैसले को बुधवार को बरकरार रखा जिसमें कहा गया था कि प्रधान न्यायाधीश का कार्यालय सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के दायरे में आता है। इस मामले से जुड़े घटनाक्रम इस प्रकार है:

11 नवम्बर, 2007: आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल ने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की और न्यायाधीशों की संपत्तियों पर सूचना मांगी।

30 नवम्बर, 2007: जवाब में उन्हें सूचना देने से इनकार कर दिया गया।

08 दिसम्बर, 2007: सूचना दिए जाने से इनकार के खिलाफ उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री में पहली अपील दाखिल की गई।

12 जनवरी, 2008: उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री ने पहली अपील खारिज की।

05 मार्च: अग्रवाल ने सीआईसी का रुख किया।

06 जनवरी, 2009: सीआईसी ने उच्चतम न्यायालय से इस आधार पर न्यायाधीशों की संपत्तियों पर सूचना का खुलासा करने को कहा कि सीजेआई का कार्यालय

आरटीआई अधिनियम के दायरे में आता है।

17 जनवरी: उच्चतम न्यायालय ने सीआईसी आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया।

19 जनवरी: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीआईसी के आदेश पर रोक लगाई।

26 फरवरी: उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उसके न्यायाधीशों के प्रधान न्यायाधीश के समक्ष अपनी संपत्तियों की घोषणा व्यक्तिगत जानकारी है जिसका आरटीआई अधिनियम के तहत खुलासा नहीं किया जा सकता है।

17 मार्च: उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उसके न्यायाधीश अपनी संपत्तियों की घोषणा करने के खिलाफ नहीं है और संसद को इस तरह की घोषणा किए जाने से संबंधित एक कानून बनाना चाहिए लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस कानून का दुरुपयोग नहीं हो।

24 मार्च: उच्च न्यायालय ने कहा कि संपत्ति की घोषणा के मामले में न्यायाधीशों के साथ नेताओं की तरह बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए।

चार मई: उच्चतम न्यायालय ने कहा कि बहुत अधिक पारदर्शिता न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रभाव डाल सकती है।

04 मई: उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा।

02 सितम्बर: उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने सीआईसी के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें कहा गया था कि सीजेआई का कार्यालय आरटीआई अधिनियम के दायरे में आता है और पारदर्शिता कानून के तहत न्यायाधीशों की संपत्तियों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

05 अक्टूबर: शीर्ष न्यायालय ने एकल पीठ के फैसले को दो सदस्ईय पीठ के समक्ष चुनौती दी।

06 अक्टूबर: उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए सहमति दी।

07 अक्टूबर: उच्च न्यायालय ने अपील को स्वीकार किया और इस मुद्दे पर फैसला लेने के लिए तीन सदस्ईय विशेष पीठ गठित की।

13 नवम्बर: उच्च न्यायालय ने अपील पर फैसला सुरक्षित रखा।

12 जनवरी, 2010: उच्च न्यायालय ने कहा कि सीजेआई का कार्यालय आरटीआई अधिनियम के दायरे में आता है।

26 नवम्बर: उच्चतम न्यायालय के सेक्रेटरी जनरल और सीपीआईओ ने उच्च न्यायालय और सीआईसी के आदेशों के खिलाफ तीन अपील दायर की।

17 अगस्त, 2016: उच्चतम न्यायालय ने मामले को एक संविधान पीठ के पास भेजा।

04 अप्रैल, 2019: उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में फैसला सुरक्षित रखा कि क्या सीजेआई का कार्यालय आरटीआई अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण है या नहीं।

13 नवम्बर: उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 2010 में दिए गए फैसले को बरकरार रखा जिसमें कहा गया था कि प्रधान न्यायाधीश का कार्यालय एक सार्वजनिक प्राधिकार है और यह आरटीआई के दायरे में आता है।

भारत-फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास का समापन

जयपुर। भारत और फ्रांस का संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति बुधवार को बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में समाप्त हो गया। सैन्य प्रवक्ता कर्नल सोंबित घोष ने बताया कि 31 अक्टूबर से 13 नवम्बर तक आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का उद्देश्य आपसी - सहयोग एक दूसरे के सैन्य कार्यवाहियों के तौर तरीकों को जानकार कॉम्बेट ड्रिल, और इन परिस्थितियों में एक दूसरे के कार्यवाही की समझ बढ़ाना था। उन्होंने बताया कि इस संयुक्त अभ्यास के दौरान दोनों सेनाओं ने वैश्वि वातावरण पर आधारित आतंकवाद निरोधी अनुभवों को सांझा किया। समापन समारोह में फ्रांसीसी सेना की तरफ से ब्रिगेडियर जनरल जान क्रिस्टोफ बेचोन, डिप्टी हेड ऑफ मिशन तथा भारतीय सेना की तरफ से गांडीव डिवीज़न के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल इंदरजीत सिंह समीक्षा अधिकारी रहे।

अमरिंदर ने एसजीपीसी को अपने खजाने से 20 डॉलर सेवा शुल्क अदा करने कहा

एजेंसी। चंडीगढ़

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) से गुरुद्वारा दरबार साहिब की यात्रा के लिए पाकिस्तान द्वारा लिए जा रहे 20 डॉलर का सेवा शुल्क अपने खजाने से अदा करने को कहा है। अमरिंदर ने बुधवार को इसके लिए यह तर्क दिया कि करतारपुर गलियारा शुरू होने के बाद से बहुत कम संख्या में श्रद्धालु वहां जा पा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने गुरु नानक देव के 550 वें प्रकाश वर्ष को मनाने के लिए मंगलवार को सुल्तानपुर लोधी में कार्यक्रम आयोजित करने पर एसजीपीसी के अकूत खर्च करने का जिक्र करते हुए कहा कि यह दृष्टांत है कि धार्मिक संस्था (एसजीपीसी) के पास प्रचुर मात्रा में धन है।

कम संख्या में श्रद्धालुओं का गुरुद्वारा दरबार साहिब जाना रूचि में कमी के चलते नहीं है बल्कि दो शर्तों के चलते हैं-- पासपोर्ट और 20 डॉलर शुल्क, जिसे पड़ोसी देश ने लगाया है। करतारपुर गलियारा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नौ नवंबर को उद्घाटन किए जाने के बाद प्रथम तीन दिनों में महज 897 श्रद्धालु ही वहां (पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा) जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिखों के शीर्ष धार्मिक संगठन एवं प्रचुर मात्रा में नकदी रखने वाले एसजीपीसी को कम से कम पीला कार्ड धारकों का सेवा शुल्क वहन करना चाहिए। ऐसे श्रद्धालु हैं जो गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करते हैं और वे यह शुल्क वहन नहीं कर सकते।

श्रद्धालुओं के बीच भ्रम की स्थिति की खबरों के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने दोनों देशों, भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों से करतारपुर गलियारा के जरिए यात्रा के लिए पासपोर्ट की शर्त में छूट देने का भी अनुरोध किया। आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अन्य पहचान पत्रों को भी स्वीकार किया जाना चाहिए। एसजीपीसी को आड़े हाथ लेते हुए सिंह ने कहा कि अपने अहम को पूरा करने के लिए धन खर्च करने और इस धार्मिक मौके के मार्फत राजनीतिक हित साधने के बजाय उसे यह राशि श्रद्धालुओं की मदद के लिए खर्च करना चाहिए। एसजीपीसी और उनके राजनीतिक आका, शिरोमणि अकाली दल (शिअद) और खासतौर पर बादल परिवार समुदाय के वास्तविक हित के लिए धन क्यों नहीं खर्च करते।

करतारपुर साहिब यात्रा पंजीकरण प्रक्रिया सरल बनाने की मांग की

चंडीगढ़। करतारपुर गलियारा के रास्ते पाकिस्तान में गुरुद्वारा दरबार साहिब जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या बेहद कम रहने के बीच बुधवार को एसजीपीसी ने श्रद्धालुओं की कम संख्या के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि यह प्रक्रिया सरल होनी चाहिए। शीर्ष गुरुद्वारा निकाय ने सुझाव दिया कि प्रक्रिया को सरल बनाने के उपायों के हिस्से के रूप में आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए केंद्र उसे अधिकृत करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौ नवंबर को करतारपुर गलियारे का भव्य उद्घाटन किया था। उसके बाद पहले तीन दिनों में, करतारपुर गलियारे के जरिए सिर्फ 897 श्रद्धालु ही पाकिस्तान में करतारपुर साहिब गए।

न्यायमूर्ति मुहम्मद रफीक ने बुधवार को मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ ली। राज्यपाल तथागत राय ने यहाँ राज भवन में मुख्यमंत्री कोनराड संगमा, कैबिनेट मंत्रियों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में उन्हें शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति रफीक (59) ने न्यायमूर्ति अजय कुमार का स्थान ग्रहण किया है जो अब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाल रहे हैं। न्यायमूर्ति रफीक को 2008 में राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया था। वे मूलत: राजस्थान के निवासी हैं और उन्होंने 1984 में राजस्थान उच्च न्यायालय में कानून की प्रैक्टिस शुरू की थी।

मप्र सरकार ने करतारपुर साहिब गुरुद्वारा को किया मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना में शामिल

भोपाल। गुरुनानक देव के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर सिख समाज को तोहफ़ा देते हुए मध्य प्रदेश के कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस नीत सरकार ने बुधवार को पाकिस्तान के प्रसिद्ध करतारपुर साहिब गुरुद्वारा को महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना में शामिल कर लिया है। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने यहां बताया कि यह निर्णय हाल ही में बनाए गए मध्य प्रदेश के आध्यात्म विभाग ने लिया है और इसके आदेश भी आज जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश आध्यात्म विभाग के आदेश में कहा गया है, मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना में वर्तमान तीर्थस्थलों की सूची में पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब का नाम जोड़ा जाता है। मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार ने लागू किया था। इस योजना के तहत प्रदेश के 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों पर तीर्थ यात्रा के पात्र होते हैं और उनकी इस यात्रा पर होने वाले पूरे खर्च का वहन मध्य प्रदेश सरकार करती है। इस योजना में अब पाकिस्तान का धार्मिक स्थल करतारपुर साहिब भी शामिल किया गया है।

मप्र उच्च न्यायालय ने शहरी निकायों की सीमाओं में बदलाव की प्रक्रिया पर रोक लगाई

एजेंसी। इंदौर

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की नौ महीने पुरानी उस अधिसूचना के पालन पर रोक लगा दी है जिसके तहत संबंधित जिलाधिकारियों को अधिकार देते हुए कुछ क्षेत्रों को शहरी निकायों की सीमा में जोड़ने या घटाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। अदालत के इस आदेश को नगर पालिकाओं और नगर निगमों के आगामी चुनावों से पहले मिले प्रदेश सरकार को झटके के रूप में देखा जा रहा है।

उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति एससी शर्मा और न्यायमूर्ति शैलेंद्र शुक्ला की पीठ ने शहर के भाजपा पार्षद दिलीप शर्मा की याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राज्य सरकार की संबंधित अधिसूचना के पालन पर पांच नवम्बर को स्थगन आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने यह आदेश बुधवार को मीडिया के साथ साझा किया।

शर्मा के वकील पीयूष माथुर ने संवाददाताओं को बताया कि मामले में मध्यप्रदेश के नगरीय विकास और आवास विभाग की ओर से राजपत्र में 23 फरवरी को प्रकाशित अधिसूचना को मध्यप्रदेश नगर पालिक अधिनियम 1956 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत चुनौती दी गई थी। इस अधिसूचना के जरिए कुछ इलाकों को नगर पालिका क्षेत्रों में जोड़ने या घटाने के इरादे से जुड़ी सूचना के प्रारंभिक प्रकाशन के अधिकार संबंधित जिलाधिकारियों को दिए गए थे।

माथुर ने कहा, राज्य सरकार द्वारा यह अधिसूचना जारी किया जाना सरासर गलत था, क्योंकि कानूनी प्रावधानों के मुताबिक किसी क्षेत्र को शहरी सीमा में जोड़ने या घटाने को लेकर शुरूआती इरादा राजपत्र में जाहिर करने का अधिकार केवल राज्यपाल को है और राज्य सरकार राज्यपाल की सहमति के बिना शहरी सीमाओं में बदलाव की प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकती। उच्च न्यायालय ने इंदौर के जिलाधिकारी के उस आदेश के अमल पर भी रोक लगा दी है, जिसमें नगरीय विकास और आवास विभाग की जारी अधिसूचना की रोशनी में दो गांवों-बांक और नैनोद को मल्हारंगज तहसील के तहत इंदौर नगर निगम की सीमा में शामिल करने का इरादा जाहिर किया गया था। मामले में अगली सुनवाई के लिए दो दिसंबर की तारीख तय की गई है।

केंद्र ने अपने विभागों से सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों का पारदर्शिता लेखा-परीक्षण कराने के लिए कहा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अपने विभागों से कहा है कि वह कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुरूप सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण संस्थानों को उनकी वेबसाइट पर दी जाने वाली सूचनाओं के पारदर्शिता लेखा-परीक्षण की इजाजत दें। सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 की धारा 4 (2) के तहत जनता को स्वत: जानकारी देना अनिवार्य है, ताकि लोगों को जानकारी प्राप्त करने के लिए इस कानून का कम उपयोग करना पड़े। नियमों के मुताबिक प्रत्एक मंत्रालय या सार्वजनिक प्राधिकरण को सक्रिय रूप से दी जाने वाली सूचनाओं का साल में एक बार किसी तीसरे पक्ष द्वारा लेखा-परीक्षण करवाना अनिवार्य है। लेखा-परीक्षण के दौरान सक्रिय प्रकटीकरण दिशानिर्देशों के साथ-साथ पैकेज में शामिल बिंदुओं का अनुपालन करना चाहिए। इस दौरान यह भी जांचना होगा कि क्या कोई और ऐसी जानकारी है, जिसको प्रकट किया जा सकता है। लेखा-परीक्षण हर साल किया जाएगा और इस बारे में केंद्रीय सूचना आयोग को हर साल जानकारी दी जाएगी। मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है, इसके अलावा प्रत्एक मंत्रालया विभागा सार्वजनिक प्राधिकरण और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के तहत आने वाले संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों को पारदर्शिता ऑडिट करने का कार्य दिया जा सकता है।

भारत में 2018 में निमोनिया के कारण हर घंटे 14 से अधिक बच्चों की मौत हुई

एजेंसी। नई दिल्ली

भारत में 2018 में हर घंटे पांच साल से कम उम्र के 14 से अधिक बच्चों की मौत निमोनिया से हुई। यह जानकारी एक अध्ययन में सामने आई है। भारत उस वर्ष वैश्विक स्तर पर इस बीमारी के कारण होने वाली बच्चों की आधी से अधिक मौतों के लिए जिम्मेदार शीर्ष पांच देशों में से एक है। सेव द चिल्ड्रन , यूनीसेफ और एवरी बर्थ काउंट्स द्वारा किए गए अध्ययन- भारत में सांस लेने की लड़ाई - में कहा गया है कि निमोनिया से 2018 में पांच साल से कम आयु के 1,27,000 बच्चों की मौत हुई।

सेव द चिल्ड्रन के स्वास्थ्य एवं पोषण के उप निदेशक डा.राजेश खन्ना ने कहा कि भारत में, निमोनिया के कारण हर चार मिनट में पांच साल से कम आयु के एक बच्चे की मौत हो जाती है और इसके लिए कुपोषण और प्रदूषण दो प्रमुख कारक जिम्मेदार हैं। अध्ययन में कहा गया है कि निमोनिया के कारण आधे से अधिक मौतें पांच देशों नाइजीरिया (1,62,000), भारत (1,27,000), पाकिस्तान (58,000), कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (40,000) और इथोपिया (32,000) में हुई। उन्होंने कहा, निमोनिया के कारण आधे से अधिक बच्चों की मौतों से जुड़ा कारण कुपोषण है। इन मौतों के लिए 22 प्रतिशत भीतरी वायु प्रदूषण और 27 प्रतिशत बाहरी वायु प्रदूषण जिम्मेदार है। निमोनिया बच्चों की मौतों के लिए दुनिया की प्रमुख संक्रामक बीमारी बनकर सामने आया है जिससे हर साल पांच साल से कम आयु के आठ लाख से अधिक बच्चों की मौत हो जाती है। प्रतिदिन के हिसाब से यह संख्या दो हजार से अधिक है।

अध्ययन में कहा गया है, भारत में, 2017 में निमोनिया के कारण 14 प्रतिशत बच्चों की मौत हो गई। वर्ष 2018 में निमोनिया से पांच साल से कम आयु के।,27,000 से अधिक बच्चों की मौत हुई। अध्ययन में कहा गया है भारत में 2016 में सरकार ने 16 डॉलर प्रति व्यक्ति के हिसाब से स्वास्थ्य पर खर्च किए। यूनीसेफ के कार्यकारी निदेशक हेनेरीटा फोर ने कहा, निमोनिया के कारण प्रतिदिन, पांच साल से कम आयु के लगभग 2,200 बच्चों की मौत हो जाती है। इस बीमारी के खिलाफ लड़ने के लिए कड़ी वैश्विक प्रतिबद्धता और निवेश में वृद्धि करना महत्वपूर्ण है।

पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना जिले में बुलबुल चक्रवात से प्रभावित लोगों के परिजन को राहत कोष से चेक देते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी

चक्रवात बुलबुल से पश्चिम बंगाल को पचास हजार करोड़ रुपए का नुकसान : ममता

एजेंसी। बशीरहाट (पश्चिम बंगाल)

उत्तर 24 परगना जिले के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि प्राकृतिक आपदा से नुकसान का आंकड़ा पचास हजार करोड़ रुपए तक जा सकता है। बनर्जी ने आपदा में मारे गए जिले के पांच लोगों के परिजनों को 2.4-2.4 लाख रुपए के चेक प्रदान किए। बुलबुल चक्रवात के कारण कम से कम पंद्रह लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर फसल बर्बाद होने का संज्ञान लेते हुए बनर्जी ने कहा कि आपदा प्रभावित किसानों को राज्य सरकार सभी तरह की सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने यहां एक प्रशासनिक समीक्षा बैठक में कहा, जो कुछ भी मैंने देखा है उससे मुझे लगता है कि चक्रवात ने अत्यधिक तबाही मचाई है। अत्यधिक से मेरा मतलब वास्तव में बहुत अधिक है...[8230] कोलकाता और राज्य के अन्य स्थानों पर बैठे लोग तबाही का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे।... मुझे लगता है कि पचास हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।

ममता ने कहा कि जिन्होंने अपना नाम राज्य सरकार की फसल बीमा योजना में दर्ज कराया है उनके नुकसान की सौ प्रतिशत भरपाई की जाएगी। उन्होंने कहा, कुल 15 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि बर्बाद हुई है। धान की पूरी फसल तबाह हो गई है। मैं किसानों को सरकार की ओर से पूरी सहायता का आश्वासन देती हूं। राज्य फसल बीमा नीति के अंतर्गत आने वाले सभी किसानों की सौ प्रतिशत भरपाई की जाएगी।

तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही प्रभावित किसानों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करेगी। बनर्जी ने बैठक के दौरान बताया कि बुलबुल चक्रवात के कारण कम से कम नौ लोगों की जान गई है। मुख्यमंत्री के अनुसार इस चक्रवात से छह लाख लोग प्रभावित हुए और पांच लाख से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो गए। उन्होंने आश्वासन दिया कि क्षतिग्रस्त हुए घरों की मरम्मत राज्य सरकार की बंगलार बाड़ी योजना के अंतर्गत कराई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि चक्रवात से प्रभावित प्रत्एक परिवार को तूफान में भी जलने वाली लालटेन और पांच लीटर केरोसिन तेल उपलब्ध कराया जाएगा। बनर्जी ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि वह चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में बोर्ड की परीक्षा दे रहे स्कूली बच्चों को पुस्तकें उपलब्ध कराए।

आइएएस अकादमी में तीरंदाजी का कोर्स

देहरादून। मसूरी स्थित प्रतिष्ठित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में सिविल सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए पहली बार, आज से तीन दिन का तीरंदाजी कोर्स शुरू हुआ। सिविल सेवा के प्रशिक्षणार्थियों को एकाग्रता बनाने और भविष्य की जिम्मेदारियों के बारे में तैयार होने में मदद करने के मकसद से यह कोर्स शुरू किया गया है। तीन बार के राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियन और इस कोर्स का संचालन करने वाले दिनेश भील ने बताया कि यह पहली बार है जब आइएएस, आइपीएस और आइएफएस प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत अकादमी में तीरंदाजी का कोर्स चलाया जा रहा है। भील ने बताया कि प्रशिक्षणार्थियों को इस खेल की मूल बातें सिखाई जा रही हैं जिससे उन्हें बेहतर नतीजों के लिए धैर्य रखने और लक्ष्य पर ध्यान लगाने में सहायता मिले। गुजरात में स्पोर्ट्स अथारिटी आफ इंडिया के तीरंदाजी कोच भील ने कहा कि हांलांकि, तीरंदाजी की मूल बातें सीखने के लिए कम से कम छह माह की जरूरत है लेकिन केवल तीन दिनों की इस बहुत छोटी अवधि में भी प्रशिक्षुओं को यह सिखाया जाएगा कि चुनौतीपूर्ण स्थितियों में भी कैसे शांत रहा जा सकता है और बेहतर एकाग्रता और ध्यान लगाकर सर्वश्रेष्ठ नतीजे हासिल किए जा सकते हैं।

बढ़ रहा है मधुमेह : स्वस्थ रखने के लिए आने वाली पीढ़ी बदले अपनी आदतें

नई दिल्ली। डायबिटीज देश में तेजी से बढ़ने वाली बीमारियों में से एक है। एक शोध की मानें तो पिछले 25 बरस में इस बीमारी के मामलों में 64 प्रतिशत इजाफा हुआ है और विशेषज्ञ इस बढ़ोतरी को देश की आर्थिक प्रगति के साथ जोड़कर देख रहे हैं। इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि आने वाले छह बरसों में देश में इस बीमारी के मरीजों की संख्या 13.5 करोड़ से ज्यादा हो सकती है, जो वर्ष 2017 में 7.2 करोड़ थी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड एवेल्यूएशन और पब्लिक हैल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया की नवंबर 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 25 बरस में भारत में डायबिटीज के मामलों में 64 प्रतिशत का इजाफा हुआ। अब विश्व बैंक की एक रिपोर्ट पर नजर डालें तो 1990 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 24, 867 रुपए थी, जो 2016 में बढ़कर 1,09,000 हो गई। इसका सीधा अर्थ है कि खुशहाली बढ़ने के साथ साथ मधुमेह के रोगी भी बढ़ते जा रहे हैं।

शोध के अनुसार साल 2017 में दुनिया के कुल डायबिटीज रोगियों का 49 प्रतिशत हिस्सा भारत में था और 2025 में जब यह आंकड़ा 13.5 करोड़ पर पहुंचेगा तो देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर एक बड़ा बोझ होने के साथ ही आर्थिक रूप से भी एक बड़ी चुनौती पेश करेगा।

धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सीनियर कंसलटेंट, इंटरनल मेडिसिन, डॉ. गौरव जैन के अनुसार टाइप1 डायबिटीज में हमारा शरीर में इन्सुलिन बनना बंद हो जाती है और मरीज को मुख्यत: इन्सुलिन थैरेपी पर आश्रित होना पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज में शरीर में इन्सुलिन के इस्तेमाल कि प्रक्रिया बाधित होती है। यह टाइप 1 से कम घातक होती है और आम है। दवाएं खाकर बीमारी को नियंत्रित रखा जा सकता है।

श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टिट्यूट के सीनियर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, डॉ. साकेत कांत, ने एक सर्वे के हवाले से बताया कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले तकरीबन 30 फीसदी बच्चे मोटापे की गिरफ्त में हैं, बहुत से बच्चे प्री-डायबटिक हाइपरटेंशन के भी शिकार थे। यह आने वाली पीढ़ियों की सेहत की हालत की बड़ी चिंताजनक तस्वीर है। बच्चों की इस हालत के लिए बच्चों से ज्यादा उनके माता पिता जिम्मेदार है क्योंकि उनकी दिनचर्या और खानपान की आदतें बच्चों की भी बीमारी के मुहाने पर ले आई हैं। उनका मानना है कि बच्चों पर किसी भी तरह की कठोर पाबंदी लगाने या उन्हें हिदायतें देने की बजाय अभिभावक स्वयं स्वस्थ आदतें अपनाएं। जेपी अस्पताल, नोएडा में सीनियर कंसल्टेंट, डायबिटीज़ एंड एंडोक्रिनोलॉजी, डॉ. निधि मल्होत्रा का कहना है कि यदि परिवार में किसी को डायबिटीज है तो बाकी सभी सदस्यों को सावधान होना होगा। डायबिटीज होने पर इसकी दवा लेना जरूरी है। मीठे का सेवन कम करने, खानपान और दिनचर्या में बदलाव और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के साथ ही दवा भी लेनी होगी। अन्यथा यह बीमारी एक घुन की तरह सारे शरीर को खोखला करती रहती है और अगर इसपर पूरी सावधानी से नजर न रखी जाए तो किडनी की समस्याएं, हृदयरोग, त्वचा सम्बन्धी समस्याएं, आँखों की रौशनी का प्रभावित होना, सुनने में दिक्कत, पैरों की नसों पर प्रभाव और घाव जल्दी न भरने जैसी बहुत सी परेशानियां घेर सकती हैं।

डेंगू के बढ़ते मामलों के विरोध में भाजपा ने कोलकाता में निकाली रैली

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और इसके आस पास के क्षेत्र में डेंगू के तेजी से बढ़ते मामलों का विरोध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक रैली निकाली और राज्य सरकार पर आंकड़ों को छिपाने के प्रयास का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से शहर के सेंट्रल एवेन्यू से निकाले गए विरोध मार्च का समापन कोलकाता नगर निगम मुख्यालय पर होना था। इसका उद्देश्य निकाय मुख्यालय का घेराव था। रैली की अगुवाई करने वाले प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने संवाददाताओं को बताया, राज्य सरकार जानबूझ कर (मरने वालों और प्रभावितों के) आंकड़ों को छिपाने की कोशिश कर रही है। सरकार और केएमसी (कोलकाता नगर निगम) इस समस्या से निपटने की अपेक्षा आंकड़ों को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के पास बैरिकेड लगाया था। भगवा पार्टी ने कहा कि वह कोलकाता के महापौर फिरहाद हाकिम को डेंगू के प्रकोप को लेकर ज्ञापन सौंपना चाहती है और अगर रोका गया तो हम वहीं धरना शुरू कर देंगे। राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कोलकाता और इसके आस-पास के इलाकों में कुल 44 हजार 852 डेंगू के मामले दर्ज किए गए हैं। सरकारी अधिकारियों के अनुसार डेंगू के कारण जनवरी से अबतक 25 लोगों की मौत हो चुकी है।

कोलकाता में नगर निगम कार्यालय के सामने डेंगू के प्रकोप के विरोध में प्रदर्शन करते हुए भाजपा कार्यकर्ता

महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन

संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को धक्का

महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होने से स्पष्ट हो जाता है कि यहां जनता के वैध चुनावी फैसले व नैतिकता को राजनीतिक लालच पर कुर्बान कर दिया गया है। राज्यों में फैसला चाहे जो भी हुआ हो, पर कोई केन्द्रवादी पार्टी अपने अंतर्गत पदों का उपयोग करते हुए उसे अपने पक्ष में निश्चिय ही बदल सकती है। कांग्रेस व उसकी गठबंधन सरकारें पूर्व में ऐसा ही करती रही हैं। हालांकि, भाजपा-शिवसेना के चुनाव-पूर्व गठबंधन को जनादेश मिला था, पर भाजपा अपने घमंड में सहयोगी शिवसेना को समान दर्जा नहीं देना चाहती थी जिससे वह वैकल्पिक गठबंधन तलाशने पर मजबूर हुई। वह विपक्षी कांग्रेस-रांकापा गठबंधन के साथ रास्ता तलाश रही है। लेकिन कांग्रेस और रांकापा स्थानीय विधायकों के बजाय अपनी राष्ट्रीय छवि पर ध्यान दे रहे हैं। इससे पूरे देश में एक पार्टी के प्रभुत्व की इच्छा रखने वाली भाजपा प्रसन्न है। इसलिए उसने राज्यपाल के पद का प्रयोग लोकतांत्रिक संघीय ढांचे में परिवर्तन हेतु किया। राज्यपाल ने भाजपा को काफी समय दिया और उससे सदन में परीक्षण की बात भी नहीं की, जबकि राज्यपाल को संसदीय लोकतंत्र की भावना से ऐसा करना चाहिए था। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भले ही तकनीकी रूप से उचित किया हो, पर उन्होंने विपक्षी पार्टियों को समुचित समय नहीं दिया तथा शिवसेना को समर्थन पत्र प्राप्त होने का मौका तक नहीं दिया। हालांकि, भाजपा-शिवसेना के पक्ष में निर्णायक जनादेश के बाद उनमें से किसी को व्यक्तिगत रूप से ऐसा करने का अधिकार नहीं था। लेकिन शिवसेना को सबूत पेश करने के लिए 48

घंटे मिले, जबकि रांकापा को केवल 24 घंटे। राज्यपाल ने यह समयसीमा समाप्त होने से पहले ही राष्ट्रपति शासन की संस्तुति कर दी। संवैधानिक रूप से राज्यपाल को बोम्मई बनाम भारतीय संघ, 1994 मामले में दिए फैसले के अनुसार सदन में शक्ति परीक्षण कराना चाहिए था, 'मंत्रिमंडल की शक्ति का आंकलन निजी या किसी व्यक्ति की राय नहीं है, चाहे वह राज्यपाल हो या राष्ट्रपति।' आशंका है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन भाजपा शासन का विस्तार होगा, चाहे उसके शिखर पर फडनवीस हो या नहीं।

राज्यों में नवीनतम उदाहरणों को देखने से स्पष्ट है कि अकेली सबसे बड़ी पार्टी न होने के बावजूद भाजपा सत्ता में आई है, चाहे इसके पीछे चुनाव-पश्चात गठबंधन बनाना हो या विपक्षी पार्टियों को तोड़ना या दावेदारों को अपने साथ ले आना। गोवा, मणिपुर व मेघालय में कांग्रेस अकेली सबसे बड़ी पार्टी थी। मार्च, 2016 में कांग्रेस विद्रोहियों व भाजपा विधायकों ने हरीश रावत सरकार को चुनौती दी थी, पर विद्रोही विधायकों को अयोग्य ठहराया गया। राज्यपाल ने मोदी सरकार से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी, पर उत्तराखंड न्यायालय ने इसे खारिज कर हरीश रावत को सदन में बहुमत सिद्ध करने का अवसर दिया। विकृतियों के इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि जब गठबंधन की भावना समाप्त करने की योजना बनाई जाती है और क्षेत्रीय पार्टियों को मुहरे की तरह प्रयोग किया जाता है तो मतदाता अगले चुनाव में अपनी राय बदल देते हैं। महाराष्ट्र में किसान आत्महत्याओं की स्थिति गंभीर है तथा पिछले चार सालों में 12,000 से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं। देश की सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था मंदी की शिकार है, रियल इस्टेट क्षेत्र ध्वस्त हो गया है, कृषि संकट है तथा विनिर्माण में नौकरियों की कमी है। वास्तव में मराठी गौरव की बात इन समस्याओं से ध्यान बंटाने की चाल है। लेकिन राज्य के विभिन्न पक्षों को अनदेखा कर ऊपर से अधिकार थोपने से इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा।

सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय

अयोध्या में लंबे समय से विवादित स्थल पर सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेखनीय निर्णय ऐतिहासिक प्रमाणों पर आधारित है। इससे भारत में सभ्यतामूलक विमर्श को लाभ होगा।

संध्या जैन
लेखिका नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय में वरिष्ठ फेलो हैं)

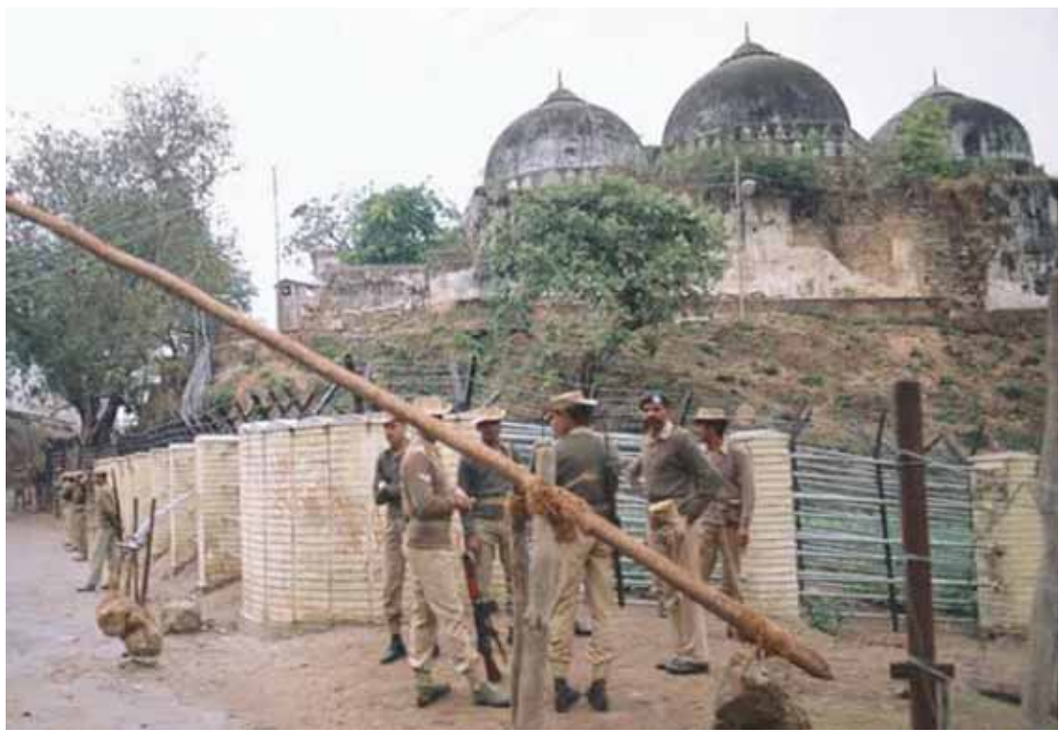

सर्वोच्च न्यायालय में पांच न्यायाधीशों की पीठ के एक विद्वान न्यायाधीश ने श्रीराम जन्मस्थान के बारे में प्रमाणों को सतर्कता से एकत्र किया। 9 नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में इसके आधार पर विवादित स्थल पर रामलला विराजमान का अधिकार स्वीकार किया है। विश्व हिंदू परिषद के 116 पेज के संलग्नक में हर प्रमाण एकत्र कर भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम के जन्मस्थान को विधिक रूप से स्थापित किया गया है। ये प्रमाण अकाट्य हैं। फैसले को एक समुदाय का पक्षधर बताने वाले आलोचकों ने 1,045 पेज का दस्तावेज नहीं पढ़ा है।

यह विवाद अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर नष्ट कर बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा बनवाई मस्जिद पर केन्द्रित था। ऐसे में 1528 से पहले पवित्र मंदिर संबंधी प्रमाण महत्वपूर्ण हैं। गुरु नानक देव की जन्म साखियों या जीवनी से स्पष्ट है कि वे भारत में बाबर के हमले के पश्चात 1510-1511 ईस्वी में अयोध्या आए थे। गुरु तेग बहादुर व उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह भी अयोध्या मंदिर में आए थे। हालांकि, जन्म साखियों में जन्मभूमि का सही स्थान नहीं बताया गया है, पर गुरु नानक की यात्रा से स्पष्ट है कि मंदिर नष्ट करने के पहले तीर्थयात्री अयोध्या आते थे। इस प्रकार भगवान राम के जन्मस्थान के प्रति हिंदुओं के विश्वास को पुरालेखों व पवित्र पुस्तकों में बताया गया है जो आधारहीन नहीं हैं। इनमें वाल्मीकि रामायण व स्कंद पुराण शामिल हैं।

सम्राट अकबर के शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरित मानस की रचना की थी। इसके बालकांड में वर्णित है कि ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों व धरती की रावण के अत्याचारों से रक्षा की प्रार्थना की थी। भगवान विष्णु ने वादा किया था, 'ऋषि, सिद्ध व इंद्र भयभीत न हों। आपकी रक्षा के लिए मैं मानव रूप में अवतार लूंगा। गौरवशाली सूर्य वंश में मैं अपने अंशावतार के रूप में प्रकट होऊंगा।' भगवान विष्णु ने ऋषि कश्यप व उनकी पत्नी अदिति को अयोध्या में दशरथ व कौशल्या के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। भगवान विष्णु ने चार भाइयों के रूप में जन्म लिया जो 'रघु वंश के गौरव' थे।

अकबर की जीवनी आईने-अकबरी में अयोध्या का उल्लेख भगवान रामचंद्र के जन्मस्थान व धरती पर एक पवित्रतम स्थल के रूप में किया गया है। 1607 से 1611 ईस्वी तक भारत की यात्रा करने वाले विलियम फिंच ने भगवान राम के महल के भग्न अवशेषों का उल्लेख किया है।

फादर जोसेफ टिफिनथेलर ने 1766 व 1771 ईस्वी में भारत की यात्रा की थी। उन्होंने अवध में मिट्टी के एक टीले पर प्रख्यात सीता रसोई का वर्णन किया है। सम्राट औरंगजेब ने रामकोट नामक महल को नष्ट कर उसके स्थान पर तीन बुर्जों वाली एक मुस्लिम मस्जिद का निर्माण कराया था। टिफिनथैलर ने बताया कि कुछ लोग इसे बाबर द्वारा बनवाई मस्जिद कहते थे। इसमें महल से उखाड़े गए 14 काले पत्थर के स्तंभ लगे थे जिनमें से 12 मस्जिद की महराबों को सहारा देते थे। उन्होंने बताया है कि यहां राम की वेदी थी। औरंगजेब या बाबर ने मंदिर नष्ट करवाया ताकि 'राजपरिवार के लोगों को उनके धार्मिक कर्मकांडों से वंचित किया जा सके।' लेकिन जनता यहां 'तीन बार परिक्रमा कर धरती पर दण्डवत प्रणाम करती है।' यह स्पष्ट प्रमाण है कि टिफिनथेलर के समय में हिंदू एक देवता के रूप में जन्मस्थान की पूजा करते थे। वाल्टर हैमिल्टन के ईस्ट इंडिया गजेटियर, 1828 में लिखा है कि मुख्यत: रमता पंथ अवध की

यह विवाद अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर नष्ट कर बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा बनवाई मस्जिद पर केन्द्रित था। ऐसे में 1528 से पहले पवित्र मंदिर संबंधी प्रमाण महत्वपूर्ण हैं। गुरु नानक देव की जन्म साखियों या जीवनी से स्पष्ट है कि वे भारत में बाबर के हमले के पश्चात 1510-1511 ईस्वी में अयोध्या आए थे।

यात्रा करता था। 1838 में प्रकाशित मांटगुमरी मार्टिन की 'हिस्ट्री, एंटीक्विटीज़, टोपोग्राफी एंड स्टेटिस्टिक्स आफ ईस्टर्न इंडिया' में अयोध्या की महिमा बताई गई है। एडवर्ड थार्नटन के गजेटियर आफ इंडिया, 1854 तथा गजेटियर आफ द टेरीटरीज़ आफ द नेटिव स्टेट्स आन द कांटीनेंट आफ इंडिया, 1858 में अवध का विस्तृत विवरण है।

मिर्जा जान की हदीथे-सहबा, 1856 के अनुसार, 'उपरोक्त स्थान भगवान राम के पिता का स्थान था। यहां स्थित बुतपरस्ती स्थल, यानी मंदिर को नष्ट किया गया। इस पूजा स्थल को भगवान राम का जन्मस्थान कहा गया था। यह स्थल सीता की रसोई नामक स्थल से सटा है। इस स्थान पर बाबर शाह ने सैय्यद मूसा आशिकन की निगरानी में 923 हिजरी में एक बहुत बड़ी मस्जिद बनवाई जिसका इतिहास दर्ज किया गया है। आज उपरोक्त सीता की रसोई को मस्जिद कहा जाता है।' विद्वान न्यायाधीश ने कहा, 'यह पुस्तक स्पष्ट रूप से स्वीकार करती है कि भगवान राम के जन्मस्थल पर बाबर ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया था।'

1858 में ब्रिटिश सरकार ने अवध को अधिग्रहीत कर लिया। इसके बाद आधिकारिक रिपोर्टों, पत्र व्यवहार व आदेशों में 'मस्जिद' को 'मस्जिद जन्मस्थान' कहा गया। जिला फैजाबाद में तहसील फैजाबाद के आधिकारिक कमिश्नर व अयोध्या तथा फैजाबाद के बंदोबस्त अधिकारी पी. कार्नेगी ने 1870 में कहा कि हिंदुओं के लिए अयोध्या का वही स्थान था जो मुसलमानों के लिए मक्का तथा यहूदियों के लिए येरूशलेम का था। कार्नेगी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जन्मस्थान पर सम्राट बाबर ने 1528 ईस्वी में एक मस्जिद बनवाई जिसे अब भी उसके नाम से जाना जाता है। इन तथ्यों को बाद में कई अन्य गजेटियरों में दुहराया गया।

उत्तर पश्चिमी प्रांतों व अवध पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट, 1889 में कहा गया है, 'जन्मस्थान पर भगवान रामचंद्र का पुराना मंदिर बहुत शानदार रहा होगा, जिसके अनेक स्तंभों का प्रयोग मुसलमानों ने बाबर की मस्जिद के निर्माण में किया।' एएसआई में अलोइस अंटोन फूहरर की रिपोर्ट, 1889, जौनपुर की शरकी वास्तुकला, जफराबाद की टिप्पणियों, सहेत-महेत व उत्तर-पश्चिमी प्रांतों तथा अवध के अन्य स्थानों पर उल्लेख मिलता है कि अयोध्या में बाबर की मस्जिद उसी स्थान पर बनाई गई थी जहां भगवान राम का पुराना जन्मस्थान मंदिर था। फूहरर ने 'मान्यूमेंटल एंटीक्विटीज़ एंड इन्सिक्रिप्शन्स इन द नार्थ वेस्टर्न प्राविंसेज़ एंड अवध', 1891 तथा प्रोफेसर बी.बी. लाल ने एएसआई द्वारा बाद में कराए उत्खननों में इसका उल्लेख किया है। बाराबंकी गजेटियर खंड 48, 1921 में उल्लेख है कि 1853 में बैरागियों ने जन्मस्थान मंदिर की भूमि पर कब्जा कर लिया था जिससे अमीर अली के नेतृत्व मुस्लिमों ने अयोध्या की तरफ कूच किया। उनको कर्नल बार्लो के नेतृत्व में अवध की पहली रेजीमेंट ने रोका। इस लड़ाई में रेजीमेंट का सफाया हो गया तथा अमीर अली व अनेक अन्य मारे गए।

30 नवंबर, 1858 को बाबरी मस्जिद के मुअज्जिम सैय्यद मुहम्मद खातिब ने शिकायत की कि निहंग सिंह ने मिट्टी का एक चबूतरा मस्जिद के भीतर बना दिया, उस पर 'राम राम' लिखा तथा वहां हवन कर रहे हैं। मस्जिद के अधिकारियों ने यह चबूतरा हटाने की बार-बार प्रार्थना की। 1866 में बैरागियों ने मस्जिद के भीतर मूर्तियां रख दीं। 1877 में अयोध्या के डिप्टी कमिश्नर ने जन्मस्थान के महंत खेम दास को मस्जिद की उत्तरी दीवाल में एक दरवाजा खोलने की अनुमति दी ताकि हिंदुओं को वहां आने के लिए अलग रास्ता मिल सके। 1934 में दंगे के कारण मस्जिद का एक बुर्ज गिर गया था जिसकी मरम्मत प्रशासन ने करवाई।

इन विवरणों से स्पष्ट है कि हिंदुओं ने लगातार इस स्थल पर आने और पूजा करने के लिए संघर्ष किया। इसलिए सुन्नी वक्फ बोर्ड इस पर अपने आधिपत्य का अधिकार सिद्ध नहीं कर सका। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान फैसला ऐतिहासिक प्रमाणों पर आधारित है और भारतीय सभ्यता को इससे लाभ होगा।

योग्यता आधारित नौकरशाही की आवश्यकता

देबाशीष भट्टाचार्य
(लेखक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं)

प्रशासनिक प्रणाली में, नौकरशाही प्रमुख भूमिका निभाती है क्योंकि सिविल सेवक अथवा बाबू लोग निर्वाचित सरकार की नीतियों को तर्कसंगत, दक्षतापूर्ण एवं पक्षपात-रहित तरीके से क्रियान्वित करने का दायित्व निभाते हैं। हालांकि, लोगों को प्राय: अनुभव हुए हैं कि जब मामला क्रियान्वयन का आता है, तो निष्पादन असंतोषजनक होता है जो खराब जनसेवा और लगभग सेवाएं मुहैया न हो पाने के रूप में सामने आता है। और, इसके बहुत से कारकों में से एक है नेताओं, नौकरशाहों एवं अन्य निहित स्वार्थों के बीच का गठजोड़। इस पर विश्वास करने के बाध्यकारी कारण हैं। और, आश्चर्य है कि भारी कीमत चुकानी पड़ती है। जबकि बहुत से लोग महसूस करते हैं कि नौकरशाही पहलकदमियों को बाधित करती है, जोखिम लेने की क्षमता को क्षीण करती है और सृजनात्मकता का दमन करती है, अन्य लोगों को लगता है कि हमारे वृहद और विविधतापूर्ण देश में नौकरशाही अपरिहार्य है। लोगों का एक और समूह यह मानता है कि नौकरशाही में औपनिवेशिक विरासत का प्रभाव एक अत्यंत हताशापूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करता है, क्योंकि भारत जैसे कल्याणकारी राज्य के समक्ष विद्यमान सामाजिक व आर्थिक चुनौतियों से निबटने में असमर्थ है।

हालांकि, यह बात सही है, महारानी एलिजाबेथ-1 के हवाले से। लॉर्ड विलियम सेसिल को अपना सचिव बनाने के बाद, एलिजाबेथ ने उन्हें सलाह दी, ''मेरा आपके बारे में निष्कर्ष है कि आप उपहारों के तरीकों से भ्रष्ट नहीं होंगे और आप राज्य के प्रति वफादार रहेंगे तथा, मेरी निजी इच्छा का सम्मान किए बगैर, आप मुझे वही परामर्श देंगे जो आपको श्रेष्ठ लगता हो।'' यद्यपि सरकार द्वारा निर्धारित नीतियां, परियोजनाएं एवं कार्यक्रमों का ध्येय देश का विकास तथा जनता का कल्याण होता है, उत्तरोत्तर सरकारें इस तथ्य को सिद्ध करने में विफल रही हैं कि नेतृत्व बदल सकते हैं, लेकिन प्रशासन का इंजन सरकार में आने वाले किसी नए चालक के कारण दिशाभ्रमित नहीं होता जिसके पास सापेक्षत: सुप्रसिद्ध नौकरशाही होती है। हालांकि, अत्यधिक काम की अपेक्षा करने वाली राजनीतिक प्रणालियों में यह कम दिखावा होता है कि देश की नौकरशाहियां जनहित से गहराई से प्रभावित हैं। सैद्धांतिक एवं रीढ़विहीन, दोनों प्रकार के सिसिल सेवक व्यवस्था में विद्यमान हैं। एक देश को सेवा प्रदान करता है तो दूसरा राजनीतिकों एवं स्वयं के प्रतिबद्ध रहता है। इस प्रकार नौकरशाही का एक तबका राजनीतिक मशीन के पुर्जे की भांति काम करता हुआ नजर आता है जो सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए हुकूमत के प्रति वफादारी दर्शाता है और अपनी पहचान पूर्णत: शासकों एवं आधिकारिक वैचारिकता से जोड़ता है।

संयोग से, अशोक खेमका जैसे अधिकारियों की संख्या ज्यादा नहीं होती (जिनके 27 वर्ष की नौकरी के दौरान 50 बार तबादले किए गए और अभी भी जारी हैं) जिनके पास लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति झुकाव रखने के लिए प्रच्छन्न एजेंडे, खराब नीतियों, भ्रष्टाचार एवं उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होने का साहस होता है। मगर भिन्न रूप से, ऐसे सिसिल सेवक भी होते हैं जो आतमविश्वास, दक्षता, साहस एवं प्रतिबद्धता के साथ चलने की इच्छा तो रखते हैं मगर अपने दायित्व निभाने के कारण भीषण दबाव झेलते हैं। पुनरावलोकन प्राधिकरण द्वारा 9.92/10 की ग्रेडिंग पाने वाले अशोक खेमका के बारे में पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में टिप्पणी की थी जिसपर गौर करना समीचीन होगा : ''हमारे विचार से ऐसे पेशेवर सत्यनिष्ठा वाले व्यक्ति को संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता है क्योंकि हमारी राजनीतिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक प्रणाली में सत्यनिष्ठा व ईमानदारी का क्षरण तेज गति से हो रहा है...।''

ऐसा कहकर, मुझे एक सेवानिवृत्त कर्तव्यनिष्ठ आईएएस अधिकारी एवं लेखक व स्तम्भकार का एक बयान याद आता है जिनसे मेरी मुलाकात भारत अंतरराष्ट्रीय केंद्र में हुई थी। क्योंकि मैंने उन्हें एक शक्तिशाली केंद्रीय मंत्री के खिलाफ साहसपूर्ण लेख लिखने पर बधाई दी थी। मैंने उन्हें एक सलाह भी दी कि यदि वो ऐसे लेख लिखना जारी रखते हैं, तो वो राज्यपाल अथवा सरकार द्वारा गठित किसी समिति के अध्यक्ष बनने की इच्छा नहीं रख सकते। और जवाब में उन्होंने कहा, ''मैं उन नौकरशाहों में से नहीं हूं जो अनैतिक नेताओं व मंत्रियों के भरोसे का आनंद उठाते हैं। मुझे दरकिनार किया गया, और राजनीतिक रूप से सहज न होने के कारण बार-बार तबादला कर दिया जाता था। मगर मैं कभी लोभ का शिकार नहीं हुआ।''

हालांकि, कुछ ही दिनों बाद, एक समूह चर्चा के दौरान बोलते हुए, दिल्ली सरकार के पूर्व मुख्य सचिव शैलजा चंद्रा ने कहा, ''यह कहना आसान है कि नेताओं ने आईएएस अधिकारियों को विफल कर दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि यह पूरी तरह सही नहीं है। जो सेवा में है उन्हें आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। यदि उनके अन्यथा स्वार्थ नहीं है, तो कोई भी उन्हें जनता की सेवा करने से नहीं रोक सकता।''

अभी तक, सरकारी एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं की कमजोर जवाबदेही, ने भारत में लोक प्रयासन के चरित्र को परिभाषित किया है। आगे चुनौती बाधाकारी एवं ढुलमुल नौकरशाही अथवा ग्राहकवाद के आगे घुटने टेके बगैर नागरिकों की सेवा करने के साथ-साथ विधि के शासन को अक्षुण्ण रखने की है। इसके बावजूद, लालफीताशाही, कागजी खानापूरी एवं अतिशय नौकरशाही प्रवृत्ति को लेकर शिकायतें होती हैं मगर तथ्य यह है कि अंतत: जनता देश को स्वरूप देने के लिए इस पर भरोसा करती है। राजग सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में, भारतीय सिविल सेवाओं में कुछ विशेषज्ञों के पार्श्व प्रवेश तथा कुछ अधिकारियों के जबरन सेवानिवृत्ति से पहल प्रारम्भ की है। लेकिन, उसके सामने असंख्य सामाजिक व राजनीतिक चुनौतियां हैं। इनसे प्रभावी रूप से निबटने के लिए सक्षम नौकरशाही और इसके लिए केंद्र के स्तर पर समुचित विचार विमर्श व कार्रवाई जरूरी है।

देश की व्यापक प्रशासनिक मशीनरी को दुरुस्त करने का एकमात्र रास्ता उसके कामकाज में सुधार लाना है। भारतीय सोच तथा देश के कानूनों को सक्षम नौकरशाही द्वारा प्रयोग में लाना चाहिए। यह विधि निर्माताओं व खासकर मंत्रियों पर निर्भर है कि वे देश को आगे ले जाना सुनिश्चित करें क्योंकि नौकरशाही उनके प्रति जवाबदेह है। समय आ गया है कि नौकरशाही को संरक्षण आधारित के बजाए योग्यता आधारित बनाया जाए तथा उसकी प्रगति तेज की जाए।

आप की बात

आज की कथित सभ्य दुनिया

मैं जरा देर से इस दुनिया में पहुंचा तब तक पूरी दुनिया सभ्य हो चुकी थी ,सारे जंगल काटे जा चुके थे ,सारे जानवर मारे जा चुके थे, दोनों तरफ लोहे और कंक्रीट के जंगल उग आए थे, जिनमें दिखाई दे रहे थे ,अत्यंत विकसित तरीकों से आदमी का शिकार करते आदमी : दार्शनिक कवि डॉ. कुंवर नारायण। अमेरिका द्वारा ही पोषित बगदादी को स्वयं अमेरिका द्वारा ही बहुत ही सहजता से मारे जाने वाली घटना को उक्त यथार्थपरक कविता से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। हकीकत में आज की सभ्य दुनिया में धन व ऐश्वर्य के लालच और हवश में खुद एक सामान्य मानव का कोई महत्व रह ही नहीं गया है, तभी तो अमेरिका द्वारा पैदा किए तालिबान नामक जिन्न के दो बेटे अलकायदा और बाद में आईएसआईएस नामक जिन्न पैदा हुए और वे सार्वजनिक रूप से सैकड़ों-हजारों आदमियों का कई वर्षों तक शिकार करते रहे, और उस नृशंसता का वीडिओ बना-बनाकर दुनिया के सभ्य लोगों को दिखाते रहे। इस परिप्रेक्ष्य में ईरान के एक मंत्री का यह कथन सर्वथा उचित प्रतीत होता है कि जब उस कथित दुर्दांत आतंकी को मारने लिए एक कुत्ता ही काफी था ,तो इतने लम्बे समय तक उसे इतने आदमियों के शिकार करने की मुहलत ही क्यों दी गई?

– **निर्मल के शर्मा,** गाजियाबाद

राजनीति में सब जायज़ है!

राजनीति में संभावनाओं की सीमा नहीं है अर्थात राजनीति में असंभव लगने वाली घटनाएं भी कभी-कभी घटित हो सकती हैं। क्या कभी आपने सोचा था बिहार में लालू यादव नीतीश कुमार एक हो सकते हैं ? इसके साथ ही शायद उत्तर प्रदेश की जनता ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि सपा और बसपा एक साथ चुनाव लड़ेंगे? मायावती और मुलायम सिंह को एक ही मंच साझा करते हुए देखा जाएगा पर यहां सब हकीकत में तब्दील हुआ। इसी कड़ी में ताजा मामला महाराष्ट्र का है एनडीए का घटक दल शिवसेना आज भाजपा को छोड़ अपने धुर विरोधी रही राकांपा और कांग्रेस के साथ सरकार बनाने की तैयारी में है। आम जनता के लिए यह एक अचंभित करने वाली बात है पर एक प्रसिद्ध कहावत है कि राजनीति में मुर्दे कभी दफनाए नहीं जाते। महाराष्ट्र चुनाव में सबसे ज्यादा 105 सीटें लाने के बावजूद भी भाजपा सत्ता पर काबिज नहीं हो पाएगी क्योंकि उनका सहयोगी दल शिवसेना अपना मुख्यमंत्री चाहता हैं जो भाजपा को नामंजूर था। आखिर तक कयास लगाए जाते रहे पर शायद लगता है कि इस बार शिवसेना ने दृढ़ संकल्प कर लिया था।

– **अभिनव दीक्षित**, बांगरमऊ

परिपक्वता का प्रदर्शन

दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत जटिल तर्कों के बाद केवल एक सु-विचारित एवं व्यापक फैसला ही दोनों पक्षों को संतुष्ट कर सकता था। हालांकि, शनिवार को आए फैसले का व्यापक स्वागत हुआ है, पर संकेत है कि इससे सभी संतुष्ट नहीं हैं। सौभाग्य से दोनों धर्मों के सर्वाधिक जिम्मेदार संगठनों ने अत्यन्त संतुलित प्रतिक्रिया दी है और उनके अनुयायी किसी उकसावे में नहीं आए हैं। सरकार द्वारा पहले से ही उठाए कठोर कदमों से दुष्ट तत्वों की नकारात्मक भूमिका पर लगाम लगी है। इससे वे लोग खामोश रहने पर मजबूर हुए हैं जो दंगे करवा कर भारत की एकता व अखंडता को चोट पहुंचाना चाहते थे। अयोध्या के लोग भी इस राजनीतिक टकराव से ऊब चुके हैं और अब वे यह मामला समाप्त करना चाहते हैं। विवाद की छाया में पली-बढ़ी हिंदू व मुस्लिम नौजवान पीढ़ी के दिमाग में शिक्षा और रोजगार की समस्यायें हैं। अयोध्या का फैसला भारत की सहिष्णुता व सामाजिक-धार्मिक विविधता को प्रकट करता है। जनता ने भी प्रशंसनीय सकारात्मक रुख दिखाया है।

– **सौमित्र वशिष्ठ**, प्रयागराज

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते है।

फरमाया

कांग्रेस नेतृत्व हमेशा पार्टी को देश के पहले रखता है। अब वे प्लेट पर रख कर महाराष्ट्र भाजपा को सौंप रहे हैं।

– **प्रीती शर्मा**
आप नेता

भारत और चीन उदाहरण हैं कि स्वतंत्र व गुलाम सरकारों द्वारा पैदा खतरों में क्या अंतर होता है।

– **निक्की हेली**
संरा. में पूर्व अमेरिकी राजदूत

महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की संस्तुति कर राज्यपाल कोश्यारी ने लोकतंत्र और संवैधानिक प्रक्रिया का मजाक उड़ाया है।

– **रणदीप सुरजेवाला**
कांग्रेस प्रवक्ता

समस्याओं के समाधान को लेकर काम कर रही भाजपा

शिक्षक एमएलसी उमेश द्विवेदी बीजेपी में शामिल

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

बीजेपी में बुधवार को शिक्षक, एमएलसी व माध्यमिक शिक्षक महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डा उमेश द्विवेदी तथा वित्त विहीन शिक्षक महासभा के प्रदेश महासचिव अजय सिंह ने बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह तथा उपमुख्यमंत्री डा दिनेश शर्मा ने सभी को भाजपा परिवार में शामिल करते हुए अभिनंदन किया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जेपीएस राठौर, प्रदेश महामंत्री गोविन्द नारायण शुक्ला, प्रदेश मंत्री अमर पाल मौर्य तथा प्रदेश सरकार के मंत्री राजेन्द्र प्रताप मोती सिंह उपस्थित रहे।

स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि भाजपा के लिए राजनीति एक मिशन है। देश के आजादी के लिए कुर्बानी देने वाले लाखों-करोड़ों देश भक्तों के सपनों को साकार करने के लिए भाजपा निरंतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जो संकल्प हमारे पूर्वजों ने लिया उस संकल्प को पूरा करने के लिए पार्टी अनवरत रूप से जन-जन के जीवन स्तर को सुधारने के काम में लगी है। भाजपा समस्याओं के समाधान का संकल्प लेकर काम कर रही है। सिंह ने कहा कि मोदी-योगी सरकार द्वारा लोककल्याण के लिए किये जा रहे कार्यों और योजनाओं के माध्यम से आमजन को मिल रही सुविधाओं से आम जनमानस का विश्वास भाजपा और उसके नेतृत्व के प्रति और अधिक बढ़ा है। दिनेश शर्मा ने कहा कि वित्तविहीन शिक्षकों के बड़े समूह ने पार्टी को ज्वॉइन किया है। आप सभी के भाजपा के साथ जुड़ने से स्थानीय निकाय के साथ शिक्षक व स्नातक क्षेत्र के विधान परिषद चुनावों में बड़ा परिवर्तन आयेगा। भाजपा सभी चुनावों को पूरी ताकत से लड़ेगी और जीत का परचम लहरायेगी।

सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों की पहचान कर करें कार्रवाई: डीजीपी

● पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग कर की कानून व्यवस्था की समीक्षा

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

डीजीपी ओपी सिंह ने निर्देश दिए हैं कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट के जरिए सामाजिक सौहार्द भंग करने की चेष्टा करने वालों की शिनाख्त कर वैधानिक कार्रवाई की जाए। उन्होंने पुलिस अफसरों को अयोध्या प्रकरण को लेकर सोशल मीडिया की मानीटरिंग के दौरान दर्ज हुई एफआईआर की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए राज्य की कानून-व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। वीडियो कांफ्रेंसिंग में सभी जोनल एडीजी, आईजी, रेंज के आईजी, डीआईजी और जिलों के पुलिस कप्तान शामिल रहे। डीजीपी ने सभी जिलों के संभ्रान्त नागरिकों जिनके द्वारा अयोध्या प्रकरण में स्थानीय पुलिस का सहयोग किया गया है, की प्रशंसा करते हुए सभी को निर्देशित किया कि ऐसे संभ्रान्त नागरिकों को थाना स्तर पर उनको साभार सक्रिय बनाए रखा जाए। सोशल मीडिया सेल एवं डिजीटल वालंटियर्स द्वारा बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया गया है, उनसे अपेक्षा है कि वह आगे भी निरन्तर ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी-वीडियो आदि के माध्यम से सामाजिक सौहार्द को भंग करने की चेष्टा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अज्ञात में दर्ज एफ आईआर की समीक्षा करते हुए तत्काल ऐसे असमाजिक तत्वों की शिनाख्त कर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए। डीजीपी ने निर्देश दिए कि समस्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा निरन्तर समय-समय पर पैदल गश्त की कार्रवाई प्रचलित रहेगी तथा पैदल गश्त के दौरान संदिग्ध वाहनों-व्यक्तियों की चेकिंग की कार्रवाई भी की जाए। इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, अपर पुलिस महानिदेशक रेलवेज, अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं, अपर पुलिस महानिदेशक एटीएस, पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था आदि पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।

नकारात्मकता का चश्मा उतारें अखिलेश

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ने कहा कि अपने शासन में प्रदेश को गर्त में धकेलकर जनता का जीवन नर्क बनाने वाले सपा मुखिया अखिलेश यादव नकारात्मकता का चश्मा उतारकर देखें तो उन्हें पता चलेगा कि मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया में सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बना दिया है।

प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि सपा और कांग्रेस के राज में फ ले-फू ले कालाबाजारियों और बिचैलियों के दिन अब लद गये हैं। इसलिए अब महंगाई नाम की सुरसा का मुंह बढ़ने से पहले ही सिल दिया जाता है। मौसमी कारणों से प्याज की कीमतें बढ़ीं तो केंद्र सरकार ने बफर स्टॉक से प्याज निकालकर सभी राज्य सरकारों को दिया। साथ ही प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर अनेक देशों से प्याज मंगाने का कदम उठाया है तथा बाजार में प्याज उपलब्ध करायी गई। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि बिजली कर्मचारियों के भविष्य निधि का 2600 करोड़ रुपए डिफाल्टर निजी कंपनी के खाते में डालने का मार्ग प्रशस्त करने वाले अखिलेश यादव को अपने शासन के उन दिनों को याद करना चाहिए जब पूरा प्रदेश उनके चपरासी की भर्ती से लेकर लोक सेवा आयोग की भर्ती तक में भ्रष्टाचार से त्राहि-त्राहि कर रहा था और प्रदेश के नौजवानों का भविष्य संकट में पड़ गया था। अखिलेश यादव के शासन में पूरा प्रदेश अंधेरे में डूबा हुआ था और सैफई व इटावा को छोड़कर पूरे प्रदेश में केवल टुकड़े-टुकड़े में बिजली मिलती थी। उन्होंने कहा कि अखिलेश शासन के संरक्षण में अपराध व भूमाफिया उद्योग रिकार्ड वृद्धि पर था और प्रदेश से उद्योग-धंधे बंद हो रहे थे जनता बेरोजगारी के कारण दूसरे प्रदेशों में पलायन कर रही थी। आज देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लक्ष्य पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिसमें मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में उप्र का योगदान 1 ट्रिलियन का होगा। श्रीवास्तव ने कहा कि मोदी की सरकार में देश की अर्थव्यवस्था चमक रही है। मोदी सरकार के आने के बाद पांच साल में ही 2019 में भारत विश्व बैंक की ईज आफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में 2014 के 137 वें स्थान से ऊपर आकर आज भारत 63 वें पायदान पर पहुंच गया है। भारत की बिजली कमी वित्तीय वर्ष 2014 के 4.2 प्रतिशत से घटकर वित्तवर्ष 2018 में एक प्रतिशत से भी कम 0.7 पहुंच गयी है। अप्रैल 2018 तक मोदी सरकार बनने के चार वर्ष के भीतर ही देश के शत प्रतिशत गांवों में बिजली पहुंचा दी गयी।

मदरसों के बच्चों को भी मिलेगी एनसीसी व एनएसएस की ट्रेनिंग

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मदरसों के आधुनिकीकरण में जुटी प्रदेश सरकार मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को अन्य स्कूलों के बच्चों की भांति राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) व नेशनल कैडेट कोर (एनसीसी) का प्रशिक्षण देगी। इस बारे में सरकार का मानना है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को सामाजिक कार्यक्रमों से जोड़े जाने की जरूरत है।

मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार राघवेन्द्र सिंह ने बताया कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को अन्य शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों की भांति अग्रसर बनाने के लिए उनकी भागेदारी सामाजिक कार्यक्रमों में सुनिश्चित करनी होगी। छात्र-छात्राओं में भाईचारा, अनुशासन, धर्म निरपेक्षता, निस्वार्थ सेवा का भाव जागृत करने के लिए अब राष्ट्रीय कैडेट कोर व राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रशिक्षण दिए जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस बावत मदरसा शिक्षा परिषद की तरफ से सभी मदरसों को इसके निर्देश भेज दिए गये हैं। रजिस्ट्रार के मुताबिक, एनसीसी का उद्देश्य होता है कि देश की रक्षा के लिए सभी को अग्रसर करें। इससे मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को भारतीय सेना में करियर बनाने का मौका भी मिलेगा। इसके अलावा उन्हें शिक्षा के अलावा देश सेवा में तत्पर रहने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सिंह ने बताया कि बोर्ड यह भी देखेगा कि उसके निदेर्शों का पालन कितने मदरसों ने किया है। उन्होंने कहा कि मदरसा छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए एनएसएस का प्रशिक्षण भी बेहद जरूरी है। इसके प्रशिक्षण में सामाजिक कुरीतियों के निवारण, पयार्वरण सुरक्षा, साफ-सफाई, आपातकलीन या प्राकृतिक आपदा से सहायता जैसे विषयों पर छात्रों को जागरूक किया जाएगा।

लीडरशिप फॉर एकेडमिशियन प्रोग्राम के लिए चयन

लखनऊ। बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय के माइक्रोबायलॉजी डिपार्टमेंट के प्रो. रामचंद्र को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यम से लीडरशिप फॉर एकडेमिशन प्रोग्राम 2019 शिक्षाविदों के लिए नेतृत्व के लिए 3 सप्ताह के प्रशिक्षण के लिए के लिए चुना गया है। इसमें वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में से किसी एक में एक सप्ताह का विदेशी प्रशिक्षण शामिल होगा।

प्रो. रामचंद्र जनवरी 2020 में विदेशी प्रशिक्षण के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भाग लेंगे, जबकि दो सप्ताह के लिए इस कार्यक्रम का भारत मे प्रशिक्षण 8 से 21 दिसंबर के बीच वाराणसी में आयोजित किया जाएगा।

संगठनात्मक कार्यों की सुगमता के लिए भाजपा ने किया विस्तार

● नवसृजित संगठनात्मक चार जिले व 423 मंडल स्वीकृत

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने संगठनात्मक कार्यों की सुगमता के लिए नवसृजित चार जिलों को स्वीकृति प्रदान की। इसके साथ ही अब भाजपा के संगठनात्मक दृष्टि से 1918 मंडल व 27779 सेक्टरों की संरचना होगी। भाजपा के प्रदेश महामंत्री विजय बहादुर पाठक ने बताया कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष द्वारा बृज क्षेत्र के अन्तर्गत बरेली जिले में आने वाले आंवला को तथा शाहजहांपुर महानगर को संगठनात्मक जिला स्वीकृत किया गया है। इसी तरह गोरखपुर क्षेत्र के आजमगढ़ जिले में आने वाले लालगंज को नया संगठनात्मक जिला घोषित किया है जिसका मुख्यालय निजामाबाद होगा। इसी क्रम में काशी क्षेत्र के जौनपुर में मछलीशहर भाजपा का नया संगठनात्मक जिला होगा और जिसका मुख्यालय मड़ियाहूँ होगा। प्रदेश में अब भाजपा के 98 संगठनात्मक जिले हो गए है। भाजपा प्रदेश महामंत्री विजय बहादुर पाठक ने बताया कि प्रदेश में चार नये जिलों के सृजन की स्वीकृति के साथ ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने संगठनात्मक कार्यों की सुगमता और सरलता के लिए संगठनात्मक मंडलों की संख्या में भी विस्तार किया है। प्रदेश में पार्टी के संगठनात्मक मंडलों की संख्या अब तक 1494 थी जो अब बढ़कर 1918 हो गई है। इसी प्रकार संगठनात्मक कार्यों के लिए 27779 सेक्टरों को स्वीकृति प्रदान की गई है जबकि इससे पूर्व प्रदेश में 15430 सेक्टर थे। प्रदेश में अब पश्चिम क्षेत्र में 19 जिले, 330 मंडल, 4865 सेक्टर, ब्रज क्षेत्र में 19 जिले, 334 मण्डल, 4835 सेक्टर, कानपुर क्षेत्र में 17 जिले, 253 मंडल, 3461 सेक्टर, अवध क्षेत्र में 15 जिले, 377 मंडल, 5067 सेक्टर, गोरखपुर क्षेत्र में 12 जिले, 286 मंडल, 4237 सेक्टर तथा काशी क्षेत्र में 16 जिले, 338 मंडल व 5314 सेक्टरों की संरचना के अंतर्गत पार्टी का कैडर काम करेगा।

राज्य व निगम कर्मियों ने दिया बिजली कर्मचारियों के आंदोलन को समर्थन

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों के कई कर्मचारी संघों ने एक संयुक्त बैठक कर पीएफघोटाले के विरोध में चल रहे उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों के आन्दोलन को पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया है। कर्मचारी संघों ने बिजली कर्मचारियों के 14 नवम्बर को होने वाली रैली में भी राज्य कर्मचारियों से बड़ी संख्या में सम्मिलित होने की अपील की है।

कर्मचारी संघों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि उप्र सरकार प्राविडेन्ट फंड घोटाले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए ऊर्जा क्षेत्र के कर्मचारियों के पीएफ के भुगतान की जिम्मेदारी ले और इस सम्बन्ध में आवश्यक गजट नोटिफि केशन जारी कर बिजली कर्मचारियों को आश्वस्त करें। कर्मचारी संघो ने पीएफ घोटाले के मुख्य आरोपी पावर कारपोरेशन के पूर्व चेयरमैन को सेवा से बर्खास्त कर तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है। कर्मचारी संघों ने मुख्यमंत्री की घोषणा के 12 दिन बाद भी सीबीआई जांच न प्रारम्भ किये जाने और घोटाले पर पर्दा डालने की कोशिशों पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। संयुक्त बैठक में उप्र राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कमलेश मिश्र, उप्र इंजीनियर्स ऐसोसिएशन के अध्यक्ष सुरजीत सिंह निरंजन, यूपी फेडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल सर्विस ऐसोसिएशन के अध्यक्ष नरेन्द्र प्रताप सिंह, सुपरवाइजर ऐसोसिएशन बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की प्रांतीय अध्यक्ष रेनू शुक्ला, उप्र जल निगम समन्वय समिति के संयोजक वाई एन उपाध्याय, उप्र जल निगम इंजीनियर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डीपी मिश्रा एवं उप्र जल निगम इंजीनियर्स एसोसिएशन के सचिव नौशाद उपस्थित थे।

दुबई पुलिस अवार्ड-2019 के अंतिम चरण में पहुंचा डायल-112

● विश्व भर के 25 सर्वश्रेष्ठ काल सेंटर ले रहे प्रतियोगिता में हिस्सा, आज होगी परिणाम की घोषणा

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

यूपी की आपात सेवा डायल-112 का चयन दुबई में चल रहे इंटरनेशल काल सेंटर अवार्ड समारोह के पुलिस सेक्टर की श्रेणी के अंतिम चरण में हुआ है। अवार्ड समारोह 12 से 14 नवंबर तक चलेगा, जिसमें विश्व भर से पुलिस, सार्वजनिक एवं निजी सेंटर के चयनित काल सेंटरों को पुरस्कृत किया जाएगा।

एडीजी असीम अरुण ने बताया कि दुबई सरकार और दुबई पुलिस व आवाया के संयुक्त तत्वावधान में पुलिस, सार्वजनिक एवं निजी सेक्टर की श्रेणियों के अन्तर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट काल सेंटरों को पुरस्कृत करने के लिए इस वर्ष इंटरनेशल काल सेंटर अवार्ड का गठन किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस प्रतियोगिता में विश्व के सर्वश्रेष्ठ लगभग 25 काल सेंटरों ने प्रतिभाग किया है। जिमसें प्रमुख रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका-911, आस्ट्रेलिया-102 और यूरोप-112 शामिल हैं। एडीजी ने बताया कि प्रतियोगिता के परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। सर्वश्रेष्ठ काल सेंटर का चयन मूल्यांकनकर्ताओं के एक विशेषज्ञ पैनल द्वारा किया जाएगा। एडीजी ने कहा कि डायल-112 सेवा, नवीन उन्नत तकनीक पर आधारित आपातकालीन सेवा है। जिसकी बेहतर प्रक्रिया एवं संयुक्त कार्रवाई के लिए पीड़ित को त्वरित सहायता प्रदान की जा रही है। इवेंट क्लोजर सिस्टम द्वारा सम्पूर्ण प्रक्रिया को साफ्टवेयर के मायध्म से पीड़ित की पूर्ण संतुष्टि के स्तर पर परिणति तक संपादित किया जा रहा है। आधुनिक तकनीक के प्रयोग से पीआरवी की गश्त प्रबंधन को और सुदृढ़ बनाया गया है। जिसमें पूर्व में गठित प्रकरणों के आधार पर वैज्ञानिक प्रणाली के उपयोग से प्रत्येक जिले में पीआरवी का व्यवस्थापन किया जा रहा है। साथ ही साथ 'सवेरा' पहल अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों केम पंजीकरण हो रहे हैं। जिसके अन्तर्गत उनकी पहचान, पता दर्ज कर उन तक पुलिस कम से कम समय में पहुंचेगी और उनकी समस्याओं का निवारण बेहतर रूप से हो सकेगा।

अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का खुलासा, एक गिरफ्तार

● आधा दर्जन तमंचे, कारतूस व असलहा बनाने के उपकरण बरामद

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

एसटीएफ की प्रयागराज इकाई ने कौशांबी जिले में अवैध शस्त्र बनाने की एक फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। एसटीएफ ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से आधा दर्जन तमंचे, कारतूस और असलहे बनाने के उपकरण बरामद किए।

एसटीएफ को सूचना मिली कि कौशांबी जिले के थाना सराय आकिल क्षेत्र के तिलहापुर गांव का ननका उर्फ गोरे उर्फ वीरेन्द्र पासी अपने घर में ही भारी मात्रा में अवैध तमंचे बनाता व बेचता है। आज कुछ लोग उसके पास तमन्चा खरीदने आने वाले हैं। इस सूचना पर एसटीएफ ने उसके घर के पास घेराबंदी की। मौके पर असलहा खरीदने आए तीन व्यक्ति ननका उर्फ गोरे से बातचीत कर रहे थे। एक के हाथ में दो झोले थे। एसटीएफ ने मुखबिर के इशारे पर छापा मारा तो चारों भागने लगे। एसटीएफ ने एक अभियुक्त को झोले सहित पकड़ लिया जबकि तीनों अन्य संकरी गालियों का फ ायदा उठाकर फरार हो गए। दोनों झोलों से छह तमंचे, दो अर्द्धनिर्मित तमंचे और तमंचे बनाने के उपकरण व कारतूस बरामद हुए।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त ने अपना नाम सूरज यादव निवासी बेगम बाजार, बम्हरौली थाना धूमनगंज बताया। सूरज के अनुसार वह अपने साथी राज कुमार पासी निवासी ग्राम कोटिया थाना सरायआकिल जनपद कौशाम्बी के साथ महेन्द्र पासी निवासी तिल्हापुर को साथ लेकर तमंचे खरीदने के लिये ननका उर्फ गोरे पासी के पास आया था। ननका को पैसे दे दिए थे और माल लेने वाला ही था कि इसी बीच में टीम को देख कर ननका अपने झोलों को मेरे हाथ में देकर भाग गया। अभियुक्त ने यह भी बताया कि ननका उर्फ गोरे पासी काफी हड़बड़ी में था तथा कह रहा था कि पुलिस को इस ठिकाने के बारे में किसी ने सूचना दे दी है, इसी कारण से वह तमंचे बनाने का सारा सामान समेट कर कहीं छिपाने जा रहा है।

सभी जिलों में सामूहिक विवाह आज, 21 हजार का लक्ष्य

● कार्यक्रम के आयोजन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी: रमापति शास्त्री

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

गरीब व निर्धन परिवारों की कन्याओं की शादी के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर शुरू की गयी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गुरुवार को सभी जिलों में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है। सामूहिक विवाह योजना के तहत 21 हजार शादियों का लक्ष्य रखा गया है। इस बावत प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है सामूहिक विवाह कार्यक्रम को बेहतर ढंग से सम्पन्न कराया जाये। कार्यक्रम के आयोजन में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी।

सामूहिक विवाह कार्यक्रम के तैयारियों की समीक्षा करते हुए शास्त्री ने कहा कि प्रदेश के सभी 75 जनपदों में एक साथ 14 नवम्बर 2019 को आयोजित किये जाने वाले सामूहिक विवाह का लक्ष्य 21 हजार निर्धारित किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये है कि निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष सामूहिक विवाह सम्पन्न कराया जायें इसका विशेष ध्यान रखा जाये। सामूहिक विवाह के आयोजन में जनपद के प्रभारी मंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक व जन प्रतिनिधि को अवश्य आमंत्रित किया जाये तथा उनसे इस कार्यक्रम के आयोजन में सहयोग की अपील भी की जाये। उन्होंने बताया कि 2 लाख रूपये वार्षिक आय सीमा के अन्तर्गत आने वाले परिवारों को इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित किया जाता है। सभी वर्गों के जरूरतमंद निराश्रित परिवारों के कन्याओं के विवाह हेतु सामूहिक आयोजन किया जाता है। योजना के तहत विधवा, परित्यागता, तलाकशुदा महिलाओं के विवाह की भी व्यवस्था है। शास्त्री ने बताया कि इस योजना में दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु कन्या के खाते में 35000 हजार की धनराशि का अनुदान एवं विवाह संस्कार के लिए आवश्यक, सामग्री यथा कपड़े, बिछिया, पायल, बर्तन आदि पर 10 हजार रूपये की धनराशि से क्रय करते हुए प्रदान किया जाता है तथा प्रत्येक जोड़े के विवाह आयोजन पर 6 हजार की धनराशि व्यय किये जाने की व्यवस्था है, इस प्रकार योजना के अन्तर्गत एक जोड़े के विवाह पर कुल 51 हजार रूपये की धनराशि व्यय किये जाने की व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अभी तक 71378 जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराया गया है।

शिशु मृत्यु दर कम करने पर जोर, आज से चलेगा जागरूकता कार्यक्रम

नवजात की उचित देखभाल व स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए करेंगे जागरूक

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रदेश में शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने गुरुवार से 21 नवंबर तक जनसामान्य को नवजात शिशु के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करन के लिए नवजात शिशु देखभाल सप्ताह मनाने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के मिशन निदेशक की तरफ से अपर मिशन निदेशक जसजीत कौर ने प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को पत्र लिख कर नवजात शिशु देखभाल सप्ताह के दौरान आयोजित होने वाली प्रमुख गतिविधियों के बारे में गाइडलाइन जारी की है।

अपर मिशन निदेशक जसजीत कौर की तरफ से जारी निर्देश में सप्ताह का मुख्य उद्देश्य नवजात शिशु की आवश्यक देखभाल करने के संबंध में जनसमुदाय को जागरूक कर नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। इसके अलावा जन्म के उपरांत शीघ्र स्तनपान, छह माह तक केवल स्तनपान और छह माह बाद ऊपरी आहार के द्वारा बच्चों को कुपोषित होने से बचाने और समय से नियमित टीकाकरण कराने के प्रति स्वास्थ्य विभाग के साथ अन्य विभाग भी मिलकर जागरूकता की अलख जगाएँगे। नवजात शिशु की आवश्यक देखभाल के बारे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के महाप्रबन्धक बाल स्वास्थ्य डॉ वेद प्रकाश का कहना है कि प्रसव चिकित्सालय में ही कराएं और प्रसव पश्चात 48 घंटे तक माँ और शिशु की उचित देखभाल के लिए अस्पताल में ही रुकें। नवजात को तुरंत नहलाएँ नहीं और शरीर पोंछकर नर्म साफ कपड़े पहनाएं। जन्म के एक घंटे के भीतर माँ का पीला गाढ़ा दूध पिलाना शुरू कर दें और छह माह तक केवल स्तनपान ही कराएं। जन्म के तुरंत बाद नवजात का वजन लें और विटामिन के1 का इंजेक्शन लगवाएँ। नियमित और सम्पूर्ण टीकाकरण कराएं क्योंकि यह टीके बच्चों को कई तरह की बीमारियों से बचाते हैं। पाँच साल से कम उम्र के बच्चों की मौत का प्रमुख कारण डायरिया और निमोनिया होते हैं, जबकि इन दोनों बीमारियों से बचाने के लिए रोटा वायरस और पेंटावैलेंट जैसे कई टीके मौजूद हैं। इसके साथ ही इसका इलाज भी सस्ता और सुलभ है। नवजात की नाभि सूखी और साफ रखें, संक्रमण से बचाएं और माँ एवं शिशु की व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखें।

उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण विकास के अवसर प्रदान करते हैं : नायडू

एजेंसी। नई दिल्ली

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता और विचारक दत्तोपंत ठेंगड़ी के शताब्दी वर्ष समारोह में बोलते उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू

उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने बुधवार को कहा कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण भले ही चुनौतियां पेश करते हैं लेकिन वे देश के विकास का अवसर भी प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता और विचारक दत्तोपंत ठेंगड़ी के शताब्दी वर्ष समारोह के मौके पर उन्होंने कहा, हम कारोबार सुगमता की वैश्विक रैंकिंग पर लगातार चढ़ते जा रहे हैं। हम अर्थव्यवस्था में रचनात्मक व्यवधान देख रहे हैं। अर्थव्यवस्था पर उनका प्रतिकूल प्रभाव क्षणिक ही होगा और अर्थव्यवस्था फिर से उच्च वृद्धिदर के मार्ग पर लौट आएगा।

ठेंगड़ी ने अर्थव्यवस्था के स्वदेशी मॉडल की वकालत की थी और भारतीय मजदूर संघ, स्वदेशी जागरण मंच और संघ के कई अन्य संगठनों की स्थापना की थी। नायडू ने एक नई शब्दावली एलपीजी गढी जिसमें एल यानी लिबराइजेश (उदारीकरण), पी यानी प्राइवेटाइजेशन (निजीकरण) और जी यानी ग्लोबलाइजेशन (वैश्वीकरण) है। उन्होंने कहा कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण भले ही चुनौतियां पेश करते हैं लेकिन वे देश के विकास का अवसर भी देते हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ कदमताल करते हुए भारत भी बदल रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा, पारदर्शी, टिकाऊ कुशल और उच्च वृद्धि वाली समावेशी अर्थव्यवस्था के लिए नई विधाई ढांचा तैयार किया जा रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था में नए स्टार्टअप क्षेत्र उभर रहा है। भारत स्टार्टअप में स्टार्ट की तीसरी बड़ी संख्या है। ठेंगड़ी को सच्चे प्रेरणादाई व्यक्ति और कर्मयोगी करार देते हुए नायडू ने कहा, मैं उन्हें इतनी गहराई से जानने का सौभाग्यशाली रहा हूं।

स्मार्ट सिटी को लेकर आज होगी बैठक

बरेली। स्मार्ट सिटी को लेकर कमिश्नर की अध्यक्षता में बैठक आज होगी। तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए टेंडर ऑनलाइन आमंत्रित किये गये है। इन पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मंजूरी मिलेगी। नए डीएम को भी बतौर डायरेक्टर शामिल करने की औपचारिकता भी होगी। गांधी उद्यान मकें वाकओवर डांसिंग फाउंटेन के लिए टेंडर निकाला है। अलग अलग जगह सोलर पॉवर वाले वाटर एटीएम, उनकी डिजाइनिंग, ऑपरेशन पर भी बोर्ड निर्णय करेगा। पांच स्थानों पर वर्टिकल गार्डेन, एरिया बेस डवलपमेंट के प्रोजेक्ट भी बैठक में रखे जायेंगे। कंपनी के शेयर कैपिटल को बढ़ाने पर भी विचार किया जाएगा। शहर को स्मार्ट सिटी में चयनित हुए काफी समय बीत गया है। कंपनी भी गठित हुई। किंतु मेयर और नगर आयुक्त के बीच पटती नहीं है। इसकी खामियाजा जनता भुगत रही है। पानी, प्रकाश, सफाई आदि को लेकर कई शिकायतें है लेकिन इन पर सुनवाई नहीं हो पा रही है।

चेन्नई में बंगाल की खाड़ी में मरीना बीच पर सेल्फी लेते हुए व्यक्ति

न्यायालय ने तीन तलाक को चुनौती देने वाली नई याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब

एजेंसी। नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय ने तीन बार तलाक कह कर संबंध विच्छेद करने को दंडनीय अपराध बनाने के कानून की वैधानिकता को चुनौती देने वाली ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) की याचिका पर केंद्र से बुधवार को जवाब मांगा। न्यायमूर्ति एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने नोटिस जारी करते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की याचिका मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 को चुनौती देने वाली अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ दी।

यह अधिनियम तलाक ए बिद्दत और मुस्लिम पति द्वारा दिए गए किसी भी फौरी तलाक को अमान्य करार देता है और इसे और गैर कानूनी बनाता है। पीठ ने सीरथ उन नबी अकादमी की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस बात पर नाराजगी जताई कि विभिन्न लोगों और संगठनों ने बड़ी संख्या में रिट याचिकाएं दायर कर रखी हैं। पीठ ने कहा कि एक बार में तीन तलाक के मुद्दे पर 20 से अधिक याचिकाएं लंबित हैं। पीठ ने अकादमी के वकील से जानना चाहा, एक ही मुद्दे पर कितनी याचिकाएं दायर की जाएंगी। प्रत्एक मामले में अधिसूचना आती है और आप सभी जनहित याचिका लेकर आ जाते हैं। इस समय तीन तलाक के मसले पर 20 से अधिक याचिकाएं लंबित हैं। क्या हमें 100 याचिकाओं को संलग्न कर देना चाहिए और इन पर सौ साल तक सुनवाई करनी चाहिए ? हम एक ही मसले पर 100 याचिकाओं को नहीं सुन सकते। एआईएमपीएलबी और कमाल फारुकी की याचिका में कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है।

एसटीपी के जरिए मिटेगा गंगा से प्रदूषण

बरेली। वर्षो से प्रदूषण की मार झेल रही राष्ट्रीय नदी गंगा को प्रदूषण रूपी दानव के प्रकोप से मुक्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जारी प्रोग्राम नमामि गंगे के जरिए प्रयास किये जा रहे है। इसी कड़ी में शहर में चार सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बनने हैं। इनमें से एक चौबारी में प्रस्तावित था। अब यह प्लांट बारीनगला में बनेगा। इसके लिए आठ हजार वर्गमीटर जमीन तलाश ली गयी है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी है। नालो और अन्य उपयोग का दूषित जल नदी में जाने से बचाने और शहर में जलशोधन के लिए चार एसटीपी प्लांट प्रस्तावित है। अधिकारियों के अनुसार पहले चौबारी में जमीन देखी गयी थी। यह उपयुक्त नहीं पायी गयी। किसान अधिक दाम मांग रहे थे। इस वजह से भी बारीनगला में जमीन फाइनल की गयी है। ततारपुर में एक हजार वर्गमीटर जमीन चाहिए। एसटीपी प्लांट के जरिए दूषित जल शोधित होकर जायेगा।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आरटीआई कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत

एजेंसी। नई दिल्ली

प्रधान न्यायाधीश के कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लाने के उच्चतम न्यायालय के फैसले को आरटीआई कार्यकर्ताओं ने बुधवार को सराहना की और कहा कि शीर्ष अदालत ने मामले में कानून में स्थापित स्थिति को दोहराया है। गैर सरकारी संगठन राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल (सीएचआरआई) के सूचना पहुंच कार्यक्रम के प्रमुख वेंकटेश नायक ने कहा, मैं (उच्चतम न्यायालय की) संविधान पीठ द्वारा कानून में स्थापित रूख दोहराए जाने के फैसले का स्वागत करता हूं कि भारत का प्रधान न्यायाधीश सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकारी है।

अपने ऐतिहासिक फैसले में प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 2010 में दिए फैसले को बरकरार रखा कि भारत के प्रधान न्यायाधीश का कार्यालय सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आता है। शीर्ष न्यायालय ने अदालत के सेक्रेटरी जनतरल और मुख्य जनसंपर्क अधिकारी की अपील को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम की ओर से सिफारिश किए गए नामों का खुलासा किया जा सकता है न कि इसके कारणों की।

अदालत ने यह चेताते हुए कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम को टोह लेने के उपकरण की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। पारदर्शिता के साथ काम करने में न्यायिक आजादी के बारे में विचार किया जाना आवश्यक है। आरटीआई का इस्तेमाल निगरानी के लिए नहीं किए जा सकने वाली उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी को नायक ने बेहद दुर्भाग्यपूर्ण विचार करार दिया। उन्होंने कहा, यह विचार बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि सूचना का अधिकार अधिनियम का इस्तेमाल न्यायपालिका की टोह लेने के लिए किया जा सकता है। दुभार्ग्यपूर्ण है कि टोह लेने की तुलना संसद से पारित कानून के तहत पारदर्शिता से की गई है। पूर्व सूचना आयुक्त शैलेश गांधी ने भी शीर्ष अदालत के इस निर्णय की सराहना की है।

उन्होंने कहा, शीर्ष अदालत का यह एक बेहतर निर्णय है। मुझे वही निर्णय आने की उम्मीद थी क्योंकि तार्किक रूप से कुछ और नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह फैसला आने में दस साल लग गए। मुख्य सूचना आयुक्त ने इसे बरकरार रखा था और दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी इसे बरकरार रखा था। अब उच्चतम न्यायालय ने भी इसे बरकरार रखा है। सभी लोक सेवक जिन्हें सरकार की तरफ से वेतन दिया जाता है वह लोकसेवा है, उनकी स्थिति क्या है यह मायने नहीं रखता है।

सरकार बजट सत्र में पेश करेगी व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल संहिता विधेयक: गंगवार

एजेंसी। नई दिल्ली

सरकार व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल परिवेश पर तैयार विधेयक को संसद की मंजूरी के लिए बजट सत्र में पेश करेगी। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। इस संहिता को लोकसभा में 23 जुलाई 2019 को पेश किया गया था। इसके पारित होने से कामगारों का कवरेज कई गुणा फैल जाने तथा 13 केंद्रीय श्रम कानूनों के बदले एक संहिता के अमल में आने का अनुमान है। यह संहिता ऐसे सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होगी, जिसमें 10 या इससे अधिक कर्मचारी हों।

मंत्री ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से कहा, हम निश्चित तौर पर बजट सत्र में व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल परिवेश संहिता को पेश करेंगे। संसद की स्थाई समिति ने संहिता पर लोगों से टिप्पणियां मंगाई है। संसद का बजट सत्र जनवरी के अंतिम सप्ताह में शुरू होने का अनुमान है। सरकार को श्रम सुधार की प्रक्रिया में मानदेय संहिता पर पहले ही संसद की मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल स्थिति संहिता की बारी है। सरकार 44 श्रम कानूनों को मिलाकर चार संहिता बनाना चाहती है। गंगवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी संहिता यानी सामाजिक सुरक्षा संहिता के बारे में अवगत कराया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार चारों नई संहिताओं को जल्द से जल्द अमल में लाना चाहती है। सामाजिक सुरक्षा और औद्योगिक संबंध को लेकर शेष दो संहिताओं के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा, श्रम संबंधी मुद्दों पर कानून का मसौदा तैयार करने की त्रिकोणीय प्रक्रिया है।

पेज एक का शेष

प्रदूषण से ...

तक हवा की रफ्तार बढ़ेगी। सफर के अनुसार 15 नवंबर के बाद प्रदूषण छंटने के आसार हैं लेकिन दो दिन से बिगड़ी स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जरूरत पड़ी तो 4 से 15 नवंबर के लिए लागू की गई ऑड ईवन योजना को आगे बढ़ाया जा सकता है। केजरीवाल ने दिल्ली में लगातार गहराए वायु प्रदूषण के लिए फिर पड़ोसी राज्यों हरियाणा और पंजाब में जलाई जाने वाली पराली को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि इसे रोका जाना चाहिए, क्योंकि इससे वैश्विक स्तर पर दिल्ली की छवि प्रभावित हो रही है। उच्चतम न्यायालय के कड़े निर्देश के बावजूद पड़ोसी राज्य पराली जलाने से रुक नहीं रहे हैं।

अयोग्यता सही ...

आ सकती। पीठ ने यह भी कहा कि इन परिस्थितियों में संसद को 10 वीं अनुसूची के कुछ पहलुओं को सुदृढ़ बनाने के लिए फिर से विचार करना चाहिए ताकि अलोकतांत्रिक आचरणों को हतोत्साहित किया जा सके। अध्यक्ष के आदेश को चुनौती देने वाले अयोग्य विधायकों की याचिकाओं की विचारणीयता के बारे में पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 , जो स्वंय में ही बुनियादी ढांचे का हिस्सा है, में प्रदत्त रिट का अधिकार महत्वपूर्ण अधिकारों में है। पीठ ने संविधान पीठ के पहले के फैसले का जिक्र करते हुए कहा, हमें इस न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र के तहत इस मुद्दे का निर्णय करने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं मिला है। न्यायालय ने कहा कि अयोग्यता की याचिका पर निर्णय करते समय अध्यक्ष अर्द्ध न्यायिक प्राधिकार के रूप में काम करते हैं और इसलिए उनके आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। शीर्ष अदालत ने कहा कि उसके पास रिट अधिकार क्षेत्र के तहत अयोग्यता के मामलों पर विचार करने का पर्याप्त अधिकार होने के बावजूद अयोग्यता के आदेश को चुनौती देने वाले पक्षकार को पहले उच्च न्यायालय जाना जरूरी है क्योंकि यही उचित और प्रभावकारी होगा।पीठ ने कहा, इस न्यायालय के पास उच्च न्यायालय के सुविचारित न्यायिक फैसले का लाभ होता। यदि पक्षकार को फिर भी कोई शिकायत होती तो वह इस न्यायालय में आ सकता है। न्यायालय ने कहा कि किसी सदस्य के त्यागपत्र को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के संबंध में अध्यक्ष के पास इसकी जांच का दायरा सीमित है कि क्या यह स्वेच्छा से दिया गया है। पीठ ने कहा, एक बार जब यह स्पष्ट हो जाता है कि सदस्य अपनी मर्जी से इस्तीफा देना चाहता है तो अध्यक्ष के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता और त्याग पत्र पर विचार करते समय उसके पास सांविधानिक रूप से किसी भी दूसरे पहलू को ध्यान में रखने की अनुमति नहीं है। अध्यक्ष का संतुष्ट होना न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। न्यायालय ने इस मामले को वृहद पीठ को सौंपने से इंकार करते हुए कहा कि इसमें कोई ठोस कानूनी सवाल नहीं बचा है। शीर्ष अदालत ने अध्यक्ष के आदेश को चुनौती देने वाली इन अयोग्य विधायकों की याचिकाओं पर 25 अक्टूबर को सुनवाई पूरी की थी। तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष ने एचडी कुमार स्वामी के नेतृत्व वाले कांग्रेस-जद(एस) गठबंधन के सदन में विश्वास मत से ठीक पहले जुलाई के पहले सप्ताह में 17 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था। इसके बाद, कुमारस्वामी सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। बाद में राज्य में भाजपा की बीएस येदियुदप्पा सरकार का गठन हुआ था। राज्य विधानसभा की 17 में से 15 रिक्त सीटों के लिए पांच दिसंबर को उपचुनाव हो रहा है। इन सीटों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 18 नवंबर है। अयोग्य घोषित किए गए विधायक प्रताप गौड़ा पाटिल, बीसी पाटिल, शिवराम हेब्बर, एसटी सोमशेखर, बी बसवाराज, आनंद सिंह, आर रोशन बेग, एन मुनिरत्न, के सुधाकर, एमटीबी नागराज, श्रीमंत पाटिल, रमेश जारकिहोली, महेश कुमातल्ली और आर शंकर (सभी कांग्रेस) हैं। जद (एस) के अयोग्य घोषित किए गए विधायकों में के. गोपालैया, एएच विश्वनाथ और केसी नारायण गौड़ा शामिल हैं।

भाजपा मे ...

नई दिल्ली में मुलाकात की। उन्होंने बताया कि पार्टी नेता और अयोग्य विधायक मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष से गुरूवार को मुलाकात करेंगे और भविष्य की योजना के बारे में निर्णय करेंगे। उप मुख्यमंत्री ने बताया, कोई दिक्कत या कोई अन्य चीज नहीं है, वे पार्टी में शामिल होना चाहते हैं और शामिल होंगे,उपचुनाव और अन्य बातें बाद में होंगी।

प्रधान न्यायाधीश...

लिखे। न्यायालय ने कहा कि निजता का अधिकार एक महत्वपूर्ण पहलू है और प्रधान न्यायाधीश के कार्यालय से जानकारी देने के बारे में निर्णय लेते समय इसमें और पारदर्शिता के बीच संतुलन कायम करना होगा। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि न्यायिक स्वतंत्रता और पारदर्शिता को साथ-साथ चलना है। न्यायमूर्ति रमण ने न्यायमूर्ति खन्ना से सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि निजता के अधिकार और पारदर्शिता के अधिकार तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बीच संतुलन के फार्मूले को उल्लंघन से संरक्षण प्रदान करना चाहिए। उच्च न्यायालय ने 10 जनवरी, 2010 को कहा था कि प्रधान न्यायाधीश का कार्यालय सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आता है और न्यायिक स्वतंत्रता किसी न्यायाधीश का विशेषाधिकार नहीं है बल्कि उन्हें इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। 88 पेज के इस फैसले को तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश के जी बालाकृष्ण के लिए व्यक्तिगत रूप से एक झटका माना जा रहा है क्योंकि वह सूचना के अधिकार कानून के तहत न्यायाधीशों से संबंधित सूचना की जानकारी देने के पक्ष में नहीं थे। उच्च न्यायालय की तीन सदस्ईय पीठ ने अपने फैसले में उच्चतम न्यायालय की वह याचिका खारिज कर दी थी जिसमें दलील दी गई थी कि प्रधान न्यायाधीश के कार्यालय को सूचना के अधिकार कानून के दायरे में लाने से न्यायिक स्वतंत्रता प्रभावित होगी। यह फैसला सुनाने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए पी शाह पहले ही सेवानिवृत्त हो गए थे जबकि इसके एक अन्य सदस्य न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन शीर्ष अदालत के न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। इस समय इस पीठ के तीसरे सदस्य न्यायमूर्ति एस मुरलीधर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं।प्रधान न्यायाधीश का कार्यालय सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आने का मुद्दा आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल ने उठाया था। केन्द्रीय सूचना आयोग ने अग्रवाल के आवेदन पर जब जनवरी 2008 में उच्चतम न्यायालय को अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश दिया तो इसके खिलाफ यह मामला उच्च न्यायालय पहुंचा था।

राफेल मामले ...

के केंद्र के राफेल सौदे को क्लीन चिट दी गई थी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के. एम. जोसफ की पीठ ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस मामले पर 10 मई को सुनवाई पूरी की थी। पीठ ने कहा था कि इस पर फैसला बाद में सुनाया जाएगा। गौरतलब है कि 14 दिसम्बर 2018 को शीर्ष अदालत ने 58,000 करोड़ के इस समझौते में कथित अनियमितताओं के खिलाफ जांच का मांग कर रही याचिकाओं को खारिज कर दिया था। सुनवाई पूरी करते हुए शीर्ष अदालत ने सौदे के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर केंद्र से संप्रभु गारंटी से छूट और समझौते में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण उपबंध का ना होने आदि पर सवाल किए थे।

सबरीमाला मामले ...

खानविलकर, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ और न्यायमूर्ति इन्दु मल्होत्रा शामिल हैं। सबरीमला मंदिर में 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं का प्रवेश वर्जित होने संबंधी व्यवस्था को असंवैधानिक और लैंगिक तौर पर पक्षपातपूर्ण करार देते हुए 28 सितंबर, 2018 को तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से फैसला सुनाया था। इस पीठ की एक मात्र महिला सदस्य न्यायमूर्ति इन्दु मल्होत्रा ने अल्पमत का फैसला सुनाया था।

राहुल गांधी ...

था कि इस पर फैसला बाद में सुनाया जाएगा। राहुल गांधी उस वक्त कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे और उन्होंने पीठ से कहा था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से संबंधित अपनी टिप्पणी गलत तरीके से शीर्ष अदालत के हवाले से कहने पर वह पहले ही बिना शर्त माफी मांग चुके हैं।

अयोध्या की ...

बीच 5 किलोमीटर का फ्लाईओवर बनेगा। सरयू नदी के किनारे भगवान राम की 251 मीटर की विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति बनेगी। दिसंबर से 5 पांच सितारा होटल का काम भी शुरू हो जाएगा। दिसम्बर में 10 बड़े रिजार्ट के निर्माण का काम भी शुरू होगा। उन्होंने बताया कि मंदिर निर्माण के लिए अभी तक 65 प्रतिशत पत्थर तराशे जा चुके हैं और अगर 2000 कारीगर एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं तो ढाई वर्ष में मंदिर बन कर तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के आसपास के 5 किलोमीटर के मंदिरों की देखभाल की जिम्मेदारी भी प्रस्तावित ट्रस्ट देखेगा। मंदिर के पास 77 एकड़ परिसर में कई धार्मिक संस्थान बनाएं जाएंगे। इनमें राम मंदिर के पास में गोशाला, धर्मशाला ओर वैदिक संस्थान के साथ कई धार्मिक परिसर शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि अयोध्या में 10 श्री राम द्वार बनाए जाएंगे और उसे एक आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित किया जाएगा। तीर्थ यात्रियों के रूकने के लिए रैनबसेरों का भी निर्माण किया जाएगा और भगवान राम से जुड़े सभी कुंडों का पुर्निर्माण होगा।

विहिप का सुझाव ...

के मुताबिक मंदिर 268 फुट लंबा, 140 फुट चौड़ा और शिखर तक 128 फुट ऊंचा होगा। इसमें कुल 212 खंभे होंगे। शर्मा ने उम्मीद जताई कि नए ट्रस्ट में न्यास का भी कोई प्रतिनिधि होगा। उन्होंने कहा, हमें लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इस ट्रस्ट में शामिल करना चाहिए। राम मंदिर ट्रस्ट का गठन सोमनाथ ट्रस्ट की तर्ज पर होना चाहिए। गौरतलब है कि विहिप राम जन्मभूमिन्यास की समर्थक रही है। विहिप के सदस्य कार्यशाला में अपनी सेवाएं देते रहे हैं।

विपक्ष के...

राज्यपाल के पास जा सकता है। शाह ने कहा- चुनाव के पहले और चुनाव के समय मैंने सौ बार कहा था, नरेंद्र मोदीजी ने कई बार कहा था कि अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। तब किसी ने कोई विरोध दर्ज नहीं कराया था। अब वे नई मांगें लेकर आ रहे हैं और यह हमें स्वीकार नहीं है। हमने विश्वासघात नहीं किया है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा- आज भी सभी लोग सरकार बना सकते हैं। शिवसेना 2 दिन मांग रही थी, राज्यपाल ने 6 महीने का मौका दे दिया है। कपिल सिब्बल जैसे वकील ऐसे बयान दे रहे हैं कि मौका छीन लिया। आपको पूरा मौका है। यह स्पष्ट करने के लिए ही मैं यहां पर हूं कि सबके पास मौका है। शाह ने कहा 'मैं मानता हूं कि राज्यपाल ने उचित काम किया है। इस मुद्दे पर विपक्ष राजनीति कर रहा है। राज्यपाल के संवैधानिक पद को इस तरह से राजनीति में घसीटने को मैं लोकतंत्र के लिए स्वस्थ परंपरा नहीं मानता हूं। विपक्ष को लगता है कि इस तरह से वे भ्रांति फैलाकर लोगों को सहानुभूति हासिल कर लेंगे तो ये उनकी भूल है।' उन्होंने यह भी कहा कि मैं मध्यावधि चुनाव नहीं चाहता।

सीएमपी पर ...

आप में सकारात्मक कदम है। ठाकरे ने एक उपनगरीय होटल में थोराट, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चह्वाण और एक अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता माणिकराव ठाकरे से मुलाकात की। इस बीच शरद पवार नीत एनसीपी ने सरकार गठन के लिए शिवसेना के साथ संभावित गठबंधन से पहले साझा न्यूनतम कार्यक्रम तैयार करने के लिए कांग्रेस के साथ बनाई जाने वाली संयुक्त समिति की खातिर अपने पांच सदस्यों को नामित किया। एनसीपी की ओर से विधायक दल के नेता अजीत पवार, जयंत पाटिल, छगन भुजबल, नवाब मलिक और धनंजय मुंडे समिति का हिस्सा होंगे। प्रदेश एनसीपी प्रमुख पाटिल ने शरद पवार से मुलाकात करने के बाद संवाददाताओं से कहा कि सत्ता में हिस्सेदारी के फार्मूले पर अभी चर्चा नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा, हमने शिवसेना के सामने कोई शर्त नहीं रखी है। फिलहाल, हम सरकार के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। अरविंद सावंत ने नरेंद्र मोदी सरकार से इस्तीफा दे दिया है और हम मानते हैं कि शिवसेना इस कदम से आधिकारिक रूप से भाजपा नीत राजग से बाहर हो गई है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि तीनों दलों के शीर्ष नेताओं द्वारा साझा न्यूनतम कार्यक्रम को मंजूर किए जाने के बाद ही सरकार बनाने के लिए वार्ता शुरू होगी। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि नई सरकार में कांग्रेस को उप मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष का पद मिल सकता है तथा मुख्यमंत्री का पद शिवसेना और राकांपा के बीच साझा हो सकता है। हालांकि, चव्हाण ने कहा कि सत्ता साझेदारी फार्मूले पर अभी चर्चा नहीं हो रही है। चव्हाण ने कहा कि उनकी पार्टी अन्य दलों के विधायकों को अपने (भाजपा के) पाले में करने के लिए भाजपा द्वारा संभावित ऑपरेशन लोटस को रोकने के लिए चौकस है। इस बीच, न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय करने से जुड़ी कांग्रेस और एनसीपी की प्रस्तावित संयुक्त बैठक रद्द हो गई है। निराश दिखाई दिए एनसीपी नेता अजीत पवार ने बुधवार रात यह जानकारी दी, जिससे अटकलें लगनी शुरु हो गई हैं। वहीं, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नवाब मलिक ने इससे इंकार करते हुए कहा कि बैठक अब भी चल रही है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे अजित ने शरद के घर के बाहर मौजूद पत्रकारों से कहा कि वह पुणे जिले में अपने विधानसभा क्षेत्र बारामती जा रहे हैं। इस बीच, मीडिया के एक वर्ग द्वारा घटना की कवरेज से नाराज शरद पवार ने कहा कि अगर नेताओं की निजता में ताकझांक की गई तो वह पत्रकारों से नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा, 'अजित पवार मुंबई में हैं। वह कल आपसे मुलाकात करेंगे।

यदि वह मजाक में कुछ भी कहते हैं तो आपका (मीडिया का) वाहन उसका पीछा करना शुरू कर देता है। यह निजता में ताकझांक है। लिहाजा उन्होंने (अजित) जानबूझकर ऐसा (बारामती जाने वाला बयान) किया...अगर आप बातों को तोड़ना-मरोड़ना चाहते हैं, तो कल से यहां (पवार के आवास) न आएं।' वहीं, एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा कि बैठक चल रही है। साथ ही उन्होंने अफवाह नहीं फैलाने की अपील की। उधर भाजपा ने शिवसेना पर हिंदुत्व को लेकर तंज कसा जो विपरीत विचारधारा वाले दलों कांग्रेस और एनसीपी के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाने की संभावनाएं तलाश रही है। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे ने कहा, ये शिवसेना पर है कि वह कांग्रेस के साथ न्यूनतम साझा कार्यक्रम में अपने हिंदुत्व के एजेंडे को कैसे फिट करती है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में प्रकाशित एक संपादकीय में भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया गया है कि वह महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए अन्य दलों के संघर्ष से परपीड़क आनंद उठा रही है। एक संबंधित घटनाक्रम में कांग्रेस के विधायक बुधवार को जयपुर से वापस मुंबई लौट आए। वे पांच दिनों से जयपुर में एक रिजॉर्ट में ठहरे हुए थे। सरकार गठन के लिए और समय नहीं देने के महाराष्ट्र के राज्यपाल के फैसले को चुनौती देने वाली शिवसेना ने उच्चतम न्यायालय में अपनी याचिका का बुधवार को उल्लेख नहीं किया। पार्टी के वकीलों ने कहा कि राष्ट्रपति शासन लग जाने के कारण स्थिति बदल गई है और पार्टी ने याचिका का उल्लेख नहीं करने का फैसला किया।

जेएनयू ने...

ने छात्रावास शुल्क और अन्य नियमों को बहुत हद तक वापस लेने का फैसला किया है। आर्थिक रूप से कमजोर तबके (ईब्ल्यूएस) के छात्रों के लिए आर्थिक सहायता की एक योजना का भी प्रस्ताव किया गया है। कक्षाओं में लौटने का वक्त आ गया है। परिषद जेएनयू की फैसला लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष एन साई बालाजी ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव आर सुब्रमण्यम द्वारा फीस बढ़ोतरी वापस लेने की घोषणा को धोखा करार दिया। जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि ने भी कहा कि सही खबर मिलने पर ही कोई प्रतिक्रिया दी जा सकती है। अभी जो सूचना है, उसके अनुसार तो फीस बढ़ोतरी को सिर्फ छलावा ही कहा जा सकता है।

वाम दल समर्थित छात्र संगठनों के विद्यार्थी छात्रावास शुल्क में वृद्धि के खिलाफ करीब पखवाड़े भर से प्रदर्शन कर रहे थे। बुधवार को उन्होंने अपना आंदोलन और तेज कर दिया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने बुधवार को प्रशासन खंड के बाहर जेएनयू प्रशासन और कुलपति के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों ने सोमवार को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के बाहर उस समय उग्र प्रदर्शन किया था जब वहां जेएनयू का दीक्षांत समारोह चल रहा था। एआईसीटीई परिसर के अंदर मानव संसाधन विकास मंत्री छह घंटे तक फंसे रहे थे और पुलिस ने छात्रों को तितर-बितर करने के लिए पानी की तेज बौछारें छोड़ी थीं।

कर्नाटक की नाजायज एदियुरप्पा सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए : कांग्रेस

एजेंसी। नई दिल्ली

कांग्रेस ने कर्नाटक के 17 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने संबंधी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय को उच्चतम न्यायालय द्वारा बरकरार रखे जाने के बाद बुधवार को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह एवं मुख्यमंत्री बी एस एदियुरप्पा पर तीखा हमला बोला और कहा कि प्रदेश की नाजायज सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। पार्टी के संगठन महासचिव एवं कर्नाटक प्रभारी केसी वेणुगोपाल ने यह दावा भी किया कि न्यायालय के फैसले के बाद अब एदियुरप्पा मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार खो चुके हैं और ऐसे में राष्ट्रपति एवं भारत सरकार कर्नाटक की भाजपा सरकार को बर्खास्त करने के लिए तत्काल कदम उठाएं।

उन्होंने ट्वीट कर कहा, हम कर्नाटक में विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। इससे कांग्रेस के रुख की पुष्टि हुई है। यह फैसला सत्ता की भूखी भाजपा के मुंह पर जोरदार तमाचा है जिसने विधायकों की खरीद-फरोख्त की साजिश रची। वेणुगोपाल ने कहा, उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद बी एस एदियुरप्पा ने पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार खो दिया है। राष्ट्रपति एवं भारत सरकार को चाहिए कि वह कर्नाटक की भाजपा

सरकार को बर्खास्त करने के लिए तत्काल कदम उठाए। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एदियुरप्पा सरकार को बर्खास्त करने और विधायकों की कथित खरीद-फरोख्त के लिए चलाए गए ऑपरेशन कमल की जांच का साहस दिखा पाएंगे? उन्होंने ट्वीट कर दावा किया, उच्चतम न्यायालय के निर्णय ने कर्नाटक में ऑपरेशन कमल के ढोल की पोल खोल दी। अब साफ़ है कि भाजपा ने जद(एस)-कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को जबरन गिराया था। सुरजेवाला ने कहा, एदियुरप्पा सरकार क़ानून और संविधान की दृष्टि से एक नाजायज़ सरकार है और उसे फ़ौरन बर्खास्त कर देना चाहिए। उन्होंने यह मांग भी की, जनमत और प्रजातांत्रिक मूल्यों की माँग है कि न केवल नाजायज़ एदियुरप्पा सरकार बर्खास्त हो बल्कि विधायकों को धन बल के आधार पर ख़रीद कर चुनी हुई सरकार गिराने के भाजपाई षड्यंत्र की भी जांच हो। कांग्रेस नेता ने कहा, एदियुरप्पा टैप्स की जांच होनी चाहिए। ये सारा काला धन कहां से आया? भाजपा नेतृत्व की क्या भूमिका थी? उन्होंने सवाल किया, अब गेंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाले में है। क्या राजनीति की शुचिता की रोज़ दुहाई देने वाले मोदी जी अब नाजायज़ एदियुरप्पा सरकार को बर्खास्त करने का साहस दिखाएँगे? क्या ऑपरेशन कमल की निष्पक्ष जाँच होगी? क्या एदियुरप्पा और अमित शाह की भूमिका की जांच होगी? सुरजेवाला ने यह भी पूछा, क्या आप अब भी इन भगोड़े विधायकों को भाजपा का टिकट देंगे, जिन्हें उच्चतम न्यायालय ने अयोग्य घोषित किया है? उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी, अगर आपने ए चार कदम नहीं उठाए तो राजनीति की गँगा को मैली करने की जिम्मेदारी सदा के लिए आपकी है। कांग्रेस प्रवक्ता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा कि एदियुरप्पा को पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, भाजपा की सरकार ने पैसे के बल पर लोकतांत्रिक मूल्यों को नष्ट करने का प्रयास किया है। उच्चतम न्यायालय के फैसले ने विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष के फैसले पर 95 फीसदी सहमति जताई है। इससे जाहिर है कि पूरे देश में आपरेशन कमल चल रहा है। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष द्वारा 17 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के फैसले को बुधवार को बरकरार रखा लेकिन साथ ही विधायकों को पांच दिसंबर को उपचुनाव लड़ने की अनुमति भी दे दी।न्यायालय ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले का वह हिस्सा हालांकि हटा दिया जिसमें कहा गया था कि ए विधायक 15वीं कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने तक अयोग्य ही रहेंगे।

पटना में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भाग लेते जीतन राम मांझी, उपेन्द्र कुश्वाहा, उपेन्द्र सैनी एवं अन्य नेता

चक्रवात प्रभावित इलाकों के दौरे पर बाबुल सुप्रियो को दिखाए गए काले झंडे

एजेंसी। कोलकाता

केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो जब चक्रवात बुलबुल से प्रभावित इलाकों में स्थिति का जायजा लेने बुधवार को दक्षिण 24 परगना पहुंचे तो उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा और लोगों के एक समूह ने उन्हें वापस जाने के लिए कहा। सुप्रियो ने दावा किया कि प्रदर्शनकारी सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के कार्यकर्ता थे। उन्होंने मंगलवार को बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे पश्चिम बंगाल में चक्रवात प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए कहा है। उनके काफिले को चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में से एक नमखाना पहुंचने के फौरन बाद प्रदर्शनकारियों ने रोक दिया और उन्हें काले झंडे दिखाए। केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि वह जमीनी हकीकत का जायजा लेने जिले में आए हैं लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों ने उन्हें वापस जाने के लिए कहा। सुप्रियो ने कहा, मैं जानता था कि मुझे चक्रवात प्रभावित इलाकों के अपने दौरे के दौरान प्रदर्शनों का सामना करना पड़ेगा। सभी प्रदर्शनकारी टीएमसी के कार्यकर्ता थे।

राकांपा ने कांग्रेस के साथ संयुक्त समिति के लिए पांच सदस्यों को किया नामित

एजेंसी। मुंबई

राकांपा ने महाराष्ट्र में सरकार गठन के वास्ते शिवसेना के साथ संभावित गठबंधन से पहले साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर फैसला लेने के लिए कांग्रेस के साथ बनाई जाने वाली संयुक्त समिति के लिए अपने पांच सदस्यों को बुधवार को नामित किया। राकांपा के विधायक दल के नेता अजीत पवार, उसकी महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख जयंत पाटिल, पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल, मुंबई इकाई के अध्यक्ष नवाब मलिक और राज्य विधान परिषद में विपक्ष के नेता धनंजय मुंडे समिति का हिस्सा होंगे। राकांपा के विधायकों की बुधवार को यहां वाई बी चह्वाण केंद्र में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी के एक नेता ने कहा, राकांपा ने संयुक्त समिति का हिस्सा बनने वाले नेताओं को नामित किया है। कांग्रेस भी इस उद्देश्य के लिए अपने सदस्यों को नामित करेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख शरद पवार और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने मंगलवार को यहां मुलाकात की थी जिसके बाद समिति गठित की जा रही है। उन्होंने शिवसेना के साथ गठबंधन की संभावना पर काम करने से पहले साझा न्यूनतम कार्यक्रम (सीएमपी) तय करने की जरूरत जताई। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना ने भाजपा के साथ गठबंधन में 21 अक्टूबर को हुआ विधानसभा चुनाव लड़ा था लेकिन मुख्यमंत्री पद साझा करने की शिवसेना की मांग पर दोनों पार्टियां अलग हो गई। महाराष्ट्र में मंगलवार को राष्ट्रपति शासन लागू होने के साथ राकांपा और कांग्रेस इस पर बातचीत कर रही हैं कि क्या वह राज्य में वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए शिवसेना के साथ गठबंधन कर सकती हैं। पिछले महीने हुए राज्य विधानसभा चुनावों में 288 सदस्ईय सदन में भाजपा ने 105 सीटें, शिवसेना ने 56, राकांपा ने 54 और कांग्रेस ने 44 सीटें जीती। इस बीच, शरद पवार ने यहां विधानसभा परिसर में महाराष्ट्र के दिवंगत मुख्यमंत्री वसंत पाटिल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर वरिष्ठ राकांपा नेता और पार्टी विधायक मौजूद रहे।

क्विक न्यूज

तेजपाल मामला: बचाव पक्ष ने गोवा की अदालत में पीड़िता से की जिरह

पणजी। तहलका पत्रिका के संस्थापक तरुण तेजपाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला से बचाव पक्ष के वकील ने गोवा की अदालत में बुधवार को लगातार तीसरे दिन भी जिरह की। मामले की सुनवाई बंद कमरे में हो रही है। तेजपाल पर उनकी सहयोगी रह चुकी महिला ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए है। इस मामले की सुनवाई उत्तरी गोवा के मापुसा कस्बे में जिला न्यायाधीश क्षमा जोशी कर रही है। लोक अभियोजक फ्रांसिस्को तावोरा ने यहां संवाददाताओं से कहा, 23 अक्टूबर को स्थगन के बाद मामले में जिरह सोमवार को शुरू हुई। यह गुरुवार तक चलेगी। उन्होने बताया कि सुनवाई के दौरान तेजपाल अदालत में मौजूद थे। पिछले महीने पीड़िता से दो दिन की जिरह के बाद जिला अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी थी। महिला का आरोप है कि तेजपाल ने वर्ष 2013 में गोवा के एक पांच सितारा होटल में एक लिफ्ट के भीतर उसका कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया था। हालांकि, तेजपाल ने इन आरोपों से इनकार किया है। अपराध शाखा ने तेजपाल को 30 नवंबर 2013 को गिरफ्तार किया था।

हर्ष फायर की गोली लगने से दूल्हे के पिता की मौत

उज्जैन। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर रावली थानाक्षेत्र के एक गांव मे विवाह के उपलक्ष्य मे किए गए कथित हर्ष फायर की चपेट मे आने वाले दूल्हे के पिता की मौत हो गई। रावली पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक शंकर सिंह चौहान ने बुधवार को बताया कि जगोटी गांव मे आज सुबह विक्रम और गोवर्धन सिंह के पुत्रो के विवाह के उपलक्ष्य मे घर के लोग माता पूजन के लिए मंदिर जा रहे थे। उन्होने बताया कि इसी दौरान 12 बोर की बंदूक से एक हर्ष फायर किया गया और इस हर्ष फायर की गोली लगने से दूल्हे के पिता विक्रम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए जहां से अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। चौहान ने बताया कि पुलिस सम्बधितो से पूछताछ कर रही है। शव का पोस्टमार्टम उज्जैन के जिला चिकित्सालय मे कर के परिजन को सौप दिया गया है।

सुकमा जिले में मुठभेड़ में नक्सली कमांडर ढेर

रायपुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले मे सुरक्षा बलो ने गोलीबारी मे कुख्यात नक्सली कमांडर कड़ती मुत्ता को मार गिराया है और समाचार लिखे जाने तक अभियान जारी है। बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने आज भाषा को दूरभाष पर बताया कि सुकमा जिले के भेजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गच्चनपल्ली गांव के जंगल मे सुरक्षा बलो ने जनमिलिशिया कमांडर कड़ती मुत्ता को मार गिराया है। उन्होने बताया कि मुत्ता के सिर पर एक लाख रुपए का इनाम था।

सुंदरराज ने बताया कि भेजी थाना क्षेत्र मे सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन, एसटीएफ और डीआरजी के दल को नक्सल विरोधी अभियान मे रवाना किया गया था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुकमा डीआरजी का दल आज जब गच्चनपल्ली गांव के जंगल मे था तब नक्सलियो ने गोलीबारी शुरू कर दी और इसके बाद सुरक्षा बलो ने भी जवाबी कार्रवाई की।

गहलोत का आरोप: राज्यपाल ने स्थिरता के बजाय अस्थिरता पैदा कर दी

एजेंसी। जयपुर

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के राज्यपाल ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाकर स्थिरता कायम करने की बजाय अस्थिरता कायम कर दी।

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में संवाददाताओं से बातचीत में गहलोत ने कहा, महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बारे में हमारे हाईकमान के प्रतिनिधि आपस में चर्चा कर रहे हैं। फैसला क्या होगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा... पर यह अच्छा फैसला नहीं किया... राज्यपाल महोदय ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाकर स्थिरता कायम करने के बजाय अस्थिरता कायम कर दी। राज्यपाल की भूमिका के बारे में पूछे गए एक के सवाल पर गहलोत ने कहा, कि भाजपा शासन में पूरे देश में इन्होंने घमंड से राजनीति शुरू की है, उसमें आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि

महाराष्ट्र देश का एक महत्वपूर्ण राज्य है और उसमें अगर त्रिशंकु विधानसभा आ गई तो राज्यपाल का कर्तव्य था कि वह कम से कम तय करते कि स्थिति कैसे संभल सकती है और किस प्रकार स्थाई सरकार बन सकती है। उन्होंने कहा, (नारायण) राणे पहले कांग्रेस और शिवसेना में थे और अब वह भाजपा में हैं और कहते हैं कि हम तो साम, दाम, दंड, भेद कुछ भी कर सरकार बनाएंगे। आप सोच सकते हैं कि देश किस दिशा में जा रहा है। उस रूप में राजग सरकार देश को चला रही है। पूरा मुल्क देख रहा है कि इनको महाराष्ट्र और हरियाणा में झटका लग गया है तब भी अगर इनकी सोच नहीं बदली है तो आने वाले वक्त में जनता और सबक सिखाएगी। शिवसेना के साथ गठबंधन के सवाल पर गहलोत ने कहा, ऐसे फैसले अहम फैसले होते हैं, भविष्य को देख कर किए जाते हैं। हमें सत्ता का लोभ नहीं है पहले भी सरकारें आई और गई हैं परन्तु कांग्रेस चाहेगी कि स्थाई सरकार हो उसके लिए क्या कदम उठाते हैं, वो समय बताएगा। उन्होंने कहा कि देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग सत्ता में आकर बैठ गए हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से युवा पीढी को पंडित नेहरू के व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर गुमराह कर रहे हैं जबकि पंडित नेहरू के व्यक्तित्व और कृतित्व को पूरी दुनिया मान रही है, देश मान रहा है।

भोपाल में मध्य प्रदेश के राज्यपाल लाल जी टंडन से मिलकर उनको ज्ञापन सौंपते हुए भाजपा प्रतिनिधिमंडल के सदस्य

भाजपा ने राज्यपाल से की बर्खास्त विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता बहाल करने की मांग

एजेंसी। भोपाल

मध्य प्रदेश भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन से मांग की है कि पवई विधानसभा सीट के भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता रद्द करने के विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति के फैसले में हस्तक्षेप कर तत्काल उनकी सदस्यता बहाल करें। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार की दोपहर में राज्यपाल से उनके निवास पर मुलाकात की और उनको एक ज्ञापन सौंप कर मांग की कि लोधी के मामले में हस्तपेक्ष कर उनकी विधायकी बहाल करें।

मालूम हो कि 31 अक्टूबर को सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई कर रहे भोपाल के विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने प्रहलाद लोधी सहित 12 लोगों को रेत खनन के खिलाफ कार्वाई करने वाले सतना जिले की तहसील रैपुरा में पदस्थ तहसीलदार आर के वर्मा को 28 अगस्त 2014 को ग्राम मडवा के पास रोककर उसके साथ मारपीट और गालीगलोच करने के मामले में दोषी करार देते हुए दो साल की जेल और 3,500 रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। विशेष अदालत के निर्णय के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने दो नवंबर को लोधी की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी। लोधी ने दो साल की इस सजा पर रोक लगाने की अपील करते हुए 4 नवंबर को विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। इस पर अदालत ने उन्हें सात नवंबर को राहत देते हुए निचली अदालत के फैसले पर सात जनवरी 2020 तक रोक लगाने के साथ-साथ उन्हें जमानत दे दी। भाजपा नेताओं ने राज्यपाल को दिए गए ज्ञापन में कहा है कि लोधी को मिली दो साल की सजा पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है, इसलिए उनकी सदस्यता बहाल की जाए। मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि निचली अदालत से सजा सुनाए जाने के बाद उच्च न्यायालय में अपील के लिए प्रहलाद लोधी को एक महीने की मोहलत मिली थी। इसके बावजूद विधानसभा अध्यक्ष प्रजापति ने लोधी को दो साल की जेल की सजा सुनाए जाने के मात्र 48 घंटे के अंदर ही उसकी विधायकी रद्द की दी और चुनाव आयोग को पवई विधानसभा सीट रिक्त होने की जानकारी भी दे दी। उन्होंने कहा, विधानसभा अध्यक्ष केवल दल-बदल के मामले में विधायक को अयोग्य घोषित करने के संबंध में फैसला ले सकते हैं। सजा के मामले में चुनाव आयोग की सलाह पर राज्यपाल ही फैसला लेते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने जो निर्णय लिया वह पूर्णत: असंवैधानिक है। सिंह ने कहा कि इसके विपरीत उच्च न्यायालय द्वारा विशेष अदालत के फैसले पर रोक लगाए जाने के सात दिन बाद भी विधानसभा अध्यक्ष ने लोधी की सदस्यता बहाल नहीं की है। इसलिए हमने राज्यपाल से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। इस बीच, मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता भूपेन्द्र गुप्ता ने लोधी की सदस्यता खत्म करने के प्रजापति के निर्णय को सही ठहाराया है।

मूल सिद्धांतों को कायम रखते हुए महाराष्ट्र में सरकार बनाने में सहयोग करेगी कांग्रेस : पांडे

एजेंसी। जयपुर

कांग्रेस महासचिव अविनाश पांडे ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर तथा अपने मूल सिद्धांतों व मूल्यों को बनाए रखते हुए महाराष्ट्र में शिवसेना व राकांपा के साथ सरकार बनाने में अपनी मुख्य भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन को लेकर जल्द ही शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और राकांपा प्रमुख शरद पवार के साथ विचार विमर्श करेगा।उन्होंने यहां एक रिसार्ट में संवाददाताओं से कहा, महाराष्ट्र की जनता ने चार दलों को खंडित जनादेश दिया है और वहां एक गठबंधन सरकार की जरूरत है। नई सरकार के गठन में कांग्रेस क्या भूमिका निभा सकती है इसको लेकर हमारी चर्चा हुई है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के कुछ नवनिर्वाचित विधायक शुक्रवार से इस रिसार्ट में रुके हुए थे और वे आज वापस रवाना हो गए। उन्होंने कहा, इस पर दिल्ली में कांग्रेस की कार्यसमिति में चर्चा हुई जहां पार्टी नेताओं ने अपनी राय व नवनिर्वाचित विधायकों के सुझावों से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अवगत कराया। यह तय किया गया कि कांग्रेस अपने मूल मूल्यों और सिद्धांतों पर बने रहते हुए, महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन में समर्थन करेगी ताकि भाजपा को दूर रखा जा सके। पांडे ने बताया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल ने इस बारे में कल मुंबई में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ विचार-विमर्श किया और यह तय किया गया कि नई सरकार के गठन के लिए विचार-विमर्श एक-दो दिन में पूरा कर लिया जाएगा।

लड़ाई जमीन की नहीं, उसूल और हक की थी : मौलाना अरशद मदनी

एजेंसी। नई दिल्ली

अयोध्या मामले में पक्षकार प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा ए हिन्द के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय का फैसला समझ से परे है, लेकिन हम इसका सम्मान करते हैं। मदनी ने कहा कि शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने पर बृहस्पतिवार को जमीयत की कार्य समिति की बैठक में निर्णय किया जाएगा।

मौलाना मदनी ने भाषा को दिए साक्षात्कार में कहा कि शरियत के लिहाज से बाबरी मस्जिद की हैसियत देश में मौजूद अन्य मस्जिदों से ज्यादा नहीं है, लेकिन लड़ाई हक की थी, जो हमने 70 साल तक लड़ी। जमीयत प्रमुख ने कहा, इस्लाम में शरीयत के मुताबिक सिर्फ तीन मस्जिदें अहमियत रखती हैं। उनमें मक्का की मस्जिद अल हराम (खाना ए काबा), मदीना की मस्जिद ए नबवी और यरुशलम में स्थित बैत उल मुकद्दस। उन्होंने कहा, इनके बाद सारी मस्जिदें बराबर हैं और शरीयत के लिहाज से बाबरी मस्जिद की हैसियत भी देवबंद के किसी कोने में बनी मस्जिद से ज्यादा नहीं है। जमीयत उलेमा हिन्द की स्थापना 1919 में हुई थी। यह भारत के मुस्लिम उलेमा (धर्मगुरुओं) का संगठन है। इस संगठन ने 1919 में खिलाफत आंदोलन को चलाने में अहम भूमिका निभाई थी और आजादी की लड़ाई में योगदान दिया था। भारत में मुसलमानों के सबसे बड़े संगठनों में इसकी गिनती होती है। मदनी का कहना था कि यह लड़ाई उसूल और हक की थी। उन्होंने कहा, ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी मस्जिद में जबरन मूर्तिया रखी गई हों और उसे तोड़ा हो गया हो। यह बात उच्चतम न्यायालय ने भी मानी है कि मस्जिद में मूर्तियां रखना और उसे तोड़ना गैर कानूनी और जुर्म है। मदनी ने कहा अदालत ने यह सारी बातें मानी हैं और फिर भी जमीन हिन्दू पक्षकारों को दे दी। इसलिए हम कहते हैं कि यह फैसला हमारी समझ से परे हैं। हमने सारे सबूत अदालत में पेश किए थे और उम्मीद की थी कि अदालत सुबूतों के आधार पर फैसला देगी न कि आस्था के आधार पर। मगर अदालत ने आस्था के आधार पर फैसला दिया। उन्होंने कहा, देश का मुसलमान भारत की न्यायिक व्यवस्था में पूरा यकीन रखते हुए इस फैसले का पूरा एहतराम (सम्मान) करता है। प्रमुख मुस्लिम नेता ने कहा, उच्चतम न्यायायलय ने माना है कि मुसलमानों ने बाबर के जमाने में मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई थी। यह हमारे लिए खुशी की बात है। न्यायालय द्वारा पांच एकड़ जमीन मुस्लिम पक्षकारों को देने पर उन्होंने कहा, अगर हमें पांच-10 एकड़ जमीन चाहिए होती तो हम 70 साल तक मुदकमा नहीं लड़ते। मुसलमानों के पास जमीन की कमी नहीं है। हमने अपनी जमीनों पर मस्जिदें बनाई हैं और आगे भी बनाएंगे। जमीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दी गई है। अगर हमें दी जाती तो हम लेने से इनकार कर देते। इस सवाल पर कि मुस्लिम समुदाय इस फैसले को कैसे देखता है, मौलाना मदनी ने कहा, यह बहुत अच्छी बात है कि फैसला खिलाफ आने के बावजूद मुसलमानों ने किसी तरह का कोई विरोध नहीं किया और अपने जज्बातों पर काबू रखा। उम्मीद है कि आगे भी ऐसा ही रहेगा। उन्होंने यह भी कहा, फैसला हक में आने के बाद भी हिन्दू समुदाय ने जीत का जुलूस नहीं निकाला जो देश में अमन रखने के लिए अहम है और उन्होंने अपनी समझदारी का सुबूत दिया। गौरतलब है कि, एक सदी से भी पुराने बाबरी मस्जिद-राम जन्म भूमि मामले का उच्चतम न्यायालय ने बीते शनिवार को निपटारा कर दिया। विवादित भूमि हिन्दुओं को दे दी और मुसलमानों को कहीं और पांच एकड़ जमीन देने का निर्देश दिया है।

सीतारमण पर प्रियंका का तंज, जब जागे तभी सवेरा

एजेंसी। नई दिल्ली

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने औद्योगिक उत्पादन में गिरावट एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एक बयान को लेकर बुधवार को यह कह कर कटाक्ष किया कि सीतारमण ने आखिरकार मान लिया कि देश में मंदी है। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा, ओला-उबर थ्योरी और फिल्म हिट होने की थ्योरी के बुरी तरह से फ्लॉप होने के बाद अब सरकार की वित्त मंत्री ने मंदी के बारे में क़बूलनामा दिया है। कल पहली बार उनको लगा कि मंदी है।

उन्होंने तंज कसते हुए कहा, चलिए जब जागे तभी सवेरा। दरअसल, हाल ही में सीतारमण ने कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में कुछ चुनौतियों का सामना कर रही है।प्रियंका का तंज सीतारमण के साथ साथ केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के कथित बयान को लेकर भी है।

अर्थव्यवस्था की चिंता

अमेरिका-चीन व्यापार समझौते को लेकर भ्रम से सेंसेक्स 229 अंक टूटा

एजेंसी। मुंबई

घरेलू शेयर बाजारों में बुधवार को चौतरफा बिकवाली देखी गई। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट, डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर होने तथा अमेरिका-चीन व्यापार समझौते को लेकर भ्रम बढ़ने से निवेशकों की चिंता बढ़ गई जिससे बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 229 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ। हांगकांग में जारी विरोध प्रदर्शन का भी क्षेत्रीय शेयर बाजारों पर असर रहा।

तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स बुधवार को कारोबार की समाप्ति पर 229.02 अंक यानी 0.57 प्रतिशत गिरकर 40,116.06 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सूचकांक 386 अंक के दायरे में रहा। इसी प्रकार, नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी 73 अंक यानी 0.61 प्रतिशत की गिरावट के साथ 11,840.45 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के शेयरों में सर्वाधिक नुकसान यस बैंक को हुआ। इसमें 6.51 प्रतिशत की गिरावट आई। उसके बाद क्रमश: एसबीआई, एक्सिस बैंक, वेदांता, सन फार्मा, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, आईटीसी, इन्फोसिस तथा टेक महिंद्रा का स्थान रहा जिसमें 3.69 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई।

वहीं दूसरी तरफ टीसीएस, आरआईएल, एचयूएल, मारुति और एनटीपीसी 3.76 प्रतिशत तक की बढ़त के साथ बंद हुए। कमजोर आर्थिक आंकड़ों से निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई। आंकड़ा नरमी को बताता है और पुनरूद्धार के लिए और सुधारों की जरूरत को बताता है। सोमवार को जारी आधिकारिक आंकड़े के अनुसार औद्योगिक उत्पादन सितंबर में 4.3 प्रतिशत घटा जो सात साल में सबसे कमजोर प्रदर्शन रहा है। विनिर्माण, खनन और बिजली क्षेत्रों में गिरावट के कारण औद्योगिक उत्पादन घटा है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, हाल की तेजी के बाद मूल्यांकन और आय वृद्धि का फासला बढ़ा है। निवेशक इस सप्ताह आने वाले आर्थिक आंकड़ों को देखते हुए थोड़े सतर्क हैं। कमजोर आर्थिक आंकड़ा तथा आय वृद्धि में नरमी को लेकर चिंता से निवेशकों की धारणा प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि आरबीआई के लगातार पांच बार नीतिगत दर में कटौती के बावजूद बुनियादी उद्योग की वृद्धि स्थिर बनी हुई वहीं मुद्रास्फीति में तेजी देखी जा रही है। इसको देखते हुए आरबीआई भविष्य में सतर्क रह सकता है। इस बीच, बुधवार को जारी सरकारी आंकड़े के अनुसार खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर में उछलकर 4.62 प्रतिशत पहुंच गई जबकि सितंबर में यह 3.99 प्रतिशत थी। इसके अलावा एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट में जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर 2019-20 में 5 प्रतिशत रहने के अनुमान का भी बाजार पर प्रभाव पड़ा। पूर्व में एसबीआई रिसर्च ने आर्थिक वृद्धि दर 6.1 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया था। इससे अर्थव्यवस्था की सेहत को लेकर चिंता बढ़ी है। विदेशी मुद्रा बाजार में कारोबार के दौरान अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 57 पैसे लुढ़ककर 72.04 तक नीचे चला गया। इसका भी बाजार पर असर पड़ा। अमेरिका-चीन के बीच व्यापार समझौते को लेकर भ्रम की स्थिति बने रहने से भी बाजार पर असर पड़ा। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को व्यापार के मामले में धोखेबाज कहा जबकि दूसरी तरफ 18 महीनों से जारी व्यापार युद्ध को समाप्त करने के लिए शुरूआती समझौते पर जोर दिया। इससे दोनों देशों के बीच समझौते को लेकर अनिश्चितता बढ़ी है। उधर, हांगकांग में उग्र विरोध प्रदर्शन के कारण शंघाई, हांगकांग, तोक्यो और सोल 1.82 प्रतिशत तक गिरावट के साथ बंद हुए। शुरूआती कारोबार में यूरोप के प्रमुख बाजारों में गिरावट का रुख रहा।

बने फ्लैटों का स्टॉक निकालने में दिल्ली-एनसीआर के बिल्डरों को लगेंगे 44 महीने : रिपोर्ट

एजेंसी। नई दिल्ली

रीयल एस्टेट डेवलपर्स को अपने बने फ्लैटों का स्टॉक निकालने में काफी समय लग रहा है। संपत्ति क्षेत्र की सलाहकार एनारॉक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बने मकानों का स्टॉक निकालने में बेंगलुरु के बिल्डरों को सबसे कम 15 माह का समय लगेगा। वहीं दिल्ली-एनसीआर के बिल्डरों को अपने बन चुके फ्लैटों को बेचने में साढ़े तीन साल से अधिक यानी 44 महीने लगेंगे।

सितंबर तिमाही के अंत तक सात प्रमुख शहरों, दिल्ली-एनसीआर, मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर), चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में बन चुके लेकिन बिक नहीं पाए फ्लैटों की संख्या 6.56 लाख थी। शीर्ष सात शहरों में 2019 की तीसरी तिमाही तक फ्लैटों का 30 महीने का स्टॉक था। एक साल पहले समान अवधि में यह 37 माह था। देश की आईटी राजधानी बेंगलुरु में फ्लैटों का स्टॉक निकालने में सबसे कम यानी 15 महीने का समय लगेगा। वहीं एनसीआर में सबसे अधिक यानी 44 माह का समय लगेगा। मौजूदा बाजार परिदृश्य से इस बात का संकेत मिलता है कि फ्लैटों के स्टॉक को निकालने में कितना समय लगेगा। एनारॉक के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा कि अब बिल्डर अपना स्टॉक निकाले पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसके अलावा बिल्डरों ने बाजार में अपनी आपूर्ति भी सीमित कर दी है। चेन्नई में बन चुके फ्लैटों को निकालने में 31 महीने, मुंबई महानगर क्षेत्र में 34 महीने और कोलकाता में 38 माह का समय लगेगा। एनसीआर इस समय देश का सबसे अधिक प्रभावित आवासीय बाजार है। यहां फ्लैटों के स्टॉक को निकालने में कम से कम 44 माह का समय लगेगा। हालांकि, 2018 की तीसरी तिमाही में यह 58 माह था। आंकड़ों के अनुसार 2019 की तीसरी तिमाही के अंत तक शीर्ष सात शहरों में कुल मिलाकर बिक नहीं फ्लैटों की संख्या 6.56 लाख थी।

बीबीबी ने सार्वजनिक क्षेत्र के तीन बैंकों के प्रमुखों के लिए नामों की सिफारिश की

एजेंसी। नई दिल्ली

बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) ने सार्वजनिक क्षेत्र के तीन बैंकों के प्रमुखों के पद के लिए नाम सुझाए हैं। बैंक आफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के पद के लिए संजीव चड्ढा के नाम की सिफारिश की गई है। वहीं केनरा बैंक के प्रमुख के लिए एल वी प्रभाकर और बैंक आफ इंडिया के लिए अतनु कुमार दास का नाम सुझाया गया है। बीबीबी ने यह चयन मंगलवार को हुए साक्षात्कार के आधार पर किया है। बीबीबी ने बयान में कहा कि पात्रता के आधार पर बैंक आफ बड़ौदा, केनरा बैंक और बैंक आफ इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के नामों की सिफारिश की गई है।

इसके अलावा बैंक आफ महाराष्ट्र के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ए एस राजीव और करुड़ वैश्य बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ पी आर शेषाद्रि का नाम आरक्षित सूची में रखा गया है। चड्ढा फिलहाल एसबीआई कैपिटल मार्केट्स के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ हैं। यह भारतीय स्टेट बैंक की मर्चेंट एवं निवेश बैंकिंग इकाई है। प्रभाकर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में कार्यकारी निदेशक हैं। दास अभी बैंक आफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक हैं। उन्हें पदोन्नत कर मुंबई के इस बैंक का प्रबंध निदेशक बनाने की सिफारिश की गई है। दीनबंधु महापात्रा के एक जुलाई को सेवानिवृत्त होने के बाद से बैंक आफ इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का पद रिक्त है। वहीं बैंक आफ बड़ौदा के प्रमुख पी एस जयकुमार का एक साल का सेवा विस्तार अक्टूबर में समाप्त हो गया है। सरकार ने बैंक में दो छोटे सरकारी बैंकों, देना बैंक और विजया बैंक के विलय की वजह से जयकुमार को कार्यकाल विस्तार दिया था। इस बीच, केनरा बैंक में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का पद 31 जनवरी को रिक्त होगा। बीबीबी द्वारा सुझाए गए नामों की नियुक्ति का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति करेगी। बीबीबी के प्रमुख कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पूर्व सचिव बी पी शर्मा हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में बीबीबी के गठन की मंजूरी दी थी। इसमें पेशेवरों और अधिकारियों को शामिल किया गया है। बीबीबी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों के साथ गैर कार्यकारी चेयरपर्सन के नामों पर सुझाव देता है।

भीम यूपीआई का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहली बार सिंगापुर में प्रदर्शन

एजेंसी। सिंगापुर

भुगतान सुविधा उपलब्ध कराने वाले मंच भीम यूपीआई की क्यूआर आधारित भुगतान व्यवस्था का बुधवार को सिंगापुर में पायलट आधार पर प्रदर्शन शुरू किया गया। सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल 2019 में एक मर्चेंट टर्मिनल पर लेनदेन के जरिए भीम यूपीआई का प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन इस महोत्सव के दौरान जारी रहेगा और 15 नवंबर को बंद होगा। क्यूआर आधारित प्रणाली के जरिए भीम एप के साथ कोई भी नेट्स टर्मिनल पर एसजीक्यूआर कोड को स्कैन कर सिंगापुर में भुगतान कर सकता है। सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त जावेद अशरफ ने कहा कि यह पहला मौका है जबकि भीम एप अंतरराष्ट्रीय हुआ है। उन्होंने भीम एप के लाइव डेमो की शुरुआत की। इस परियोजना का नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन आफ इंडिया (एनपीसीआई) तथा सिंगापुर के नेटवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स (नेट्स) ने संयुक्त रूप से विकास किया है। उच्चायुक्त ने कहा कि इसे यहां फरवरी, 2020 तक शुरू करने का लक्ष्य है। उच्चायोग ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि फरवरी, 2020 तक सभी रूपे कार्ड (घरेलू सहित) सिंगापुर में स्वीकार किए जाएंगे। यह वित्तीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और सिंगापुर के बीच सहयोग की एक और उपलब्धि है।

कंपनी सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन कल से जयपुर में

जयपुर। कंपनी सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन 14 नवंबर से जयपुर में होगा जिसमें देश भर से 2000 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) के अध्यक्ष रंजीत पांडेय ने बुधवार को बताया कि कंपनी सचिवों का तीन दिवसीय 47वां राष्ट्रीय सम्मेलन यहां 14 से 16 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में देश भर के कंपनी सचिव विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस सम्मेलन की थीम एम्पावरिंग न्यू इंडिया-रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म रखी गई है और इसमें देश भर के 2000 कंपनी सचिवों व इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के भाग लेने की संभावना है।

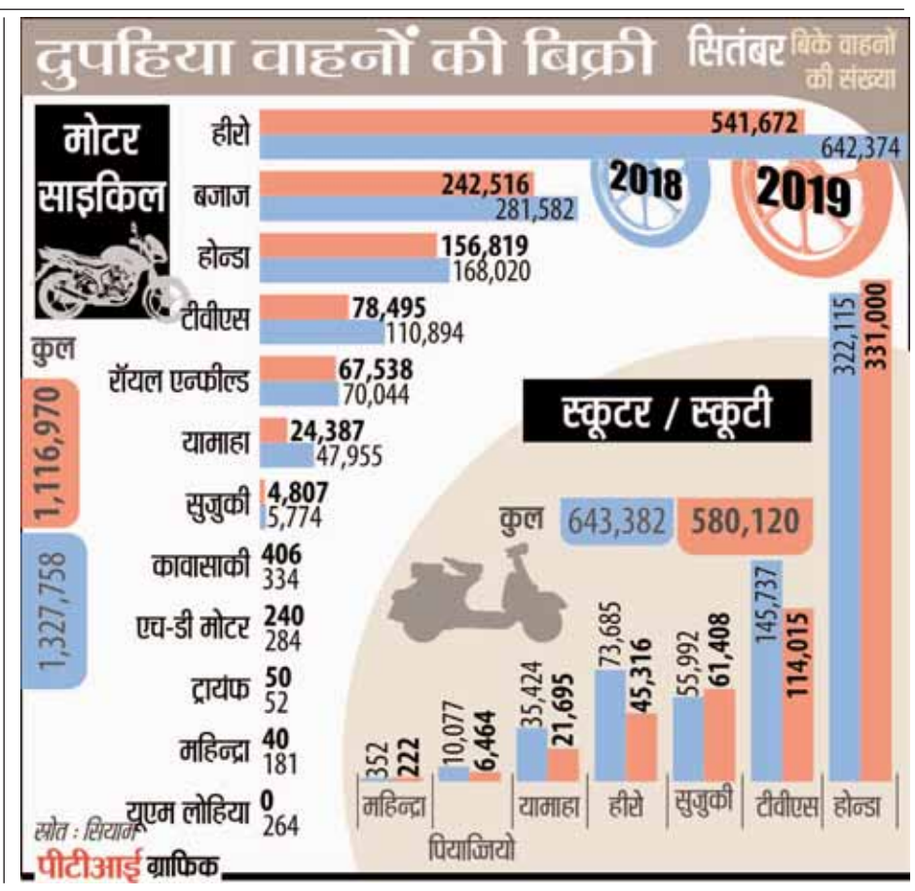

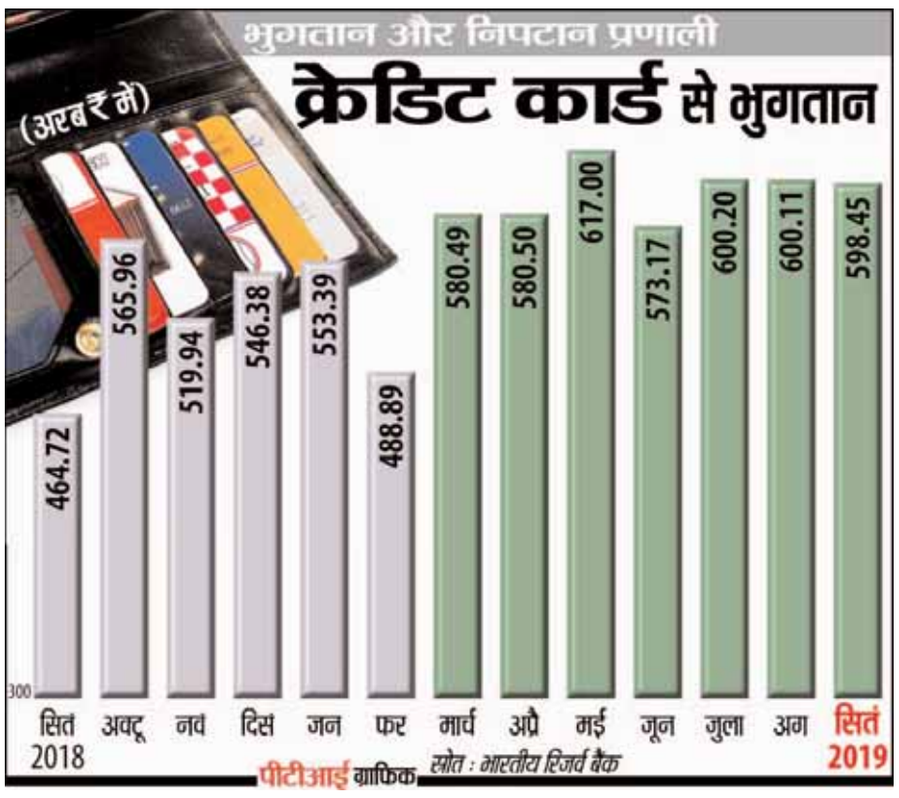

बजट 2020: वित्त मंत्रालय ने आयकर, अन्य शुल्कों को तर्कसंगत बनाने को लेकर मांगे सुझाव

एजेंसी। नई दिल्ली

वित्त मंत्रालय ने अगले बजट की तैयारी शुरू करते हुए उद्योग और व्यापार संघों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में बदलाव के बारे में उनके सुझाव मांगे हैं। संभवत: यह पहली बार है जबकि वित्त मंत्रालय ने इस तरह के सुझाव मांगे हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2020-21 का बजट एक फरवरी 2020 को पेश करेंगी। सीतारमण ने अपने पहले बजट को संसद की मंजूरी के एक महीने के भीतर सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए अतिरिक्त उपायों की घोषणा की। मंत्रालय जहां विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों और अंशधारकों के साथ बजट पूर्व विचार विमर्श करता है। संभवत: यह पहली बार है जबकि वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने सर्कुलर जारी कर व्यक्तिगत लोगों और कंपनियों के लिए आयकर दरों में बदलाव के साथ ही उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क जैसे अप्रत्यक्ष करों में बदलाव के लिए सुझाव मांगे हैं। 11 नवंबर को जारी इस सर्कुलर में उद्योग और व्यापार संघों से शुल्क ढांचे, दरों में बदलाव और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए कर दायरा बढ़ाने के बारे में सुझाव आमंत्रित किए हैं।

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जो भी सुझाव दिए जाएं, वे आर्थिक रूप से उचित होने चाहिए। सर्कुलर में कहा गया है, आपके द्वारा दिए गए सुझाव और विचारों के साथ उत्पादन, मूल्य, बदलावों के राजस्व प्रभाव के बारे में सांख्यिकी आंकड़े भी दिए जाने चाहिए। सीतारमण ने पांच जुलाई को अपने पहले बजट के बाद 20 सितंबर को घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट कर की दर को 30 से घटाकर 22 प्रतिशत करने की घोषणा की थी। इससे सभी तरह के अतिरिक्त शुल्कों को शामिल करने के बाद प्रभावी कॉरपोरेट कर की दर 25.2 प्रतिशत पर पहुंचती है। इसके साथ ही एक अक्टूबर के बाद स्थापित होने वाली सभी विनिर्माण कंपनियों के लिए कर की दर को 15 प्रतिशत रखा गया है। इसमें अतिरिक्त कर और अधिभार सहित यह दर 17 प्रतिशत तक पहुंच जाती है। इसके साथ ही व्यक्तिगत आयकर की दर को घटाने की मांग भी उठी थी जिससे आम आदमी के हाथ में अधिक पैसा बचे और उपभोग बढ़ाकर देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सके।

वेदांता सेज ने स्थानीय स्तर पर पेट्रोलियम कोक खरीदने की मंजूरी मांगी

नई दिल्ली। वेदांता विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ने सरकार से ओड़िशा में स्थानीय रूप से कैलसिनेड पेट्रोलियम कोक खरीदने की अनुमति मांगी है। कंपनी इसका उपयोग अपनी इकाई में एल्युमीनियम इनगॉट्स तथा वॉयर राड के विनिर्माण में करेगी। कंपनी के अनुरोध पर मंजूरी बोर्ड 15 नवंबर को विचार करेगा। मंजूरी बोर्ड सेज के बारे में निर्णय लेने वाला उच्च निकाय है। इस अंतर मंत्रालई मंजूरी बोर्ड के अध्यक्ष वाणिज्य सचिव हैं। कंपनी ने यह मंजूरी इसीलिए मांगी है क्योंकि सेज के बाहर किसी भी सामग्री की खरीद को आयात माना जाता है। सीमा शुल्क नियमों के तहत सेज को विदेशी इकाई माना जाता है। आयातित पेट्रोलियम कोक का उपयोग ईंधन मकसद से प्रतिबंधित है। मंजूरी बोर्ड के एजेंडा पत्र के अनुसार, इकाई ने अपने अधिकृत परिचालन को लेकर कैलसीनेड पेट्रोलियम की स्थानीय बाजार से खरीद की मंजूरी का आग्रह किया है। लेकिन वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के तहत पेट्रोलियम कोक प्रतिबंधित जिंस है। हालांकि, कंपनी ने कहा कि ओड़िशा के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेज इकाई को स्वदेशी स्रोत से कोक खरीदने की अनुमति दे दी है। कंपनी के अनुसार यूनिट को कच्चे माल के रूप में इस कोक की जरूरत है। वह इसका उपयोग एल्युमीनियम इनगॉट्स, वॉयर रड और बिलेट बनाने में करेगी। सेज से 2018-19 में 7 लाख करोड़ रुपए का निर्यात कारोबार किया गया।

आयातित कारों पर अतिरिक्त शुल्क के फैसले को टाल सकता है अमेरिका

वाशिंगटन। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन आयातित कारों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के अपने फैसले को इस सप्ताह टालने की घोषणा कर सकता है। उद्योग सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने कहा कि इस फैसले को छह माह के लिए और टाला जा सकता है। इसकी घोषणा बुधवार को ही या बाद में की जा सकती है। अमेरिका के वाहन विनिर्माण क्षेत्र को राहत के लिए ट्रंप प्रशासन पिछले साल से वाहनों के आयात पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाने की चेतावनी देता रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति इससे पहले मई में भी वाहनों पर शुल्क के फैसले को 180 दिन के लिए टाल चुके हैं। अमेरिका की इस चेतावनी के बाद यूरोपीय कार उद्योग विशेषरूप से जर्मनी में अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई थी। सितंबर में ट्रंप प्रशासन की जापान के साथ वाहन शुल्क को स्थगित रखने पर सहमति बनी थी। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी रही थी। इसी तरह पिछले साल अमेरिका की दक्षिण कोरिया के साथ सहमति बनी थी। इसमें दक्षिण कोरिया ने अपने बाजार को अमेरिकी वाहन विनिर्माताओं के लिए और खोलने का वादा किया था।

व्यापार संवर्धन परिषद ने एसएमई की मदद के लिए सिंगापुर के प्राधिकरण से किया गठजोड़

नई दिल्ली। भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद (टीपीसीआई) ने बुधवार को कहा कि घरेलू क्षेत्र के छोटे एवं मध्यम उपक्रमों (एसएमई) से निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए उसने सिंगापुर स्थित मॉनिटरी अथॉरिटी से हाथ मिलाया है। परिषद ने एक बयान में कहा कि एसएमई को विभिन्न देशों के क्रेताओं-विक्रेताओं से जुड़ने, सीमा शुल्क की मंजूरियां पाने में निर्यातकों की मदद करने, वित्तीय विकल्प आदि सेवाएं मुहैया कराने के लिए एक मंच तैयार किया जाएगा। परिषद के चेयरमैन मोहित सिंगला ने कहा, हम इसकी डिजिटल बुनियादी संरचना तैयार कर चुके हैं और अत्याधुनिक वित्तीय प्रौद्योगिकी प्रणाली का इस्तेमाल कर निर्यात संवर्धन के विचार का लाभ उठाने के लिए उत्साहित हैं। यह मंच उपक्रमों को माल की मांग एवं आपूर्ति संबंधी आंकड़ों को अपलोड करने की भी सुविधा देगा। उन्होंने कहा कि मंच किसी व्यापार को तभी स्वीकार करेगा जब उपक्रमों की मांग एवं आपूर्ति में मेल होगा। यह साम्यता वाले व्यापार में लेन-देन पूरा करेगा।

जावड़ेकर ने भारी उद्योग एवं लोक उपक्रम मंत्रालय का कार्यभार संभाला

नई दिल्ली। प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को केंद्रीय भारी उद्योग एवं लोक उपक्रम मंत्री का कार्यभार संभाल लिया। दो दिन पहले शिवसेना नेता अरविंद सावंत ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद जावड़ेकर को इस मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया। जावड़ेकर के पास पहले से सूचना एवं प्रसारण, पर्यावरण तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भी हैं। जावड़ेकर ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह अतिरिक्त प्रभार अस्थाई अवधि के लिए होगा। इसके लिए जल्द नियमित व्यवस्था हो जाएगी। जावड़ेकर ने कहा, मैंने भारी उद्योग और संबंधित मंत्रालयों का प्रभार संभाल लिया है। मुझे उम्मीद है कि यह अस्थाई व्यवस्था है। मैं आज से ही कामकाज करना शुरू कर दूंगा। सावंत ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा पर आरोप लगाया था कि वह शिवसेना को सीटों और सत्ता में समान भागीदारी देने के अपने वादे से पीछे हट रही है। उन्होंने भाजपा पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात सितंबर में छह प्रतिशत घटा: ईईपीसी इंडिया

एजेंसी। नई दिल्ली

देश का इंजीनियरिंग निर्यात सितंबर महीने में 6 प्रतिशत से अधिक घटकर 6.36 अरब डॉलर रहा। यह लगातर चौथा महीना है जब निर्यात में गिरावट दर्ज की गई। इससे पूर्व वित्त वर्ष के इसी महीने में यह 6.77 अरब डॉलर था। ईईपीसी इंडिया ने बुधवार को यह कहा। देश का इंजीनियरिंग निर्यात का देश के कुल निर्यात में योगदान 25 प्रतिशत है।इंजीनियरिंग निर्यात संवर्द्धन परिषद (ईईपीसी) के अनुसार वैश्विक स्तर पर नरमी का इंजीनियरिंग निर्यात पर स्पष्ट प्रभाव दिख रहा है। अमेरिका, यूरोपीय संघ, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया या स्वतंत्र राष्ट्रकुल देशों समेत सभी प्रमुख निर्यात गंतव्यों से क्षेत्र को झटका लग रहा है।

इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात सितंबर महीने में 6 प्रतिशत घटा। यह लगातार चौथा महीना है जब इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में गिरावट आई है। वहीं चालू वित्त वर्ष 2019-20 में यह पांचवा मौका है जब इसमें गिरावट दर्ज की गई। ईईपीसी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में सितंबर महीने में भारतीय इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात 6.36 अरब डॉलर रहा जो इससे पूर्व वित्त वर्ष के इसी महीने में 6.77 अरब डॉलर था। वित्त वर्ष 2019-20 के अप्रैल-सितंबर के दौरान इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात 3.77 प्रतिशत घटकर 38.74 अरब डॉलर रहा जो इससे पूर्व वित्त वर्ष की इसी अवधि में 40.26 अरब डॉलर था। परिषद के चेयरमैन रवि सहगल ने कहा, ज्यादातर बाजारों के आंकड़े से नरमी के संकेत मिलते हैं। इस भारतीय निर्यातकों के लिए बड़ी चुनौती है। सभी प्रमुख पक्षों...निर्यातक समुदाय, सरकार, आरबीआई तथा नीति आयोग को निर्यात को गति देने के लिए साथ मिलकर काम करने और नए सिरे से रणनीति बनाने की जरूरत है।

आकाश एजुकेशनल सर्विसेज, सैमसंग ने रणनीतिक भागीदारी पर किया समझौता

चेन्नई। टीवी, फ्रीज जैसे इलेक्ट्रिक सामान बनाने वाली दक्षिण कोरिया की कंपनी सैमसंग के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाली संस्थान आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लि. ने रणनीतिक भागीदारी की है। इस गठजोड़ का मकसद छात्रों को डिजिटल तरीके से शिक्षा उपलब्ध कराना है। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड (एईएसएल) ने बुधवार को एक बयान में कहा कि इस भागीदारी से उपकरणों के जरिए छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा के माहौल से अवगत कराने में मदद मिलेगी। इस तरह के उपकरणों को सैमसंग उपलब्ध कराएगी।

सिंगापुर की कंपनियों, आंध्र प्रदेश सरकार ने अमरावती राजधानी परियोजना को निरस्त किया

सिंगापुर। सिंगापुर की कंपनियों के एक समूह तथा आंध्र प्रदेश सरकार ने अरबों डॉलर की अमरावती राजधानी शहर परियोजना को आपसी सहमति से रद्द कर दिया। इस परियोजना का विचार पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू का था और इसकी अनुमानित लागत 15 अरब सिंगापुर डॉलर थी। नायडू मई में चुनाव हार गए। सिंगापुर के व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि यह निर्णय आंध्र प्रदेश सरकार और कंपनियों के समूह ने आपसी सहमति से लिया। इस समूह में एसेंडास सिंगापुर और सेम्बकॉर्प डेवलपमेंट शामिल थीं। एसेंडास सिंगापुर अब कैपिटललैंड ग्रुप का हिस्सा है।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने सोमवार को एक सरकारी आदेश में परियोजना को बंद करने का निर्णय लिया। राज्य के व्यापार संबंधों के प्रभारी मंत्री एस. ईश्वरन ने कहा कि एसेंडास-सेम्बकॉर्प के समूह को 2017 में तत्कालीन राज्य सरकार ने 6.84 वर्गकिलोमीटर का क्षेत्र विकसित करने के लिए नियुक्त किया था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अन्य प्राथमिकताओं को देखते हुए इस परियोजना को बंद करने का निर्णय लिया है। मंत्री के अनुसार, सिंगापुर की कंपनियों के समूह ने कहा है कि इस परियोजना पर उनके कुछ लाख डॉलर की खर्च हुए हैं और इसके बंद होने से देश में निवेश की उसकी योजनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

प्रधानमंत्री मोदी को ब्रिक्स सम्मेलन से आर्थिक व सांस्कृतिक संबंध मजबूत होने की उम्मीद

● प्रधानमंत्री 11 वें ब्रिक्स सम्मेलन से इतर ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो के साथ बैठक करेंगे और द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे

एजेंसी। ब्रासीलिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को यहां पहुंचने पर उम्मीद जताई कि ब्रिक्स सम्मेलन सदस्य देशों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करेगा।

प्रधानमंत्री मोदी दो दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए यहां आए हैं। मोदी ने यहां अपने आगमन के बाद ट्वीट किया, ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ब्राजील पहुंचा। यात्रा के दौरान विश्व के कई नेताओं से भी मुलाकात करूंगा। प्रधानमंत्री 11 वें ब्रिक्स सम्मेलन से इतर ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो के साथ बैठक करेंगे और द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री का बुधवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ भी अलग-अलग बैठकें करने का कार्यक्रम है। उन्होंने कहा, मैं आश्वस्त हूं कि ब्रिक्स सम्मेलन ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच सांस्कृतिक एवं आर्थिक संबंधों को बढ़ाएगा।

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रासीलिया पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया

ब्रिक्स विश्व की पांच उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। इस साल का कार्यक्रम ब्रिक्स : नवोन्मेषी भविष्य के लिए आर्थिक वृद्धि विषय के तहत हो रहा है। यह छठा मौका है, जब मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने प्रधानमंत्री के स्वागत को ब्रिक्स जितना ही शानदार बताते हुए ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ब्रासीलिया पहुंच गए हैं। इस साल के सम्मेलन का विषय ब्रिक्स : नवोन्मेषी भविष्य के लिए आर्थिक वृद्धि है, जो ब्रिक्स देशों के बीच परंपराग संबंधों को और मजबूत करेगा। सम्मेलन के दौरान विश्व के इन पांचों देशों का लक्ष्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष में उनके सहयोग को मजबूत करना होगा। मोदी ने अपनी रवानगी बयान में यह कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पांचों देश ब्रिक्स के ढांचे के दायरे में डिजिटल अर्थव्यवस्था पर सहयोग बढ़ाने और आतंकवाद रोधी सहयोग के लिए तंत्र बनाने पर भी गौर करेंगे।

वह ब्रिक्स व्यापार मंच समापन समारोह और क्लोज्ड सत्र (जिसमें सिर्फ ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे) तथा सम्मेलन के पूर्ण सत्र में भी शरीक होंगे। क्लोज्ड सत्र में चर्चा समकालिक विश्व में राष्ट्रीय संप्रभुता के उपयोग के लिए चुनौतियों एवं अवसरों पर केंद्रित रहने की उम्मीद है। इसके बाद ब्रिक्स का पूर्ण सत्र होगा, जिसमें सदस्य देशों के नेता ब्रिक्स समाजों के आर्थिक विकास के लिए अंत:-ब्रिक्स सहयोग पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक सम्मेलन में व्यापार एवं निवेश संवर्द्धन एजेंसियों के बीच एक ब्रिक्स सहमति पत्र पर भी हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।

भारतीय पीएचडी छात्र ने जीता ब्रिक्स-युवा नवोन्मेषक पुरस्कार

रियो दि जिनेरियो/नई दिल्ली। छोटे एवं सीमांत ग्रामीण डेरी किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कच्चा दूध को अत्यधिक ठंडा करने वाली वहनीय स्वदेशी इकाई का आविष्कार करने को लेकर भारतीय पीएचडी छात्र रवि प्रकाश ने 25,000 डॉलर का ब्रिक्स-युवा नवोन्मेषक पुरस्कार जीता है। आईसीएआर-नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट (एनडीआरआई) के पीएचडी छात्र प्रकाश चौथे ब्रिक्स-युवा वैज्ञानिक मंच, 2019 के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ब्राजील भेजे गए 21 सदस्ईय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे। प्रकाश बिहार के रहने वाले हैं। विभाग ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि मंच में भारत ने 25,000 डॉलर का प्रथम पुरस्कार जीता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट किया, भारत ने ब्राजील में छह से आठ नवंबर, 2019 के दौरान ब्रिक्स युवा वैज्ञानिक मंच के सम्मेलन में प्रथम पुरस्कार जीता।

जाधव को अपील इजाजत देने के लिए पाकिस्तान आर्मी एक्ट में करेगा संशोधन

● पाक ने जासूसी व आतंकवाद का आरोप लगाकर सुनाई है मौत की सजा

एजेंसी। इस्लामाबाद

पाकिस्तान मृत्युदंड का सामना कर रहे कुलभूषण जाधव को अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ एक दीवानी अदालत में अपील दायर करने का अधिकार देने की इजाजत देने के लिए थल सेना कानून में संशोधन की तैयारी कर रहा है। एक रक्षा सूत्र ने यहां यह जानकारी दी।

जाधव (49) भारतीय नौसेना के एक सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। अप्रैल 2017 में उनके खिलाफ पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत के बंद कमरे में चली सुनवाई के बाद उन्हें जासूसी एवं आतंकवाद के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। हालांकि, भारत का यह कहना रहा है कि जाधव को ईरान से अगवा किया गया था जहां वह नौसेना से सेवानिवृत्त होने के बाद कारोबार के सिलसिले में गए थे। रक्षा सूत्रों ने बताया कि सरकार थल सेना कानून में संशोधन करने के मसौदे पर काम कर रही है, ताकि जाधव को अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ एक दीवानी अदालत में अपील दायर करने की इजाजत मिल सके। यह कदम अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के 17 जुलाई के फैसले के अनुपालन में उठाया जा रहा।

संशोधित कानून में सैन्य अदालतों द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ दीवानी अदालतों में समाधान मांगने की प्रक्रिया की रूपरेखा निर्धारित की जाएगी। गौरतलब है कि आईसीजे ने 17 जुलाई को अपने फैसले में कहा था कि पाकिस्तान को जाधव की मौत की सजा की अवश्य ही समीक्षा करनी चाहिए। भारत ने दलील दी थी कि उसके नागरिक को राजनयिक पहुंच मुहैया करने से इनकार करना राजनयिक संबंधों पर वियना संधि का उल्लंघन है। पाकिस्तान ने काफी टाल-मटोल के बाद आईसीजे के निर्देश के तहत दो सितंबर को जाधव को राजनयिक पहुंच प्रदान की थी।

काबुल में कार बम विस्फोट में सात की मौत

एजेंसी। काबुल

काबुल में बुधवार को सुबह भीड़-भाड़ वाले इलाके में एक छोटी वैन में विस्फोट हुआ जिसके कारण चार विदेशी नागरिकों समेत कम से कम सात लोगों की मौत हो गई और और दस घायल हो गए।

आतंरिक मंत्रालय प्रवक्ता नसरत रहीमी ने कहा कि बम का लक्ष्य एक कनाडाई सुरक्षा कंपनी गार्डावल्र्ड का वाहन था। उन्होंने बताया कि विस्फोट जिस स्थान पर हुआ वह काबुल हवाई अड्डे के उत्तर में है और आतंरिक मंत्रालय के पास है। रहीमी ने कहा, विस्फोट के कारण हमारे सात लोग मारे गए और सुरक्षा कंपनी के चार विदेशी सदस्यों सहित दस लोग घायल हो गए। रहीमी के अनुसार मृतक अफगान नागरिक थे। उन्होंने मारे गए विदेशी व्यक्तियों की नागरिकता की पुष्टि नहीं की। आतंरिक मंत्री मसूद अंदराबी ने कहा कि मृतकों में तेरह साल का एक बच्चा भी शामिल है। आंतरिक मंत्रालय के सूत्र ने बताया कि कार में एक आत्मघाती हमलावर ने यह विस्फोट किया। हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली है। गौरतलब है कि शहर में तालिबान और इस्लामिक स्टेट दोनों ही सक्रिय हैं।

काबुल में कार बम विस्फोट के बाद विस्फोट स्थल पर तैनात सुरक्षाकर्मी

जयशंकर ने फ्रांस के राष्ट्रपति से की मुलाकात, रणनीतिक मुद्दों पर हुई चर्चा

एजेंसी। पेरिस

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने यहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की और महत्वपूर्ण रणनीतिक मुद्दों पर उनके साथ अच्छी चर्चा की। दोनों नेताओं की मंगलवार को पेरिस शांति मंच में मुलाकात हुई।

जयशंकर ने बैठक के बाद ट्वीट किया, पेरिस शांति मंच में इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात हुई। महत्वपूर्ण रणनीतिक मुद्दों पर अच्छी चर्चा हुई। वर्ष 1998 में भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक भागीदारी स्थापित हुई थी। रक्षा, सुरक्षा सहयोग, अंतरिक्ष सहयोग और असैन्य परमाणु सहयोग रणनीतिक भागीदारी के महत्वपूर्ण घटक हैं। भारतीय वायु सेना ने पिछले महीने फ्रांस से 36 लड़ाकू विमानों की खेप से पहला राफेल लड़ाकू विमान ग्रहण किया था।

पेरिस शांति मंच में जयशंकर ने अपने संबोधन के दौरान, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रूप से राष्ट्रों द्वारा समन्वित कार्वाई का आह्वान किया, ताकि आतंकवाद और चरमपंथ की ताकतों को डिजिटल क्षेत्र में उपस्थिति से रोका जा सके। साइबरजगत में शासन के संबंध में जयशंकर ने कहा कि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर साइबर हमलों सहित विशिष्ट सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए, देशों को जल्द कार्वाई और इसका असर कम करने के लिए समझौता करने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन जगत से आतंकवादी और हिंसक चरमपंथी विषयवस्तु को

पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करते विदेश मंत्री एस. जयशंकर

समाप्त करने के लिए भारत क्राइस्टचर्च कॉल का समर्थन करता है। इसके तहत देशों को समान सोच वाले देशों के साथ काम करते हुए सुनिश्चित करना है कि डिजिटल जगत हमारी सुरक्षा के लिए खतरा बने बिना हमारे समाज और अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए काम करे।

इस साल 15 मार्च को न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च शहर में आतंकवादी हमले में मुस्लिम समुदाय के 51 लोगों की मौत हो गई थी। इस आतंकवादी घटना का इंटरनेट पर लाइव प्रसारण कर दिया गया था। इसी घटना के बाद क्राइस्टचर्च कॉल कार्य योजना की शुरूआत की गई। भारत ने ऑनलाइन जगत में आतंकवाद और चरमपंथी विषयवस्तु से मुकाबले और इंटरनेट को सुरक्षित बनाने के लिए फ्रांस, न्यूजीलैंड, कनाडा और कई अन्य देशों के साथ हाथ मिलाया है। जयशंकर ने कहा कि साइबर जगत को खुला, सुरक्षित बनाए रखने के लिए अगर वैश्विक नियमन ना भी तैयार हो तो कम से कम वैश्विक सहमति बनाने की जरूरत है। इसके लिए पहले से ज्यादा बहुपक्षीय होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत जैसे बड़े विकासशील देश के लिए डिजिटल जगत और इसकी प्रौद्योगिकी हमारे लोकतंत्र और विकास कार्यक्रमों में बड़ी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे बड़े 1.2 अरब बायोमीट्रिक आधारित डिजिटल यूनिक पहचान पत्र कार्यक्रम, 1.2 अरब मोबाइल फोन कनेक्शन, एक अरब बैंक खाते, और 50 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट कनेक्शन ने बड़ा ढांचा तैयार किया है, जो शासन के साथ विकास को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा, हम अवसर से रोमांचित हैं लेकिन साइबर जगत के खतरों के बारे में चिंतित भी हैं।

भारत 2020 में संरा की फलस्तीन शरणार्थी एजेंसी को 50 लाख डॉलर का दान देगा

एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र

भारत ने 2020 में संयुक्त राष्ट्र की फलस्तीन शरणार्थी एजेंसी को 50 लाख डॉलर दान देने का संकल्प लिया है। उसने एजेंसी की खराब वित्तीय हालत पर चिंता भी जताई।

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई उप प्रतिनिधि के. नागराज नायडू ने कहा कि फलस्तीन के शरणार्थियों के साथ एका दिखाने के संकेत के तौर पर भारत की सरकार ने संरा राहत एवं कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) को सालाना वित्तीय मदद बढ़ाकर 50 लाख डॉलर करने का फैसला किया है। वर्ष 2016 में यह रकम 12.5 लाख डॉलर थी।

यूएनआरडब्ल्यूए पर महासभा की चौथी समिति की बैठक में उन्होंने कहा, हमने 2019 में 50 लाख डॉलर दान किए और 2020 में इतनी ही राशि देने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि फलस्तीन के 55 लाख शरणार्थियों को भारत का समर्थन और एका मजबूत है। भारत ने अन्य परंपरागत दानदाताओं से भी योगदान बढ़ाने की अपील की और गैर दानदाता सदस्य देशों से दान देने का अनुरोध किया।

अमेरिका में 2018 में सिखों के खिलाफ घृणा अपराधों के 60 मामले दर्ज हुए

वाशिंगटन। अमेरिका के संघीय जांच एजेंसी (एफबीआई) ने 2018 में सिखों के खिलाफ नस्ली घृणा के अपराधों के करीब 60 मामले दर्ज किए। एफबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में धार्मिक आधार पर निशाना बनाए जाने के लिहाज से यहूदियों और मुस्लिमों के बाद सिख समुदाय का तीसरा स्थान है। एफबीआई ने मंगलवार को बताया कि अमेरिका में बीते साल नस्ली घृणा अपराधों के कुल 7,120 मामले दर्ज किए गए, जो 2017 के 7,175 के मुकाबले कम है। एफबीआई द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक कानून व्यवस्था से संबंधित 16,039 एजेंसियों ने इन घटनाओं के बारे में सूचनाएं, पीड़ित, अपराधी और अपराध के स्थान के बारे में जानकारी दी।

गुरु नानक देव के सिद्धांत आज ज्यादा प्रासंगिक हैं

एजेंसी। वाशिंगटन

● अमेरिकी सांसदों ने गुरु पर्व पर कहा

अमेरिका के शक्तिशाली सांसदों और प्रतिष्ठित भारतीय-अमेरिकियों ने सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व का जश्न मनाया और कहा कि उनके सिद्धांत आज के वक्त में और भी प्रासंगिक हैं।

इंडियाना से रिपब्लिक पार्टी के सांसद टोड यंग ने इस मौके पर सदन में एक प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा कि सिख-अमेरिकी देशभर में गहरा असर छोड़ने में कामयाब रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहले सिख गुरु की शिक्षाओं का अनुसरण किया। गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व का जश्न मनाने के लिए भारतीय दूतावास द्वारा कैपिटोल हिल में आयोजित एक कार्यक्रम में यंग ने कहा कि उनके पड़ोसी इलाके में बड़ी संख्या में सिख अमेरिकी परिवार हैं। उन्होंने कहा, मुझे इसकी भी खुशी है कि समानता और समावेश के प्रति आपकी प्रतिबद्धता से यह ऐतिहासिक समझौता हुआ जिससे गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर सिखों के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर गलियारा खोला गया। सांसद जूडी चू ने कहा कि गुरु नानक देव का जीवन हम सभी के लिए सच्ची मिसाल हैं। उन्होंने महिलाओं को समानता देने की सीख दी।

इंडियाना से रिपब्लिक पार्टी के सांसद ग्रेग पेंस ने सदन में कहा, इंडियाना 10,000 से अधिक सिखों का घर है जो हमारे समुदायों को समृद्ध कर रहे हैं और देशवासी मूल्यों के अर्थ को मूर्त रूप दे रहे हैं। देश के सिख इंडियाना में तेजी से बढ़ रहे औद्योगिक समुदायों में से एक हैं और हमारी अर्थव्यवस्था तथा सांस्कृतिक मूल्यों में योगदान दे रहे हैं। न्यूजर्सी के अटॉर्नी जनरल गुरबीर सिंह ग्रेवाल ने कहा कि सिख धर्म के बारे में जागरूकता लाने की आज कहीं अधिक जरूरत है। हमें यह भी बताना होगा कि धर्म की सीखें आज के आधुनिक दौर में कितनी प्रासंगिक बनी हुई हैं।

इजराइली हवाई हमलों में इस्लामिक जिहादियों का सफाया

● इजराइल के हवाई हमले में एक वरिष्ठ इस्लामिक जिहादी कमांडर मारा गया था जिस पर हालिया हमलों का मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप था

एजेंसी। गाजा सिटी

इजराइल की ओर राकेट हमले फिर से शुरू होने के साथ ही इजराइल ने इस्लामी जिहादियों के खिलाफ हवाई हमलों में इजाफा कर दिया जिससे गाजा पट्टी में 18 फलस्तीनी मारे गए। कई महीनों के विराम के बाद यह बड़ा हमला है।

सेना ने बताया कि इजराइल द्वारा किए गए एक हवाई हमले के बाद भड़की हिंसा में इजराइली समुदायों पर 250 से अधिक राकेट दागे गए। इजराइल के हवाई हमले में एक वरिष्ठ इस्लामिक जिहादी कमांडर मारा गया था जिस पर हालिया हमलों का मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप

था। इजराइल ने ईरान और क्षेत्र में उसके सहयोगियों के खिलाफ संघर्ष तेज कर दिया है। इन ताजा हमलों के बाद इजराइल में जीवन ठहर गया है।गाजा सीमा के पास इजराइली समुदायों में स्कूल बंद रहे और राकेट हमलों के बीच लोगों के बड़ी संख्या में एकत्र होने पर रोक लगी रही।

मंगलवार की सुबह हुए हमलों में बाहा अबू अल अता और उसकी पत्नी मारे गए थे। इस बीच, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने विशेष कैबिनेट बैठक में बताया कि टकराव को बढ़ाने में इजराइल की कोई दिलचस्पी नहीं है लेकिन उन्होंने ईरान समर्थित इस्लामिक जिहाद को चेतावनी दी कि राकेट हमले बंद होने तक वह उन पर बम बरसाना जारी रखेगा। इजराइल और गाजा आतंकवादियों के बीच अक्सर सुलह समझौते के लिए मध्यस्थता करने वाले मिस्र के प्रयासों को खारिज करते हुए इस्लामिक जिहाद ने कहा है कि उसकी प्राथमिकता इजराइली आक्रमण का जवाब देना है। हालांकि इजराइली सेना भी मामले को बढ़ाना नहीं चाहती और इसीलिए उसने इस्लामिक जिहादियों को ही निशाना बनाया है।

चीन में उइगर हिरासत केंद्रों की संख्या ज्ञात से कहीं अधिक

आर्लिंग्टन (अमेरिका)। उइगर कार्यकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने जातीय समूह को हिरासत में लेने के लिए चीन द्वारा चलाए जा रहे करीब 500 शिविर और जेल देखे हैं। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि चीन में हिरासत में रह रहे लोगों की संख्या 10 लाख बताई जाती है लेकिन यह आंकड़ा कहीं ज्यादा हो सकता है। चीन के मुस्लिम क्षेत्र शिनजियांग के लिए आजादी की मांग कर रहे वाशिंगटन स्थित समूह द ईस्ट तुर्किस्तान नेशनल अवेकनिंग मूवमेंट ने 182 संदिग्ध हिरासत शिविरों के बारे में संकेत दिए हैं जहां उइगरों पर अपनी संस्कृति छोड़ने के लिए कथित तौर पर दबाव बनाया गया। गूगल अर्थ पर उपलब्ध ताजा तस्वीरों का आकलन करने के बाद समूह ने कहा कि मंगलवार को उसने 209 संदिग्ध जेल और 74 संदिग्ध श्रम शिविर देखे जिनके संबंध में वह बाद में जानकारियां साझा करेगा। मूवमेंट के अभियान निदेशक कायले ओल्बर्ट ने कहा, बड़े हिस्से में पहले इनकी पहचान नहीं की गई इसलिए हम कहीं अधिक संख्या में लोगों को हिरासत में लिए जाने की बात कह सकते हैं।

क्विक न्यूज

फाइनेंशियल टाइम्स को मिली पहली महिला संपादक

लंदन। फाइनेंशियल टाइम्स ने मंगलवार को घोषणा की कि उसकी उप संपादक रौला खलाफ अगले साल से अखबार के संपादक का पद संभालेगी। वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला होगी। रौला लिओनेल बारबर की जगह लेगी जो करीब 15 साल संपादक रहने के बाद पद मुक्त हो रहे है। 1995 मे रौला फाइनेंशियल टाइम्स से उत्तरी अफ्रीका की संवाददाता के तौर पर जुड़ी। विदेश मामलो की संपादक बनने से पहले उन्होने अरब देशो मे 2011 मे शुरु हुई क्रांति के कवरेज का पूरा जिम्मा उठाया था। उन्होने कहा मुझे बहुत खुशी है और मै बहुत उत्साहित हूं।

इंडोनेशिया में संदिग्ध बम धमाके में एक हमलावर की मौत

मेदान। इंडोनेशिया मे पुलिस थाने के बाहर संदिग्ध आत्मघाती बम धमाके मे कम से कम एक हमलावर मारा गया। अधिकारियो ने बताया कि धमाका स्थानीय समयानुसार सुबह 8:45 पर सुमात्रा द्वीप के मेदान के पुलिस परिसर मे हुआ। राष्ट्रीय पुलिस प्रवक्ता देडी प्रसातियो ने जकार्ता मे संवाददाताओ से कहा, हमे संदेह है कि यह आत्मघाती बम धमाका था, जिसमे एक हमलावर मारा गया। मौके पर मौजूद एएफपी के एक पत्रकार ने बताया कि पुलिस स्टेशन के बाहर एक शव पड़ा था। पुलिस के एक सूत्र ने एएफपी को बताया कि कम से कम दो आत्मघाती हमलावर इसमे शामिल थे, लेकिन इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नही हो पाई है। अपुष्ट स्थानीय मीडिया खबरो के अनुसार एक पुलिस अधिकारी को भी अस्पताल मे भर्ती कराया गया, उसकी हालत के बारे मे अभी कोई जानकारी नही है। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम बहुल देश मे कट्टरपंथी अक्सर पुलिस थानो को निशाना बनाते है।

तुर्की पुलिस ने पत्रकार अहमत अल्तान को फिर किया गिरफ्तार

अंकारा। तुर्की पुलिस ने अदालत के आदेश का पालन करते हुए पत्रकार एवं लेखक अहमत अल्तान को मंगलवार को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया। वर्ष 2006 मे तख्तापलट की नाकाम कोशिश मे कथित संलिप्तता के मामले मे पिछले सप्ताह ही उन्हे रिहा किया गया था। अल्तान और एक अन्य पत्रकार नजली इलायक को आतंकवादी समूह की मदद करने के मामले मे दोषी पाया जाने के बावजूद चार नवम्बर को रिहा कर दिया गया था। इस्तांबुल की अदालत ने अल्तान को 10 साल से अधिक की जेल की सजा सुनाई थी, लेकिन उसे और इलायक को करीब तीन-तीन साल जेल की सजा काटने के बाद रिहा कर दिया गया। अदालत ने कहा कि रिहा करने के बाद भी उन पर नजर रखी जाए। उनके देश से बाहर जाने पर भी प्रतिबंध था। सरकार समाचार एजेंसी अनादोलु के अनुसार मुख्य लोक अभियोजक ने अल्तान को रिहा करने के फैसले के खिलाफ अपील की थी, जिसके बाद मंगलवार को उसे गिरफ्तार करने का वारंट जारी किया गया।

डेमोक्रेट्स ने महाभियोग जन सुनवाई के लिए आठ और गवाहों की सूची जारी की

वाशिंगटन। अमेरिका के डेमोक्रेटिक सांसदों ने आठ और गवाहों की सूची जारी की है जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की महाभियोग जांच के तहत, खुली सुनवाई में गवाही देंगे। सांसदों ने जांच के दौरान बंद कमरे में हुई सुनवाई में इन सभी आठों के बयान दर्ज किए। प्रतिनिधि सभा में वर्चस्व रखने वाले डेमोक्रेट्स ने सितंबर में जांच शुरू की थी। ट्रम्प पर आरोप है कि उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी डेमोक्रेट और 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में संभावित रूप से उन्हें चुनौती देने वाले जो बिडेन के बारे में गलत सूचनाएं देने के लिए यूक्रेन पर दबाव डालने के वास्ते अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। मामले में अंतिम मतदान अमेरिकी सीनेट करेगी जिसमें रिपब्लिकन का बहुमत है। अत: ट्रंप को हआए जाने की संभावना कम ही है।

अमेरिका की नजरें अब इस्लामिक स्टेट के नए नेता पर : ट्रम्प

एजेंसी। वाशिंगटन

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का कहना है कि अब उनकी नजर इस्लामिक स्टेट के नए नेता पर है और हम जानते हैं कि वह कहां है।

ट्रम्प ने आईएस के नए नेता का नाम नहीं बताया लेकिन संभवत: वह अबू इब्राहिम अल-हाशिमी अल-कुरैशी का जिक्र कर रहे थे। ऐसी खबरें हैं कि अल-कुरैशी ने आतंकवादी संगठन के सरगना के तौर पर अबू बकर अल-बगदादी का स्थान लिया है। बगदादी ने उत्तरी सीरिया में अमेरिकी कमांडो द्वारा पीछा किए जाने के बाद खुद को विस्फोटकों से उड़ा लिया था। मंगलवार को दिए भाषण में ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका ने अल-बगदादी को खत्म किया और फिर दूसरे सरगना को, अब हमारी नजर तीसरे पर है। उन्होंने कहा तीसरे सरगना को काफी दिक्कतें होंगी क्योंकि हम जानते हैं कि वह कहां है। अल-कुरैशी के बारे में सार्वजनिक रूप से ज्यादा जानकारी नहीं है। आईएस का पदानुक्रम स्पष्ट नहीं है और उसके बाकी के शीर्ष नेताओं के बारे में बहुत कम जानकारियां हैं। ट्रम्प ने जिस दूसरे सरगना का जिक्र किया है वह अबू हसन अल-मुहाजिर हो सकता है जो अल-बगदादी का करीबी सहायक था और 2016 से आतंकी समूह का प्रवक्ता था। अल-बगदादी की मौत के बाद अमेरिका और कुर्दिश सेना के संयुक्त अभियान में वह भी मारा गया था।

बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहेगा

पहला टेस्ट आज से

एजेंसी। इंदौर

आत्मविश्वास से लबरेज भारतीय क्रिकेट टीम का पलड़ा गुरूवार से यहां शुरू हो रहे पहले टेस्ट में बांग्लादेश पर भारी होगा और लाल गेंद से खेले जा रहे इस मुकाबले से पहले भी चर्चा गुलाबी गेंद का ही हो रहा है। यहां कोलकाता में होने वाले ऐतिहासिक दिन रात्रि के टेस्ट पर लगातार चर्चा हो रही है जो गुलाबी गेंद से खेला जाना है। दोनों टीमों के लिए यह दिन रात का पहला टेस्ट होगा। विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप कैलेंडर की यह ऐसी श्रृंखला है जिसमें शानदार फार्म में चल रहे विराट के वीर सितारों के बिना खेल रही बांग्लादेश टीम को चार दिन में ही हरा सकते हैं।

तामिम इकबाल और शाकिब अल हसन के बिना बांग्लादेश के लिए जीत की कल्पना भी मुश्किल है। सीमित ओवरों के क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन करने वाली बांग्लादेशी टीम पारंपरिक प्रारूप में हमेशा कमजोर साबित हुई है। पिछली श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका को हराने वाली भारतीय टीम के पास अब तक का सर्वश्रेष्ठ तेज आक्रमण है। दूसरी ओर बांग्लादेश के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कप्तान मोमिनुल हक ने टेस्ट क्रिकेट में दस से भी कम शतक जमाए हैं। मुशफिकुर रहीम और महमूदुल्लाह रियाद समर्पित क्रिकेटर हैं लेकिन इस प्रारूप में कद्दावर नाम नहीं हैं।

वहीं भारत के कप्तान विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में 26 शतक जमा चुके हैं जबकि अजिंक्य रहाणे के नाम 11 और चेतेश्वर पुजारा के नाम 18 सैकड़े हैं। बांग्लादेश के मुस्ताफिजूर रहमान, तैजुल इस्लाम और मेहिदी हसन मिराज के लिए भारतीय बल्लेबाजों पर अंकुश लगाना काफी कठिन होगा। इन तीनों से पहले उन्हें सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल और रोहित शर्मा से पार पाना होगा जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की बखिया उधेड़ सकते हैं। भारतीय गेंदबाज मिलकर 800 से ज्यादा विकेट ले चुके हैं लिहाजा इसे बेमेल मुकाबला कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बांग्लादेशी टीम शाकिब की कप्तानी में पिछला टेस्ट अफगानिस्तान से हार गई थी। शाकिब दो साल के निलंबन के कारण क्रिकेट से दूर हैं। होल्कर स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों की मददगार रही है। इसकी बाउंड्री छोटी है लेकिन पिच में उछाल है। मोहम्मद शमी और उमेश यादव तेज गेंदबाजी की कमान संभालेंगे जबकि रविंद्र जडेजा और आर अश्विन स्पिन का जिम्मा लेंगे। पिच की उछाल को देखते हुए कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव की जगह ईशांत शर्मा को तीसरे तेज गेंदबाज के रूप में शामिल किया जा सकता है। वैसे अफगानिस्तान के राशिद खान के सामने बांग्लादेशी बल्लेबाजी जिस तरह से चरमराई थी, उसके मद्देनजर कोहली इस मैच में कुलदीप को उतार भी सकते हैं। टीमें : भारत : विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, रविंद्र जडेजा, रिधिमान साहा, आर अश्विन, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, ईशांत शर्मा , कुलदीप यादव। बांग्लादेश : मोमिनुल हक (कप्तान), इमरूल काएस, मुशफिकुर रहीम, महमूदुल्लाह रियाद, मोहम्मद मिथुन, लिटन दास, मेहिदी हसन मिराज, मुस्ताफिजूर रहमान, नईम हसन, सैफ हसन, शादमान इस्लाम, तैजुल इस्लाम, अबु जाएद, इबादत हुसैन, मुसद्दक हुसैन सैकत।

इंदौर टेस्ट के लिए बनाया गया जीवंत विकेट : मुख्य क्यूरेटर

इंदौर। भारत और बांग्लादेश के बीच यहां होलकर स्टेडियम में बृहस्पतिवार से शुरू होने वाले टेस्ट मैच से पहले मध्यप्रदेश क्रिकेट संघ (एमपीसीए) के मुख्य क्यूरेटर ने कहा कि पांच दिवसीय मुकाबले के लिए जीवंत विकेट तैयार किया गया है। एमपीसीए के मुख्य क्यूरेटर समंदर सिंह चौहान ने कहा कि हमने टेस्ट क्रिकेट की जरूरतों के मुताबिक जीवंत विकेट बनाया है। इस विकेट में गेंदबाजों और बल्लेबाजों, दोनों की मदद के लिए कुछ न कुछ है।

कप्तानी से मेरी बल्लेबाजी प्रभावित नही होगीः मोमिनुल हक

इंदौर। बांग्लादेशी कप्तान मोमिनुल हक को टीम की अगुआई का इतना अनुभव नहीं है लेकिन उन्हें भरोसा है कि अतिरिक्त जिम्मेदारी से उनकी बल्लेबाजी प्रभावित नहीं होगी जो गुरूवार से यहां शुरू हो रही टेस्ट श्रृंखला में भारत को हराने की उनकी उम्मीदों के लिए अहम होगी। 28 वर्षीय मोमिनुल को शाकिब अल हसन की जगह कप्तान चुना गया जिन्हें आईसीसी ने दो साल के लिए निलंबित किया है। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने कहा, मैं सिर्फ कप्तान नियुक्त किए जाने से दबाव महसूस नहीं कर रहा हूं। कप्तानी से पहले मैं जिस तरह बल्लेबाजी करता था, उसी तरह से अब भी बल्लेबाजी करता रहूंगा। टीम के इस मुख्य बल्लेबाज ने 36 टेस्ट में आठ शतक जड़े हैं। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा सकारात्मक पहलुओं के बारे में सोचने की कोशिश करता हूं। कप्तान होने में भी कुछ सकारात्मक चीजे हैं। आपकी खेल की जानकारी बढ़ती है। आप बतौर खिलाड़ी भी ज्यादा जिम्मेदार हो जाते हो। इसलिए मुझे लगता है कि इससे मुझे अपने प्रदर्शन को सुधारने में मदद मिलेगी। मोमिनुल को लगता है कि उनकी टीम से उम्मीदें इतनी ज्यादा नहीं हैं तो दबाव भी थोड़ा कम होगा। भारत की मजबूत तेज गेंदबाजी के बारे में पूछने पर मोमिनुल ने कहा, भारत की टीम ऐसी है कि वह विभिन्न तरह के प्रतिद्वंद्वियों को अलग तरह से चुनौती दे सकती है।

सिंधू और प्रणय जीते, साइना और समीर बाहर

हांगकांग ओपन

एजेंसी। हांगकांग

विश्व चैम्पियन पीवी सिंधू ने जीत के साथ आगाज किया जबकि भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल और समीर वर्मा बुधवार यहां चार लाख डालर इनामी हांगकांग ओपन के पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए। पिछले कुछ टूर्नामेंटों में पहले दौर से बाहर हुई सिंधू ने 36 मिनट के भीतर दुनिया की 19वें नंबर की खिलाड़ी कोरिया की किम गा यून को 21-15, 21-16 से हरा दिया।

ओलंपिक रजत पदक विजेता सिंधू का सामना अब थाईलैंड की बुसानन ओंगबामरूंगफान से होगा। एचएस प्रणय भी पहले दौर की बाधा पार करने में सफल रहे। उन्होंने चीन के हुआंग यु शियांग को 44 मिनट में 21-17 21-17 से हराया। वह अगले दौर में इंडोनेशिया के छठे वरीय जोनाथन क्रिस्टी से भिड़ेंगे। वहीं आठवीं वरीयता प्राप्त साइना पिछले छह टूर्नामेंटों में पांचवीं बार पहले दौर में हारी है। इस साल जनवरी में इंडोनेशिया मास्टर्स जीतने वाली साइना को चीन की केइ यान यान ने लगातार दूसरी बार 21-13, 22-20 से हराया। पिछले सप्ताह भी वह केइ से हारी थी। दुनिया के 16वें नंबर के खिलाड़ी समीर 54 मिनट तक चले मुकाबले में चीनी ताइपै के वांग जू वेइ से 11-21, 21-13, 8-21 से हार गए। यह पहले दौर में उनकी लगातार तीसरी हार है। साइना और समीर दोनों को अगले सप्ताह ग्वांग्झू कोरिया मास्टर्स सुपर 300 टूर्नामेंट खेलना है। अश्विनी पोनप्पा और एन सिक्की रेड्डी की जोड़ी भी पहले दौर में आगे बढ़ने में नाकाम रही। भारतीय जोड़ी को माइकेन फ्रुरगार्ड और सारा थिगेसन की डेनमार्क की जोड़ी के खिलाफ 13-21 12-21 से हार झेलनी पड़ी। दुनिया की छठे नंबर की खिलाड़ी सिंधू ने 8-4 की बढ़त बनाई लेकिन किम वापसी करते हुए ब्रेक तक 11-10 से आगे हो गईं। भारतीय खिलाड़ी ने इसके बाद 13-13 के स्कोर पर लगातार छह अंक जुटाए और फिर आसानी से पहला गेम जीत लिया। दूसरे गेम में भी सिंधू ने 5-5 के स्कोर के पर लगातार सात अंक के साथ 12-5 की बढ़त बना ली जिसके बाद उन्हें गेम और मैच जीतने में अधिक परेशानी नहीं हुई। साइना पहले गेम से ही केइ की चुनौती के सामने टिक नहीं सकी। चीनी खिलाड़ी ने ब्रेक तक 11-4 से बढ़त बना ली और पहला गेम आसानी से जीत लिया।

लंदन। डोमिनिक थिएम ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए नोवाक जोकोविच को हराकर एटीपी फाइनल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया और अब सर्बियाई खिलाड़ी का सामना शूटआउट में रोजर फेडरर से होगा। आस्ट्रिया के पांचवीं वरीयता प्राप्त थिएम ने दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी को 6-7, 6-3, 7-6 से हराया। वहीं छह बार के चैम्पियन फेडरर ने इटली के मातेओ बेरेतिनी को 7-6, 6-3 से शिकस्त दी। फेडरर और जोकोविच अब एक दूसरे के सामने होंगे जो पिछले साल के विम्बलडन फाइनल का रिप्ले होगा।

Chola
Enter a better life

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

कार्पोरेट कार्यालय : नंबर 2, 'डेयर हाउस' प्रथम तल, एन.एस.सी. बोस रोड, चेन्नई–600 001
शाखा कार्यालय : प्रथम एवं द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 6, मेन पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005, सम्पर्क नंबर : 9899245509, 9818460101

नीलामी–सह–बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना (इसको धारा 8 (6) के तहत नोटिस माना जाए।)

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कर्जदारो से बकाया राशि की वसूली के लिए **वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002** के अधीन यहां नीचे वर्णित प्रत्याभूत आस्तियों का कब्जा लिए जाने के अनुसरण में, अधोहस्ताक्षरी द्वारा यहां नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जोकि कब्जे में है, की बिक्री **"जैसा है जहां है आधार", "जो है जैसा है आधार" "जो भी है वहां है आधार"** पर करने हेतु सीलबंद लिफाफों में ऑफर्स आमंत्रित की जाती हैं, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :–

क्र. सं.	कर्जदार(गण) /सह–कर्जदार(गण)/गारंटर(गण)	मांग सूचना तिथि एवं राशि	अचल सम्पत्ति का वर्णन	सुरक्षित मूल्य	धरोहर राशि जमा	कुल बकाया राशि	कब्जा का प्रकार
1.	(ऋण संख्या) **(X0HEDHE00001239641 X0HEDHE00001091630)** **राजेश कुमार यादव** (कर्जदार) **रेवती यादव, नीतू यादव** (सह–कर्जदार) All are having address for communication at :- Plot No-6, Road No, N-12, DLF City, Phase-II, Gurgaon, Haryana-122022 **Also At:-** H.No.-164-P, Sec-15, part-I, Vill-Jharsa, Gurgaon, Haryana-122022 Also At:- J-3/32/DLF-II, Second Floor, Gurgaon,Haryana-1220022	**24–10–2016** **रू. 1,74,94,680.11** (रू. एक करोड़ चौहत्तर लाख चौरानवे हजार छह सौ अस्सी तथा पैसे ग्यारह मात्र) **and Rs.3,20,21,630.73/-** (Rupees Three Crore Twenty Lakhs Twenty One Thousand Six Hundred Thirty and Seventy Three Paisa Only) 22–10–2016 तक	**प्लॉट नंबर 6, सम्पूर्ण द्वितीय तल, परिमाप 1600 वर्ग फीट, टेरेस के अधिकार के साथ, भूमि परिमाप 2250.56 वर्ग मीटर, रोड नंबर एन–12, डीएलएफ सिटी फेज–2, गुड़गांव**	**रू. 80,00,000/–** (रू. अस्सी लाख मात्र)	**रू. 8,00,000/–** (रू. आठ लाख मात्र)	**रू. 1,74,94,680.11** (रू. एक करोड़ चौहत्तर लाख चौरानवे हजार छह सौ अस्सी तथा पैसे ग्यारह मात्र) **and रू.3,20,21,630.73/-** (Rupees Three Crore Twenty Lakhs Twenty One Thousand Six Hundred Thirty and Seventy Three Paisa Only)+Interest	सांकेतिक
			आवासीय मकान नंबर 164–पी, सेक्टर–15, पार्ट–1, अर्बन एस्टेट, परिमाप 220 वर्ग मीटर (2368.06 वर्ग फीट) गुरूग्राम	**रू. 2,55,00,000/–** (रू. दो करोड़ पचपन लाख मात्र)	**रू. 25,50,000/–** (रू. पच्चीस लाख पचास हजार मात्र)		
			जे–3/32/डीएलएफ–II, द्वितीय तल, गुड़गांव, हरियाणा–122022 परिमाप 215 वर्ग गज	**रू. 60,00,000/–** (रू. साठ लाख मात्र)	**रू. 6,00,000/–** (रू. छह लाख मात्र)		
2.	(ऋण खाता सं. **X0HEEDL00001835007, X0HEEDL00001826804 दिल्ली** शाखा) **श्री/सुश्री अजय त्यागी** (कर्जदार) **प्रियंका त्यागी, रजनी मेडिकोज** (सह–कर्जदार) सभी का पत्रव्यवहार हेतु पता : जे–84, द्वितीय तल, विकास पुरी, नई दिल्ली–110018	**रू. 1,18,92,080.90** (रूपए एक करोड़ अठारह लाख बानवे हजार अस्सी तथा पैसे नब्बे मात्र)	**द्वितीय तल छत टेरेस का अधिकार नहीं (उक्त सम्पत्ति) सम्पत्ति सं. जे–84 का हिस्सा, परिमाप 104 वर्ग मीटर, विकास पुरी, नई दिल्ली–110018**	**रू. 1,00,00,000/–** (रूपए एक करोड़ मात्र)	**रू. 10,00,000/–** (रूपए दस लाख मात्र)	**रू. 1,18,92,080.90** (रूपए एक करोड़ अठारह लाख बानवे हजार अस्सी तथा पैसे नब्बे मात्र) + **ब्याज**	सांकेतिक
3.	(ऋण खाता सं. **X0HEEDL00001429783, X0HEEDL00001429784 दिल्ली** शाखा) **श्री/सुश्री नरेन्दर पाल सिंह** (कर्जदार) **विक्रम सिंह, रमन दीप कौर, मंजीत कौर** (सह–कर्जदार) सभी का पत्रव्यवहार हेतु पता : बी–2/1, मेन रोड, गोल्डन पार्क, शिवपुरी, नई दिल्ली–110051	**29–04–2019** **रू. 1,70,00,256.46** (रूपए एक करोड़ सत्तर लाख दो सौ छप्पन तथा पैसे छियालीस मात्र)	**गोल्डन पार्क मेन रोड शिवपुरी एक्सटेशन, शाहदरा, दिल्ली की आबादी में ग्राम खुरेजी खास के क्षेत्र में स्थित सम्पत्ति सं. बी–2/1, परिमाप 80 वर्ग गज, खसरा नंबर 9/3, 7/23, 7/14, 25. 6/2/1, 2/2, 2/3 एवं 21का हिस्सा।**	**रू. 1,60,00,000/–** (रूपए एक करोड़ साठ लाख मात्र)	**रू. 16,00,000/–** (रूपए सोलह लाख मात्र)	**रू. 1,70,00,256.46** (रूपए एक करोड़ सत्तर लाख दो सौ छप्पन तथा पैसे छियालीस मात्र) + **ब्याज**	सांकेतिक
4.	ऋण खाता संख्या **(X0HEELD00002272331, X0HEELD00001598962 & X0HEDHE00001394182)** **नितिन गुप्ता (कर्जदार), पूजा गुप्ता, जय प्रकाश गुप्ता, मैसर्स जेपी केबल ऐंड वायर्स (सह–कर्जदार)** **सभी का पत्राचार हेतु पता** : एफ–30, ब्लॉक–एफ, मानसरोवर पार्क, शाहदरा, दिल्ली–110032 **अन्य पता** : 27/94/10, जावला नगर, तिकोना पार्क, नई दिल्ली–110032	**26–06–2019** **रू. 1,03,06,490.39/–** (रूपए एक करोड़ तीन लाख छह हजार चार सौ नब्बे तथा पैसे उन्तालीस मात्र)	**कम्पाउण्ड नंबर 30, परिमाप 150 वर्ग गज, सामने का हिस्सा, ब्लॉक–एफ, खसरा नंबर 1096/322 एवं 1097/322 मौजा चंद्रावली, मानसरोवर पार्क, शाहदरा, नई दिल्ली–110032**	**रू. 1,00,00,000/–** (रूपए एक करोड़ मात्र)	**रू. 10,00,000/–** (रूपए चार लाख अस्सी हजार मात्र)	**रू. 1,03,06,490.39/–** (रूपए एक करोड़ तीन लाख छह हजार चार सौ नब्बे तथा पैसे उन्तालीस मात्र) + **ब्याज**	सांकेतिक
5.	ऋण खाता संख्या **(X0HEDHE00001005151)** **राहुल गुप्ता (कर्जदार), जुगेन्दर प्रसाद, मधु गुप्ता (सह–कर्जदार)** **सभी का पत्राचार हेतु पता** : सी–4/2, राणा प्रताप बाग, नई दिल्ली–110007	**26–06–2019** **रू.1,97,58,365.65/–** (रूपए एक करोड़ सत्तानवे लाख अठ्ठावन हजार तीन सौ पैंसठ तथा पैसे पैंसठ मात्र)	**सम्पत्ति सं. सी–4/2, भू तल, परिमाप 233.33 वर्ग गज, राणा प्रताप बाग के नाम से मशहूर कालोनी, दिल्ली–110007**	**रू. 1,08,00,000/–** (रूपए एक करोड़ आठ लाख मात्र)	**रू. 10,80,000/–** (रूपए दस लाख अस्सी हजार मात्र)	**रू.1,97,58,365.65/–** (रूपए एक करोड़ सत्तानवे लाख अठ्ठावन हजार तीन सौ पैंसठ तथा पैसे पैंसठ मात्र) + **ब्याज**	सांकेतिक
			सम्पत्ति सं. सी–4/2, प्रथम तल, परिमाप 233.33 वर्ग गज, राणा प्रताप बाग के नाम से मशहूर कालोनी, दिल्ली–110007	**रू. 1,08,00,000/–** (रूपए एक करोड़ आठ लाख मात्र)	**रू. 10,80,000/–** (रूपए दस लाख अस्सी हजार मात्र)		सांकेतिक
			सम्पत्ति सं. सी–4/2, द्वितीय तल, परिमाप 233.33 वर्ग गज, राणा प्रताप बाग के नाम से मशहूर कालोनी, दिल्ली–110007	**रू. 1,04,50,000/–** (रूपए एक करोड़ चार लाख पचास हजार मात्र)	**रू. 10,45,000/–** (रूपए दस लाख पैंतालीस हजार मात्र)		सांकेतिक
			सम्पत्ति सं. सी–4/2, तृतीय तल, परिमाप 233.33 वर्ग गज, राणा प्रताप बाग के नाम से मशहूर कालोनी, दिल्ली–110007	**रू. 1,04,50,000/–** (रूपए एक करोड़ चार लाख पचास हजार मात्र)	**रू. 10,45,000/–** (रूपए दस लाख पैंतालीस हजार मात्र)		सांकेतिक
6.	ऋण खाता सं. **(X0HEDHE00000876068, X0HEDHE00001017505)** **प्रवीण सेठी (कर्जदार)** **मोना सेठी (सह–कर्जदार)** **सभी का पत्र व्यवहार पता** : जी–4ए, प्रथम एवं द्वितीय तल, काल्काजी, नई दिल्ली–110019	**06–10–2016** **रू. 2,88,84,535.89** (रूपए दो करोड़ अठासी लाख चौरासी हजार पांच सौ पैंतीस तथा पैसे नवासी मात्र)	**सम्पत्ति सं. जी/4–ए, प्रथम एवं द्वितीय तल, निर्मित क्षेत्रफल 1350 वर्ग फीट, तथा भूमि परिमाप 100 वर्ग गज, काल्काजी, नई दिल्ली–110019**	**रू. 1,48,75,000/–** (रूपए एक करोड़ अड़तालीस लाख पचहत्तर हजार मात्र)	**रू. 14,87,500/–** (रूपए चौदह लाख सतासी हजार पांच सौ मात्र)	**रू. 2,88,84,535.89** (रूपए दो करोड़ अठासी लाख चौरासी हजार पांच सौ पैंतीस तथा पैसे नवासी मात्र) + **ब्याज**	भौतिक
7.	(ऋण खाता सं. **X0HEELD00001735155 दिल्ली** शाखा) **श्री/सुश्री सरनजीत सिंह सोंधी** (कर्जदार) **गुरमीत कौर, हरमीत सिंह सोंधी, कंट्रोल टेकसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड** (सह–कर्जदार) सभी का पत्रव्यवहार हेतु पता : पी–402, आदित्य मेगा सिटी, वैभव खंड, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201014	**13–05–2019** **रू. 2,98,60,527.36** (रूपए दो करोड़ अठ्ठानवे लाख साठ हजार पांच सौ सत्ताईस तथा पैसे छत्तीस मात्र)	**दुकान नंबर जीसी–202, द्वितीय तल, गोल्ड क्रश आदित्य मेगा सिटी (छत का अधिकार नहीं) परिमाप 1053 वर्ग फीट, प्लॉट नंबर सी/जीएच–3 में अवस्थित 64,489.62 वर्ग मीटर परिमाप के कॉम्प्लेक्स वैभव खंड, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश –201014 में स्थित।**	**रू. 65,00,000/–** (रूपए पैंसठ लाख मात्र)	**रू. 6,50,000/–** (रूपए छह लाख पचास हजार मात्र)	**रू. 2,98,60,527.36** (रूपए दो करोड़ अठ्ठानवे लाख साठ हजार पांच सौ सत्ताईस तथा पैसे छत्तीस मात्र) + **ब्याज**	सांकेतिक
			आवासीय प्लॉट नंबर 013, परिमाप 250 वर्ग मीटर, ब्लॉक–डी, सेक्टर–61, गौतमबुद्ध नगर, नोएडा जिला	**रू. 2,35,00,000/–** (रूपए दो करोड़ पैंतीस लाख मात्र)			सांकेतिक
8.	ऋण खाता सं. **(X0HEDHE00001316727 एवं X0HEEDDL00001546761)** **मुकुल खन्ना** (कर्जदार) **विद्योत्तमा खन्ना, एस.एन. खन्ना, ग्रासरोट एग्रोफार्म्स प्रा. लि.** (सह–कर्जदार) **सभी का पत्राचार हेतु पता** :एच–28, भू, प्रथम तल, मस्जिद मोठ, ग्रेटर कैलाश–II, नई दिल्ली–110048	**22–11–2017** **रू. 5,87,79,739.67** (रू. पांच करोड़ सतासी लाख उनासी हजार सात सौ उन्तालीस तथा पैसे सड़सठ मात्र)	**सम्पत्ति परिमाप 216 वर्ग गज, भू एवं प्रथम तल (ड्यूपलेक्स) मकान नंबर 28, मस्जिद मोठ, ग्रेटर कैलाश–II, नई दिल्ली–110048**	**रू. 5,00,00,000/–** (रू. पांच करोड़ मात्र)	**रू. 50,00,000/–** (रू. पचास लाख मात्र)	**रू. 7,19,95,263/–** (रू. सात करोड़ उन्नीस लाख पिच्यानवे हजार दो सौ तिरेसठ मात्र)+ **ब्याज**	भौतिक
9.	(ऋण खाता सं. **X0HEDHE00001282721 दिल्ली** शाखा) **श्री/सुश्री धनेश कालरा** (कर्जदार) **रंजीत सिंह, सुरिन्दर कालरा, सुरिन्दर कालरा, जय राम सिंह, किरण सेल्स प्रा. लि.** (सह–कर्जदार) सभी का पत्रव्यवहार हेतु पता : मकान नंबर जे–232, जे पाकेट, भू तल तथा प्रथम तल, सरिता विहार, नई दिल्ली –110044 **अन्य पता** : मकान नंबर जे–12/42, राजौरी गार्डन, द्वितीय तल, नई दिल्ली–110027	**24–05–2019** **रू. 3,30,69,745.00** (रूपए तीन करोड़ तीस लाख उनहत्तर हजार सात सौ पैंतालीस मात्र)	**सम्पत्ति 2 – फ्लैट नंबर 232, भू तल तथा प्रथम तल, कैट–एसएफएस–III, पाकेट–के, सरिता विहार के लेआउट प्लान में स्थित, नई दिल्ली**	**रू. 1,30,00,000/–** (रूपए एक करोड़ तीस लाख मात्र)	**रू. 13,00,000/–** (रूपए तेरह लाख मात्र)	**रू. 3,30,69,745.00** (रूपए तीन करोड़ तीस लाख उनहत्तर हजार सात सौ पैंतालीस मात्र) + **ब्याज**	सांकेतिक
			सम्पत्ति 3 – सम्पत्ति सं. जे–12/42 का सम्पूर्ण द्वितीय तल छत टेरेस के अधिकार सहित, परिमाप 200 वर्ग गज, राजौरी गार्डन के नाम से मशहूर ग्राम ततारपुर, नई दिल्ली के क्षेत्र में स्थित।	**रू. 1,22,00,000/–** (रूपए एक करोड़ बाईस लाख मात्र)	**रू. 12,20,000/–** (रूपए बारह लाख बीस हजार मात्र)		

नीलामी के नियम एवं शर्तें

1. **सीलबंद बिड/ऑफर प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि** : सीलबंद बिड/ऑफर निर्धारित निविदा प्रपत्र में ईएमडी तथा केवाईसी सहित शाखा कार्यालय : **प्रथम एवं द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 6, मेन पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 में 29–11–2019** तक अप. 05.30 बजे से पूर्व प्रस्तुत की जा सकती है। अधूरी निविदाएं अथवा अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त निविदाएं अवैध मान्य होंगी और तदनुसार अस्वीकृत होंगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
2. **बिड/ऑफर खोलने की तिथि (नीलामी तिथि)** : सम्पत्ति हेतु बिड/ऑफर उपरोक्त पते पर स्थित शाखा कार्यालय में **30–11–2019** को पूर्वा. 10.00 बजे खोली जाएगी। निविदा प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में खोली जाएगी।
3. **अचल सम्पत्ति की निरीक्षण की तिथि** 19–11–2019 को **पूर्वा. 10.00 बजे** से **अप. 03.30 बजे** के बीच है।
4. इसके अतिरिक्त, सूचना में वर्णित बकाया राशि पर, इसकी पूर्ण वसूली तक, ऋण अनुबंध के अनुसार ब्याज तथा अनुषंगी व्यय, लागत इत्यादि प्रभारित किए जाएंगे।
5. एतद्द्वारा कर्जदारों तथा गारंटरों को बिक्री के समय पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने की सूचना दी जाती है तथा वे बिक्री के नियम एवं शर्तों के अनुसार उपरोक्त अचल सम्पत्ति के क्रय हेतु इच्छुक क्रेता/खरीदार ला सकते हैं।
6. **एतद्द्वारा कर्जदार(रों)/तथा गारंटर(रों) को सरफासी ऐक्ट, 2202 के तहत बिक्री के संबंध में 15 दिन का नोटिस दिया जाता है** कि वे उपरोक्त राशि नीलामी की तिथि से पहले चुकता कर दें, जिसमें असफल रहने पर सम्पत्ति की नीलामी की जाएगी तथा शेष राशि, यदि कोई होगी, ब्याज एवं लागत सहित वसूल की जाएगी। यदि कर्जदार चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड की बकाया पूरी राशि बिक्री से पहले चुका देता है, तो नीलामी रोक दी जाएगी।
7. नीलामी के विस्तृत नियम एवं शर्तें निर्धारित निविदा प्रपत्र में दी गई हैं। निविदा प्रपत्र उपरोक्त शाखा कार्यालय में उपलब्ध हैं।
8. अचल सम्पत्ति उच्चतम निविदादाता को बेची जाएगी। तथापि प्राधिकृत अधिकारी को आवश्यक समझे जाने पर परस्पर बोलीदान की अनुमति देने का विवेकाधिकार प्राप्त है। उपरोक्त सम्पत्ति सुरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी।
9. **चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड उपरोक्त सम्पत्ति पर किसी भी लम्बित देयता के लिए जिम्मेदार नहीं है। सम्पत्ति "जैसा है जहां है आधार", "जो है जैसा है आधार" "जो भी है वहां है आधार" पर नीलाम की जाएगी।**
10. कुल बकाया ऋण राशि ऋण पूर्वबंदी राशि नहीं है। अन्य सभी प्रभारों (यदि कोई) की गणना ऋण बंद करते समय की जाएगी।
11. डिमांड ड्राफ्ट केवल **'चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड'** के पक्ष में बनाया जाना चाहिए।

अतिरिक्त विवरण के लिए, प्राधिकृत अधिकारी से उपरोक्त कार्यालय पते पर सम्पर्क करें।

स्थान : दिल्ली/एनसीआर दिनांक : 14–11–2019

हस्ता./–
प्राधिकृत अधिकारी
चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

पलटवार करने उतरेगी अफगानिस्तान

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

अपने घरेलू मैदान अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में वनडे सीरीज 3-0 से गंवाने के बाद अफगानिस्तान की टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ बृहस्पतिवार से शुरू हो रही तीन टी-20 मैचों में अपना दमखम दिखाने की कोशिश करेगी। वैसे छोटे फार्मेट में अफगानिस्तान अपने प्रदर्शन से प्रतिद्वंदी वेस्टइंडीज पहले भी कई बार चौंका चुकी है। अफगानिस्तान के पास कई मिस्ट्री स्पिनर और बड़े शॉट खेलने वाले बल्लेबाज हैं, जो किसी भी वक्त मैच का पासा पलट सकते हैं। हजरतउल्लाह जाजाई, जावेद अहमदी, असगर अफगान और नजीबुल्लाह जादरान लंबे शॉट खेलने में माहिर हैं। टीम में मुजीब उर रहमान और कप्तान राशिद खान के रूप में दो खतरनाक स्पिन गेंदबाज हैं। हालांकि वनडे सीरीज में राशिद का प्रदर्शन अपेक्षा अनुरूप नहीं रहा था और तीन मैचों में उन्हें सिर्फ दो ही विकेट मिले थे। मगर टी-20 की बदली हुई गणित में वह अफगान टीम के लिए तुरुप का पत्ता साबित हो सकते हैं।

दूसरी ओर, मौजूदा टी-20 विश्व चैंपियन वेस्टइंडीज को भी क्रिकेट का यह सबसे छोटे प्रारूप बहुत भाता है। कैरेबियाई टीम के पास लंबे शॉट लगाने वाले खिलाड़ियों की लंबी जमात है। हालांकि गेंदबाजी विभाग में वह कुछ कमजोर नजर आती है।

वेस्टइंडीज की टीम में टी-20 स्पेशलिस्ट लेंडल सिमंस को अंतिम 11 में जगह मिलने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा अनुभवी विकेटकीपर दिनेश रामदीन की भी वापसी हुई है। टीम की बल्लेबाजी पर नजर डालें तो इसमें सिमंस एविन लेविस, कप्तान काइरन पोलार्ड, निकोलस पूरन, ब्रेंडन किंग और जेसन होल्डर के रूप में ताबड़तोड़ बल्लेबाज शामिल हैं। जहां तक गेंदबाजी का सवाल है तो इसका दारोमदार मुख्य रूप से होल्डर और शेल्डन कॉटरेल पर होगा। टीमें-अफगानिस्तान : हजरत उल्लाह जजई, इब्राहिम जादरान, जावेद अहमदी, नजीबुल्लाह जादरान, असगर अफगान, गुलबदन नईब, राशिद खान (कप्तान), रहमान उल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), नवीन उल हक, सैयद शहजाद और मुजीब उर रहमान। वेस्टइंडीज : लेंडल सिमंस, एविन लेविस, ब्रेंडन किंग, दिनेश रामदीन, निकोलस पूरन, काइरन पोलार्ड, कप्तान जेसन होल्डर, खैरी पियरे, हेडन वाल्श जूनियर, अलजारी जोसेफ और शेल्डन कॉटरेल।

पूरन चार मैचों के लिए निलंबित

दुबई। वेस्टइंडीज के विकेटकीपर बल्लेबाज निकोलस पूरन को अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान गेंद से छेड़छाड़ की बात स्वीकार करने के लिए बुधवार को चार मैचों के लिए निलंबित कर दिया गया। पूरन इस अपराध के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांग चुके हैं। पूरन अब वेस्टइंडीज की ओर से चार टी-20 मैचों में नहीं खेल पाएंगे और उनके रिकार्ड में पांच डिमेरिट अंक जोड़े गए हैं। तीसरा एकदिवसीय मैच लखनऊमें सोमवार को खेला गया था। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने बयान में कहा, खिलाड़ियों और खिलाड़ियों के सहयोगी स्टाफ से जुड़ी आईसीसी आचार संहिता के लेवल तीन के उल्लंघन की बात स्वीकार करने के लिए निकोलस पूरण को चार निलंबन अंक दिए गए हैं। आईसीसी ने कहा कि वीडियो फुटेज में दिखा था कि यह क्रिकेटर अंगूठे के नाखून से गेंद की सतह को खरोंच रहा था जिसके बाद पूरन पर संहिता के नियम 2.14 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था जो गेंद की दशा बदलने से संबंधित है। पूरन ने मंगलवार को अपराध स्वीकार कर लिया और साथ ही मैच रैफरी क्रिस ब्राड की सजा भी स्वीकार की। पूरन ने कहा कि मुझे पता चल गया है कि मैंने फैसला करने में बहुत बड़ी गलती की और मैं आईसीसी की सजा को पूरी तरह से स्वीकार करता हूं। उन्होंने कहा कि लखनऊ में सोमवार को खेल के मैदान पर जो हुआ उसके लिए मैं टीम के अपने साथियों, समर्थकों और अफगानिस्तान की टीम से माफी मांगना चाहता हूं। लेवल तीन के उल्लंघन पर कम से कम चार निलंबन अंक दिए जाते हैं जिससे खिलाड़ी के रिकार्ड में पांच डिमेरिट अंक जुड़ जाते हैं। खिलाड़ियों को इसके लिए दो टेस्ट मैच या चार एकदिवसीय अंतराष्ट्रीया टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों से प्रतिबंधित किया जाता है। अधिकतम सजा 12 निलंबन अंक की है जो छह डिमेरिट अंक के बराबर है।

अभ्यास सत्र के दौरान बैटिंग करता वेस्टइंडीज काखिलाड़ी

ट्रेंट बोल्ट मुंबई इंडियन्स और राजपूत राजस्थान रायल्स की ओर से खेलेंगे

नई दिल्ली। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट अगले साल के इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियन्स की ओर से खेलेंगे जबकि घरेलू स्तर पर उम्दा प्रदर्शन करने वाले तेज गेंदबाज अंकित राजपूत राजस्थान रायल्स का हिस्सा होंगे। आईपीएल के बयान के अनुसार दिल्ली कैपिटल्स ने ट्रेडिंग विंडो के दौरान बोल्ट को मुंबई इंडियन्स को सौंपने का फैसला किया जबकि किंग्स इलेवन पंजाब ने राजपूत को राजस्थान रायल्स को दिया। बोल्ट ने 2014 में आईपीएल पदार्पण किया। वह 2018 और 2019 सत्र में दिल्ली की ओर से खेले। उन्होंने 33 मैचों में 38 आईपीएल विकेट चटकाए हैं। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज राजपूत 2018 में किंग्स इलेवन पंजाब से जुड़े थे। उन्होंने 23 आईपीएल मैचों में 22 विकेट चटकाए हैं। राजपूत ने 2018 में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ लीग चरण में शानदार प्रदर्शन करते हुए 14 रन देकर पांच विकेट चटकाए थे। वह आईपीएल में किसी मैच में पांच विकेट हासिल करने वाले ऐसे एकमात्र गेंदबाज हैं जिन्होंने कभी अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है।

विश्व कबड्डी कप 2019 एक से नौ दिसंबर तक होगा

चंडीगढ़। पंजाब सरकार द्वारा आयोजित विश्व कबड्डी 2019 एक से नौ दिसंबर तक खेला जाएगा। राज्य के खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढी ने बुधवार को यहां यह जानकारी दी। उन्होंने साथ ही कहा कि इस साल का टूर्नामेंट सिख गुरु गुरुनानक देव जी की 550वीं जयंती को समर्पित होगा। सोढी ने कहा कि टूर्नामेंट में नौ टीमों- भारत, अमेरिका आस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, श्रीलंका, कीनिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और कनाडा- के हिस्सा लेने की उम्मीद है। उन्होंने हालांकि बताया कि पाकिस्तान और कनाडा की टीमों को अभी भारत सरकार से स्वीकृति नहीं मिली है। सोढी ने बयान में कहा कि पाकिस्तान और कनाडा के अलावा सभी टीमों को केंद्र सरकार से एनओसी मिल गई है। इन दो देशों से जुड़े अनापत्ति प्रमाण पत्र का अभी इंतजार है। टूर्नामेंट का उद्घाटन एक दिसंबर को सुल्तानपुर लोधी के गुरुनानक स्टेडियम में होगा और इस दिन चार मुकाबले खेले जाएंगे। समापन समारोह डेरा बाबा नानक के शहीद भगत सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगा।

एशियाई युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के छह पदक पक्के

उलानबटोर (मंगोलिया)। भारत ने बुधवार को यहां एशियाई युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में दबदबा बनाया जब उसके छह मुक्केबाजों ने पदक पक्के करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। साय सेलाय (49 किग्रा), अमन (94 किग्रा से अधिक), अंकित नरवाल (60 किग्रा), नाओराम चानू (51 किग्रा), जास्मिन (57 किग्रा) और विंका (64 किग्रा) ने यहां अंतिम चार में प्रवेश किया। सेलाय ने फिलिपीन फ्लिंट जारा को 5-0 से हराया जबकि अमन ने ताइवान के काइ सुंग वैंग को नाकआउट किया। नरवाल ने भी ताइवान के यू लिन को एकतरफा मुकाबले में 5-0 से शिकस्त दी। महिला ड्रा में चानू ने कोरिया की युनसु सुन को 5-0 से हराया। जस्मिन और विंका ने भी अपने अपने मुकाबलों में दबदबा बनाया। जास्मिन ने जापान की किमुरा मोना को हराया जबकि विंका ने ताइवान की सुएह जू सुइ को शिकस्त दी। नेहा कासन्याल (60 किग्रा) और रोहित मोर (52 किग्रा) को हालांकि क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। नेहा को कोरिया की मिह्युन जो के खिलाफ 2-3 से शिकस्त झेलनी पड़ी जबकि रोहित को थाईलैंड के सुरावुत सुखतेत ने इसी अंतर से हराया।

भारत के शीर्ष खिलाड़ी पुणे चैलेंजर के प्रीक्वार्टर फाइनल में

पुणे। प्रजनेश गुणेश्वरन की अगुआई में भारत के शीर्ष एकल खिलाड़ियों ने बुधवार को यहां केपीआईटी-एमएसटीएलए चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई लेकिन साकेत माइनेनी को अच्छी स्थिति में होने के बावजूद हार का सामना करना पड़ा। भारत के नंबर एक खिलाड़ी और शीर्ष वरीय प्रजनेश ने सिर्फ 49 मिनट में चंद्रील सूद को 6-1 6-3 से हराया जबकि तीसरे वरीय सुमित नागल ने एक घंटा और 16 मिनट में आर्यन गोवियास को 6-3 7-6 से शिकस्त दी। छठे वरीय रामकुमार रामनाथन ने आठ ऐस की मदद से यूनान के मार्कोस कालोवेलोनिस को 6-3 6-4 से हराया। आठवें वरीय शशिकुमार मुकुंद ने जापान के तोशिदे मातसुई को 6-2 6-3 से शिकस्त दी। दूसरी तरफ 10वें वरीय माइनेनी को दूसरे दौर में तुर्की के एर्गी किरकिन के खिलाफ 6-3 4-2 की बढ़त बनाने के बावजूद 6-3 5-7 4-6 से हार झेलनी पड़ी।

एशियाई टूर पर 300वें टूर्नामेंट में खेलेंगे गोल्फर ज्योति रंधावा

गुरुग्राम। भारतीय गोल्फर ज्योति रंधावा गुरुवार से यहां शुरू हो रहे चार लाख डालर इनामी पैनासोनिक ओपन इंडिया के साथ एशियाई टूर पर 300वें टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। रंधावा 1994 में पेशेवर बने और तब से एशियाई टूर पर आठ खिताब जीत चुके हैं। उन्होंने इनमें से पांच खिताब भारत में जीते। रंधावा के करियर का सर्वश्रेष्ठ सत्र 2002 रहा जब वह एशियाई टूर आर्डर आफ मेरिट में शीर्ष पर रहे और तब एशिया के नंबर एक खिलाड़ी बने। इस भारतीय गोल्फर ने हालांकि एशियाई टूर पर अपना पिछला खिताब लगभग एक दशक पहले जीता था।

गोल्फर रिद्धिमा दिलावड़ी और दीक्षा ने संयुक्त बढ़त बनाई

कोलकाता। भारतीय गोल्फर रिद्धिमा दिलावड़ी ने बुधवार को यहां हीरो डब्ल्यूपीजीटी के 15वें चरण के पहले दौर के अंतिम होल में बर्डी कर दीक्षा डागर के साथ संयुक्त बढ़त हासिल की। सत्र के पांचवें खिताब की कोशिश में जुटी रिद्धिमा और दीक्षा ने एक अंडर 71 का कार्ड खेला। दीक्षा एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने इस साल लेडीज यूरोपीय टूर खिताब जीता है। थाईलैंड की पी सुपाकचाया 73 के कार्ड से तीसरे जबकि वाणी कपूर और सिद्धि कपूर 74 के कार्ड से संयुक्त चौथे स्थान पर बनी हुई हैं।

भारत की अफगानिस्तान से भिड़ंत आज

विश्व कप क्वालीफायर मैच

एजेंसी। दुशान्बे (ताजिकिस्तान)

भारतीय फुटबाल टीम की निगाहें गुरूवार को यहां कड़ाके की ठंड में अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले विश्व कप के अहम क्वालीफाइंग मैच में शानदार प्रदर्शन कर जीत हासिल करने पर लगी होंगी। भारत ने अभी तक अपने अभियान में जीत हासिल नहीं की है और उनके पास अगले दौर की संभावना बनाए रखने के लिए जीत हासिल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। भारत ने क्वालीफायर के दूसरे दौर का अभियान अपने से ऊंची रैंकिंग की ओमान के खिलाफ मिली 1-2 की हार से शुरू किया, इसके बाद उसने दोहा में सितंबर में एशियाई चैम्पियन कतर से गोलरहित ड्रा खेला। पहले दो मैचों में दिखाए गए प्रदर्शन से तीसरे दौर में जगह बनाने की संभावनाएं बनीं लेकिन 15 अक्टूबर को कोलकाता में पड़ोसी देश बांग्लादेश से 1-1 के ड्रा ने इसे कम कर दिया।

आदिल खान ने 88वें मिनट में किए गए हेडर गोल से यह ड्रा हासिल किया, वर्ना साल्ट लेक स्टेडियम में उन्हें बुरी तरह निराश होना पड़ता। टीम ग्रुप ई तालिका में तीन मैचों में दो अंक लेकर चौथे स्थान पर बनी हुई है। पांच टीमों के ग्रुप में उप विजेता के भी तीसरे दौर में पहुंचना तय नहीं है इसलिए भारतीय टीम के अफगानिस्तान के खिलाफ हार से संभावनाएं खत्म ही हो जाएंगी। अफगानिस्तान की टीम फीफा रैंकिंग में 149वें स्थान पर काबिज है जबकि भारत 106वें स्थान पर बना हुआ है। ग्रुप में अफगानी टीम एक जीत और दो हार से तीसरे स्थान पर है। भारतीय कोच इगोर स्टिमक अपनी टीम की स्थिति से भली भांति वाकिफ हैं और वह किसी भी हालत में इस मैच को गंवाना नहीं चाहते।

क्रोएशियाई कोच ने कहा, हमें इस मौके को हथियाकर मैच में जीत हासिल करनी ही होगी। इसके लिए सिर्फ हमारा प्रदर्शन ही अहम होगा। अफगानिस्तानी टीम ने दुशान्बे को अपना घरेलू स्थल चुना है और यह मैच कड़ाके की ठंड में कृत्रिम टर्फ पर खेला जाएगा। इससे स्टिमक की परेशानियां बढ़ गई हैं क्योंकि खिलाड़ी इन परिस्थितियों में खेलने के आदी नहीं हैं।

मेलबर्न। आस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट ने हरभजन सिंह को कठिनतम प्रतिद्वंद्वी करार देते हुए कहा कि भारत का यह आफ स्पिनर और श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन उनके अंतरराष्ट्रीय कैरियर में दो सबसे कठिन गेंदबाज रहे। अपने शानदार कैरियर की उपलब्धियों और यादगार पलों को याद करते हुए गिलक्रिस्ट ने 2001 के भारत दौरे का जिक्र किया जिसमें हरभजन ने गेंदबाजी के जौहर दिखाए थे। उन्होंने कहा कि हरभजन मेरे पूरे कैरियर में सबसे कठिन प्रतिद्वंद्वी रहे हैं।

सीजीएफ प्रतिनिधिमंडल से मिलेगा आईओए

नई दिल्ली । भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) गुरुवार को यहां राष्ट्रमंडल खेल महासंघ (सीजीएफ) के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक करके 2022 बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में निशानेबाजी को दोबारा शामिल कराने का अंतिम प्रयास करेगा। अध्यक्ष नरिंदर बत्रा और सचिव राजीव मेहता सहित आईओए के शीर्ष अधिकारियों के अलावा खेल मंत्री किरेन रीजीजू सीजीएफ अध्यक्ष लुईस मार्टिन और सीईओ डेविड ग्रेवेमबर्ग से मुलाकात करके राष्ट्रमंडल खेलों से निशानेबाजी को हटाने का विरोध करेंगे।

स्थानीय आयोजन समिति ने साजो-सामान से जुड़े मुद्दों के कारण निशानेबाजी को खेलों से बाहर कर दिया था। आईओए ने निशानेबाजी को बाहर किए जाने को लेकर जुलाई में खेल मंत्रालय को खेलों के बहिष्कार का प्रस्ताव भेजा था जिसके बाद इस बैठक पर सहमति बनी।

दुती चंद टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल

नई दिल्ली। भारतीय धाविका दुती चंद को टाइम पत्रिका की दुनिया की सबसे प्रभावी 100 व्यक्तियों की सूची के विस्तार के अंतर्गत शुरू की गई टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल किया गया। यह सूची टाइम पत्रिका ने शुरू की है जिसमें 100 उदीयमान सितारों को शामिल किया गया जो व्यवसाय, मनोरजंन, खेल, राजनीति, स्वास्थ्य और विज्ञान में भविष्य बनाने को तैयार हैं।

मो. शाहिद हाकी स्टेडियम में बुधवार से शुरू शीला चतुर्वेदी स्कूल हाकी लीग में जयपुरिया स्कूल, कैपिटल पब्लिक स्कूल और त्रिलोकी सिंह स्कूल ने अपने-अपने मुकाबले जीत लिए हैं।

PUBLIC NOTICE
To whom it may Concern
It is for information for General Public that my Client, Mr. Khursheed Anwar son of Late Iqbal Hussain Resident of K-3, Gaffar Manzil Extention Part-II (Haji Colony), Jamia Nagar, Okhla, New Delhi-25 have disowned his son Saifuddin Asad he shall have no right and concern with us or our moveable and immoveable properties, I shall not be held liable & responsible for the acts/ deeds/ offence/ guarantee/ loan/ liability / debts / responsibilities of him and I shall not be held responsible for the same.
Jawaid Hussain Khan, Advocate
Lawyers Block, Saket Court Complex, N.D.

कैमेक कॉमर्शियल कम्पनी लिमिटेड
(सीआईएन:एल70109डीएल1980पीएलसी169318)
पंजी. कार्यालय : प्रथम तल, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
ई-मेल : camaccommercial@gmail.com
फोन : 7303495375
वेबसाइट : www.camaccommercial.com;
सूचना
सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 29 के साथ पठित विनियम 47 के अनुसरण में, एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक शुक्रवार, 22 नवम्बर, 2019 को आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य के साथ 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त दूसरी तिमाही (क्यू 2) हेतु कम्पनी के अ-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम विचारित एवं अनुमोदित किए जाएंगे।
उपरोक्त सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.camaccommercial.com पर भी उपलब्ध है तथा कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को भेजी जा चुकी है।
बोर्ड के आदेश द्वारा
वास्ते कैमेक कॉमर्शियल कम्पनी लिमिटेड
हस्ता./-
स्वाति श्रीवास्तव
स्थान : नई दिल्ली (निदेशक)
तिथि : 13-11-2019 डीआईएन - 08529225

पीएनबी फाइनैंस ऐण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
सीआईएन : एल65929डीएल1947पीएलसी001240,
ई-मेल : pnbfinanceindustries@gmail.com
पंजी. कार्यालय : प्रथम तल, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
वेबसाइट : www.pnbfinanceandindustries.com ;
फोन : 91-7303495375
सूचना
सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 29 के साथ पठित विनियम 47 के अनुसरण में, एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक बृहस्पतिवार, 21 नवम्बर, 2019 को आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य के साथ 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही हेतु कम्पनी के पृथक्कृत और समेकित अ-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम विचारित एवं अनुमोदित किए जाएंगे।
उपरोक्त सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.pnbfinanceandindustries.com पर भी उपलब्ध है तथा कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को भेजी जा चुकी है।
बोर्ड के आदेश द्वारा
वास्ते पीएनबी फाइनैंस ऐण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
हस्ता./-
तिथि : 13-11-2019 श्वेता सक्सेना
स्थान : नई दिल्ली कम्पनी सचिव

ADDI INDUSTRIES LIMITED
CIN:- L51109DL1980PLC256335
Regd Office: 23, Eastern Avenue, Maharani Bagh, New Delhi - 110065
E-mail: atul.addi@gmail.com, Ph.: 0120-2529335
Statement of Standalone & Consolidated Financial Results for the Quarter and Half Year Ended September 30, 2019
(Rs. in Lacs, except per share data)

Sr No.	Particulars	Standalone			Consolidated		
		Quarter Ended	Correspond-ing 3 months ended in the previous year	Half Year Ended	Quarter Ended	Correspond-ing 3 months ended in the previous year	Half Year Ended
		30.09.2019	30.09.2018	30.09.2019	30.09.2019	30.09.2018	30.09.2019
		(Unudited)	(Unudited)	(Unudited)	(Unudited)	(Unudited)	(Unudited)
1.	Total income from operations	25.05	10.76	42.37	28.22	13.71	48.70
2.	Net Profit for the period (before Tax and exceptional items)	3.26	(15.35)	1.69	6.38	(12.43)	7.95
3.	Net Profit for the period (before Tax, after exceptional items)	3.26	(15.19)	1.61	6.38	(12.27)	7.87
4.	Net Profit for the period after Tax (after exceptional items)	3.10	(14.98)	2.02	5.97	(12.25	7.79
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the Period after Tax and Other Comprehensive Income after Tax)	4.12	(14.76)	4.05	6.99	(12.03)	9.82
6.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	-	-	-
7.	**Paid-up equity share capital (Face Value Rs 5/- each)**	**540.00**	**540.00**	**540.00**	**540.00**	**540.00**	**540.00**
8.	Earnings Per Share (of Rs 5/- each)(Not Annualised)						
	a) Basic (amount in Rs.)	0.03	(0.14)	0.02	0.06	(0.11)	0.07
	b) Diluted (amount in Rs.)	0.03	(0.14)	0.02	0.06	(0.11)	0.07

Notes :
1. The above is an extract of the detailed format of quarter & half year financial results filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure requirements) Regulation, 2015. The full format of the quarter & half year financial results are available on the webites of the stock exchange. (URL-www.bseindia.com).
2. The above financial results have been reviewed by Audit Committee and thereafter approved and taken on record by the Board of Directors in its meeting held on November 13, 2019. The Statutory auditors have expressed an unmodified audit opinion.
3. The Impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s) due to change(s) in accounting policies shall be disclosed by means of a footnote.

For and on behalf of Directors
ADDI Industries Limited
Sd/-
Place : New Delhi Hari Bansal
Date : November 13, 2019 Director
Din : 00022923

GULSHAN
GULSHAN POLYOLS LIMITED
CIN:L24231UP2000PLC034918
Regd. Off: 9th K.M., Jansath Road, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh
Ph.:0131-3201231, Fax: 0131- 2661378, website: www.gulshanindia.com
FINANCIAL HIGHLIGHTS Q2 FY2019-20
Statement of Un - Audited Financial Results for the Quarter & Half Year ended 30th September, 2019
(₹ In Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended		Half year ended		Year Ended
		30.09.2019	30.09.2018	30.09.2019	30.09.2018	31.03.2019
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total income from Operations (Refer Note -2)	**17,672.44**	16,483.68	**34,578.77**	33,175.81	67,584.91
2	Net Profit/ (Loss) for the period (Before Tax, Exceptional and / or Extraordinary Items)	**812.72**	752.59	**1,790.89**	1,689.44	2,701.73
3	Net Profit/ (Loss) for the period Before Tax (After Exceptional and / or Extraordinary Items)	**812.72**	752.59	**1,790.89**	1,689.44	2,701.73
4	Net Profit/ (Loss) for the period After Tax (After Exceptional and / or Extraordinary Items)	**573.63**	541.89	**1,302.57**	1,193.12	2,142.52
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (After Tax) and other Comprehensive Income (After Tax)]	**573.63**	541.89	**1,302.57**	1,193.12	2,139.50
6	Paid-up equity share capital (Face Value of ₹ 1/- each)	**469.17**	469.17	**469.17**	469.17	469.17
7	Reserves Excluding Revaluation Reserve					
8	Earnings Per Share for Continuing and Discontinued Opreations (Before & After Extraordinary Items) (Face Value of ₹ 1/-each)					
	Basic	**1.22**	1.15	**2.78**	2.54	4.56
	Diluted	**1.22**	1.15	**2.78**	2.54	4.56

NOTES :
1. The Auditor has conducted Limited Review of these Financial Results. The results were reviewed by the Audit Committee. The Board of Directors has taken on record the financial results at its meeting held on November 13, 2019.
2. The statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015, (IND-AS) prerscribed under Section 133 of the Comapanies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.
3. Effective April 1, 2019, the Company adopted Ind AS 116 "Leases", applied to all lease contracts existing on April 1, 2019 using the modified retrospective method along with the transition option to recognize Right-of-Use asset (ROU) at an amount equal to the lease liability. Accordingly, comparatives for the quarters ended September 30, 2018 and half yearly ended September 30, 2018 and year ended March 31, 2019 have not been retrospectively adjusted. The effect of this adoption is not material on the profit for the period and earnings per share.
4. Figures for the previous period have been regrouped/ rearranged wherever necessary to make them comparable with current figure.

On behalf of Board of Directors
For, Gulshan Polyols Limited
Sd/-
Date : 13th November, 2019 (Dr. Chandra K. Jain)
Place : Delhi Chairman and Managing Director

'जीवन के अनुभव ही मेरे अभिनय में विविधता लाते हैं'

अभिनेता **आयुष्मान खुराना** स्वयं को सामान्य मध्यमवर्गीय देशवासी के परिवेश में ढालने के इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि अब ऐसा करना उनके लिए एक सहज सी बात हो गई है। अधिक ब्यौरा दे रही है पायनियर संवाददाता **सायमी सत्तार** की ये रिपोर्ट-

वो एक ऐसे अभिनता हैं जो सामान्य भारतीय की दैनिक गतिविधियों को इतने सटीक ढंग से परदे पर उतारते हैं कि आज उनकी अलग पहचान बन चुकी है। वो चंडीगढ़ में पैदा हुए और उनका लालन-पालन भी वहीं हुआ। लेकिन वो आज भी हर फिल्म को एक बाहरी व्यक्ति की तरह लेते हैं। विकी डोनर से साल 2012 में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाले आयुष्मान खुराना मुंबई में पिछले सात सालों से हैं। वो बताते हैं, 'मैं एक प्रशंसक के रूप में आज भी उतना ही उत्साह अनुभव करता हूं। मैं मसाला फिल्में देखकर ही बड़ा हुआ हूं और अपने स्कूली दिनों में मैंने इसके लिए ब्लैक से टिकट भी खरीदे थे। मैं तब अत्यंत उत्साहित होता हूं जब मुझे किसी पुरस्कार वितरण आयोजन में अपने खान्स तथा अमिताभ बच्चन जैसे वरिष्ठ कलाकारों को देखने का अवसर मिलता है। हाल ही में आने वाली फिल्म गुलाबो सिताबो में जब मैं अमिताभ बच्चन के साथ पहली बार काम कर रहा था तो मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई थी। मुझमें किसी बाहरी जैसी मासूमियत विद्यमान है। वो फॉरेस्ट आउटफिट में थे और वो अपने व्यवहार में इतने सामान्य हैं कि परदे पर भी उन्हें देखकर लगता है जैसे कोई अपने बीच का ही व्यक्ति हो।

वो बाहरी होते हुए भी रेडियो जॉकी, गायक, अभिनता और टीवी परिचारक भी रह चुके हैं। उन्होंने बताया, 'मैं पहले पत्रकार था और लोगों से प्रश्न पूछता था लेकिन आज मैं उनके उत्तर दे रहा हूं। मैंने एमटीवी और रेडियो पर फिल्मों की समीक्षा भी की है। अब मेरी फिल्मों की समीक्षा हो रही है। मैंने कई सितारों का साक्षात्कार किया है।' ये बताने के साथ ही वो स्वयं के सितारे होने के अनुभव का आनंद लेने लगते हैं। फिर वो बताते हैं, 'ये यात्रा सुखद रही है। रेडियो पर प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं सामान्य जनता के संपर्क में था और लगभग 20 अनजान निम्नवर्गीय लोगों से वार्तालाप और उनकी पसंद और नापसंद को जानने का प्रयास किया करता था। मैंने स्ट्रीट थियेटर में भी काम किया है और तब भी निम्नवर्गीय लोगों के बीच रहने का अनुभव लिया करता था। कम ही फिल्मी सितारों को ये अनुभव होगा। मेरे अनुभव ही मेरे अभिनय में विविधता लाते हैं।' आज भी किसी रोल को लेते समय वो सामान्य व्यक्ति का ध्यान अवश्य रखते हैं और ऐसी ही कहानियों को हां कहते हैं। फिल्म बाला में एक गंजे व्यक्ति बालमुकुंद का चरित्र निभा रहे आयुष्मान का कहना है, 'मैं स्टार का मुखौटा उतारकर एक आम दर्षक की भांति सोचता हूं और तब निर्णय करता हूं। मैं केवल अपने चरित्र के बारे में ही नहीं बल्कि पूरी कहानी को सुनता हूं। स्क्रिप्ट कितना नयापन लिये है ये भी मेरे निर्णय का कारक बनती है। हिंदी सिनेमा में वैसे तो ये पहली बार दर्शकों के सामने आ रही हो और यदि ऐसा न हो सके तो ये दर्षकों को दो घंटे बांधकर रखने में समर्थ होनी चाहिये। आजकल कि हाई कॉन्सेप्ट फिल्म की विचारधारा से मैं सहमत नहीं हूं। ये केवल केक पर लगी चेरी हो सकता है। जबकि पूरी फिल्म ही दर्शकों की रुचि के अनुसार होना जरूरी है। यदि ऐसा संभव हो तो हाई कॉन्सेप्ट की आवष्यकता ही नहीं पड़ेगी।'

> यदि आप में कमी है तो आपको अपने मजबूत पक्ष पर ध्यान देना चाहिये।

'मुझे उसमें बाल कहा जाता है जबकि मेरे बाल होते ही नहीं,' आयुष्मान ने हंसते हुए बताया। जब उन्होंने इसकी कहानी सुनी तो उन्होंने अनुभव किया कि वो इससे पहले शुक्राणुदान, स्तंभन समस्या वाली फिल्में तो कर चुके हैं लेकिन गंजा होना तो उन सभी से अधिक सामान्य है। 'इस अवधारणा को समझने के लिए तो किसी को माता-पिता के मार्गदर्षन की जरूरत भी नहीं होती, अत: ये मेरे लिए सर्वाधिक अनुकूल था,' हंसते हुए आयुष्मान ने बताया।

किसी छोटे नगर के सामान्य व्यक्ति की समस्या पर बनी किसी पहली फिल्म में काम नहीं कर रहे थे। इन समस्याओं को पहचान दिलाने के लिए भी वो इन्हें करते हैं, 'हम ऐसी समस्याओं को मध्यमवर्गीय इसलिये मानते हैं क्योंकि वे परंपरावादी होते हैं किसी प्रगतिषील समाज के लिए इनका कोई महत्व नहीं होता। उन्हें इसमें जरा भी हंसी नहीं आती। पहले से परिवर्तित व्यक्ति को उपदेश देने का कोई अर्थ नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए जब हम नपुंसकता पर बात करते हैं तो प्रगतिशील समाज के लोग उसका समाधान तलाश ही लेते। लेकिन मध्यमवर्ग और छोटे नगरों के लिए ये रोचक कहानी बन जाती है। अंतत: हमें अपने समाज के ऐसे ही लोगों को प्रगतिषील बनाना है।'

सामान्य व्यक्ति की इन्हीं असुरक्षा की भावना के कारण ही उनकी फिल्में अधिक व्यावहारिक होती हैं। आयुष्मान बताते हैं, 'हाल फिलहाल तक हम संपूर्ण नायक वाली फिल्में देखते रहे हैं लेकिन लोगों को कोई ऐसा चेहरा चाहिये था जो उनके जैसा हो, अब समय आ गया है कि हम सामान्य व्यक्ति को भी उनके समकक्ष रखकर उनमें भी आत्मविष्वास पैदा करने का कार्य करें।' उन्होंने बताया कि आजकल तो युद्ध से जुड़ी फिल्म 'उरी...' से लेकर 'सांड की आंख' या 'आर्टिकल 15' जैसी फिल्में भी अच्छा व्यवसाय कर रही हैं। 'लेकिन मानवदुर्बलताओं को कहानी के केन्द्र में रखना आजकल का नया रुझान है और अच्छा भी है। ये प्रगतिशील और वास्तविक है।'

उनका मानना है कि समस्या पर कटाक्ष करना किसी समस्या को संबोधित करने का सबसे सटीक ढंग है, 'ऐसा न हो तो ये भी वृत्तचित्र बनकर रह जाएंगी। सभी मनोरंजन चाहते हैं।' वो इस बात से भी सहमत हैं कि बाला को मिलाकर इन सभी फिल्मों में एक संदेश भी छिपा है, 'यदि आप में कमी है तो आपको अपने मजबूत पक्ष पर ध्यान देना चाहिये। गंजे लोग भी इसे दो तरह से देख सकते हैं या तो लोग इसपर शर्म करते रहें या फिर विग पहनना प्रारंभ कर दें दूसरा दृष्टिकोण ये है कि उन्हें इसे सामान्य मानते हुए अपने जीवन के लक्ष्यों पर ध्यान देना चाहिये। कुछ महिलाओं को गंजे लोग सेक्सी लगते हैं,' अंधाधुन के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके अभिनेता ने बताया। इस फिल्म में उनकी अभिनेत्रियों में यामी गौतम जिनके साथ 'विकी डोनर' में उन्होंने पदार्पण किया था और भूमि पेडनेकर जिनके साथ उन्होंने 'दम लगाकर हैसा' की थी, हैं। पहले साथ में काम कर चुकी अभिनेत्रियों के साथ पुन: काम करना दुधारी तलवार जैसा होता है। आप उनके साथ काम कर चुके होते हैं लेकिन कुछ बातों पर संशय भी रहता ही है। आपकी उनके साथ की केमिस्ट्री भी पूर्व जैसी नहीं होनी चाहिये। ये एक प्रकार की चुनौती ही है,' रोडीज़ 2 जीत चुके अभिनेता ने हमें बताया।

विविध प्रकार के चरित्र निभाने और उनके लिए प्रशंसा प्राप्त कर चुके आयुष्मान भी कभी संशय तथा असुरक्षा के शिकार थे। वो बताते हैं, 'मैं खेल की टीम में होने के बाद भी अत्यंत दुर्बल था। मैं कभी अच्छा नहीं लगता था, रेडीमेड कपड़े मुझे कभी फिट नहीं आते थे। मेरे दांतों में ब्रेसेज़ लगे थे और मैं चश्मा पहनता था। मैं हर किशोर की भांति अल्हड़ टाइप का था। मेरे भी मनोविकार थे। लेकिन हमें ये पीछे छोड़कर अपने को सुधारना होता है।'

हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म उजड़ा चमन, के बारे में पूछने पर, जिसमें भी नायक को गंजा दिखाया गया है, आयुष्मान ने कहा, 'मैंने इसकी कहानी कोलकाता के लेखक पवेल भट्टाचार्य जिनका संदर्भ मुझे शुभ मंगल सावधान के निर्देशक प्रसन्ना से मिला था। कहानी सुनने के बाद मैं दिनेश विजन और अमर कौशिक के पास गया क्योंकि मुझे लगा कि वे इसे सही अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। कहानी और पटकथा को निरेन भट्ट ने बाद में और विकसित किया। आष्चर्य की बात है कि एक ही विषय पर मुझे चार लोगों से चार अलग विचार मिले थे लेकिन मैंने सही संयोजन को ही चुना। कुछ ने उस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया और मुझे इसे आगे बढ़ाने के लिए कहा। लेकिन एक टीम ने अंतत: इसे पूरा किया।'

यदि वर्तमान अभिनेताओं को देखा जाए तो आयुष्मान ही ऐसे हैं जो बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सफलता के साथ ही समीक्षकों से भी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। ऐसा उनकी छ: अनवरत सफल फिल्मों से भी पता चलता है। लेकिन उन्होंने कहा, 'आप बॉक्स ऑफिस सफलता का कोई फार्मूला नहीं ढूंढ सकते। क्योंकि जो बात आज प्रासंगिक है कल नहीं भी हो सकती है। फिल्मों में बदलाव तो आते ही रहेंगे। बस हमें भी समय के साथ बदलते रहना होगा। हम अभिनेता लोग कई बार सड़क के आदमी से कटने लगते हैं और वास्तविक लोगों के संपर्क में नहीं रहते। हमें उनके संपर्क में लगातार बने रहना होगा।'

भविष्य में उनकी इच्छा के बारे में पूछने पर आयुष्मान बताते हैं कि वो बद्रीनाथ की दुल्हनियां, स्त्री और हैप्पी फिर भाग जाएगी में काम कर चुके अपने भाई अपारशक्ति खुराना के साथ किसी फिल्म में काम करना चाहते हैं, 'हम ऐसी स्क्रिप्ट चाहते हैं जो हम भाइयों के लिए बनाई गई हो और हमारा बराबर का रोल हो। अब उसे भी लीड रोल मिलना चाहिये, उन्होंने अपनी राह स्वयं बनाई है।'

लेकिन वो अब टीवी पर परिचारक के रूप में काम नहीं करना चाहते, 'यदि मैं टीवी पर वापस जाना भी चाहूं तो मेरे भीतर वो उत्साह होना चाहिये और शो में भी जान होनी चाहियें, नहीं तो अतीत जैसे काम करना मेरे विचार से निरर्थक ही रहेगा।' लेकिन परदे रजतपट पर उनके धमाकेदार प्रदर्शन को देखकर ऐसी संभावना नगण्य ही है।

लता मंगेशकर जीवनरक्षक प्रणाली पर, हालत नाजुक

मुंबई। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर अभी भी जीवनरक्षक प्रणाली पर हैं। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है लेकिन सेहत में सुधार भी हो रहा है। अस्पताल के सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। लता मंगेशकर (90) को सोमवार की सुबह ब्रीच कैंडी अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में भर्ती करवाया गया था। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उनका इलाज डॉक्टर पतित समधानी कर रहे हैं। अस्पताल के एक सूत्र ने बताया, मामूली सुधार के बावजूद उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। वह अभी भी आईसीयू में, जीवन रक्षक प्रणाली पर हैं। सेहत में सुधार होने में थोड़ा वक्त लगेगा। लता मंगेशकर की पीआर टीम ने कहा कि उनकी हालत स्थिर है। टीम की ओर से जारी वक्तव्य में कहा गया, लताजी की हालत स्थिर है और पहले से अच्छी है। आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। हम उनके अच्छे होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वह जल्द से जल्द घर लौट आएं। हमारा साथ देने, हमारी निजता का सम्मान करने के लिए शुक्रिया।

भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिखाई जाएंगी आराधना और सत्यकाम

मुंबई। भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफ एफआई) के गोल्डन लाइनिंग इंडियन फिल्म्स सेक्शन में हृषिकेश मुखर्जी की सत्यकाम और शक्ति सामंत की आराधना प्रदर्शित की जाएंगी। धर्मेंद्र, संजीव कुमार और शर्मिला टैगोर अभिनीत सत्यकाम को भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक माना जाता है। आराधना साठ के दशक की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जिसमें राजेश खन्ना और शर्मीला टैगोर ने अभिनय किया था। इस सेक्शन में ओड़िया, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी, असमी और मलयालम भाषाओं की 2398ीिल्में दिखाई जाएँगी। इस सेक्शन में दिखाई जाने वाली अन्य फिल्मों में सत्यजीत रे, सिद्धार्थ, एन लक्ष्मीनारायण और के एस सेतुमाधवन की फिल्में शामिल हैं। आईएफएफआई का 50वां संस्करण गोवा में 20 से 28 नवंबर तक आयोजित होगा। इस दौरान इसमें 76 देशों की दो सौ से अधिक फिल्में दिखाई जाएंगी।

दुनिया के सबसे बड़े कला संग्रहालय के बोर्ड में चुनी गईं नीता अंबानी

न्यूयॉर्क। समाज सेवी और व्यवसाई नीता अंबानी को भारत की कला एवं संस्कृति को संरक्षित करने तथा उसका प्रचार करने में उनकी असाधारण प्रतिबद्धता के लिए द मेट्रोपोलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के बोर्ड में चुना गया है। दुनिया में सबसे बड़े और सबसे अधिक देखे जाने वाले कला संग्रहालयों में से एक इस संग्रहालय के अध्यक्ष डेनियल ब्रॉडस्की ने ऐलान किया कि अंबानी को इसका मानद न्यासी नामित किया गया है। मंगलवार को बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया।

बोर्ड में नीता अंबानी का स्वागत करते हुए ब्रॉडस्की ने कहा, द मेट और भारत की कला एवं संस्कृति को संरक्षित करने तथा उसको बढ़ावा देने में उनकी प्रतिबद्धता सही मायने में असाधारण है। उनके सहयोग का दुनिया के हर कोने की कला प्रदर्शित करने की संग्रहालय की क्षमता पर गहरा असर पड़ा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन हैं। रिलायंस फाउंडेशन 2016 से द मेट को सहयोग दे रहा है। वह मेट की अंतरराष्ट्रीय परिषद की सदस्य भी हैं। संग्रहालय ने अक्टूबर 2017 में बताया था कि रिलायंस फाउंडेशन ने भारतीय कला के संवर्धन के लिए उसे अच्छी-खासी राशि उपहार में देने का वादा किया है। हालांकि, उसने यह नहीं बताया कि यह राशि कितनी है। संग्रहालय ने नीता और मुकेश अंबानी को ग्रेट चैंपियंस ऑफ दि मेट बताया। नीता ने 2017 में उपहार की घोषणा के समय कहा था कि भारत में कला और संस्कृति की समृद्ध विरासत है। उन्होंने कहा कि फाउंडेशन का उद्देश्य न सिर्फ भारत में बल्कि विदेश के विभिन्न संस्थानों में भारतीय कला को बढ़ावा देना है।

इंस्टाग्राम पर अर्जुन कपूर के प्रशंसकों की संख्या हुई एक करोड़ 10 लाख

मुंबई। अभिनेता अर्जुन कपूर ने इंस्टाग्राम पर लाख फॉलोवर की संख्या पार होने पर अपने प्रशंसकों को उनके प्रेम के लिए धन्यवाद दिया है। अर्जुन ने मंगलवार को इंस्टाग्राम पर लिखा, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपने परिचय के तौर पुत्र ,भाई,मित्र और अभिनता बताया है और उनका कहना है कि जो कहते हैं कि समय धन है, वह झूठ बोलते हैं। समय जीवन है। र्जुन कपूर आशुतोष गोवारिकर की पानीपत फिल्म में नजर आएंगे।

कैटी पेरी मुंबई पहुंची बोलीं, घूमना है पसंद

मुंबई में इंटरनेशनल पॉप स्टार केटी पेरी के साथ अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीस

एजेंसी। मुंबई

पॉप गायिका कैटी पेरी इस सप्ताह के अंत में होने वाली अपनी परफॉर्मेंस के लिए शहर में पहुंच चुकी हैं। उनका कहना है कि वह रास्तों से खरीददारी करने और बॉलीवुड हस्तियों के साथ पार्टी करने समेत कई ऐसी चीजों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं जो भारत की खासियत है।

वह वन प्लस संगीत महोत्सव के तहत 16 नवंबर को डी.वाई पाटिल स्टेडियम में प्रस्तुति देंगी। पेरी ने संवाददाताओं से कहा, मैं कुछ अन्य लोगों की प्रस्तुति देखने के लिए उत्साहित हूं। मैं इस हफ्ते मुंबई में, खुद को यहां की संस्कृति में ढालने के लिए पूरी तरह उत्साहित हूं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कमरे के अंदर रह कर रूम सर्विस के लिए कहूंगी। मैं बाहर जाती हूं, दुनिया देखती हूं, मुझे लोग, संस्कृति और परंपराएं पसंद है।

आप मुझे यहां के रास्तों पर पाएंगे।' वह यहां आयोजित विशेष संवाददाता सम्मेलन में बोल रहीं थीं जहां उनके साथ अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस भी मौजूद थीं जो इस कार्यक्रम का संचालन करेंगी। संगीत की दुनिया में कदम रखने के बाद से अपने जीवन पर पडने् वाले प्रभावों के बारे में पेरी ने कहा कि वह अब अपने जीवन का आनंद लेना चाहती हैं।

उन्होंने कहा कि वह भविष्य में लाइव कार्यक्रम करना चाहती हैं जहां वह अपने प्रशंसकों के साथ ज्यादा अच्छा समय बिता पाएं। पेरी ने कहा कि 11-12 वर्षों से लगातार संगीत की दुनिया में सक्रिय रहने के बाद अब उन्हें काम और निजी जिंदगी में संतुलन बनाना पड़ेगा।

तनुश्री मेरी बैकबोन हैं: इशिता दत्ता

मुंबई। तुनश्री दत्ता को हाल ही में टीवी शो 'बेपनाह प्यार' के सेट पर देखा गया, जिसमें उनकी बहन इशिता दत्ता काम कर रही हैं। बड़ी बहन तनुश्री को प्यार से 'दी' कहने वाली इशिता ने कहा, 'दी कुछ साल पहले अमेरिका चली गई थीं और इसलिए वह मिलने सेट पर नहीं आ सकती थीं। पहली बार उन्होंने मुझे कैमरे के सामने परफॉर्मेंस करते देखा। वह बेहद खुश हुईं। दीदी को अच्छा समय गुजारते देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। पूरा यूनिट उनकी मौजूदगी से खुश था और उन्हें सहज महसूस कराने की कोशिश की।'

इशिता ने यह भी बताया कि कैसे तनुश्री ने उनके सपनों को पूरा करने में उनकी मदद की। उन्होंने कहा, 'तनुश्री ने मुझे मेकअप करना सिखाया जबकि मैं ब्रश भी ढंग से पकड़ना नहीं जानती थी। उन्होंने मुझे तब एक्टिंग स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित किया, जब मैं अपने व्यक्तित्व और अभिनय को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं थी। यहां तक उन्होंने शहर के सबसे अच्छे फोटोग्राफरों से मेरा फोटो शूट कराया। उन्होंने मुझे मेरा सर्वश्रेष्ठ करने के लिए प्रोत्साहित किया। आज मैं बड़ी फिल्मों में से एक में और शहर के बड़े टीवी प्रोडक्शन हउस में से एक में काम कर रही हूं। कई लोग नहीं जानते कि मेरी बहन मेरी बैकबोन रही है।'

पिछले साल तनुश्री तब सुर्खियों में आई थीं जब उन्होंने नाना पाटेकर के खिलाफ यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए खुलकर बोला था। उन्होंने कहा था कि 2008 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान नाना ने उनके साथ यौन दुर्व्यवहार किया था। उनके मामले के बाद भारत में हैशटैगमीटू मूवमेंट ने जोर पकड़ लिया और कई महिलाओं ने यौन उत्पीड़न संबंधी अपने बुरे अनुभव साझा किए।

वेब सीरीज 'पवन पूजा' को लेकर उत्साहित हैं एंजेला क्रिसलिंज्की

मुंबई। फिल्म '1921' में दर्शकों का मनोरंजन कर चुकीं अभिनेत्री एंजेला क्रिसलिंज्की आगामी वेब सीरीज 'पवन पूजा' को लेकर उत्साहित हैं। वेब सीरीज के निर्देशक 'बंटी और बबली' फेम शाद अली हैं। यह शो एक जोड़े पवन और पूजा के बारे में है। इसमें शरमन जोशी, गुल पनाग, कुणाल, माधिवाला, मृणाल दत्त, गीतिका विद्या, जैकी श्रॉफ, नीना गुप्ता और आंचल चंदेल भी हैं।

इस समय एंजेला अपने नए म्यूजिक वीडियो 'तेरा बदन' के लिए मिल रही तारीफों का लुत्फ ले रही हैं। वह जल्द ही दिल्ली में फिल्म 'आराम से' की शूटिंग शुरू करेंगी।